

प्रस्तुत पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी  
शब्दावली आयोग की मानक ग्रन्थ योजना  
के अन्तर्गत, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार  
के शत प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित हुई है।

मूल्य : पाँच रु०

प्रकाशक : सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

मुद्रक : राजस्थान विश्वविद्यालय मुद्रणालय,  
जयपुर।

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिये यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक से अधिक संख्या में तैयार किए जाएं। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्व-विद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने आधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

“कराधान : एक सैद्धान्तिक विवेचन” नामक पुस्तक सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसमें कराधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रसिद्ध ग्रन्थों एवं पत्रिकाओं में अधिकारी विद्वानों के चुने हुए लेखों का हिन्दी अनुवाद एवं विषय-प्रवेश का मौलिक लेखन श्री लक्ष्मीनारायण पाथुराभका ने किया है। लेखों के चयन में डा० राजा जे० चेलैया, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। अनुवाद का पुनरीक्षण डा० इन्द्रदेव, केन्द्र के भूतपूर्व कार्यवाहक निदेशक, द्वारा किया गया है। आशा है भारत सरकार द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रदान का सभी क्षेत्रों में, विशेषतया सार्वजनिक वित्त के पाठशालों द्वारा स्वागत किया जाएगा।



## प्राक्कथन

भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पद्याओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के गिरन्तर बढ़ने हुए उपयोग से विभिन्न विषयों में हिन्दी में प्रामाणिक एवं उच्चस्तरीय साहित्य की मांग तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा के स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए यह निरान्त आवश्यक है कि एक तरफ विद्वान् अधिकारियों द्वारा हिन्दी में मौखिक रचनाएँ प्रस्तुत की जाएँ और दूसरी तरफ विभिन्न विषयों पर उपलब्ध अंग्रेजी के ग्रन्थों एवं क्वालिटी प्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशित उच्चकोटि के उपयोगी लेखों का शुद्ध, सरल एवं सुन्दर अनुवाद भी सीधेतापूर्वक प्रकाशित किया जाय। मेरी यह मान्यता है कि अंग्रेजी से हिन्दी माध्यम में परिवर्तन की अवधि यथासंभव कम की जानी चाहिए, अन्यथा वैज्ञानिक स्तरों में होने वाली गिरावट को रोक सक्ता कठिन हो जायेगा। इसके लिए व्यापक पैमाने पर श्रेष्ठ रचनाओं के हिन्दी अनुवाद विद्यार्थियों को उपलब्ध किये जाने चाहिए।

मुझे यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 'सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र' की ओर से कराधान के विभिन्न पहलुओं पर अधिकृत सामग्री का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। प्राचा है यह ग्रन्थ 'सार्वजनिक वित्त' के कराधान-पक्ष में शक्ति रखने वाले छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा और यह विभिन्न विश्व-विद्यालयों के संबंधित पाठ्यक्रमों में निस्तदेह शामिल किया जा सकेगा।

मेरा विश्वास है कि सुयोग्य अनुवादक व सक्षमनवर्ता ने बड़ी तत्परता एवं लगन से इस कार्य को सम्पादित किया है। फिर भी यदि इसमें अधिक लेखों का समावेश हो सक्ता तो इस रचना की उपयोगिता और भी बढ़ सकती थी, लेकिन मुझे यह बतलाया गया है कि अनुवादधिकार प्राप्त करने में काफी समस्याएँ हैं जिनके कारण प्रथम संस्करण में इससे आगे जा सकना दुष्कर था। संभवतः आगामी संस्करणों में यह संभाव दूर किया जा सकेगा।

प्रफुल्ल बिहारी पाण्डे

उप-कुलपति

23 दिसम्बर, 1966.

राजस्थान विश्वविद्यालय



## आभार-प्रकाश

हम उन लेखकों व प्रकाशकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनके लेखों एवं पुस्तकों के अध्यायों का हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थ में शामिल किया गया है। प्रथम अध्याय में डेविड वाकर के सुप्रसिद्ध लेख "The Direct-Indirect Tax Problem : Fifteen Years of Controversy" का अनुवाद है जो नीदरलैंड से प्रकाशित होने वाले Public Finance के खण्ड x/x-iii Anne'e संख्या 2, 1955 में छपा था। दूसरे अध्याय में भारत के कराधान-जांच-आयोग की रिपोर्ट, खण्ड 1, 1953-54 से आठवें अध्याय : Outlines of Tax Policy का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में भार० ए० मसप्रॉव के लेख "On Incidence" का हिन्दी अनुवाद है जो "Journal of Political Economy" खण्ड LXI, अगस्त, 1953, संख्या 4 में छपा था। यह University of Chicago Press की अनुमति से प्रकाशित किया जा रहा है। अतुर्थ अध्याय में जेम्स एम० बुकानन की पुस्तक Fiscal Theory and Political Economy—Selected Essays (1960) से "The Methodology of Incidence Theory : A Critical Review of Some Recent Contributions" नामक अध्याय का अनुवाद शामिल किया गया है। पाँचवें व छठे अध्यायों में डा० राजा जे० चेल्वैया की पुस्तक "Fiscal Policy in Underdeveloped Countries" से क्रमशः "The Principle of Taxation According to Ability to Pay" (Pp 60-71) एवं "Indirect Taxation" (Pp 85-105) का हिन्दी अनुवाद जोड़ा गया है। सातवें, आठवें व नवें अध्यायों में प्रोफेसर विक्टोरस बेहदोर की Indian Tax Reform नामक रिपोर्ट से क्रमशः अध्याय 1, 2 व 3 के प्रमुख प्रकरणों का अनुवाद दिया गया है।



## आभार-प्रकाश

हम उन लेखकों व प्रकाशकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनके लेखों एवं पुस्तकों के अध्यायों का हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थ में शामिल किया गया है। प्रथम अध्याय में डेविड वाकर के सुप्रसिद्ध लेख "The Direct-Indirect Tax Problem : Fifteen Years of Controversy" का अनुवाद है जो नीदरलैंड से प्रकाशित होने वाले Public Finance के खण्ड x/x-m Anne'e संख्या 2, 1955 में छपा था। दूसरे अध्याय में भारत के कराधान-जाच-आयोग की रिपोर्ट खण्ड 1, 1953-54 से आठवें अध्याय : Outlines of Tax Policy का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में चार० ए० महप्रोब के लेख "On Incidence" का हिन्दी अनुवाद है जो "Journal of Political Economy" खण्ड LXI, प्रगस्त, 1953, संख्या 4 में छपा था। यह University of Chicago Press की अनुमति से प्रकाशित किया जा रहा है। चतुर्थ अध्याय में जेम्स एम० बुकानन की पुस्तक Fiscal Theory and Political Economy—Selected Essays (1960) से "The Methodology of Incidence Theory : A Critical Review of Some Recent Contributions" नामक अध्याय का अनुवाद शामिल किया गया है। पाँचवें व छठे अध्यायों में डा० राजा जे० बेल्लैवा की पुस्तक "Fiscal Policy in Underdeveloped Countries" से क्रमशः "The Principle of Taxation According to Ability to Pay" (Pp 60-71) एवं "Indirect Taxation" (Pp 85-105) का हिन्दी अनुवाद जोड़ा गया है। सातवें, आठवें व नवें अध्यायों में प्रोफेसर निकोलस केल्हॉर की Indian Tax Reform नामक रिपोर्ट से क्रमशः अध्याय 1, 2 व 3 के प्रमुख प्रकरणों का अनुवाद दिया गया है।





## आभार-प्रकाश

हम उन लेखकों व प्रकाशकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनके लेखों एवं पुस्तकों के अध्यायों का हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थ में शामिल किया गया है। प्रथम अध्याय में डेविड वाकर के सुप्रसिद्ध लेख "The Direct-Indirect Tax Problem : Fifteen Years of Controversy" का अनुवाद है जो नीदरलैंड से प्रकाशित होने वाले Public Finance के खण्ड x/x-III Anne'e संख्या 2, 1955 में छपा था। दूसरे अध्याय में भारत के कराधान-जांच-आयोग की रिपोर्ट, खण्ड 1, 1953-54 से आठवें अध्याय : Outlines of Tax Policy का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में थार० ए० मसघोब के लेख "On Incidence" का हिन्दी अनुवाद है जो "Journal of Political Economy" खण्ड LXI, अगस्त, 1953, संख्या 4 में छपा था। यह University of Chicago Press की अनुमति से प्रकाशित किया जा रहा है। चतुर्थ अध्याय में जेम्स एम० बुकानन की पुस्तक Fiscal Theory and Political Economy—Selected Essays (1960) से "The Methodology of Incidence Theory : A Critical Review of Some Recent Contributions" नामक अध्याय का अनुवाद शामिल किया गया है। पांचवें व छठे अध्यायों में डा० राजा जे० चेतन्या की पुस्तक "Fiscal Policy in Underdeveloped Countries" से क्रमशः "The Principle of Taxation According to Ability to Pay" (Pp 60-71) एवं "Indirect Taxation" (Pp 85-105) का हिन्दी अनुवाद जोड़ा गया है। सातवें, आठवें व नवें अध्यायों में प्रोफेसर निकोलस देहबॉर की Indian Tax Reform नामक रिपोर्ट से क्रमशः अध्याय 1, 2 व 3 के प्रमुख प्रकरणों का अनुवाद दिया गया है।



# विषय-सूची

प्रस्तावना : डा० विट्ठलकरेण सेठी

अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

प्राक्कषण : प्रोफेसर एम० बी० मायूर,

उप-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय

आभार-प्रकाश

विषय-प्रवेश ... i—xx

- 1 प्रत्यक्ष-परीक्ष कर-समस्या :  
विवाद के पश्चात् कार्य—डेविड वावर ... 1
- 2 कर-नीति की रूपरेखा—कराधान-जाच-आयोग,  
रिपोर्ट, प्रथम खण्ड ... 35
- 3 करापात—आर० ए० मसुमेव ... 76
- 4 करापात-सिद्धान्त की पद्धति :  
हाल ही के कुछ योगदानों की  
आलोचनात्मक समीक्षा—जेम्स एम० बुकानन ... 116
- 5 भारत के लिये कराधान का सर्वोत्तम  
ढाँचा—डा० राजा जे. बेर्लिया ... 147
- 6 परीक्ष कराधान—डा० राजा जे. बेर्लिया ... 163
- 7 वैयक्तिक कराधान में व्यापक सुधार के  
पक्ष में—प्रो० निबोलस बेल्डोर ... 191
- 8 विपुल पत्र पर वार्षिक कर—प्रो० निबोलस बेल्डोर ... 206
- 9 वैयक्तिक सर्व-कर—प्रो० निबोलस बेल्डोर ... 218



## विषय-प्रवेश

सरकार को अपने व्यय-कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है। इन वित्तीय साधनों को विभिन्न प्रकार से जुटाया जा सकता है। अधिकांश सरकारी कार्य सामूहिक उपभोग (Collective Consumption) जैसे होते हैं, अतः ये करो के द्वारा ही पूरे किये जाने चाहिए। चूंकि इन सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा सम्पूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होता है, अतः इनको छोटे घंशों में बांट कर नहीं बेचा जा सकता है। सामूहिक उपभोग की वस्तुओं में हम निवेद्यारमक सिद्धान्त (Principle of exclusion) को नहीं अपना सकते। इस दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण समाज से ही साधन प्राप्त किए जाने चाहिए। ये साधन करों के रूप में प्राप्त किये जाते हैं। करों की विशेषता यह होती है कि ये अनिवार्य होते हैं तथा ये समाज पर किसी मान्य आधार ■ अनुसार लगाये जाते हैं। अतः सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में करो का बहुत महत्व है। जैसा स्पष्ट है कि कर अनिवार्य रूप से देने पड़ते हैं तथा किसी व्यक्ति द्वारा करों का देना उसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लाभ से सम्बन्धित नहीं होता है। अतः करों के लगाने का समाज की अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कर-निर्धारण में करो के प्रभाव तथा समाज के आर्थिक उद्देश्यों की दृष्टिगत रचना आवश्यक होता है।

करारोपण के विभिन्न सिद्धान्त :—करो की महत्ता एवं प्रभाव की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम उन सिद्धान्तों का विवेचन करें जिनके आधार पर कर लगाये जाने चाहिए। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में प्रारम्भ ■ ही करो के सिद्धान्तों के विषय में विचार प्रगट किये गये हैं। बणिजवादियों एवं प्रभुत्ववादियों ने करो के सम्बन्ध में अपने विचार बताये तथा इसके बाद एडम स्मिथ ने करो के सिद्धान्त आज तक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मकसों (McCulloch) जे०बी० से, जे०एस० मिल तथा एडवर्से ने करो के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। इस क्षेत्र में हाट्टन एवं पीट्र ने भी अपने विचारों से काफी योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बणिजवादियों से लेकर पीट्र एवं हाट्टन तक विभिन्न विद्वानों ने करारोपण के सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं तथा विज्ञान एवं भी इस सम्बन्ध में एकमत नहीं है।

तब मे करारोपण के सिद्धान्त कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित है। अभी तक के करारोपण के सिद्धान्त पेरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Paretian Welfare Economics) पर आधारित हैं, किन्तु अब कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रो० एरो (Arrow) तथा अन्य विद्वानों ने नए विचार प्रतिपादित किये हैं। इस कारण से आजकल अर्थशास्त्री पेरेटियन कल्याणकारी अर्थशास्त्र को अधिक युक्तिमय एवं उपयोगी नहीं मानते हैं, हालांकि अभी तक भी सम्पूर्ण करारोपण के सिद्धान्त पेरेटो के विचारों पर आधारित हैं। किन्तु पेरेटियन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के आधार पर अधिक कल्याण को ठीक-ठीक माप सकने के कारण ये कर के उचित ढंग के निर्माण में बम ही उपयोगी सिद्ध हो पाते हैं।

वास्तव में, करारोपण के सिद्धान्तों का निर्माण समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। ये उद्देश्य देश, काल, अर्थ-व्यवस्था के स्तर एवं प्रवृत्ति तथा उस समाज की सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिभूमि आदि कई बातों पर निर्भर करते हैं। किन्तु फिर भी सामान्य रूप में करारोपण के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए प्रो. क्यू के अनुसार निम्नलिखित चार उद्देश्य स्वीकार किये जा सकते हैं; — (1) चुनाव की अधिकतम स्वतन्त्रता (2) उद्योगिता एवं साधनों में स्वामी प्राथमिकता के अनुसार उद्योग मापनों एवं तकनीक के रूप में उच्चतम सम्भव जीवन स्तर (3) अधिक विभाग की अधिकतम दर (4) समानता के आधार पर धन का वितरण।

इन सर्वसामान्य उद्देश्यों के आधार पर प्रोफेसर क्यू ने करारोपण के तीन व्यापक सिद्धान्त दिये हैं। प्रो. केशरी ने भी अपनी पुस्तक "Indian Tax Reforms" में इसी तीन आधारों पर प्रत्येक कर का विवेचन किया है। ये निम्नलिखित हैं — (1) अधिक प्रभाव (2) समानता (3) प्रदानित बुद्धि।

**अधिक प्रभाव** — प्रत्येक कर के द्वारा करदाता को त्याग करना पड़ता है। इस कारण से कर अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। हर बताने वाला कर के द्वारा धन की प्रेरणा, बचत की प्रेरणा तथा प्रोत्ति उत्पान की प्रेरणा पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखना चाहिए। वास्तव में वही कर बंट होता है जो हम लोगों पर कम से कम कुछ प्रभाव डालता है। हमारे अर्थव्यवस्था पर करदाता, उद्योग तथा नागरिकों के स्वामी की प्राथमिक-

ताओं में भी परिवर्तन कर देता है। कर लगाते समय हमें यह बात भी दृष्टिगत रखनी चाहिए कि इन प्राथमिकताओं में परिवर्तन इस प्रकार से हो जिससे उच्चतम समय स्तर तक पहुँचा जा सके अथवा उस स्तर से कम से कम सम्भव दूरी पर रहा जा सके।

**समानता :—**यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में करों के भार को किस प्रकार से विभाजित किया जाय। "समानता" अपने आप में सामाजिक मूल्यों पर आधारित एक विचार है। सर्वाधिक समान कर-व्यवस्था वही मानी जाती है जो समाज द्वारा स्वीकृत वास्तविक आय के वितरण की समानता के स्तर के अनुरूप हो।

अर्थशास्त्रियों ने समानता की धारणा का दो प्रकार से विश्लेषण किया है। प्रथम, क्षैतिज समानता (horizontal equity)। तथा द्वितीय सम्भवत् समानता (vertical equity) क्षैतिजीय समानता से तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ "समान परिस्थिति" शब्द को परिभाषा एवं विवेचन अपने आप में एक बृहत् कार्य है। सम्भवत् समानता से तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों पर उनकी तुलनात्मक स्थिति के अनुसार ही भार पड़ना चाहिए। किन्तु इस सन्दर्भ में भी व्यक्तियों की तुलनात्मक स्थिति का ठीक ठीक पता लगाकर तुलनात्मक भार का निर्धारण करना एक बहुत पेचीदा कार्य है। किन्तु संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि करों के निर्धारण में क्षैतिजीय समानता और सम्भवत् समानता के सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि समानता के इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करों के विभाजन का क्या आधार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र के साहित्य में दो दृष्टिकोण रम्य गये हैं :—

### 1. लाभ-आधार (The Benefit Basis)

इसे जहाँ एडम स्मिथ का समर्पण प्राप्त था वहाँ आधुनिक रूप में लिन्डहाल (Lindahl) ने इसे ऐच्छिक विनिमय सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के नियम को सरकारी क्षेत्र में कर-निर्धारण के लिए लागू किया गया है। जिस प्रकार निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरे को उसकी किसी वस्तु या सेवा के बदले कुछ देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को उतना ही कर देना चाहिए





सकती है । (2) आय की सीमान्त उपयोगिता आय वृद्धि के साथ-साथ कम होती जाती है । (3) सब व्यक्तियों का आय का सीमान्त उपयोगिता वक्र समान होता है तथा अन्तर्व्यक्तिगत उपयोगिता भापी जा सकती है ।

इन मान्यताओं के आधार पर प्रगामी कर का समर्थन किया गया है । किन्तु अन्य अर्थशास्त्रियों ने इन मान्यताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि ये सारी मान्यताएँ व्यावहारिक दृष्टि से ठीक ही उत्तरें । सामान्य तौर पर इन मान्यताओं का पाया जाना कठिन होता है । अतः हम यह नहीं कह सकते कि समान त्याग का सिद्धान्त केवल प्रगामी कर के बाचे को ही जन्म देता है ।

वास्तव में इस समान त्याग के सिद्धान्त में न्यूनतम कुल त्याग का विचार ही अधिक आवश्यक है । इसके अनुसार करों का इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए जिससे कर के रूप में सब व्यक्तियों द्वारा दिये गए धन की सीमान्त उपयोगिता सब व्यक्तियों के लिए बराबर हो । इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ मान्यताओं के आधार पर सर्वप्रथम धनवान व्यक्तियों से कर लेना चाहिए । न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त करारोपण का सामूहिक सिद्धान्त है ।

समान त्याग या करदेय क्षमता के इस सिद्धान्त की भी प्राप्ति की गई है तथा डाल्टन एवं पीगू ने अपना एक नया सिद्धान्त दिया है । उनका कहना है कि करदेय क्षमता का सिद्धान्त एरूपक्षीय है क्योंकि यह व्यय-पक्ष को दृष्टिगत नहीं रखता है । प्रो. पीगू एवं डाल्टन ने इसमें व्यय-पक्ष को सम्मिलित कर बजट के निवारण के अधिकतम कल्याण-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इसके अनुसार—(1) विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों में साधनों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यय से प्राप्त सीमान्त मंतोप बराबर हो । (2) सार्वजनिक व्यय उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ व्यय की अन्तिम इकाई से प्राप्त लाभ करों के रूप में प्राप्त अन्तिम इकाई से उत्पन्न त्याग के बराबर हो ।

यद्यपि यह सिद्धान्त ठोस धरातल पर आधारित है, किन्तु इसका व्यावहारिक दृष्टि से उपयोग करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं ।

### कर-क्षमता सूचक (Index of Ability)

अर्थशास्त्रियों में ब्रिज वार्तो में बड़ा मतभेद है उनमें करदेय क्षमता का आधार भी एक है । जब तक हमने सारा विवेचन आय को आधार मान

तना वह सरकार के कार्यों में लाभ प्राप्त करना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने  
 हा है कि "लाभ-आधार" के अन्तर्गत सरकार एवं करदाता का सम्बन्ध  
 देने का देना" (quid pro quo) के रूप में होता है।

इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि इस आधार पर करो  
 रा गुणिमाप्युक्त विभाजन किया जा सकता है तथा इसका प्रेरणादायी  
 (disincentive) प्रभाव नहीं पड़ता।

किन्तु धर्मशास्त्रियों ने इस आधार में अनेक कमियाँ पाईं तथा इसकी  
 आलोचना की। प्रथम, समाज के विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त लाभ की वृद्धि  
 नहीं की जा सकती। क्योंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में निषेधात्मक  
 सिद्धान्त के लागू न किये जा सन्ने के कारण निम्नी क्षेत्र की वस्तुओं के समान  
 प्राप्यमिता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जे० एम० मिल  
 ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इस आधार पर की गई कर  
 व्यवस्था प्रतिगामी (regressive) होगी क्योंकि सरकार के कार्यों से गरीब  
 लोगो को अधिक लाभ प्राप्त होता है, अतः उन्हें अधिक भर देना पड़ेगा।  
 लाभ-आधार की इन कमियों के कारण दूसरा दृष्टिकोण रखा गया।

## 2. करदेय क्षमता (Ability to pay Approach) —

"कानून के आगे सबको बराबर सम्मान चाहिए" की उक्ति को  
 करदेय क्षमता के सिद्धान्त का प्रेरक स्रोत कहा जा सकता है। इसी आधार  
 पर यह कहा गया कि करो में समानता का अर्थ है त्याग की समानता। इस  
 प्रकार कर-देय क्षमता के निरपेक्ष विचार को समान त्याग के सापेक्ष विचार  
 में परिवर्तित कर दिया गया।

इस सिद्धान्त के आधार पर मिल ने प्रणामी कर को प्रतिपादित किया  
 था। किन्तु सूक्ष्म विवेचन से ज्ञात होता है कि समानता एवं आय की सीमान्त  
 उपयोगिता के विभिन्न रूपों से विभिन्न परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।  
 "समानता" शब्द का तीन प्रकार से प्रयोग किया गया है—निरपेक्ष समानता,  
 समानुपातिक समानता एवं सीमान्त समानता। इसी प्रकार आय की सीमान्त  
 उपयोगिता बढ़ सकती है, घट सकती है या स्थिर रह सकती है।

कुछ विशिष्ट मान्यताओं के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि  
 समान... सिद्धान्त प्रणामी कर के बोझ को प्रतिपादित करता है। ये  
 ... की सीमान्त उपयोगिता मात्रा की दृष्टि से मापी जा

सकती है। (2) धन की सीमान्त उपयोगिता आय वृद्धि के साथ-साथ कम होती जाती है। (3) सब व्यक्तियों का आय का सीमान्त उपयोगिता एक समान होता है तथा अन्तर्व्यक्तिगत उपयोगिता मापी जा सकती है।

इन मान्यताओं के आधार पर प्रगामी कर का समर्थन किया गया है। किन्तु अन्य अर्थशास्त्रियों ने इन मान्यताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि ये सारी मान्यताएँ व्यावहारिक दृष्टि से ठीक ही उत्तरें। सामान्य तौर पर इन मान्यताओं का पाया जाना कठिन होता है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि समान त्याग का सिद्धान्त केवल प्रगामी कर के लाने को ही जन्म देता है।

भारत में इस समान त्याग के सिद्धान्त से न्यूनतम कुल त्याग का विचार ही अधिक आकर्षक है। इसके अनुसार करों का इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए जिससे कर के रूप में सब व्यक्तियों द्वारा दिये गए धन की सीमान्त उपयोगिता सब व्यक्तियों के लिए बराबर हो। इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ मान्यताओं के आधार पर सर्वप्रथम धनवान व्यक्तियों से कर लेना चाहिए। न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त बराबरी का सामूहिक सिद्धान्त है।

समान त्याग या करदेय क्षमता के इस सिद्धान्त की भी प्रालोचना की गई है तथा डास्टन एवं पीग ने अपना एक नया सिद्धान्त दिया है। उनका कहना है कि करदेय क्षमता का सिद्धान्त एकरूपशील है क्योंकि यह व्यय-पक्ष को दृष्टिगत नहीं रखता है। प्रो. पीग एवं डास्टन ने इसमें व्यय-पक्ष को सम्मिलित कर बजट के निर्धारण के अधिकतम बरतण-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार—(1) विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों में साधनों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यय से प्राप्त सीमान्त मत्तोय बराबर हो। (2) सार्वजनिक व्यय उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ व्यय की अन्तिम इकाई से प्राप्त लाभ करों के रूप में प्राप्त अन्तिम इकाई से उत्पन्न त्याग के बराबर हो।

यद्यपि यह सिद्धान्त ठोस धारणा पर आधारित है, किन्तु इसका व्यावहारिक दृष्टि से उपयोग करने में घने कठिनाइयाँ हैं।

### कर-क्षमता सूचक (Index of Ability)

अर्थशास्त्रियों में विद्वत्ताओं में बड़ा मतभेद है उनमें करदेय क्षमता का आधार भी एक है। जब तक हमने सारा विवेचन धन की आधार मान

र विद्या या : किन्तु कई विज्ञान गणित को ध्यान के अन्त में मानते हैं ।  
 उनके परिचित प्रो केन्टॉन ने आज की छोटी-छोटी उद्योगों का काम को परिचित  
 सिद्धांत आधार माना है । इस सम्बन्ध में गार्थर अधिक सिद्धांत विज्ञान  
 गणित में शामिल दिये गये 'व्यवस्था' के धारणा देना चाहते हैं । गार्थर  
 यह कहता था गणना है कि अन्य कुछ आधारों के साथ आज ही परिचित  
 उपयुक्त तथा व्यावहारिक आधार है ।

**प्रयोगात्मक बुद्धिमत्ता:**— वनारोपण का तीव्रता महत्त्वपूर्ण सिद्धांत  
 प्रयोगात्मक बुद्धिमत्ता है । वनों के नाश करने समय यह बात ध्यान में रखनी  
 चाहिए कि हमसे प्रयोगात्मक दृष्टि से अधिक कठिनाईपूर्ण उत्पन्न न हो जायें ।  
 वर इस प्रकार का होना चाहिए जिसे धारणा में इकट्ठा किया जा सके तथा  
 वर प्राप्त करने में अनुसन्ध व्यय हो ।

**अर्द्धविकसित देशों में कर-सिद्धान्त:**—परिचित अर्द्धविकसित देशों ने  
 अपने सिद्धान्त एक विकसित अर्थ-व्यवस्था को दृष्टिगत रखकर बनाये हैं ।  
 किन्तु आजकल अर्द्धविकसित देशों की समस्याएँ अधिक गम्भीर हैं तथा इन  
 देशों को विकसित करने की आवश्यकता है । अतः हमें वनों के सम्बन्ध में  
 किसी भी सिद्धान्त को प्रतिपादित करते समय इन अर्द्धविकसित देशों की  
 समस्याओं एवं विशेषताओं को दृष्टिगत रखना होगा । विकसित देशों  
 लिए बनाये गए सिद्धान्तों को हम उसी रूप में अर्द्धविकसित अर्थ-व्यवस्था के  
 लिए लागू नहीं कर सकते ।

डा. प्रो. एन. भार्गव ने अपनी पुस्तक "Indian Public Finance"  
 के अन्तर्गत अर्द्धविकसित देशों की कर-व्यवस्था के लिए करदेय क्षमता के  
 सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, किन्तु डा. चेल्सीया तथा कुछ अन्य विद्वान  
 इस मत से सहमत नहीं हैं ।

अर्द्धविकसित देशों में मुख्य समस्या आर्थिक विकास की गति को  
 तीव्र करने की है । आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए  
 अर्थ-व्यवस्था में विनियोग की दर को बढ़ाना आवश्यक होता है । विकसित  
 देशों में आर्थिक स्थिरता या स्थिर आर्थिक विकास प्रधान लक्ष्य होता है किन्तु  
 अर्द्धविकसित देशों में तो इस विकास की गति को तीव्र करना ही मुख्य लक्ष्य  
 होता है । दोनों के उद्देश्यों के इस अन्तर के कारण ही दोनों अर्थ-व्यवस्थाओं  
 में करों के सिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होते हैं । विकसित देशों में

करों का प्रधान कामें प्रसार को रोकना होता है, किन्तु भट्टविकसित देशों में प्रसार को रोकने के लिए विनियोग को कम नहीं किया जा सकता, अपितु यहाँ कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे बचत की ऊँची दर प्राप्त करके विनियोग की दर को बढ़ाया जा सके। इकाफे पत्रिका में इन देशों में करों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है "इसलिए करारोपण ही निजी उपभोग एवं विनियोग को कम करके साधनों को आर्थिक विकास के लिए सरकार की तरफ हस्तान्तरित करने का एकमात्र प्रभावपूर्ण वितीय साधन है।" वास्तव में इन देशों में मुख्य समस्या कुल विनियोग को बढ़ाने की है। अतः यहाँ केवल निजी क्षेत्र से सांख्यिक क्षेत्र में साधनों का हस्तांतरण करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस प्रकार का कर का ढाँचा भी तैयार करना आवश्यक है जिससे निजी क्षेत्र में विनियोग बढ़ जावे या सांख्यिक क्षेत्र में विनियोग में वृद्धि निजी क्षेत्र में हुई कमी से अधिक हो। इसी आधार पर डा. चेल्सीमा ने इन भट्टविकसित देशों के लिए करदेय-क्षमता के आधार को अनुपयुक्त बताते हुए एक नया आधार आर्थिक-बचत या आधिक्य (Economic Surplus) के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि इन देशों में सम्भाव्य बचत (Potential Saving) वास्तविक बचत से अधिक होती है। अतः इस सम्भाव्य बचत को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी उपयुक्त क्षमता या आर्थिक विकास के लिए देने की क्षमता के अनुसार कर देने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। आर्थिक आधिक्य के विचार के आधार पर ही उन्होंने भारत जैसे भट्टविकसित देशों के लिए करारोपण के सिद्धान्त भी दिये हैं। जिन्हें विस्तृत रूप से इस सफलन में देखा जा सकता है।

### प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर (Direct and Indirect Tax) :—

करों से साधन प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है। कई अर्थशास्त्रियों का ऐसा मत है कि परोक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष कर अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये यह मत इस आधार पर व्यक्त करते हैं कि परोक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच उपभोक्ताओं के चुनाव को भंग कर देते हैं, अतः ये प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा उपभोक्ता पर अधिक भार डालते हैं।

कई मान्यताओं के आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मत है कि साधनों के निर्धारण की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों की अपेक्षा ज्यादा

थेन्ट होने हैं। जोसेफ-हिक्स ने उदासीनता वक्रों की सहायता से यह समझाने का प्रयास किया है कि एक समानुपातिक आय-कर के लगाने पर उदासीनता एक वस्तु पर लगाये गए विशिष्ट कर (Specific Tax) की अपेक्षा एक ढ़े उदासीनता-वक्र पर रहना है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर के द्वारा उपभोक्ता से विशिष्ट कर के बराबर वन अपेक्षाकृत कम त्याग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु विद्वानों ने इस मन की आलोचना की है। कुछ विद्वानों ने तो धार्मिक बस्यान के प्रतीक के रूप में उदासीनता-वक्र के प्रयोग पर ही गद्देह व्यक्त किया है। प्रो० बाकर ने इस तर्क को धर्म की पूर्णतया सोचदार पूर्ति एवं "भादृष्टं प्रारम्भिक दशा" की दो मान्यताओं पर आधारित होने के कारण अभ्यावहारिक बताया है।

इसके अतिरिक्त वाल्ड ने जोसेफ-हिक्स द्वारा दिये गए चित्र का ही प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर दोनों ही बराबर भार डालते हैं। इसके अतिरिक्त हेन्डरसन एवं आई० एम० डी० लिटिल ने भी इस विवाद में अपने अपने तर्क दिये हैं। किन्तु यह सारा विवेचन केवल सैद्धांतिक है। वास्तव में तो प्रत्यक्ष कर का परोक्ष कर की अपेक्षा थोड़ा होना या न होना एक जांच का विषय है। इस सारे विवाद का विस्तृत विवेचन डेविड बाकर ने Public Finance में अपने प्रसिद्ध लेख में किया है जिसका अनुवाद प्रस्तुत संकलन में शामिल किया गया है।

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के इस विवाद को उत्पादन-सम्भावना-वक्र (Production Possibility Curve) के द्वारा भी समझाने प्रयास किया गया है। इसमें यह मान्यता की गई है कि कर लगाने से पूर्व साधनों के आदर्श निर्धारण (Ideal allocation of resources) की स्थिति होती है। इस स्थिति में  $P_1$  उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही की दृष्टि से दोहरा संतुलन बिन्दु (Double equilibrium point) होता है। इस स्थिति में यदि समानुपातिक आय-कर (proportional income tax) लगाया जाता है तो संतुलन बिन्दु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। किन्तु यदि इसके स्थान पर वस्तु क पर कर लगाया जाता है तो एक नया  $P_2$  दोहरा संतुलन बिन्दु प्राप्त होता है जो  $P_1$  बिन्दु की अपेक्षा नीचे उदासीनता-वक्र पर होता है। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों की अपेक्षा थोड़ा होते हैं। किन्तु आलोचकों ने इसी विवेचन का प्रयोग परोक्ष करों को थोड़ा सिद्ध करने के लिए किया है। उनका कहना है कि यदि हम साधनों के आदर्श निर्धारण की स्थिति अर्थात्  $P_1$  बिन्दु से प्रारम्भ न कर  $P_2$  से प्रारम्भ

करें तो यह कहा जा सकता है कि समानुपातिक आय-कर लगाने पर तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आवेगा किन्तु वस्तु पर कर लगाने पर हम साधनों के भादर्थ निर्धारण की स्थिति में पहुँच जायेंगे । अतः यह कहा जा सकता है कि परोक्ष कर प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं ।

इसके प्रतिरिक्त इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ और भी तर्क दिये जाते हैं । साधारणतया आय-कर प्रगामी होता है । अर्थशास्त्रियों ने उदाहरणों के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक प्रगामी आयकर असमान आय वाले व्यक्ति पर समान आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक भार डालता है । असमान आय की सम्भावना अधिकतर जोखमी व्यवसायों में होती है तथा समान आय सुरक्षित व्यवसायों में होती है । इसलिए आय-कर कार्य के पारितोषिक पर कर होता है । हमारे शब्दों में, इसे कभी-कभी आराम पर रियायत (subsidy) भी कहा जाता है । इस प्रकार कई अर्थशास्त्री आय-कर (प्रत्यक्ष कर) को कार्य करने की प्रेरणा पर बुरा प्रभाव डालने वाला बताते हैं । इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि आय-कर और उत्पादन-कर दोनों ही कार्य और आराम के बीच के चुनाव को समाप्त कर देते हैं किन्तु इसके प्रतिरिक्त उत्पादन-कर वस्तुओं के बीच चुनाव को भी समाप्त कर देता है, अतः परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा घटिया होता है ।

मसग्रैव ने एक उदाहरण द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा घटिया नहीं होता है । उसने तीन वस्तुएँ  $X$ ,  $Y$  और  $L$  (leisure) मानी हैं ।

$X$  पर कर  $X$  और  $Y$  तथा  $X$  और  $L$  के बीच चुनाव को समाप्त कर देगा ।

$Y$  " " " " "  $Y$  और  $L$  " " " " " कर देगा । आयकर " " " तथा  $X$  और  $L$  के बीच चुनाव को समाप्त कर देगा ।

अतः मसग्रैव का तर्क है कि उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा घटिया होता है ।

इस अनिश्चयात्मक स्थिति को देखते हुए ही कुछ लोग इनके विवाद में न पड़कर दोनों को ही समान रूप से महत्व देते हैं । व्यावहारिक दृष्टि से हमें किसी एक विशेष प्रकार के कर को न चुनकर सामान्य करों को ही चुनना चाहिए ।



प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के इस सैद्धान्तिक विश्लेषण के पश्चात् व्यावहारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि अर्द्धविकसित देशों में परोक्ष करों का क्या स्थान होना चाहिये। अर्द्धविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा कुल राष्ट्रीय आय भी कम ही होती है। ऐसी स्थिति में केवल प्रत्यक्ष करों से ही योजनाओं के लिए आवश्यक साधन नहीं जुटाए जा सकते। इस दृष्टि से अर्द्धविकसित देशों में योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने में परोक्ष करों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किन्तु परोक्ष करों का उपयोग केवल आय-प्राप्ति के उद्देश्य के आधार पर ही नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि इनके माध्यम से उपभोग पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और इस प्रकार बचत प्राप्त की जा सकती है। विकास योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न आय देश के सामान्य वर्ग को प्राप्त होती है, अतः इस बड़ी हुई आय को उपभोग में जाने से रोकने में वस्तु-करों का बड़ा महत्व होता है। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अर्द्धविकसित देशों में अधिकांश व्यक्ति जीवन-निर्वाह की सीमा पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के करों का क्या महत्व होता है। इस सम्बन्ध में डा० चेर्सीया ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि परोक्ष करों का कार्य किसी समय विशेष पर विनियोग की जा सकती है, किन्तु इसका कार्य तो पूर्व-विनियोग के फलस्वरूप बड़ी हुई सम्पूर्ण आय को उपभोग में जाने से रोकना है।

उपभोग पर रोक लगाने के इस तर्क के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, किन्तु जो कोई भी अर्द्धविकसित देशों में छिपी हुई बेरोजगारी (disguised unemployment) की समस्या से परिचित है वह इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में डा० चेर्सीया ने उपभोग वस्तुओं को तीन श्रेणियों में विभक्त करके विश्लेषण किया है।

परोक्ष करों का अवैयक्तिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि किसी भी प्रकार के कर-बोझ को अपनाने से पूर्व हमें उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का भली-भाँति विश्लेषण कर लेना चाहिए। परोक्ष करों के प्रभाव को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) आय-प्रभाव (2) स्थानान्तरण-प्रभाव (3) मूल्य-प्रभाव (4) वितरण-प्रभाव।

इन चारों प्रभावों तथा परोक्ष करों में सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर अर्द्धविकसित देशों में इनके महत्व के विस्तृत विश्लेषण के लिए प्रस्तुत

ग्रन्थ में डा० बेल्होर की पुस्तक से लिया गया सम्बन्धित अंश देखा जा सकता है।

भारत के लिये एक उपयुक्त कर-ड्राफ्ट के सम्बन्ध में बेल्होर के सुझाव :—

भारत में योजनाओं के माध्यम से व्यापक विकास का मार्ग चुना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्टतः किया गया कि भविष्य में हम अपनी योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने के मार्गों के विषय में काफी अध्ययन करना होगा। इस दृष्टि से भारतीय कर-ड्राफ्ट का अध्ययन भी आवश्यक समझा गया। इस कार्य के लिए कराधान-बोर्ड आयोग की भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई तथा इसने कर ड्राफ्ट का अध्ययन करके अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। भारतीय परिस्थितियों में कर नीति की रूपरेखा के सम्बन्ध में कराधान बोर्ड आयोग के विचार हम पुस्तक में शामिल किये गये हैं। इनके अनिश्चित 1956 में प्रो० बेल्होर को भी भारतीय कर-ड्राफ्ट के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था।

प्रो० बेल्होर ने इन समय की भारतीय कर-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए कहा था "भारत में वर्तमान प्रत्यक्ष कर का ढांचा अनुपयुक्त तथा असंगत है। यह असंगत तो इसलिए है कि वर्तमान करों के रूप में आय की परिभाषा दोषपूर्ण है तथा यह कुछ विशिष्ट प्रकार के करदानों के प्रति असंगतपूर्ण है। तथा यह अनुपयुक्त इसलिए है कि इनके अन्तर्गत आय, सम्पत्ति आदि के विषय में विवरणहीन सूचना प्राप्त करने का कोई उपयुक्त तरीका नहीं है। इन कारणों से करों की कोरी व्यवस्था करों के दानों का कार्य आसान हो जाता है।"

इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करना पड़ी है। इसके अन्तर्गत कर...

लेकिन प्रो० बेल्होर ने अपनी ये व्यापक कर, वृद्धि-आय कर, वसावर को विस्तृत वा कहना है कि आय पर 1 को बढ़ाई करके कर व्यवस्था, सम्पत्ति-कर, भू-कर के अनुपयुक्त करनीय कर होने पर ही एक दूसरे पर निर्भर कर...

बड़ा देगा। यदि व्यक्ति व्यय-कर में बचने के लिए घाटे व्यय की उपहार करता है तो उसे उपहार-कर अधिक देना पड़ेगा, अथवा यदि वह सम्पत्ति रूप में व्यय करता है तो उसे सम्पत्ति-कर देना पड़ेगा। इसके अनिश्चित कर-दोषों में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिनकर भी सरकार की घोषा दे सकते।

प्रो० केल्वॉर ने अपने सुझाव देने समय विभिन्न करों की अधिकतम भी निर्धारित की थी। उनसे अनुमान आय-कर की अधिकतम दर 45%, सम्पत्ति कर की 1½% (15 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर), व्यक्तिगत व्यय-कर की 300% (50000 प्रति वर्ष से अधिक के व्यय पर) तथा उपहार-कर की अधिकतम दर 80% (उपहार सहित 40 लाख से अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपहार पर)। प्रो० केल्वॉर का कहना था कि समस्त जी-लाभ पर आय-कर की दर से ही कर लगाया जाना चाहिए।

प्रो० केल्वॉर ने भारत के लिए उपयुक्त कर-व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए प्रत्येक कर को तीन कसौटियों पर परखा है। ये कसौटियाँ हैं—समानता, आर्थिक प्रभाव, और प्रशासनिक कुशलता। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में Indian Tax Reform से प्रथम अध्याय का अनुवाद शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने भारत के लिए व्यापक कर-प्रणाली का समर्पण किया है।

प्रो० केल्वॉर के द्वारा सुझाये गये करों में से हम यहाँ दो प्रमुख करों (सम्पत्ति-कर तथा व्यय-कर) का विवेचन करेंगे।

### सम्पत्ति कर (Wealth Tax)

प्रो० केल्वॉर ने अपने सुझावों में सम्पत्ति-करों को भी सम्मिलित किया था। यह कर यद्यपि बहुत अधिक प्रचलन में नहीं था, फिर भी कुछ यूरोपीय देशों में इसे लगाया गया था। प्रो० केल्वॉर ने इस कर का तीन आधारों—समानता, आर्थिक प्रभाव एवं प्रशासनिक कुशलता के आधार पर समर्पण किया है।

समानता—समानता के आधार पर तर्क देते हुए प्रो० केल्वॉर ने कहा कि आय से प्राप्त आय तथा सम्पत्ति से प्राप्त आय एवं इसी प्रकार विभिन्न सम्पत्ति के अलग-अलग मालिकों के द्वारा प्राप्त आय के बीच कर देय समता के माप के लिए एकैली आय एक अपर्याप्त मापदण्ड होती है। इसका

प्रमुख कारण यह है कि केवल किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति का होना ही उसे अतिरिक्त करदेय क्षमता प्रदान करता है ।

प्रो० ह्यू ने कहा है कि इस प्रकार समानता के आधार पर आय-कर के पूरक के रूप में सम्पत्ति कर से तीन प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं—

(1) सम्पत्ति का होना स्वयं ही, इससे प्राप्त आय के अतिरिक्त अपने आप में धार्मिक समृद्धि का मापदण्ड है । इस सिद्धान्त के आधार पर सम्पत्ति कर सम्पत्ति से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर श्रम से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक भार डालता है ।

(2) सम्पत्ति कर के द्वारा आय-उत्पन्न न करने वाली सम्पत्तियाँ जैसे खाली पड़ी हुई भूमि, नकद-राशि आदि तक पहुँच जा सकता है तथा कम उत्पादक एवं कम जोखिम वाले निनियोगों पर अधिक अच्छी प्रकार से कर लगाया जा सकता है ।

(3) सम्पत्ति-कर के द्वारा मकानों के रूप में स्थिर सम्पत्ति पर अधिक अच्छी प्रकार से कर लगाया जा सकता है ।

इस प्रकार केवल आय-कर की अपेक्षा सम्पत्ति-कर के होने पर कर का ढाँचा अधिक समान हो सकता है ।

“समानता” के आधार पर सम्पत्ति कर की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि सम्पत्ति-कर उन लोगों पर भार डालता है जिनके पास सम्पत्ति तो है किन्तु उससे आय प्राप्त नहीं होती है । ऐसी अवस्था में उन्हें कर देने के लिए सम्पत्ति बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, किन्तु इस कठिनाई को छूट की सीमा आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है ।

धार्मिक प्रभाव— आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से सम्पत्ति कर के समर्थन में प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि यह कर आय-कर के समान सम्पत्ति को जोखिम वाले व्यवसायों में लगाने की प्रेरणा पर बुरा असर नहीं डालता है । डा० गुलाटी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आय की ऊँची सीमा पर आय-कर की बहुत ऊँची सीमान्त दर उद्यम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । अतः इस आधार पर आय-कर की दर को कम करके इस सम्पत्ति-कर को पुनर्स्थापित करने के समर्थन में तर्क दिया जाता है ।

प्रशासनिक कुशलता :—इस आधार पर यह कहा जाता है कि अनेक आय कर के स्थान पर आय-कर एवं सम्पत्ति-कर का संयोग उपयुक्त रहेगा। इस सम्बन्ध में Indian Tax Reform में से घन-कर से सम्बन्धित अध्याय का अनुवाद शामिल किया गया है।

घातोचना :—अनेक विद्वानों ने केल्टडॉर द्वारा सुभाषे गये इस कर की विभिन्न आधारों पर घातोचना की है।

- (प्र) यह आय उत्पन्न न करने वाली सम्पत्तियों पर अनावश्यक भार डालता है।
- (ब) सम्पत्ति-कर ने भार को हस्तान्तरित किया जा सकता है।
- (स) सम्पत्ति के मूल्य को मापने की कठिनाई उपस्थित होती है।
- (द) दूसरी महत्वपूर्ण समस्या अमूर्त (intangible) सम्पत्ति की सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित होती है। जैसे कूपन बॉन्ड, नकद-जमा (Cash holding), जवाहरात, सोना-चांदी आदि के रूप में रखी हुई सम्पत्ति की ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करना दुष्कर होता है।
- (इ) कुछ विद्वानों का कहना है कि सम्पत्ति-कर बचत को कम करता है। अतः यह विनियोग को कम करके राष्ट्रीय आय को भी घटाना है।

विन्नु गम्पूने विवेचन की ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि आय-कर की दर को कम करके उसके स्थान पर कुछ छूट की सीमा के साथ सम्पत्ति कर को लगाया जा सकता है।

### व्यय-कर (Expenditure Tax)

डॉ० रकार ने कराधान के आधार के रूप में आय में विभिन्न कमियाँ बढ़ाते हुए व्यय को एक आदर्श आधार बनसाया है।

रकार ने इस तर्क को चुनौती दी है कि आयकरदान की करदेव-क्षमता का मही मजबूत है। उन्होंने कहा है कि समान आय होने पर भी दो व्यक्तियों की वारिष्कारिक सत्ता, सम्पत्ति तथा आय की नियमितता आदि में अन्तर होने के कारण अलग-अलग करदेव क्षमता हो सकती है। आय दो प्रकार के कर में होती है, अर्थात् समुच्च राशि प्रति वर्ष के अनुसार होती है।

किन्तु मनुष्य की व्यय-शक्ति (spending power), स्टॉक, सम्पत्ति आदि के रूप में; प्रवाह (वेतन मजदूरी आदि के रूप में) तथा आकस्मिक प्राप्ति (Casual receipts) इन तीनों का योग होती है। अतः इन तीनों के संयोग से निर्मित व्यय-राशि को केवल आय के आधार पर मापना सर्वथा असंगत होगा। इसके प्रतिरिक्त प्रणामी आय-कर के अन्तर्गत अस्थायी या परिवर्तित आय वाले व्यक्ति पर सयान रूप से प्राप्त आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक भार पड़ता है। आय-कर के द्वारा पूर्योग्यता लाभों पर भी ठीक प्रकार से कर नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में कर का आधार वसूल की गई आय (realised income) न होकर उत्पन्नित आय (accrued income) ही होनी चाहिए, किन्तु उत्पन्नित आय की गणना करना बहुत दुष्कर होता है।

इन कारणों से बेल्जियम में कराधान के आधार के रूप में आय-आधार को हटाकर उसके स्थान पर व्यय-आधार को प्रस्थापित किया है।

व्यय-कर के पक्ष में तर्कः—प्रो. बेल्जियम ने अपनी पुस्तक "An Expenditure Tax" में इसका विस्तृत विवेचन किया है। इसके पक्ष में प्रमुख तर्क ये दिये जाते हैं—

1. एक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करता है, अतः इन सब स्रोतों से प्राप्त आय को एक सामान्य इकाई में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि हम वास्तविक व्यय को कर का आधार बनायें तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय अपने आप ही प्राप्तकर्ता द्वारा अपने व्यय के द्वारा प्रगट कर दी जाती है। यहाँ प्रो. बेल्जियम का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति व विभिन्न प्रकार की आय आदि को दृष्टिगत रखकर ही व्यय करता है। अतः ऐसी स्थिति में उम्भरा व्यय उम्भरी क्षमता के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

2. प्रो. बेल्जियम व्यय-कर के पक्ष में एक अत्यन्त गुरुरतर्क प्रस्तुत करने हुए कहते हैं कि व्यक्ति पर कर लगाने का आधार सामान्य समूह (common pool) में उम्भरा योगदान व होकर उम्भरे में प्राप्त क्षमता ही होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज पर बचाने व बचाने से नहीं किन्तु उपयोग के द्वारा ही भार हासिल है।

3. आय-कर वसूल पर दोहरा कर है। किन्तु व्यय-कर केवल उपयोग पर ही कर लागू करने वसूल को प्रोत्साहित करता है। अतः अतिरिक्त शिक्षण

के लिए जहाँ बचत की दर में कृत्रिम आवश्यक है वहाँ व्यय-कर उपयोगी निरूपित हो सकता है। इसलिए प्रो० केल्डोर ने इसे भारत के लिए उपयुक्त बताया है।

4. व्यय-कर को विनियोग तथा कार्य की प्रेरणा की दृष्टि में भी आय-कर की अपेक्षा अधिक ठीक बताया जाता है।

5. इसके प्रतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि व्यय-कर मुद्रास्फीति को रोकने में आय-कर की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होता है। क्योंकि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए उपभोग को कम तथा बचत को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और हम जानते हैं कि व्यय-कर यही काम करता है जब कि आय-कर उपभोग व बचत दोनों पर लगाया जाता है—

विपक्ष में तर्क :—अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यय-कर को करायान के आधार के रूप में प्रयुक्त करने के विपक्ष में अनेक तर्क दिये हैं।

1. व्यय कर का भार धनिकों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति की आय ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों उपभोग पर व्यय होने वाला आय का प्रतिशत कम होता जाता है। किन्तु प्रो० केल्डोर का कहना है कि इस कठिनाई को प्रणामी कर लगाकर दूर किया जा सकता है।

2. इस कर के द्वारा संग्रह को प्रोत्साहन मिलने के कारण यह सन्धति के वितरण की असमानता को और अधिक बढ़ा देगा।

3. यह कर कंजूस व्यक्ति के पक्ष में होता है। इसके प्रतिरिक्त बड़े परिवार वाले व्यक्ति को अधिक कर देना पड़ता है किन्तु पारिवारिक मर्यादा के लिए कर में विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

4. अवसाद के काल में व्यय-कर अवसाद की प्रिया में अधिक सहायक होता है अतः इस दृष्टि से व्यय-कर आय-कर की अपेक्षा अधिक ठीक होता है।

5. डा० वेल्सल्या ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम भारत में बचाव को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के केल्डोर के तर्कों से सहमत हैं, किन्तु इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत की परिस्थितियों में व्यय-कर ही प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक जटिलता इस कर के लागू करने के मार्ग में एक बहुत बड़ी

कठिनाई है। इसके अतिरिक्त व्यय-कर सब प्रकार की वस्तुओं का पक्ष लेता है। किन्तु भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों में केवल वस्तु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस वस्तु को उत्पादक विनियोग में लगाना अधिक महत्वपूर्ण है और व्यय कर यह कार्य नहीं करता।

डा० वेल्शेया सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह देते हैं कि केल्डॉर का आय-कर को व्यय-शक्ति (spending power) का सही मापक न बताने का तर्क केल्डॉर द्वारा प्रतिपादित व्यय-कर पर भी लागू होता है। क्योंकि व्यय-कर प्राप्त व्यय-शक्ति पर आधारित न होकर प्रयुक्त व्यय-शक्ति पर निर्भर होता है।

इन सब कारणों से हम केवल व्यय-कर को ही कराधान के आधार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में प्रो० केल्डॉर ने भी भारत के लिए केवल व्यय-कर का ही सुझाव न देकर आय-कर के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में कुछ छूट की सीमा व प्रगामी दर के साथ इसके उपयोग पर जोर दिया था। विस्तृत विवेचन व केल्डॉर के तर्कों के अध्ययन के लिए प्रस्तुत पुस्तक में व्यय-कर पर उनके विचार दिये गये हैं।

### करापात (Incidence of Taxation)

बरो के सम्बन्ध में करापात भी एक प्रमुख समस्या है। यह भावश्यक नहीं कि कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका सम्पूर्ण भार भी उसी पर पड़े। करों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है। अतः यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इसका भार किस पर पड़ेगा? करापात की समस्या का अर्थ-शास्त्रियों ने दो विभिन्न दृष्टियों से विवेचन किया है। प्रथम, बाल्टन तथा अन्य परम्परागत अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या का आंशिक सतुलन (partial equilibrium) के अन्तर्गत विवेचन किया है तथा द्वितीय मसखेव आदि अर्थ-शास्त्री इसका विवेचन सामान्य सतुलन (General equilibrium) के अन्तर्गत करते हैं।

बाल्टन इस समस्या के विषय में कहते हैं कि यहाँ प्रश्न यह है कि कर को कौन पुराता है? अन्तिम रूप से जिस करदानी की जेब से इस कर का पैसा निकलता है उसी पर कर का भार पड़ता है। अतः बाल्टन का कहना है कि करापात की समस्या कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार (Direct Money Burden of Tax) के वितरण की समस्या है। बाल्टन के अनुसार किसी



वस्तु पर लगाये गये कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार का विभाजन नेताओं एवं विनिर्माताओं में उस वस्तु की मांग व पूर्ति की सीमा के अनुसार होता है ।

कर के भार का हस्तान्तरण आगे एवं पीछे दोनों ओर हो सकता है ।

करान्तरण (Shifting of Tax) की समस्या का विस्तृत विवेचन बाजार के विभिन्न प्रकारों के अनुसार करना अधिक उपयुक्त होता है ।

### सामान्य बित्री-कर (General Sales Tax)

जबभी एक करापात की समस्या का विवेचन आंशिक संतुलन के अन्तर्गत किया गया था जिसमें ये मान्यताएँ होती हैं, मांग-वक्र तथा कुल आय में परिवर्तन नहीं होता तथा यह अन्य उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं डालता । किन्तु ये सारी मान्यताएँ केवल तब ही ठीक हो सकती हैं जबकि वह कर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्म हो । किन्तु अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण कर के विवेचन के लिए हमारे लिए आंशिक संतुलन को छोड़कर सामान्य संतुलन का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है ।

एक सामान्य बित्री-कर के विवेचन में आंशिक संतुलन असफल रहता है । इस कर के विवेचन में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में काफी विवाद बला छा रहा है तथा इसका विभिन्न दृष्टियों से विवेचन किया गया है ।

इस विवाद का विश्लेषण करने से पूर्व हमें करापात की परिभाषा के विवाद को भी दृष्टिगत रख लेना चाहिए । जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादक उसका उत्पादन कम कर देते हैं । इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों की उस उद्योग में मांग कम हो जाती है । यहाँ हम यदि यह मानें कि इन साधनों की भवसर-लागत (opportunity cost) धूम्य है तो यह कहा जा सकता है कि ये साधन इसी उद्योग में कम पारिधमिक स्वीकार कर लेंगे । यदि ये दूसरे उद्योगों में जाते हैं तो वहाँ पूर्ति बढ़ जाने से इन्हें कम पारिधमिक प्राप्त होगा । अतः यहाँ उठता है कि कर लगाने के इस प्रभाव के विवेचन के लिए हम केवल ... की वास्तव की प्रत्यक्ष मौद्रिक भार वाली परिभाषा को नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि इन साधनों को ... रोजगार प्रदान कर दे । अतः यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि करापात ... समस्या का विवेचन करते समय हम केवल मात्र अपने आपको एक उद्योग एवं मौद्रिक भार से ही सम्बन्धित रखें अपना सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ते

वाले प्रभाव का विवेचन करें। यहाँ मसग्रैव का कहना है कि हमें सम्पूर्ण ग्रह-व्यवस्था के अन्तर्गत आय के वितरण का अध्ययन करना चाहिए। अतः उन्होंने करापात को निजी उपयोग के लिए उपलब्ध वास्तविक आय के वितरण में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है।

मसग्रैव ने करापात का तीन प्रकार से विस्तरेण किया है—(1) भेदात्मक करापात (Differential incidence) (2) विशिष्ट करापात (Specific incidence) (3) सतुलित बजट करापात (Balanced Budget incidence) हमने इस ग्रन्थ में करापात पर मसग्रैव के सुप्रसिद्ध लेख का अनुवाद शामिल किया है जिसका उपयोग विस्तृत अध्ययन के लिए किया जा सकता है।

अब हम सामान्य बित्री-कर से सम्बन्धित विवाद का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। प्रो० एरल रोलफ (Earl Rolph) का कहना है कि सामान्य बित्री-कर का करापात उपभोक्ताओं पर न होकर साधनों के स्वामियों पर होगा। प्रो० रोलफ की मान्यता है कि साधनों तथा वस्तुओं दोनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है तथा सभी कीमतें पूर्णतया परिवर्तनीय हैं। इन मान्यताओं के आधार पर प्रो० रोलफ का कहना है कि एक सामान्य बित्री-कर में कोई भी कर-बिहीन क्षेत्र नहीं होता जिसमें साधन जा सकें। जब कर लगाया जाता है तो कर्मों प्रत्यक्ष रूप से कीमतें नहीं बढ़ा सकती। ये उत्पादन कम करती हैं। उत्पादन के कम होने से साधनों की मांग कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप साधनों की मांग कम हो जाती है। इस सारी प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम यह होता है कि सब साधनों की मांग में कमी हो जाती है तथा उत्पादन के ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं होता।

प्रो० रोलफ ने यह तर्क सरकार द्वारा प्राप्त आय के प्रयोग की उपेक्षा करते हुए दिया है। प्रो० रोलफ ने प्रो० मसग्रैव के द्वारा दिये गए विभेदात्मक, विशिष्ट और सतुलित बजट करापात (differential, specific and balanced budget incidence) को ध्यान में नहीं रखा है। प्रो० रोलफ ने अपने विवेचन में सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय के प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त साधनों के स्वामियों की आय कम हो जाने के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में नहीं रखा है।

प्रो० ड्यू ने इसका विस्तरेण करते हुए कहा है कि यदि हम यह मानें कि सरकार इस प्राप्त आय को व्यय करती है तथा इस प्रकार वह साधनों की मांग उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में साधन निजी क्षेत्र से निकलकर

गरकारी क्षेत्र में बने जाने लगे। तथा उनकी मात्र कम बनी होती। किन्तु उस मापन निरी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में जानेने लगे इनके कारण उनमें मापनों की मात्रा लगे बढ़ी बनी रहती किन्तु निरी क्षेत्र में इन वस्तुओं का उपयोग कम हो जाने के कारण कम कीमते बढ जावेगी। इस कारण उपभोक्ताओं पर होगा। किन्तु बुकानन यदि धर्मार्थियों ने इन तर्कों की जागृता करने हुए जो रोज के विचारों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि एक विधी-बद सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि नहीं कर सकता क्योंकि वह वृद्धि केवल माप मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन से ही हो सकती है। कारण पर बुकानन के विचार हम दृष्ट में दिये गये हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

किन्तु यह कहा जा सकता है कि आपूर्तिक मात्रा एवं वैश्विक व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि स्वतः ही हो सकती है क्योंकि आपूर्तिक हेतु की मात्रा-व्यवस्था बड़ी ही मोबदार होती है।

इस सम्बन्ध में मतभेद तथा कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों में परिवर्तन की दिशा का कारणात्त की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। यहाँ तक कि यदि वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहें तथा साधनों की कीमतें गिर जायें तो भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि कर का भार उपभोग पर पड़ता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि सामान्य मूल्य-स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है तो रोज का तर्क ठीक बैठता है किन्तु यदि इसमें वृद्धि होती है तो उनका तर्क ठीक नहीं निकलता है। इसके प्रतिरिक्त हमें इस प्रश्न का विवेचन स्थैतिक (Static) आधार पर न करके गतिक (Dynamic) आधार पर करना चाहिए।

करारोपण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित यह संक्षिप्त सिद्धान्तोक्त हमें इस गुड़, जटिल एवं विस्तृत विषय की महत्वपूर्ण एवं विवादग्रस्त समस्याओं के विभिन्न पक्षों से परिचित कराता है। वास्तव में इस विस्तृत विषय से सम्बन्धित सभी समस्याओं का पूर्ण विवेचन तो यहाँ करना सम्भव नहीं है, किन्तु यहाँ प्रस्तुत पुस्तक में संकलित लेखों तथा कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर उनसे परिचय-मात्र करा देने का ही प्रयास किया गया है।

# कराधान

एक सैद्धान्तिक विवेचन

समय एक सीमित दृष्टिकोण वाले विवेचन को छोड़कर अन्य सभी के लिए लगभग पूर्णतया रहस्य से ढका हुआ है और अब वह समय आ गया है जब कि इस वाद-विवाद की वर्तमान स्थिति की जाँच की जाय और इसमें भाग लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों के तर्कों एवं विचारों का मूल्यांकन किया जाय।

## 1. भूमिका

'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर समस्या' के सामान्य स्तरों के अन्तर्गत दो भिन्न-भिन्न लेकिन परस्पर सम्बन्धित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। सर्वप्रथम, एक प्रश्न तो इस तरह से रखा जा सकता है : मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति से द्रव्य की कोई निश्चित राशि प्राप्त करनी है। प्रश्न उठता है कि क्या इस बात से उसका कष्ट अपेक्षाकृत अधिक या कम हो जायगा कि यह राशि उसके प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त की जाती है अथवा परोक्ष कर के रूप में ? दूसरा प्रश्न सम्पूर्ण समुदाय के दृष्टिकोण से इसी समस्या को यो प्रस्तुत करता है : मान लीजिए, सर्वसाधारण से द्रव्य की कोई निश्चित राशि प्राप्त की जानी है। ऐसी स्थिति में भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या या तो प्रत्यक्ष करों से पड़ेगा अथवा परोक्ष करों से ?<sup>१</sup> प्रथम प्रश्न अधिक सरल एवं स्पष्ट प्रतीत होता है और पहले उसी का विवेचन किया जायगा। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व हमारे लिए उस आय को पूर्णतया स्पष्ट करना आवश्यक है जो हम 'प्रत्यक्ष' व 'परोक्ष' शब्दों से लेना चाहते हैं।

साहित्य में काफी पहले से करो को प्रत्यक्ष व परोक्ष नाम दो वर्गों में बाँटने एवं इस वर्गीकरण के सिद्धान्तों की खर्चा करने का उल्लेख मिलता है। किसी भी कर की उपयुक्त धेनी का चुनाव मुख्यतः इस बात को लेकर किया गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में कर सहे करने वाले अधिकारी को द्रव्य देता है, क्या वही अपनी आयदानी में कमी भी भुगतता है। यदि ऐसा होता है तो हम परम्परागत भाषा में यह कहेंगे कि करदेयता (Impact) और करवाहता (Incidence) दोनों एक ही व्यक्ति पर हैं और वह कर प्रत्यक्ष है; यदि ऐसा नहीं है और करनार शिफा दिया जाता है जिससे किसी दूसरे की वास्तविक आय प्रभावित हो जानी है (अर्थात् कर-देयता एवं करवाहता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर हो जाने हैं) तो वह कर परोक्ष कर कहलायेगा।<sup>२</sup>

प्रत्यक्ष व परोक्ष करों का भेद हमारे उद्देश्य की दृष्टि से पूर्णतया अनावश्यक नहीं है। सर्वप्रथम, 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर समस्या' में हमारा सम्बन्ध केवल व्यक्तिगत आय पर कर लगाने से है जब कि प्रत्यक्ष-परोक्ष का विस्तृत

वर्गीकरण व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत दोनों तरह की आय पर समान रूप से लागू होता है (जैसे बम्पनिशों की अविवरित आय) और यह पूँजी-करों पर भी लागू होता है। द्वितीय, पिछनी लगभग एक दशान्दी से मजदूरी व बैठन-भाय पर शक्ति स्थान पर ही कर सजाने की प्रणाली के विवसित हो जाने से (समुक्त राज्य में 'ज्यों ही बभाको त्यों ही बर चुकाओ' की प्रणाली और समुक्त राज्य अमेरिका में रोहने की प्रणाली) परम्परागत परिभाषा के अनुसार आयकर को प्रत्यक्ष कर में शामिल करना बटिन हो गया है क्योंकि मासिक तो बर-सपट्ट-मधिकारी को द्रव्य देता है लेकिन इसका भार कर्मचारी पर पड़ता है। तृतीय, यद्यपि स्थानीय दरों (Local Rates) और मोटरगाड़ी शुल्क जैसे करों की करदेयता और करबाह्यता एक ही व्यक्ति पर पड़ती है लेकिन यह निश्चित रूप से ज्यादा उपयुक्त होगा कि इन करों को वस्तुओं पर लगने वाले करों के साथ रखा जाय न कि आपकर के साथ जैसा कि परम्परागत वर्गीकरण की स्वीकार करने की स्थिति में करना होगा।

धीमती दिक्क ने आयकरों और व्यय करों \* में जो भेद बिभा है वह परम्परागत वर्गीकरण के अनिवार्य हमारी आवश्यकताओं को देगते हुए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें उन भुनभुन भतर को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट बिभा गया है जो 'प्रत्यक्ष-भरोस कर समस्या' के विवेचन की दृष्टि में महत्व रगता है। यह भेद उन करों के बीच में है जिनका भार उन विधि पर निर्भर करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आमदनी खर्च करते हैं और वे बर जिनका भार उन विधि पर निर्भर नहीं करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आमदनी खर्च करते हैं। यववा, एक ऐसी स्थिति में जहाँ कोई खचन नहीं की जानी है, यह भेद कर के उन हाको (Tax Structures) के बीच में होता है जिनका भार इस बात से बदलना रहता है कि व्यक्ति अपनी आमदनी कैसे खर्च करते हैं और दूसरी तरह जिनका भार इस बात से नहीं बदलना है कि व्यक्ति अपनी आमदनी कैसे खर्च करते हैं।

हमें यह स्मरण रहना होगा कि हमारी समस्या की दृष्टि से हमें उन करों में कोई रवि नहीं है जो बम्पनिशों की आय पर लगाये जाते हैं। जग ही हमें उन व्यय करों में भी कोई रवि नहीं है जो विविधोव बर एक करकारी या निर्वाह-खर्च पर लगाने जाते हैं। इस लेख में हम चीनकी दिक्क के वर्गीकरण को आनन्दके केविम साथ में द्रव्यता व वरीत हाकों को भी वादम रमों और हमका हमोद एक तरह अनिवार्य आनकारी के वर्गीकरणों के कर में और



## 2. व्यक्तिगत उपभोक्ता (The Individual Consumer)

### (घ) प्रस्तावना

इस समस्या के सम्बन्ध में हाल के वर्षों में जो विवेचन हुआ है वह 1939 में जमश: कृमारी जोसेफ व प्रोफेसर हिक्स के द्वारा किये गये इसी तरह के विवेचन से निकला है<sup>6</sup> जिसका सार नीचे दिया जाता है। हम एक ऐसे धार्मिक पुष्ट की कल्पना कर लेते हैं जो दो वस्तुओं पर अपनी धामदनी खर्च करता है। चित्र<sup>1</sup> में  $y_0$  कर-मुक्त संतुलन-स्थिति है। जब एक ऐसा भानुपातिक आयकर लगा दिया जाता है जो दो वस्तुओं पर लगाये जाने वाले समान मूल्यानुसार धर-कर के बराबर होता है तो उपभोक्ता की नई संतुलन-स्थिति  $y_1$  हो जाती है। धर्म की यही पक्षि केवल एक वस्तु पर धर्म कर लगाकर भी प्राप्त की जा सकती थी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता  $y_1$  जैसी स्थिति पर आ जाता। उल्लेखनीयता (Convexity) सम्बन्धी सामान्य धारणाओं के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि  $y_1$  बिन्दु  $y_0$  से ज्यादा अच्छा है।

उपमूर्त चित्र में जिस तरह से प्रत्यक्ष करों की महत्ता को दर्शाया गया है (धनेक पाठ्यपुस्तकों में भी ऐसा ही किया गया है)<sup>7</sup> उस पर दो सुलभत भाषारों को लेकर धारणा उठाई जा सकती है। हम नीचे यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि जब कुछ बहुत ही विधेय किस्म की एवं प्रतिबन्धात्मक और अवस्तविक मान्यताएं स्वीकार की जाती हैं, तभी जोसेफ-हिक्स के द्वारा किये गये विषय के निष्कर्ष को इस प्रस्थापना (proposition) के सच्चे व सही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि धायकर धर्म की तुलना में कम भार डालते हैं।

इन धारणियों पर ध्यान देने से पूर्व यह उपयोगी होगा और सम्भवतः आवश्यक भी, कि हम इस क्षेत्र में तटस्थता-वक्र-विक्षेपण के लागू होने के सम्बन्ध में कुछ धर्म धेतावनों के तौर पर कहें। ऐसे विक्षेपण में यह मान लिया जाता है कि तटस्थता-मानचित्र बदलता नहीं है और विधेरूप से यह भी कि मानचित्र कर की दरों में होने वाले परिवर्तनों से पूर्णतया धर्मभावित रहता है। यह मान्यता वास्तविक प्रतीत नहीं होती है।

इनके अलावा एक और भी अधिक यम्भीर धारणा यह है कि एक ऊँचे तटस्थता-वक्र पर जाना क्या वास्तव में इस बात को सूचित करता है कि लोग पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में आगये हैं। एक नीचे के तटस्थता-वक्र से ऊँचे के तटस्थता-वक्र की तरफ होने वाली गति केवल इस बात को सूचित



कर सकती है कि सम्पूर्ण कल्याण में वृद्धि हुई है और वह भी उस समय जब कि इसकी परिभाषा ऐसी ही दी जाय। ऊपर हमने जो चित्र भींचा है उसमें ऐसा लगता है जैसे हमारा यह विश्वास हो कि लोग जाने जागते उस समय ज्यादा अच्छी स्थिति में मानने हैं जब कि उन पर कर प्रयोज रूप में न लगाया जाकर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाय। लेकिन सम्भवतः ऐसा न भी हो। यह बात विरोधाभास-सी प्रतीत होती है, लेकिन संभव है कि लोग एक उच्च तटस्थता-वक्र (प्रचलित ढंग के) पर आकर भी अपने भारों पहले से कुरी स्थिति में पावें। इसमें पीछे के द्वारा आर्थिक कल्याण व कुल कल्याण में किये गये अंतर का प्रतिबिम्ब दिखलाई देता है; हो सक्ता है कि दोनों सदैव एक ही दिशा में अपसर न हों। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति आयकर चुकाना पराभ न करे। सम्भव है कर संग्रहकर्ता को द्रव्य देते समय उसे अपने मुल में ऐसी वास्तविक शक्ति प्रतीत हो जिसकी पूर्ति इस बात से न हो सके कि वह प्रत्यक्ष कर के रूप में कम आर्थिक अधिशेष (economic surplus) का परिचय कर रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति का यह विचार हो सकता है कि जीवन के लिए अनिवार्य होने वाली वस्तुओं पर कर लगाना उचित नहीं है और ऐसे कर के लगाये जाने पर अन्याय का आभास होने से उसे ऐसा कष्ट होता है जैसे कि समस्त वस्तुओं पर समान मूल्यानुसार व्यवहार लगा दिये गये हैं। इन उदाहरणों से कुल कल्याण को पहुँचने वाली प्रतिरिक्त हानियों का पता चलता है, और यह संभव है कि इस विस्मयी हानियाँ आर्थिक कल्याण में होने वाली उन वृद्धियों से अधिक हों जो एक तटस्थता-वक्र-चित्र पर प्रदर्शित की जाती हैं। अतः सामान्य तटस्थता-वक्र-विश्लेषण के द्वारा सूचित परिणाम कुल कल्याण की भाषा में गलत होते हैं।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि जब इस समस्या को तटस्थता वक्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें इन सब बातों का समावेश किया जा सकता है लेकिन सम्बन्धित साहित्य में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

विवेचन की इस अवस्था में इन आपत्तियों पर हमारी दृष्टि तो पड़ती है लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने पुराने ढंग से ही भागे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस लेख के अन्तिम भाग में हम इन पर पुनः विचार करेंगे।

जोसेफ-हिस प्रमाण (Proof) के प्रति पहली आपत्ति यह है कि इसमें यह मान्यता छिपी हुई है कि विचारणीय व्यक्ति की कर-पूर्व आय बड़ी है,

चाहे आयकर लगाया जाय अथवा क या ख यस्तु पर अलग-अलग कर लगाया जाय । यदि इसी बात को और भी विधिवत् रूप में प्रस्तुत किया जाय तो हम यों कहेंगे कि यह मान लिया गया है कि आय अथवा व्यय करों की दरों में परिवर्तन हो जाने पर भी कार्य की पूर्ति (Supply of Work) पूर्णतया बेलोच बनी रहती है । इस मान्यता को हटा लेने पर इस तथ्याकर्मित प्रमाण की सरलता, शुद्धता एवं सुनिश्चितता समाप्त हो जाती है ।

यदि हम हिक्स-ओमेफ प्रमाण को ऊपर वर्णित छिपी हुई मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो भी दूसरी आपत्ति विशेष रूप से सगत जान पड़ती है क्योंकि उनके तर्कों में एक और मान्यता अस्वीकृत है जिसे 'आदर्श प्रारम्भिक शर्तें' कहते हैं । इसका आशय यह है कि 'कर समस्या' पर विचार करते समय वे सुविधा की दृष्टि से एक ऐसी स्थिति से प्रारम्भ करते हैं जहाँ करों का कोई अस्तित्व नहीं होता है ।

लेकिन जब हम एक ऐसी स्थिति में जहाँ पहले से ही राजस्व या आय (revenue) देने वाले कुछ कर लये हुए हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष करों से अतिरिक्त आय की एक दी हुई राशि को जुटाने की अधिक वास्तविक समस्या पर विचार करने लगते हैं तो विश्लेषण में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक हो जाते हैं ।

अतः मोटे तौर से कल्याण के आधार पर परोक्ष करों के स्थान पर प्रत्यक्ष करों की सहता का जो सैद्धान्तिक दिग्दर्शन ओमेफ-हिक्स ने दिया है वह निम्न दो मान्यताओं को स्वीकार करने पर केवल एक सतोपप्रद प्रमाण ही रह जाता है—एक तो आय व व्यय करों के सम्बन्ध में धर्म की पूर्णतया बेलोच पूर्ति और दूसरे 'आदर्श प्रारम्भिक शर्तें' । इस लेख ■ दोष भागों में मैं यह बतलाने का प्रयत्न करूँगा कि इन मान्यताओं को हटा लेने पर क्या परिणाम निकलेंगे ।

(आ) जब धर्म की पूर्ति को परिवर्तित होने दिया जाता है\*

प्रोफेसर लियोनार्ड रोबिन्स ने 1930 में इकोनोमिका में प्रकाशित अपने लेख में धर्म की पूर्ति पर आयकर के प्रभावों का पूर्ण रूप से विवरण प्रस्तुत किया था<sup>१</sup> और प्रोफेसर जे० थार० हिक्स भी सटस्पल वर्मों की सहायता से अपनी पुस्तक 'मूल्य व पूँजी' में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'निगम्य-विश्लेषण (A priori analysis) से हम यह पता नहीं लगा सकते कि धर्म का पूर्ति-वक्र पीछे की ओर मुड़ेगा अथवा आगे ऊपर की ओर जायेगा ।'<sup>20</sup> यह निष्कर्ष

वास्तव में इस सर्वविदित तथ्य से निकसता है कि पूर्ति-पक्ष की ओर प्रतिफल की विद्युद्ध दर (net rate of return) में होने वाले परिवर्तन के मापक प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्यतया विपरीत दिशा में काम करते हैं।

जब एक व्यक्ति की आय घट जाती है तो वह बहुधा कम अवकाश चाहने लग जाता है। इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम, चूंकि अवकाश प्रायः अन्य वस्तुओं का पूरक होता है, इसलिए यह भाशा की जा सकती है कि इन वस्तुओं की उपलब्धि में कमी आ जाने से (दूसरे शब्दों में आय में कमी आ जाने से) अवकाश की मांग घट जायेगी। द्वितीय, यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि आय के घट जाने से (जैसे प्रति व्यक्ति कर (Poll Tax) के लग जाने से) कार्य की सीमान्त अनुपयोगिता आय की सीमान्त उपयोगिता से कम हो आय जिससे काम को प्रोत्साहन मिले।

घायकर भी कार्य की प्रत्येक सीमान्त इकाई के पुरस्कार को परिवर्धित कर देता है और इस प्रकार प्रत्येक घटे के कार्य को उस स्थिति की तुलना में कम आकर्षक बना देता है जितना कि यह कर की अनुपस्थिति में होता।

आय और प्रतिस्थापन प्रभाव विपरीत दिशाओं में चलते हैं और केवल सैद्धान्तिक बहस से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इनमें से विद्यमान प्रभाव अधिक प्रबल होता है। लेकिन सामान्य बुद्धि से और जो कुछ व्यवहार अनुभवाधिष्ठित सामग्री उपलब्ध है उससे यह पता चलता है कि आय-प्रभाव अधिकांश मामलों में बीमर-प्रभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है और आय के बढ़ने के साथ-साथ धनकाय की मांग भी बढ़ती जाती है और इसके विपरीत भी सही होना है।

हम इसी बात को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं। ऊपर-बर्गिन  
 चारों को लेकर हम माना कर सकते हैं कि कर व लगने की स्थिति की  
 तुलना में इति स्थिति कर के लग जाने से कार्य की मात्रा में वृद्धि होती है  
 क्योंकि हम परिस्थिति में केवल माप-प्रमाण ही कार्यरत रहता है; और कार्य  
 के अन्तर्गत अतिरिक्त बढ़े से होने वाले लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होता है।  
 हम यह भी माना कर सकते हैं कि कार्य की मात्रा बढ़ने जाने वाले मापदंड की  
 स्थिति में अनुसार भी परिवर्तन होती है। उदाहरणार्थ, हम कार्य की मात्रा की  
 वृद्धि में प्रोत्साह (Produce) आनुपातिक (Proportional), अवगती  
 (Hypothetical) व अन्तर्गत कार्य (Jelly Task) का इसी क्रम में लेन का  
 के साथ हम कह सकते हैं कि हमें उचित ही माना जाती है। अन्तर्गत कार्य मात्रा हम

प्रतिव्यक्ति करों (Poll Taxes) को न्यूनतम अवकाश और प्रगामी भायकरों को अधिकतम अवकाश से सम्बद्ध कर देते हैं। इन सभी दशाओं में भाय-प्रभाव तो समान रहता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिव्यक्ति कर की दशा में द्रुम्य होता है और आरोही भायकर की स्थिति में उल्लेखनीय हो सकता है एवं इसी प्रकार आनुपातिक एवं अवरोही भायकरों के साथ इसका महत्व घटता जाता है।<sup>11</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा में वर्णित दोनों लेखकों ने और वास्तव में इस विषय पर हेस्केल पी० बाल्ड<sup>12</sup> तक लिखने वाले लगभग सभी व्यक्तियों ने यह दृष्टिकोण रखा था कि भायकर का यह बुरा प्रभाव हो सकता है कि यह किये जाने वाले कार्य की मात्रा में कमी उत्पन्न कर दे। यह बात स्वीकार तो की गई थी कि आयकर से किये जाने वाले काम की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसे बुरा नहीं समझा गया था। फिर भी बाल्ड ने पूर्व-उद्धृत लेख में यह बतलाया था कि एक प्रतिव्यक्ति कर की तुलना में आनुपातिक भायकर एक व्यक्ति पर अधिक भार डालता है, चाहे भ्रम की पूर्ति बढ़े, घटे अथवा उतनी ही रहे और उसका यह दावा था कि यह अधिक भार अनिवार्यता जैसा ही अधिक भार होता है जैसा परोक्षकर से पड़ता है (जो पहले ही जोसेफ-हिवस के जैसे चित्र में दर्शाया जा चुका है)।

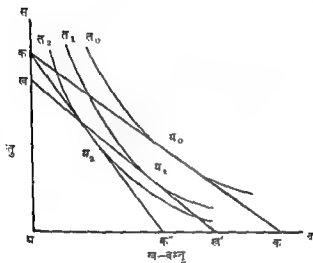
यह जानना रुचिकर होगा कि भायकर के विभिन्न रूपों का कल्याण के अनुसार क्रम विन्यास (ranking) ठीक वैसा ही होता है जैसा कि यह प्रेरणा अनुसार होता है। यह बात प्रोफेसर पीग्रू<sup>13</sup> ने बतलाई थी लेकिन प्रोफेसर बोर्डिंग<sup>14</sup> ने इस प्रस्थापना का तटस्थता-बन्धों की सहायता से बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। वास्तव में इसके पीछे ताकिक आधार यह है कि प्रतिव्यक्ति कर के मुकाबले में इन करों के अधिक भार (excess burden) की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिव्यक्ति कर के स्थान पर इन करों के जियादील होने पर एक व्यक्ति के कार्य-कलाप किस सीमा तक भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे ही पुनः हम प्रेरणा-प्रभाव (incentive effect) कह कर पुकारेंगे।

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि ये अधिक भार इस बात पर निर्भर करते हैं कि (घ) व्यक्तियों को अपने काम के घटों के घुनने की कहा तक स्वतंत्रता होती है, (घा) इस सम्बन्ध में निर्णय करने में वे करों से कहां तक प्रभावित होते हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि व्यक्तियों को न तो ऐसी स्वतंत्रता होती है और न उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है।<sup>15</sup>

वस्तु ने भी कई अनुभव दिये हैं वह इस प्रकार हैं। मान लीजिए बिज (1) में स स स करवाण को धीरे स स स स को गुंवा करवा है। ऐसी स्थिति में क क' केगा उन व्यवस्थाओं को प्रशिक्षण करती है जो स स स करवाण के सम्बन्ध में एक व्यक्ति के लिए कर सने से पूरी गुंने रहने हैं। म इस वस्तुओं के उग संयोग को प्रशिक्षण करता है बिज वह सने सगा सने करेगा। मान लीजिए, सरकार सने क स (क' स') कर के स में सने पाइती है। वह ऐसा प्रति व्यक्ति कर (Per capita tax) लगा कर कर सकती है बिजने सने व्यवस्था का एक सगा स स स' बिजगा है और सने सनुन की गई स्थिति स हो जाती है। सामुदायिक व्यवहार सगा कर भी इनकी ही दृष्टि राशि जुटाई जा सकती है। इस कर के लगाने से विपराधीन व्यक्ति के सगा सई बचत सगा क क' स जासगी और वह स, से प्रशिक्षण सगा स व्यवस्था का संयोग जुनेगा। उन्प्रोदरता सम्बन्धी सामान्य सामान्यों के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि स, बिजु स, में अधिक उत्तम है और यदि क स दृष्टि राशि प्रति व्यक्ति कर सगाकर प्राप्त करने के बजाय आयकर प्राप्त की जाती है तो उपभोक्ता पर अधिक भार पड़ता है।

उपयुक्त दृष्टान्त में एक व्यक्ति को आयकर के लगने से उस स्थिति की तुलना में कम व्यवसाय मिल पाता है जब कि कोई कर नहीं लगा हुआ है (अर्थात् वह पहले से ज्यादा काम करता है)। लेकिन यही निष्कर्ष उस स्थिति में भी निकलता है जब कि व्यवसाय व आय के सम्बन्ध में इस व्यक्ति का तटस्थता-मानबिज ऐसा होता है कि भाव-प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है जिससे वह आयकर के लगने से कम मेहनत करने लगता है, बनिस्वत उस स्थिति के जब कि कोई कर नहीं लगा हुआ है।

वाल्ट ने अपने विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला था कि यद्यपि यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति कर आयकर से ज्यादा अच्छा होता है और यह व्ययकर से भी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस तरह सैदान्तिक अध्ययनों से अतिरिक्त भार की मात्राओं पर, और कतलवरूप कल्याण के दृष्टिकोण स आयकरों व व्ययकरों के सापेक्ष गुणों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। यह तो सत्य है कि वाल्ट ने उन परिस्थितियों को भी पहचाना था जिनमें व्यय कर एवं आयकर से बचत की हानि (Loss of surplus) नहीं होती है और इनका प्रभाव प्रति व्यक्ति कर के समान हो पड़ता है। उदाहरण के लिए, उसने इस तरह से लिखा है 'वस्तुकर इस बसौटी को पूरा करता है कि मांग की आय-सोच व प्रीमियम-सोच कम शून्य होती है। इन दशाओं में



चित्र (1)



य और कर लगी हुई वस्तु के बीच प्रतिस्थापन की सोच भी धून्य ही गी।<sup>16</sup>

हम आगे चलकर देखेंगे कि ऊपर जो सारांश गहरे अक्षरों में दिया जा है उस पर आपत्ति उठाई जा सकती है, लेकिन इस बात पर हम यहाँ चार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं पाठक का ध्यान इस तथ्य की तरफ खींचना चाहूँगा कि इस समस्या के प्रति वाल्ड का दृष्टिकोण पूर्णतया सतोषजनक नहीं है। उसके मतानुसार प्रति व्यक्तिकर/आयकर एवं प्रति वस्तुकर/व्ययकर इन दोनों के विवेचन में एक से बिना बर्तक की आवश्यकता होती है। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि इसमें यह मान्यता निहित है कि वस्तु की कर-पूर्व आय व्ययकर की स्थिति में भी बही है जो आय कर की स्थिति में है। वाल्ड ने यह तो काफी सही ढंग से स्पष्ट किया है कि प्रति व्यक्ति कर की तुलना में आयकर से करदाता पर अधिक भार पड़ता है लेकिन इन व्यय कर के भार का सतोषजनक वर्णन नहीं किया है क्योंकि उसके विवेचन में यह मान्यता अन्तर्निहित है (जो निश्चित रूप से गलत है) कि वस्तुओं की कीमत और अवकाश की भांग के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्पष्टतया एक अनुचित बात है। यदि यह मान भी लिया जाय कि व्यय करों अवकाश की भांग पर कोई प्रतिस्थापन-प्रभाव नहीं पड़ते हैं तो भी आय-दाताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना समझ नहीं होगा।

प्रोफेसर ए० एम० हेन्डरसन ने भी वही भूल की जो वाल्ड ने की थी।<sup>17</sup> अपने 1948 में प्रकाशित एक लेख में उसने यह बतलाने का प्रयास किया कि वाल्ड का तर्क असतोषजनक व भ्रामक था (वास्तव में कुछ मामलों में यह था भी) और परम्परागत जोसेफ-हिक्स का दृष्टिकोण सही था (जो गलत नहीं था)। उसके तर्क का निचोड़ यह था कि समान आरोहीपन (progressiveness) वाले आय कर के दावे व व्यय कर के दावे के प्रति व्यक्ति-कर की तुलना में कार्य की पूर्ति पर एक से विकृत प्रभाव (distorting effects) पड़ते हैं और यही कारण है कि बचत की क्षति भी समान ही होती है। लेकिन इसके अलावा इसका यह भी विचार था कि जब आय के छेड़ने का समय आता है तो आयकर की तुलना में व्ययकर बचत को अतिरिक्त क्षति पहुँचाते हैं।

इस प्रकार परम्परागत निष्कर्ष सही है। प्रोफेसर हेन्डरसन का यह विचार सही है कि एक दी हुई आय की स्थिति में व्ययकर से आयकर की



अपेक्षा अधिक भार पड़ता है (हमारी 'आदर्श प्रारम्भिक स्तरों' की मान्यता के आधार पर)। यथार्थ में यह वह परम्परागत दावा है जिसका मैंने इन मान्यताओं के आधार पर समर्थन किया था। लेकिन मुख्य बात कुछ और है। वह यह है कि जिस व्यक्ति के समस्त समान आरोहीपन लिए हुए आयकर-फलन (income tax function) व व्ययकर फलन होते हैं वह वास्तव में समान आय प्राप्त नहीं कर पाता है।

इस बात को ठीक से स्पष्ट करने के लिए हमें इस संदर्भ में 'समान आरोहीपन' के अर्थ पर काफी विस्तार से विचार करना होगा। आयकर की स्थिति में तो आरोहीपन की धारणा विलकुल स्पष्ट होती है और हम यहाँ पर यह मान लेते हैं कि हम एक ऐसे कर के ढाँचे पर विचार कर रहे हैं जहाँ एक व्यक्ति यदि  $x$  आय प्राप्त करता है तो वह कर के रूप में इसका  $y\%$  चुकाता है। (सरसता के लिए हम भानुपातिक आयकर को भी ले सकते थे जो हमारी सामान्य मान्यताओं के आधार पर समस्त वस्तुओं पर  $y\%$  की दर से लागू किये जाने वाले समान मूल्यानुसार व्यय कर के ही समान होगा)। एक दृष्टिप्रद और पेचीदा बात तो यह है कि इस आयकर के साथ पाये जाने वाले समान आरोहीपन वाले व्यय कर के ढाँचे से अभिप्राय क्या निकलता है। एक व्यक्ति की स्थिति में इसका अर्थ अतमान मूल्यानुसार कर की दरों की उस प्रणाली से होगा जिसमें उसकी दृष्टि को ध्यान में रख कर इस बात की व्यवस्था की जा सकती है कि यदि उसकी आय  $x$  हो तो वह अपना सार्थक ढंग प्रकार से जमावेगा कि कर के रूप में  $y\%$  व्यय कर सके। ऐसी दशा में महत्वपूर्ण बात यह है कि विचाराधीन व्यक्ति के समस्त मकद राशि की कोई विविष्ट भाग नहीं है, बल्कि उसके समस्त वैकल्पिक कर-सूत्रों (tax formulas) की एक श्रृंखला विद्यमान है और वह अपने काम के षटों एवं विशेष वस्तुओं के अपने उपयोग को परिचित करने में पूर्णतया स्वतंत्र है। यहाँ पर हमारा विचार यह है कि जिस उपयोग के समस्त ऊपर वर्णित वैकल्पिक प्रयोजन पर परीक्षा कर की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं वह वास्तव में प्रत्येक दशा में अपने स्वयं के बड़े घटन-अलग रखना समर्थ करेगा और अन्तिम स्थिति के अर्थ में (ex post facto) कर व्यवस्थाएँ समान आरोहीपन लिए हुए नहीं होंगी। ऐसी दशा में परीक्षा करों की अनिश्चित प्रयोजन करों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा कथन प्रमाण बनना अवश्य होगा जैसा कि हेन्डरसन ने किया था।

कोई बड़ा स्रोत सचता है कि उपर्युक्त स्थिति में सुधार सामान्य यह है कि आरोहीपन की प्रणाली विविध परिस्थितियों की आय। उदाहरणार्थ, समान आरोहीपन

वाली परोक्ष व प्रत्यक्ष कर-प्रणाली को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि इनमें कर भी दरे ऐसी होती हैं कि व्यक्ति सरकार को एक सी प्रत्यक्ष-राशि देते हैं, चाहे (और ऐसा होना भी) कार्य के घटे और उपभोग-सर्व का माहुर अलग-अलग हो। ऐसी दशा में यदि यह सिद्ध किया जा सकता है कि आदकर उपभोक्ता को व्यय करों की तुलना में कम दिखता पहुँचाते हैं तो हम प्रत्यक्ष करों की उत्तमता का दावा सामने रखने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन यह सम्भव नहीं है। वास्तव में हम आगे चलकर देखेंगे कि उनके विपरीत मत के पक्ष में अच्छे तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मैं सोचता हूँ कि वाल्ड और हेन्डरसन के द्वारा किये गये उत्तम कार्य के महत्व को कम किये बिना यह काफी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह तो आयकर और वस्तुओं की मांग के बीच और दूसरी तरफ वस्तुओं की कीमत और अवकाश की मांग के बीच पाये जाने वाले पविष्ट सम्बन्ध को नहीं समझा। इन महत्वपूर्ण अन्तर्सम्बन्धों के बारे में पहला विविष्ट कथन आई०एम०डी० नोट्स<sup>२०</sup> में प्रस्तुत किया है।

प्रतिव्यक्तिगत/आयकर और प्रतिव्यक्तिगत/परोक्ष कर की समस्याओं को एक दूसरे से बिलकुल पृथक् व भिन्न मानने के बजाय नोट्स में इनको एकही समस्या के विभिन्न पहलुओं के रूप में देखा है। उसने यह मान लिया कि उपभोक्ता स्वतन्त्र है और तीन वस्तुओं,  $X$ ,  $Y$  व  $Z$  (अवकाश) के विभिन्न मूल्यों के बीच चुनाव कर सकता है। यदि वह  $X$  और  $Y$  को अधिक मात्रा चाहता है तो अवकाश का त्याग करके ही ऐसा कर सकता है, इसी प्रकार यदि वह  $X$  और  $Z$  चाहता है, तो उसे  $Y$  कम लेना होगा, इत्यादि। यदि हम उपभोक्ता पर प्रति व्यक्ति कर लगा दिया जाता है तो इसके आय-प्रभाव से उसके चुनावों पर असर पड़ेगा, लेकिन कोई प्रतिस्थापन-प्रभाव नहीं पड़ेगा। (हम यह माना करते हैं कि अवकाश के लिए उसकी मांग बढ़ेगी)। यदि  $X$  या  $Y$  या  $Z$  पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो इसके लिए कर लगा दिया जाता है तो हमने कुछ विपरीत प्रभाव (distorting effects) पड़े हैं और निम्न के समानुसार शीट्समिच दृष्टिकोण से इन विपरीत प्रभावों के सम्बन्ध में और बनावटपूर्ण इन करों के मरने से अवकाश की हानि के सम्बन्ध में पुष्टि के एकतरफ (Symmetry) होता है। वही कारण है कि वह करने लगें (जो निम्नोद् एव सिद्ध लेम का) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य का उद्देश्य कर लगाया जा :—'दरिद्रि की सामान्य निष्कर्ष की कोशिश में तो यह लगने है कि अर्थोद्गार कर के होने हैं जो उन वस्तुओं पर लगाये जाये हैं जिनकी मांग बढ़ने

बम मोचदार होती है। धातविक सहायता के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। धातवर ओ अवकाश पर ही जाने वाली सहायता है, इसका अभाव नहीं है। अवकाश की माँग के काफी बेमोच होने के कारण में ही यह एक अच्छा कर माना जा सकता है। परोक्ष कराधान या करारोपण के विषय में बेमम विद्युत्सम्प से कोई गैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत कर सकना एक भ्रम होगा।<sup>19</sup>

अतः ओमेफ-गाल्ड-हेम्बरगन-मिटल के द्वारा प्रस्तुत दिये गये विवेचन का परिणाम यह है कि बेमम गैज्ञानिक तर्क के आधार पर धातविकों की शुल्कना में उत्पादन-करों की हीनता (अथवा उत्तमता) गिढ़ नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि यह प्रश्न कि कराधान का कौनसा रूप एक ही हुई स्थिति में वषट को अपेक्षाकृत कम हानि पहुँचायेगा, एक अनुभववाचित विषय बन जाता है। इन सम्बन्ध में परिणाम प्रमदाः वस्तुओं व अवकाश के मात्र वर्णों की विशेष क्षमता से निर्धारित होता है। मैं अपने मूल लेख में इसी तरह की भावना प्रस्तुत करना चाहता था। कोरसेट व हेग<sup>20</sup> की आधुनिक छोटों के फलस्वरूप अब थोड़े कम अपरम्परागत निष्कर्ष (लेकिन केवल थोड़े ही कम) पर पहुँचना संभव हो गया है ओ इस प्रकार है: 'यदि व्यक्ति अपने कार्य की मात्रा तय कर सके तो मामूली परोक्ष कर-ढाँचा प्रत्यक्ष कराधान से उत्तम ही रहेगा।'<sup>21</sup>

क, ख और घ (अवकाश) इन तीन वस्तुओं के अस्तित्व को मान लिया गया है। धानुपातिक आयकर लागू हो रहा है और विचाराधीन उपभोक्ता ने क, ख और घ के ऐसे संयोग को चुना है जो उसे सर्वाधिक संतोष देता है। अब यदि धातवर की दर घटा दी जाती है और आय की उत्तनी ही राशि के धातविक क या ख पर थोड़ा व्ययकर लगा दिया जाता है तो इस परिवर्तन से उपभोक्ता के द्वारा चुनी जाने वाली घ की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। साधारण-तया क या ख में से कोई एक वस्तु दूसरे की वनिस्वत अवकाश की ज्यादा पूरक होगी।<sup>22</sup> यदि क वस्तु अवकाश की ज्यादा पूरक होती है और इस पर कर लागू किया जाता है तो विचाराधीन व्यक्ति ज्यादा मेहनत से काम करेगा। यदि ख वस्तु अवकाश की ज्यादा पूरक होती है और क पर कर लगा दिया जाता है तो वह इस नई कर की स्थिति में उस स्थिति की अपेक्षा कम मेहनत से काम करेगा जब कि प्रथम दशा वाली क व ख वस्तुओं पर समान मूल्यानुसार कर की दरें लागू की जाती हैं।

उक्त परिणाम कोई आश्चर्यजनक नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि धातवर के लगने में एक व्यक्ति सदैव उस स्थिति की अपेक्षा कम मेहनत से

काम करता है जब कि वह प्रति व्यक्ति कर के रूप में उतनी ही धनराशि राजकोष में जमा कराता है। प्रति व्यक्ति कर को (हमारे मॉडल में) एक ऐसा कर माना जा सकता है जो तीनों वस्तुओं के, सब पर समान मूल्यानुसार लगाया गया है। प्रति व्यक्ति कर की तुलना में आयकर शुनावों को भवकाश के पक्ष में ले जाता है। अतः कर प्रणाली का ऐसा परिवर्तन जो इस विपरीत स्थिति को ठीक करने की दिशा में अग्रसर होता है (उदाहरणार्थ, अवकाश की पूरक वस्तु पर बढ़ाया गया कर) वह एक व्यक्ति को अधिक मेहनत से काम करने लिए प्रेरित करेगा। यही नहीं बल्कि हम अपने पूर्व विवेचन से यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन से कल्याण की होने वाली क्षति कम हो जायेगी और वह व्यक्ति एक ऊँचे उत्प्रेक्षा-वक्र पर आ सकेगा, हालांकि वास्तव में ऐसा केवल उस दशा में होता है जब कि वह अपने काम के घंटों में परिवर्तन कर सकता है यद्यपि उसके काम के प्रति-वक्र की लोच धूम्य नहीं होती है।

कोरलेट-हेन के लेख की प्रमुख बात जो महत्वपूर्ण है—यह प्रदर्शित करना है कि तीन वस्तुओं की स्थिति में (जिनमें से एक अवकाश है) जहाँ व्यक्ति अपने काम के घंटे परिवर्तित कर सकते हैं, दो वस्तुओं पर समान मूल्यानुसार लगे हुए कर से असमान मूल्यानुसार करों की तरफ परिवर्तन होने से प्राप्त अवकाश की मात्रा में कमी आ जायेगी और उस व्यक्ति के आर्थिक कल्याण में घृष्टि हो जायेगी बशर्ते कि अपेक्षाकृत ऊँचे कर की दर एक ऐसी वस्तु पर लगी हुई है जो अवकाश की अधिक पूरक है और इसके विपरीत भी सही है। पूर्वमाग्यताओं की स्थिति में यह निष्कर्ष भी निश्चित है कि परोक्ष कराधान का कुछ रूप प्रत्यक्ष कराधान से सदैव उत्तम होता है।<sup>22</sup> ये सैद्धांतिक निष्कर्ष हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन व्यावहारिक सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में क्रिया के मार्गदर्शक के रूप में इनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है और वास्तव में निश्चित अधिक्य में मांग-वर्गों की विशेष धन के सम्बन्ध में और एक व्यक्ति की वस्तुओं की मांग व अवकाश की मांग के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान इस काम की दृष्टि से पूर्णतया अपर्याप्त हो बना रहेगा।

(६) जब अन्य करों का अस्तित्व होता है <sup>24</sup>

उन सभी लेखकों ने जिनका विवेचन हमने इस लेख के भाग (अ) में किया है अस्पष्ट रूप से यह मान लिया था कि 'आदर्श प्रारम्भिक दशा' <sup>25</sup>

पाई जाती है। पूर्ण सामंतीक जगत् में 'घादमं प्रारम्भिक दगाएँ' निम्न स्वरूप में होकर केवल अगवाइ-भाय ही होती हैं, दगाएँ इन मान्यता के महत्त्व और दगाएँ हटाने के परिणामों पर कुछ विचार कर लेना अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा।<sup>26</sup>

एक अनेक व्यक्ति और दो वस्तुओं (क और न) की स्थिति को मान लेने पर पार-भिन्न-भिन्न प्रारम्भिक दगाएँ बतलाई जा सकती हैं—दगा बर नोई कर न हो; आयकर (जो दोनों वस्तुओं पर लगे हुए समान मूल्यानुसार व्यय कर के बराबर हो); क-वस्तु पर व्यय कर और न-वस्तु पर व्यय कर।<sup>27</sup>

यह परम्परागत (जोसेफ-हिंग) निष्कर्ष कि-आयकर क-वस्तु पर लगे हुए समान भाय (revenue) देने वाले व्यय कर से अधिक अच्छा होता है—ऊपर-वर्णित अन्तिम प्रारम्भिक दगा को छोड़कर सर्वत्र साधु होता है; हालांकि इस सम्बन्ध में तर्क बहुत जटिल होता है विशेषतया उस स्थिति में जब कि क पर पहले से ही व्यय कर लगा हुआ है।<sup>28</sup> आयकर क-वस्तु पर लगे हुए व्यय कर में सदैव अच्छा होता है। ऐसा केवल उस समय नहीं होता है जब कि न पर पहले से ही व्यय कर लगा हुआ हो।

इस निष्कर्ष के पीछे स्पष्टतया एक सामान्य कुट्टि का कारण प्रतीत होता है। हम पहले देख चुके हैं कि एक प्रति व्यक्ति कर प्रापिक कल्याण के दृष्टिकोण से इसलिये एक अच्छा कर माना जाता है कि एक व्यक्ति के व्यवहार पर इसके प्रति-स्थापन या अन्य विपरीत (distorting) प्रभाव नहीं पड़ते हैं। एक प्रति व्यक्ति कर सापेक्ष कीमतों को प्रत्यक्षतया नहीं बदल पाता है। कीमतों पर इसका जो एकमात्र प्रभाव पड़ता है—और वह केवल उस स्थिति में महत्वपूर्ण होता है जब कि अनेक व्यक्ति होते हैं—उसका कारण यह है कि यह क्रय-शक्ति को नये ढंग से वितरित कर देता है श्रुति विशेष वस्तुओं की मांग में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि एक अर्थशास्त्री के लिए कीमतों का आशय सापेक्ष कीमतों अथवा कीमत-अनुपातों (price ratios) से होता है और जो कर-प्रणाली सापेक्ष कीमतों अथवा कीमत-अनुपातों को अपरिवर्तित बने रहने देती है वह प्रति व्यक्ति कर (poll tax) के समान ही होती है, और एक कर-प्रणाली जो इस स्थिति के विरुद्ध होती है वह व्यक्तियों को ऊंचे तटस्थता-वर्गों पर ले जाती है अथवा कर प्रणाली के जो हमके समीप नहीं होती हैं। हम अपने मॉडल में क और न की कर से पूर्व की कीमतें क्रमशः 4 और 1 मान लेते हैं। अतएव

कीमत-अनुपात 2 : 1 हो जाता है। न तो प्रतिव्यक्ति कर और न आयकर ही इन कीमतों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन क आयवा स पर कर लगने से इनके भाव बढ़न जायेंगे, इसलिए प्रतिव्यक्ति कर आयवा आयकर की तुलना में ये द्रव्य छुटाने के घटिया तरीके माने जाते हैं।

अब हम यह मान लेते हैं कि स-वस्तु पर 50% मूलानुसार कर पहले से ही लगा हुआ है। अतः इस प्रारम्भिक स्थिति में क और स की सापेक्ष कीमतें 4 और 3 होती हैं और कीमत-अनुपात  $\frac{4}{3}$  होता है। अब आयकर लगा दिया जाता है तो कीमत-अनुपात तो  $\frac{4}{3}$  ही बना रहता है, लेकिन कर न लगने के समय की प्रारम्भिक स्थिति में होने वाले कीमत-अनुपात 2 की तुलना में विपरीत ढंग का परिवर्तन आ जाता है। यदि स-वस्तु पर और कर लगा दिया जाता है जिससे कुल आय उतनी ही होती है जितनी कि स-वस्तु पर व्ययकर और आय कर के पूर्ववर्णित मेल से होती है तो प्रभाव और भी खराब हो जायगा। लेकिन क पर कर लगने से यह घट जायगा। हम यह कल्पना कर लेते हैं कि क-वस्तु पर व्यय-कर स-वस्तु पर बालू 50% व्यय कर के मेल से उतनी ही आय दे सकेगा जितनी स-वस्तु पर लगने वाले व्यय कर और आय कर के प्रथम मेल से प्राप्त हो सकती थी। ऐसी कर-प्रणाली में सापेक्ष कीमतें 6 और 3 हो जाती हैं और कीमत-अनुपात 2 हो जाता है। अतः ऐसी दशा में क-वस्तु पर लगा हुआ परोक्ष कर आय कर से उत्तम माना जायगा।

उपर्युक्त दृष्टान्त में क-वस्तु पर लगने वाले नये व्यय-कर की दर वही रहती है जो स-वस्तु के पुराने व्यय-कर की थी। हम यहाँ पर अन्य परिस्थितियों की भी कल्पना कर सकते हैं। यदि स पर पुराने कर की दर क की नई दर से ऊँची होती है तो भी यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन यदि क पर कर की नई दर स की पुरानी दर से ऊँची होती है तो यह स्पष्ट है कि कर से पहले की प्रारम्भिक स्थिति के सम्बन्ध में विपरीत प्रभाव (Distortion) की दूसरी दशा पहली दशा की अपेक्षा ज्यादा खराब होती है और इसी वजह से आय कर क-वस्तु पर लगे हुए व्यय-कर से ज्यादा घण्टा होता है, चाहे स-वस्तु पर पहले से ही व्यय कर क्यों न लगा हुआ हो।

### (ई) मार्शल

हमने ऊपर जिन सेसकों की चर्चा की है उनमें से कइयों ने यह बतलाया है कि मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की सहायता से प्रत्यक्ष कराधान

की परोक्ष में उत्तमता गिड़गन्ने का प्रयाग किया था। कुमारी प्रोफे.<sup>29</sup>  
श्री वास्ट<sup>30</sup> धीर प्रोफेसर हेन्डरसन<sup>31</sup> सभी ने इन तरह के कदम प्रस्तुत  
किये हैं।

यदि मार्शल ने लोगों ने उद्धृत ग्रंथों की जाँच करें तो हमें पता  
चलेगा कि भारतवर्ष में उमने 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर समस्या' का विन्तुन भी  
विवेचन नहीं किया है। उद्धृत विवेचन के प्रारम्भ में एक पाठिपत्री  
(footnote) घाती है जिसका प्रमुख उद्देश्य कर के मामलों पर कोई निश्चित  
मत प्रगट करना नहीं है बल्कि पूर्ति की दशाओं के परिवर्तन से उपभोक्ता की  
बचत पर पड़ने वाले प्रभावों का दृष्टान्त प्रस्तुत करना है। दूसरी बात यह है  
कि मार्शल ने अपने विवेचन में यह बनमाने का प्रयाग किया है कि व्यय कर  
की विभिन्न किस्मों से द्रव्य की समान राशि जुटाने में बचत की सापेक्ष राशि  
कितनी होती है। पाठिपत्री प्रथवा मूल पाठ में शायद करें का कोई उल्लेख  
नहीं आया है और उमका निष्कर्ष इस प्रकार है :—'अतएव यदि कर की  
कोई दी हुई कुल राशि किसी वर्ग में निष्पूरतापूर्वक समूल करनी है तो  
उपभोक्ता की बचत को कम राशि उस स्थिति में होगी जबकि कर आराम दायक  
वस्तुओं पर न लगाया जाकर अनिवार्यताओं पर लगाया जाय; हालांकि सब  
पूछा जाय तो विलासिताओं का उपभोग, और कुछ कम ग्रंथों में, आराम-  
दायक वस्तुओं का उपभोग कर वहन करने की योग्यता का सूचक होता है।'

यहाँ पर यह तो स्वीकार करना होगा कि इस निष्कर्ष के प्रति आपत्ति  
उठाई जा सकती है क्योंकि इसमें शायद प्रभावों, नार्थ की पूर्ति पर पड़ने वाले  
प्रभावों और इस तथ्य को भुला दिया गया है कि पहले से ही कुछ कर  
क्रियाशील हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर से यह दृष्टिकोण सही है और  
यह तो निश्चित है कि मार्शल ने यह सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया  
कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों से ज्यादा अच्छे होते हैं।

मार्शल की इन अव्यक्त मान्यताओं (Implicit Assumptions) के  
आधार पर कि श्रम की पूर्ति (अथवा आय की मात्रा) दी हुई है और प्रारम्भिक  
स्थिति में कर नहीं लगा हुआ है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि उक्त  
यह दावा कि सापेक्ष रूप से बेतुल्य माँग वाली वस्तु पर कर लगने से कर-  
दाना पर अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है यों भी रखा जा सकता है कि उस  
वस्तु पर कर लगाया जाना चाहिए जिसकी प्रतिस्थापन लोच कम होती है।  
इस वैकल्पिक स्पष्टीकरण में आय प्रभावों पर भी ध्यान दिया गया है। माँग

की सोच प्रतिस्थापन की सोच के साथ बदलती है। ऐसा केवल उस स्थिति में नहीं होता है जब कि वस्तु पटिया होती है।

यह भी हो सकता है कि मार्शल ने जिस तरह ॥ इस समस्या को प्रस्तुत किया है उस पर आय-प्रभाव की जटिलताओं आदि को छोड़ देने पर भी आपत्ति की जा सकती है। मार्शल का तर्क इस प्रकार था कि एक व्यक्ति जितने कर का भुगतान करता है उससे उपभोक्ता को द्रव्य में उस वित्तीय भुगतान की प्रवृत्ति अधिक होती है जो वह सरकारी खजाने में देता है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत की क्षति पहुँचती है, लेकिन (यह बात महत्वपूर्ण भी है) उसका यह कहना है कि सरकार को मिलने वाला लाभ कर के भुगतान के बराबर ही होगा। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि हम एक तरफ उपयोगिता की समानताओं (Utility Equivalents) पर ध्यान देते हैं तो हम दूसरी तरफ भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें कर से होने वाली आय के स्वर्ण से प्राप्त उपयोगिता की वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए जो एक निम्न की उपभोक्ता की बचत को जन्म दे सकती है।

लेकिन यह आपत्ति उसी दशा में उपस्थित होती है जब कि हम करके द्वारा द्रव्य जुटाने की प्रक्रिया में होने वाली बचत की निरपेक्ष हानि (Absolute Loss) पर विचार करते हैं। यह आपत्ति उस समय उत्पन्न नहीं होती है जब कि हम विभिन्न करों से होने वाली बचत की सापेक्ष हानि पर विचार करते हैं क्योंकि इस स्थिति में यह माना जा सकता है कि एकसा स्वर्ण और इसीलिए उपयोगिता के एक से सार्थों की दशा विद्यमान है और बचत की व्यक्तिगत हानियों की मात्रा की तुलना करना उचित है। सदस्यता-वर्गों के प्रयोग से भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है।

यह समझ सकता बहुत कठिन है कि ऊपर उद्धृत किये गये लेखकों ने यह भूल क्यों की कि उन्होंने यह मान लिया कि मार्शल का 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर-समस्या' के प्रति अपना कोई दृष्टिकोण था। यह विशेष रूप से एक विविध-सी बात जान पड़ती है क्योंकि प्रोफेसर पीगू को अपनी पुस्तक Public Finance <sup>22</sup> के सभी संस्करणों में काफी दूर जाकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि मार्शल ने इस प्रस्थापना को सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया और सीधे-तांग करने पर भी उसके विस्तरेण का प्रयोग इस समस्या के विवेचन में नहीं किया जा सकता है।<sup>23</sup>



## (उ) निष्कर्ष

चूँकि हमारी मुख्य रचि इस बात में है कि 'कर समस्या' के वर्तमान विवेचन का अर्थ मंत्रियों व वित्त मंत्रियों के व्यावहारिक कार्यों की दृष्टि से क्या महत्व है, और उस दृष्टिकोण से इस 'समस्या' का सामाजिक पहलू स्पष्टतः एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए होने वाली 'कर समस्या' से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ निष्कर्षों की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अब तक के विश्लेषण से यह परिणाम निकलता प्रतीत होता है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की 'कर समस्या' के सम्बन्ध में आय करों अथवा व्यय करों की उत्तमता को सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा सीधा एवं विशिष्ट प्रमाण नहीं है जिसका आर्थिक कल्याण की दृष्टि से भी व्यावहारिक महत्व हो। सम्भव है कि वास्तविक जगत में व्यय की पूर्ति पूर्णतया स्विपर न हो और 'आदर्श प्रारम्भिक दशाएँ' विद्यमान न हों। यही नहीं बल्कि माँग-वक्रों की शायद्यों एवं प्रारम्भिक दशा के सम्बन्ध में हमारा सांख्यिकीय ज्ञान भी अपर्याप्त ही रहे।

प्रतिव्यक्ति कर की कल्याण के आधार पर अन्य सभी करों से होने वाली उत्तमता को सैद्धांतिक तर्क से सिद्ध किया जा सकता है (लेकिन प्रति व्यक्ति कर यामू व्यय कर के प्रतिरिक्त लगा हुआ नहीं होना चाहिए) परन्तु आय व व्यय करों के सम्बन्धों में ऐसा नहीं किया जा सकता है।

## 3. समुदाय (The Commonality)

## (घ) प्रस्तावना

गिण्टे भाग में<sup>34</sup> हमने जिन शुद्ध के लेनकों की चर्चा की है उसी भाग्य में स्पष्ट रूप से तो एक व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष करों के रूप में द्रव्य की एक ही हुई राशि जुटाने के सापेक्ष प्रभावों की समस्या का विशेष विचार था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म रूप में यह मान लिया था कि वे ही तर्क एवं चर्चा हन सम्बन्ध समुदाय में द्रव्य की एक ही हुई राशि जुटाने की समस्या के सम्बन्ध में की परस्पर मिश्र होवे।

इस चर्चे से हमें पट्टे है कि द्विषम-ओवेष्ट प्रमाण पर उस स्थिति में भी कई अर्थ-निर्णयें उठाई जाती हैं जब कि यह एक वैयक्तिक उपभोक्ता के दायरे के अन्तर्गत है। सामुदायिक समस्या के सम्बन्ध में हम आधुनिकों पर विश्वास करने से कई इस बात को लेना स्वीकार करना होता कि इस भी स्थिति में

यह सरल प्रमाण कहाँ तक सही सिद्ध होता है। ऐसा करते समय हम इन मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं जो परम्परागत प्रमाण को पुराने रूप में सही बना देती हैं, यथा धर्म की पूर्ति पूर्णतया बेलाच होती है और अन्य कर क्रियाशील नहीं होते हैं।

हमें दो जटिल तत्त्वों पर विचार करना है। सर्वप्रथम, हमें एक ऐसे प्रश्न पर विचार करना है जिसका अनिवार्यतः अन्तर व्यक्तिगत तुलनाओं (Interpersonal Comparisons) से सम्बन्ध होता है। एक तरफ तो यह सत्य है कि व्यक्ति भिन्न-भिन्न रुचि रखते हैं और दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी भिन्न-भिन्न होती है। द्वितीय, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कराधान या करारोपण के स्तर की अपेक्षा वास्तविक सरकारी खर्च का स्तर ही निजी उपभोग व विनियोग के लिए उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की मात्रा में बड़ी उत्पन्न करता है और—ऐसी स्थिति में—आय में वृद्धि करने के बजाय निजी खर्च में कमी करना ही कराधान का मुख्यउद्देश्य हो जाता है।<sup>25</sup>

### (आ) अन्तर व्यक्तिगत तुलनाएँ

विभिन्न आय-समूहों में व्यक्ति कर का कितना भार वहन करें इसका निर्धारण एक आर्थिक प्रश्न न होकर राजनीतिक है। यदि हम यह भी मान लें कि लोगो की रुचि समान है और साथ में सामान्य बुद्धि पर प्रभावित ये मान्यताएँ भी स्वीकार कर लें कि एक ही आय समूह में होने वाले व्यक्तियों को, जिनके एकसे उत्तरदायित्व हैं, कर के रूप में एक ही घनराशि देनी चाहिए, और आय के बढ़ने के साथ-साथ आय की सीमास्त उपयोगिता लगातार घटती जाती है, तो भी हम निश्चित रूप से यह नहीं बतला सकते कि प्रतिव्यय क्रमशः एक हजार पौंड और दो हजार पौंड बमाने वाले व्यक्तियों को मर्य मंत्री को अपनी आय का कितना प्रतिशत कर के रूप में देना चाहिए।

इस क्षेत्र में अर्थशास्त्री का स्थान मामूली-सा है, हालांकि पूर्णतया महत्त्वहीन नहीं है। उसका मुख्य कार्य यह बतलाना है कि आरोहीपन के विभिन्न भंशों वाले कर के कार्यक्रम लागू करने से अबत, कार्य, उपभोगशीलता आदि इसी तरह की अन्य बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगे। राजनीतिज्ञ उपर्युक्त जानकारी एवं अन्य निपुण जानकारी के आधार पर उस कर के दांचे को चुनेगा जो उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होगा; अथवा जिससे वोटों की कम ३ कम क्षति होगी; अथवा जो प्रशासनिक सम्भावनाओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यावहारिक

होगा। यह तो माना जा सकता है कि अर्थशास्त्री आरोहीपन के विभिन्न घंशों के प्रभावों के सम्बन्ध में जो जानकारी राजनीतिज्ञों को करा सकता है उन्हा स्पष्टतया काफी महत्व है, लेकिन यहाँ हम इन बात पर बल देना चाहते हैं कि एक अर्थशास्त्री कभी भी इन स्थिति में नहीं होगा कि वह एक कानून के रूप में अथवा एक वैज्ञानिक सत्य के रूप में यह कह सके कि समुदाय आरोहीपन करने वाला कर का ढाँचा अनुभूततम् होगा। बल्कि वह तो यह भी नहीं कह सकेगा कि यह ढाँचा आरोहीपन के किसी भिन्न घंश वाले दूसरे कर के ढाँचे से ज्यादा अच्छा होगा।

यदि लोगों की रधि भिन्न-भिन्न होती है और हम यह नहीं मान कर चलते हैं कि एक ही भाविक स्थिति वाले लोगों को एक से कर देने चाहिए, तो समस्या और भी जटिल हो जाती है।

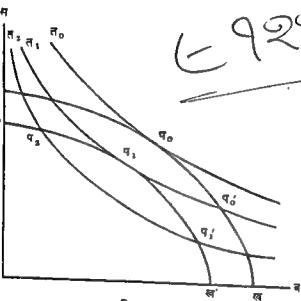
“प्रत्यक्ष-परोक्ष कर समस्या” के सामुदायिक पहलुओं के विवेचन में आये बड़ने के लिए यह मानना आवश्यक है कि सरकार अथवा किसी पुरोहित ने आरोहीपन का कोई नियम तय कर दिया है। इस साधारण ‘सामाजिक कल्याण फलन,’ (“Social Welfare Function”) के दिये हुए होने पर हम आगे बढ़ सकते हैं।

यदि हम यह मानकर चलते हैं कि किसी गैर-अर्थशास्त्री निर्णयकर्ता ने यह तय कर दिया है कि विभिन्न आय-समूहों अथवा व्यक्तियों का आय के रूप में किया जाने वाला घंशदान (Revenue Contributions) कितना होगा तो हमारे लिए यह विवेचन बाकी रह जाता है कि आय के इन विभिन्न घंशदानों की प्रत्यक्ष कर अथवा परोक्ष कर के रूप में प्राप्त करने का साधन भार क्या होगा। यह समस्या हल से परे नहीं है। हमारी इन वर्तमान मान्यताओं के आधार पर कि धन की पूर्ति स्थिर होती है और आदर्श प्रारम्भिक दशाएँ पाई जाती हैं, यह स्पष्ट है कि यह समस्या मूलतः वैसी ही है जैसी कि इसी तरह की मान्यताओं के आधार पर वैयक्तिक उपभोक्ता के समझ होती है। हम सीमाव्य से इस तरह से बहस करने की स्थिति में हैं जिस प्रकार समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर से ज्यादा अच्छा होता है, समूह समुदाय पर भी ऐसा ही निष्कर्ष लागू होना चाहिए।

हमें इस निष्कर्ष को आवश्यकता से ज्यादा महत्व देने के प्रति सावधान रहना होगा। विशेषतया हमें यह स्मरण रखना होगा कि वर्तमान प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत करदाताओं पर परोक्ष कर की अनिश्चित प्रत्यक्ष कर



८९२२



चित्र (२)



र कम पड़ता है, तथापि विभिन्न करदाताओं के लिए लाभ की मात्रा भिन्न होती है। ऐसा केवल उस स्थिति में नहीं होता है जब कि प्रत्येक ता की एक ही रूचि होती है।

### (4) करारोपण या कराधान का उद्देश्य (Object of taxation)<sup>36</sup>

एक व्यक्तिगत करदाता के सम्बन्ध में विचार करते समय यह सोचना कि उसके द्वारा राजकीय खजाने में किये जाने वाले भुगतानों को वह देने वाले सरकारी वित्त के भार के उत्तम माप के रूप में मान आय (केवल विपरीत प्रभावों को छोड़कर)। समुदाय पर विचार करते हैं इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा।

हमारी इन मान्यताओं के आधार पर कि बायें की मात्रा रिधति है और जो वस्तुओं की दशा पाई जाती है और साथ में पूर्ण प्रतिस्पर्धा तिरित्त मान्यता भी होती है, हम एक परिवर्तन-वक्र (transformation) वक्र या उत्पादन-सम्भावना-वक्र खींच सकते हैं जो किसी भी प्रकार के की व्यय की अनुपस्थिति में एक देशवासियों के समक्ष होने वाली उप-की सम्भावनाओं को प्रदर्शित करता है। चित्र 2 में हम धन-धन पर वस्तु और धन-धन पर वस्तु सेते हैं। क ज परिवर्तन-वक्र क और स रों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जो समाज में धन, पूँजी विधिक ज्ञान (सबको स्थिर मान लेने पर) के दिये हुए साधनों की मा से उत्पन्न की जा सकती है।  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  सामुदायिक तटस्थता-<sup>37</sup> का एक जोड़ा है और कराधान व सरकारी खर्च की अनुपस्थिति में धन व वस्तु-बाजारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के पाये जाने पर समुदाय क व वस्तुओं के ऐसे संयोग को चुनेगा जो परिवर्तन-वक्र पर  $U_3$  से सूचित है।  $U_3$  पर परिवर्तन-वक्र और सामुदायिक तटस्थता-वक्र का ज्ञान उन उ-अनुपात को सूचित करेगा जिन पर बाजार में क और स का विनिमय आयगा। पृष्ठभूमि में 'पैरिटी के अनुकूलन बिन्दु' ('Parelian imum') की ऐसी घनेक अटिल समानताएँ (equalities) हैं जो स्पष्टि दर्शित नहीं की गई हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि के-मुद्रा-उत्पादन में उत्पादन के साधनों की सीमांत भौतिक उत्पत्ति (marginal physical productivities) के अनुपात बने हो हैं जैसे कि- $U_1$  उत्पादन में है, इत्यादि।

यदि यदि सरकार समुदाय के साधनों का कुछ भाग अपने-बटौर के में का रिधेंद कर लेगी है तो अर्थव्यवस्था में निरी क्षेत्र के लिए चुनो होने

वाली उपभोग की सम्भावनाओं में कमी आ जायेगी। यदि सरकार अपने प्रयोग के लिए, जैसे सुरक्षा के लिए, उन साधनों को काम में लेती है जो पहले वस्तु का क क<sup>1</sup> अथवा ख वस्तु का ख ख<sup>1</sup> अथवा क ख के किसी भी बिन्दु पर क<sup>1</sup> अथवा ख ख<sup>1</sup> पट्टी की चौड़ाई से प्रदर्शित क और ख के जोड़े को उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे, तो निजी क्षेत्र की उपभोग की सम्भावनाएँ क<sup>1</sup> ख<sup>1</sup> हो जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समुदाय में निजी क्षेत्र की दसा बिगड़ जायेगी क्योंकि दूसरी स्थिति की अपेक्षा पहली स्थिति में अधिक वस्तुओं को प्राप्त करना सम्भव था।

हम जो बात कहना चाहते हैं वह यह है कि यह एक तथ्य है कि सरकार ने अपने वास्तविक खर्च में वृद्धि करली है, साधनों का उपयोग किया है और उपभोक्तारों के उपभोग-सम्भावना-वक्र को अन्दर की ओर खिंचा दिया है। कराधान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

पूर्णतया लोभदार कीमतों एवं द्राघ्यिक मजदूरी के सपर्यर्हित जगह में जहाँ सदैव पूर्ण रोजगार की दसा पाई जाती है वहाँ सरकार के वास्तविक खर्च में वृद्धि हुए बिना यदि कराधान में वृद्धि हो जाती है तो ~~॥~~ अस्त्योति-बारी (deflationary) सिद्ध होती है ऐसी दसा में कीमतों एवं द्राघ्यिक मजदूरी में तो गिरावट आयेगी लेकिन रोजगार की स्थिति बराम रखी जा सकेगी। इसी प्रकार सरकार के वास्तविक खर्च में होने वाली वृद्धि निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने वाली वास्तविक वस्तुओं व सेवाओं में कमी ला देती है। ऐसी कमी जिनके साथ कराधान में कोई वृद्धि नहीं होती है साथ ही कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होती है।

वास्तविक सरकारी खर्च में एक दिये हुए परिवर्तन की स्थिति में कराधान ~~॥~~ महत्व उम समय होगा है जब कि यह धारा की जाती है कि मुख्य-तः में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वास्तविक सरकारी खर्च की वृद्धि के साथ साथ कर के ऐसे परिवर्तन होने हैं जिनसे निजी खर्च में उन्नी हो पाएँगे में कमी आ जाती है, तो सामान्य मुख्य-तः अपरिवर्तित रह जाता है।

उत्पन्न बिन्दु में क<sup>1</sup> ख<sup>1</sup> ऐसी उपभोग की सम्भावनाओं के एक नये बिन्दु को प्रदर्शित करती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह वक्र ~~॥~~ की सम्भावनाओं को सूचित करता है चाहे सरकार अपनी वक्र को के प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर करेगी तो, अथवा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करे। कर के होने का प्रभाव दो तरह उपभोग-सम्भावना-वक्र के

उस निश्चित बिन्दु पर पहुँचा है जहाँ नई संतुलन स्थिति स्थापित होती है। यदि वाय प्रति व्यक्तिकर अथवा आयकर से प्राप्त की जाती है तो नई स्थिति  $P_1$  होगी और दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें पुनः परिवर्तन वक्र और तटस्थता-वक्र के  $P_1$  पर होने वाले ढलाव से प्रदर्शित होगी जो 'पैरेटो का अनुकूलतम बिन्दु' होगा। लेकिन यदि आवश्यक आय-व्यय कर (मान लीजिए ख-वस्तु पर) से प्राप्त की जाती है तो संतुलन की स्थिति  $P_2$  हो सकती है। इस स्थिति में क और ख की सापेक्ष कीमतें परिवर्तन-वक्र के ढलाव के बराबर नहीं होती हैं (चित्र में यह कीमत-अनुपात एक सरल रेखा से प्रदर्शित किया जा सकता है जो  $P_2$  पर तटस्थता-वक्र  $S_2$  को स्पर्श करती है) और  $P_2$ , जो स्पष्टतः 'पैरेटो का अनुकूलतम बिन्दु' नहीं है,  $P_1$  से घटिया है। इस दशा में प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर से ज्यादा अच्छा होगा।

लेकिन इस निष्कर्ष से कोई सामान्य परिणाम नहीं निकाल सकते हैं। प्रथम दशा में 'पैरेटो का अनुकूलतम स्थिति' होने पर ही यह निष्कर्ष निकलता है। यदि हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की हमारी प्रारम्भिक मान्यता को ढीला कर देते हैं तो शुद्ध सरकारी खर्च की स्थिति  $P^1$  पर न होकर  $P^2$  पर हो जाती है क्योंकि क-वस्तु उत्पन्न करने वाले उद्योग में एकाधिकारात्मक उत्पन्न विद्यमान होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपना व्यय करती है और आय (revenue) आयकर अथवा प्रतिव्यक्ति कर से प्राप्त की जाती है तो हम  $K^1$   $P^1$  पर  $P^2$ । इसी स्थिति में पहुँच जाते हैं यदि ख-वस्तु पर व्यय कर लगाया जाता तो हम  $K^2$   $P^1$  पर  $P^2$ । इसी स्थिति में पहुँच सकते थे। ऐसी दशा में व्यय कर का आयकर से अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है।

पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि यह अन्तिम बात पिछले सप्ताह के विवेचन से कितनी मिलती-जुलती है जहाँ व्यय करो पर विचार किया गया था, जैसे ख-वस्तु पर पहले से कर लगा हुआ है और क-वस्तु पर व्यय कर और लगा दिया जाता है। बहुत ही सीमित मान्यताओं की दशा में जिनके अन्तर्गत हम इस समय विवेचन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कराधान के पक्ष में कोई सैद्धान्तिक दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब कि हमें यह पता हो कि प्रारम्भिक दशा 'पैरेटो का अनुकूलतम दशा' थी।<sup>28</sup>

### (ई) उपसंहार : एक सारहीन विवाद ?

यद्यपि हम बहुत ही सीमित मान्यताओं के अन्तर्गत 'कर-समस्या' के सामुदायिक पहलुओं पर विचार कर रहे थे। यदि हम 'सामूहिक सामाजिक



कल्याण फलन' ('minor social welfare function') की धारणा को तो बनाये रखते हैं, लेकिन साधन की स्थिर प्रवृत्ति की मान्यता को ढीला कर देते हैं तो हम एक ऐसे तर्क के द्वारा जो प्रस्तुत लेख के इसी भाग के दूसरे अनुच्छेद में प्रयुक्त किये गये तर्क से काफी मिलता-जुलता है, उसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जिस पर हम एक वैयक्तिक उपभोक्ता के सम्बन्ध में पहुँचे थे। उस समय हमने यह बतलाया था कि यद्यपि सैद्धान्तिक तर्क-वितर्क से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ मात्रा में परीश कर का ढाँचा प्रत्यक्ष कर के ढाँचे से ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई भी उस समय तक यह निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि कर के लिए कौनसी वस्तुएँ उपयुक्त हैं जब तक कि उसके पास मांग-फलनों की भावृत्ति के सम्बन्ध में वर्तमान समय की तुलना में काफी अधिक ज्ञान न हो।

एक समुदाय के मामले में सैद्धान्तिक निष्कर्ष का महत्व और भी कम हो जाता है। जब तक यह (बहुत कुछ) विवेकशून्य मान्यता स्वीकार नहीं की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की रूचि एक सी है तब तक यह सम्भव है कि विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग व्यवहार आवश्यक हों क्योंकि जो वस्तुएँ अवकाश की सबसे ज्यादा पूरक होती हैं वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग-अलग दृष्टा करती हैं। वास्तविक जगत में इस तरह का अटल कर का ढाँचा बनाना सम्भव नहीं होगा। अतः समुदाय के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निश्चितता है कि यदि हमें मांग-फलनों (Demand Functions) की भावृत्ति की जानकारी भी हो (जो साधारण ही सम्भव है) तो भी सरकारी वित्त के भार को कम करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग कर सकना सम्भव नहीं होगा।

विभिन्न क्रिस्म के प्रत्यक्ष करों के भार पर विचार करते समय ध्यान देना ही घाघ-नामूद में भिन्न-भिन्न रुचियों वाले अलग-अलग व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष व परीश करों के द्वारा दाने जाने वाले भारों की सापेक्ष मात्राओं पर विचार करते समय भी ऐसे ही तर्क लागू होते हैं।

प्रारम्भिक स्थिति की समस्या के सम्बन्ध में तो हम देख चुके हैं कि समुदाय के मामले में यह और भी अटल हो जाती है क्योंकि एकाधिकार के तत्वों के कारण कीमतों व सामान्य मांग के बीच कोई काफ़ी सीमा तक सम्भव होती है। लेकिन वास्तव में यह घंटा भिन्न-भिन्न उद्योगों के अलग-अलग प्रारम्भिक स्थिति की समस्या के सम्बन्ध में लागू हो जाता है कि प्रारम्भिक

दशाओं की मान्यता पर आधारित निष्कर्षों का वास्तविक जगत में कोई सामान्य प्रयोग अव्यवा महत्व होगा।

मांग-वक्रों और प्रारम्भिक दशाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाने से यदि 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर-समस्या' से सम्बन्धित विभिन्न प्रमेयों (Theorems) को लागू करना सम्भव भी हो जाय तो भी प्रश्न उठता है कि क्या इस ज्ञान का कुछ उपयोग हो सकेगा? वास्तविक जगत में राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों के बीच कर-नीति को लेकर अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न एवं विवाद पाये जाते हैं लेकिन इनका उन समस्याओं से बहुत कम सम्बन्ध है जिन पर हमारे विचारों विचार करते रहे हैं। कराधान की विभिन्न किस्मों से बचत, कार्य एवं उद्यमशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव, करोत्तर आय-अवमानता की प्राप्ति सीमा और अजित व अनाजित आय के बीच उचित विभेद, प्रशासनिक लागतों की दृष्टि से विदेश करों को टासने एवं करों को छिपाने (Tax Evasion) की उपयुक्तता की सम्भावित सीमा; यह सीमा जहाँ तक राजस्व प्रणाली में विशेष वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग के विपक्ष में निर्णय किया जा सकता है—ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर अर्थशास्त्री कुछ-न-कुछ भोगदान दे सकते हैं और इन पर जनता व राजनीतिज्ञ दोनों इनकी धर्म व चाव से सुनेंगे। लेकिन 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर-समस्या' के विवाद में कोई ऐसी बात नहीं है जो राजनीतिज्ञों व जनता को अधिक प्रद सगे—चाहे ऊपर बतलाये हुए वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीय ज्ञान का अस्तित्व हो—क्योंकि कर के क्षेत्र में ये आय दृष्टिकोण कल्याण के पहलुओं को पूरी तरह से दबा लेते हैं और सब पूछा जाय तो वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीय ज्ञान का अस्तित्व भी नहीं है। हम जनता अथवा राजनीतिज्ञों को उनकी दधि की कमी के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं; यह समझना भी आसान नहीं है कि इस ज्ञान का उपयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। साथ में हमें उन संशयों का भी स्मरण रखना होगा जो हमने इस लेख के प्रथम भाग की भूमिका में उन तर्कों पर डाले थे जो पूर्णतया आर्थिक कल्याण के विचारों पर आश्रित हैं। कर नीति आर्थिक नीति का एक अंग होती है और आर्थिक नीति का राजनीति से सरोकार होता है। कर-नीति के निर्माण में और भी अधिक सामान्य दण के विचार शामिल होते हैं और इस प्रकार के तर्कों में कोई छार नहीं है कि केवल आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से विचार करने पर प्रमुख कर का बाका 'सर्वश्रेष्ठ' रहेगा।

अतः भय तक जो कुछ विवेचन किया गया है उसके बारे में बिना हिचक के मैं यह कहूँगा कि यह एक निस्सार विवाद है। यह तो सत्य आधुनिक कार्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुमारी जोमेफ और प्रोफेसर के 1939 के विचार पूर्णतया संतोषजनक नहीं थे और इसमें कोई सन्देह कि अर्थशास्त्रियों के लिए एक व्यवसाय से सम्बन्ध रखने के नाते इसका है, लेकिन इसकी व्यावहारिक उपयोगिता मामूली-सी है।

यह दुर्भाग्य है कि 'प्रत्यक्ष परोक्ष कर समस्या' जैसे छुट्ट विषय ने जे वपों में सार्वजनिक वित्त के विवेचन में इतना महत्वपूर्ण स्थान बना है कि अध्ययन के इस क्षेत्र के सम्बन्ध में काफी जानकारी की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है (और सिद्धान्ततः वह प्राप्य भी है)। थीमती 39 ने जिसे विभिन्न करों का ऊपरी एवं प्रभावपूर्ण करवाहता (Normal and Effective Incidence) कहा है उसके बारे में हमारा ज्ञान साथ में इन करों में होने वाले परिवर्तनों का हमारा ज्ञान प्रारम्भिक स्तर पर ही है, लेकिन यदि एक गैर-अर्थशास्त्री निर्णयकर्ता को अपना कार्य सतत्पूर्वक करना है तो उसके लिए इस तरह की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

(1) 'Some Comments on the Taxation of Personal Income and Expenditure in the United Kingdom', Public Finance, खण्ड 9, संख्या 2 पृष्ठ 191-213. इसी दृष्टिकोण के पक्ष में मैंने उद्धरण दिया था (उसी रचना में पाद टिप्पणी 7): I.M.D. Little, 'Direct Versus Indirect Taxes', Economic Journal, 1951. E. R. Rolph and G.F. Break, 'The Welfare Aspects of Excise Taxes', Journal of Political Economy, 1949.

(2) यह आवश्यक है कि हम 'प्रत्यक्ष-परोक्ष कर-समस्या' को इसके किसी भी रूप में उस विषय से भ्रम में न डालें जिसका प्रमुख सम्बन्ध ए० सी० पीयू के नाम से रहा है (यद्यपि मार्शल ने अपनी Principles आठवाँ संस्करण, खण्ड 5 अध्याय 12 में इसका उद्गम किया और अनेक हास के लेखकों ने इसका विवेचन किया

है) जिम्मे इस विषय पर अपने विचारों का सारांश अपने ग्रन्थ *Public Finance* के एक अध्याय में दिया ( भाग 2, अध्याय 7, 1947 ) जिसका शीर्षक 'कुसमायोजनो या कुसमजनों को ठीक करने के लिए लगाये गये कर व आर्थिक सहायता' ('*Taxes and Bounties to Correct Maladjustments*') है (इन्ही विचारों की उसने *The Economics of Welfare*, 1932 के संस्करण में विस्तारपूर्वक जांच की) । वास्तव में मुख्य कुसमायोजन तो यह है कि कुछ वस्तुओं के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को सीमा पर मिलने वाला प्रतिकूल समुदाय को मिलने वाले प्रतिकूल से ज्यादा अथवा कम हो सकता है, निजी लागतें सामाजिक लागतों से भिन्न हो सकती हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत धुआ (smoke) जैसी परिचित समस्याओं और बढ़ती हुई व घटती हुई पूर्ति—कीमत वाले उद्योगों की सामान्य किस्म की समस्याओं का विवेचन किया गया है । पीगू का तर्क इस प्रकार है कि ऐसे कुसमायोजनों को उन उद्योगों पर तो व्यय कर लगाकर ठीक किया जा सकता है जिनका इस अर्थ में अधिक विस्तार हो चुका है, और उन उद्योगों को आर्थिक सहायता (bounties) देकर ठीक किया जा सकता है जिनका पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं हुआ है और उसका मत है कि आर्थिक सहायता और करों का एक अनुकूलतम स्तर हुमा करता है ।

उपर्युक्त चर्चा निस्संदेह बहिर्ग्रस्त और महत्वपूर्ण है लेकिन जिस समस्या का हम विवेचन कर रहे हैं उसकी दृष्टि से इसका बहुत कम अथवा नहीं के बराबर महत्व है । भ्रमन में प्रोफेसर पीगू ने भी वक्त्याण के दृष्टिकोण से विभिन्न किस्म के ध्वयकरों के सापेक्ष गुणों से काफी सम्बन्ध रखने वाली समस्या पर विचार करते समय यह कहा है कि 'हम कल्पना कर लेते हैं कि या तो किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यक सुधार किये जा चुके हैं । इस प्रकार हम यह मान लेते हैं कि कर-आर्थिक सहायता (tax-bounty) प्रणाली के लिए जरूरी समझी जाने वाली मात्रा से भी ज्यादा घाय की आवश्यकता होती है ।' (*Public Finance*, 1947, भाग 2, अध्याय 9, पृ० 101).

- (3) देखिए J. S. Mill, *Principles of Political Economy* पुस्तक V, अध्याय III, एक सताब्दी के तीन चौथाई समय के बाद ऐसे

ही विवेचन के लिए देखिए : H. Dalton, *Public Finance*, नवा संस्करण, पृ० 33.

- (4) U. K. Hicks, *Public Finance* अध्याय IV निम्नान्वित लेख भी देखिए : 'The Terminology of Tax Analysis', *Economic Journal*, 1946.
- (5) जब भी मैं आयकर शब्द लिखता हूँ तो मेरा भाव्य प्रानुपातिक आय-कर से होता है। मैं 'आयकर' के पीछे 'आरोही' और 'अवरोही, विशेषणों का प्रयोग उस समय करूँगा जब कि मुझे इन गुणों वाले सूत्रों का उल्लेख करना होगा।
- (6) M. F. W. Joseph, 'The Excess Burden of Indirect Taxation,' *Review of Economic Studies*, खण्ड VI, संख्या 3, J. R. Hicks, *Value and Capital*, 1939, पृ० 41.

ए० टी० पीकोक और डी० बेरी ने बतलाया है ('A Note on the Theory of Income Redistribution, *Economica*, 1951, और ए० टी० पीकोक द्वारा सम्पादित *Income Redistribution and Social Policy* में डी० बेरी के 'Modern Welfare Analysis' नामक लेख में) कि ई० बेरोन ने *Giornale degli Economisti* में कितने पहले 1912 में तटस्थता-वक्र विस्तरेण का प्रयोग यह सिद्ध करने में किया था कि एक व्यक्ति धामकर के रूप में अधिक द्रव्यराशि और धन्य करो के रूप में कम राशि देकर समान रूप से संतुष्ट रह सकता है। उसी पत्रिका में 1921 में गिनो बोरगाटा (Gino Borgatta) ने, कुमारी जोसेफ और प्रोफेसर हिक्स के इस विशेष दावे को कि आय की एक सी हुई राशि करदाता की आयकर की स्थिति में ज्यादा अच्छी दशा में बने रहने देगी, उन्हीं के मिलते-जुलते तरीके से सिद्ध कर दिया था। पीकोक व बेरी ने इस खोज के लिए गेराई डेहोव (Gerard Dehove) को श्रेय दिया है (*Impot, Economie et Politique*, खण्ड I, Presses Universitaires de France, 1947)।

उपर्युक्त बयनों के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी जोसेफ और प्रोफेसर हिक्स की उद्धृत रचनाओं के प्रकाशन से प्राधुनिक विवेचन का प्रारम्भ मानना ही सही होगा। आगे चलकर मैं आसन्न के द्वारा दिये गये कार्य पर टिप्पणी करूँगा।

- (7) G. J. Stigler, *The Theory of Price*, (New York, 1946) पृ० 81-82 T. Scitovsky, *Welfare and Competition* (Chicago, 1951), पृ० 67.
- (8) इस अनुच्छेद में हम 'आदर्श' प्रारम्भिक दशाओं को मान लेते हैं।
- (9) L. Robbins, 'On the Elasticity for Income in Terms of Effort' *Economica*, 1930.
- (10) J. R. Hicks, पूर्व उद्धृत रचना, पृ० 36.
- (11) इन प्रश्नों पर निम्नलिखित देखिए : A.C. Pigou, *Public Finance* भाग II, अध्याय V, F. W. Paish, 'Economic Incentive in War-Time,' *Economics*, 1941, E. H. Phelps Brown, *A Course in Applied Economics*, Pitmans, 1951, अध्याय IV.
- (12) H. P. Wald, 'The Classical Indictment of Indirect Taxation,' *Quarterly Journal of Economics*, 1944-5.
- (13) A. C. Pigou, पूर्व उद्धृत ग्रंथ, भाग II अध्याय V
- (14) K. Boulding, *Economic Analysis* (मनोपिप्त संस्करण) पृ० 773-775.
- (15) देखिए A. C. Pigou पूर्व उद्धृत ग्रंथ (1947 का संस्करण), पृ० 69-71. E. Schwartz and D. A. Moore, 'The Distorting effects of Direct Taxation' *American Economic Review*, 1951. कुछ मात्रा में आधुनिक अनुभववाचक प्रमाण के लिए देखिए Second Report of the Royal Commission on the Taxation of Income and Profits, 1954.
- (16) Wald, पूर्व उद्धृत रचना, पृ० 596 आयकर के लिए प्रति व्यक्ति कर के समान होने के लिए एक-ही सोच की रद्दाएँ पूरी होनी आवश्यक है।
- (17) A. M. Henderson, 'The Case for Indirect Taxation' *Economic Journal*, 1948.

- (18) I. M. D. Little, पूर्ण उत्पन्न रचना ।
- (19) I. M. D. Little, पूर्ण उत्पन्न रचना, पृ० 384.
- (20) W. J. Corlett and D. C. Hague, 'Complementarity and the Excess Burden of Taxation', *Review of Economic Studies* 1953-4, पृ० 21-30.
- (21) वही, पृ० 30.
- (22) कोरलेट व हेन ने इस विषय के प्रामाण्य का स्पष्टीकरण निम्नांकित ढंग से किया है : 'यदि अवकाश की मात्रा का माप समय होता, जैसा कि उस स्थिति में होता है जब कि आय की एक अधिकतम सीमा होती है जो एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है चाहे वह कितना ही कठिन श्रम क्यों न करे, तो पूर्णता के अधिक या कम मात्रा की आसानी से परिभाषित किया जा सकता है । ऐसी दशा में अवकाश की मात्रा इस अधिकतम आय और उसकी वास्तविक आय के अंतर से मापी जा सकती है । उस स्थिति में हमारी भर्त्सना यह होगी कि एक वस्तु व अवकाश के बीच पूर्णता की लोच दूसरी वस्तु व अवकाश के बीच पाई जाने वाली पूर्णता की लोच से अधिक होनी चाहिए' (पूर्व उद्धृत लेख, पृ० 24) ।
- (23) यदि हम कुछ मान्यताओं को छोड़ा करके निम्न बातों पर ध्यान देंगे हैं, जैसे अवकाश के अतिरिक्त दो से अधिक वस्तुओं का अस्तित्व होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और आपस में आरोही अथवा अवरोही और आनुपातिक हो सकते हैं, तो भी वैसे ही निष्कर्ष निकलता है ।
- (24) इस अनुच्छेद में हम यह मान लेते हैं कि श्रम की पूर्ति स्थिर रहती है ।
- (25) मूलपाठ अथवा पाठटिप्पणियों में वर्णित लेखकों में से स्टिग्लर वार्ल्ड और सीटोवस्की ने स्पष्टतया बतलाया है कि जिन वस्तुओं पर वे विचार कर रहे हैं उनमें से एक पर कर नहीं लगाया है ।

- (26) नीचे का विश्लेषण धार० के० डेविडसन के हाल ही के एक लेख पर आधारित है 'The Alleged Excess Burden of an Excise Tax in the Case of an Individual Consumer', *Review of Economic Studies*, 1952-3). डेविडसन का इस समस्या का विश्लेषण पूर्णतया सतोषजनक नहीं है, हालांकि —मेरी राय में—उसने इस बात को नहीं पहचाना है कि उसके समस्त निष्कर्ष धर्म के प्रति-वक्र के सम्बन्ध में द्रव्य लोच की माप्यता पर कैसे आश्रित हैं। उसने इस बात को भी नहीं माना है कि कुछ लेखकों ने उसके प्रश्न पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हालांकि उनका योगदान बहुत ही कम अच्छा हो पाया है। (विशेष रूप से E. R. Rolph and G. F. Break, पूर्व उद्धृत रचना, और M. Friedman का *Journal of Political Economy* 1952 में लेख *The Welfare Effects of an Income Tax and an Excise Tax*)
- (27) इसका एक संयोग भी हो सकता है।
- (28) R. K. Davidson, पूर्व उद्धृत, पृ० 211-212
- (29) पूर्व उद्धृत, पृ० 226 यही कुमारी जोसेफ ने बाद टिप्पणी में *The Principles*, आठवाँ संस्करण, पृ० 467 दिया है।
- (30) पूर्व उद्धृत, पृ० 578 : बाल्ड ने भी बाद टिप्पणी में *The Principles*, आठवाँ संस्करण, पृ० 467 दिया है।
- (31) पूर्व उद्धृत, पृ० 538 हेन्डरसन ने भी यही संदर्भ दिया है जो कुमारी जोसेफ और प्रोवेमर बाल्ड ने दिया है।
- (32) 1928, 1929, 1947.
- (33) A. C. Pigou, *Public Finance*, भाग II, अध्याय IX.
- (34) कुमारी जोसेफ और सर्वेधी रिक्ल, बाल्ड और हेन्डरसन
- (35) मैंने यहाँ पर 'इस मद्दर्भ में' इसलिए लिखा है कि बराधान का अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे धन्य के वितरण में अधिक समानता लाने के लिए धन्यदा रिक्ली बिदेय बस्तु का उपयोग बंद करने के लिए इत्यादि।



- (36) यह अनुच्छेद निम्न लेखों पर आधारित है : Rolph and Break, पूर्व उद्धृत; Little, पूर्व उद्धृत; Friedman पूर्व उद्धृत; और 'एक उत्तर', *Journal of Political Economy*, 1952 (अगस्त) पृ० 334-336, यह भी देखिए—C.G. Phipps, 'Friedman's Welfare Effect', *Journal of Political Economy* 1952 (अगस्त) पृ० 332-334.
- (37) प्रत्येक उपभोक्ता की एक सी रचि होने पर ही यह पद्धति सर्वपूर्ण मानी जा सकती है।
- (38) यह जानना रचिप्रद होगा कि इस बहस के अन्दर जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें से अनेक बातें *Econometrica* के 1938 व 1939 में प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध होर्टलिंग-फिश बहस के दौरान कही गई थीं। यह बहस दिसम्बर 1937 में होर्टलिंग के द्वारा *Econometric Society* को दिये गये अध्यक्षीय भाषण से उत्पन्न हुई थी। ('The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates', *Econometrica*, July, 1938) इस बहस की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : प्रारम्भिक दशाओं के महत्व पर बल देना, चाहे अन्य कर नियासील हो, और एराधिकारी तत्व उपस्थित हों अथवा अनुपस्थित हों, और यह सुझाव कि आयकर प्रति व्यक्ति कर की तुलना में अधिक भार डालता है। सब पूछा जाय तो यह बेनिथ बीस्टिंग के इस निर्णय का एक दूसरा दृष्टान्त है कि 'यह एक सुन्दर धार्मिक परम्परा है कि किसी भी वस्तु के बारे में अन्वेषण करने के बजाय हम पर विश्वास करवा ज्यादा प्रामाण होना है' (*Survey of Contemporary Economics*, अर्ग 11, अध्याय 1)।
- (39) U. K. Hicks, *Public Finance*, अध्याय IX और 'The Terminology of Tax Analysis', *Economic Journal*, 1946, देखिए R. A. Musgrave, 'General Equilibrium Aspects of Incidence Theory', *American Economic Review* (परिचित) 1953 और 'On Incidence' *Journal of Political Economy*, 1953.

## कर-नीति की रूपरेखा

कर-जीव-प्रायोग  
रिपोर्ट, खण्ड I

2. विचारार्थ विषय (Terms of reference) :— हमारे विचारार्थ रखे गये विषयों के अन्तर्गत हमें कर-प्रणाली के चार मुख्य पहलुओं की जांच करनी है : (अ) कर-प्रणाली की करवाह्यता (incidence of the tax system) और आय व धन की असमानता को घटाने की दृष्टि से इसकी उपयुक्तता अर्थात् करारोपण या कराधान (taxation) के भार का वितरण और इससे पुनर्वितरणकारी प्रभाव और सम्भावनाएँ (आ) देश के विकास-कार्यक्रम और इसके लिए आवश्यक साधनों (कराधान की नई दिशाओं सहित) की दृष्टि से कर-प्रणाली की उपयुक्तता, (इ) पूँजी-निर्माण और उत्पादक व्यय के योग एवं विकास पर आय (इसके हाथे व स्तर) के कराधान के प्रभाव, और (ई) कराधान का मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति की दशाओं में प्रयोग। हमें कर-नीति सम्बन्धी प्रश्न के इन सभी पहलुओं के बारे में कर-प्रणाली में किये जाने वाले सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देने हैं।

3. विचारार्थ रखे गये विषय जांच का दृष्टिकोण निर्धारित किए जाते हैं। ऊपर वर्णित चार पहलु निम्नानुसार विषयों से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक निम्न उद्देश्यों के रूप में देखे जा सकते हैं, (अ) वितरण में सुधार, (आ) सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा, (इ) निजी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि और (ई) अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बढ़ावा। सब पूछा जाय तो उत्तर वितरण, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में अद्वैतात्मक अर्थिक उत्पादन में अर्थव्यवस्था में ऊँचे दर्जे की स्थिरता ये स्वयं राष्ट्रीय आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये उद्देश्य अपने आप में न केवल अपवादरहित बल्कि ये कई तरह से अत्यन्त आर्थिक विकास व प्रगति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कर-नीति इन उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं तक बाधात्मक सिद्ध हो गयी है ? शिवाय, कुछ उद्देश्यों के बीच विरोध के स्तर भी पाये जा सकते हैं, उ



की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाई थी। आज के युग में आर्थिक व राजनीतिक दशाएँ और उनके प्रति जनता की प्रतिक्रियाएँ उन्नीसवीं शताब्दी के उन दिनों से बिल्कुल भिन्न हैं जब कि राजनीतिक उदारतावाद (liberalism) और आर्थिक निर्बाध-नीति (laissez faire) का बोलबाला था। अब हम समानता के प्रश्न की आर्थिक व सामाजिक दृष्टियों पर नहीं छोड़ सकते हैं। इस देश की परिस्थितियों में यह विशेष रूप से सही है। संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में इस उद्देश्य को जो महत्त्व दिया गया है उसका उल्लेख पहले के अध्याय में भी हुआ है। इस समय धन व अवसरों में व्यापक मात्रा तक समानता प्राप्त करना आर्थिक विचार और सामाजिक उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। यह मान अब बहुत समय तक नहीं टाली जा सकती है कि कराधान का यत्र भाग्य के ऐसे पुनर्वितरण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय के अधिक अनुरूप हो। अतः हमें ऐसे साधन ढूँढने होंगे जिनकी सहायता से हम एक साथ दोनों दिशाओं—आर्थिक उत्पादन और उसका वितरण—में आगे बढ़ सकें।

6. इस सम्बन्ध में दो तरह की असमानताओं में अन्तर करना होगा, एक तो वह जो अधिक प्रयत्न अवस्था उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक दृष्टि से आवश्यक मानी जाती है और दूसरी वह जो इस उद्देश्य के लिए अनावश्यक होती है। यह तो स्पष्ट है कि अव्यवस्था में अज्ञित और अनाजित दोनों तरह की धन और धन में काफी मात्रा में ऐसी असमानता है जो टाली जा सकती है। असमानता को जिस बात से प्रेरणा मिलती है उसका एक प्रमुख कारण वह जीने का तरीका व सामाजिक प्राकृष्ट (Pattern) है जिसके प्रति समाज के विशिष्ट वर्ग परम्परा से अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यह तो प्रसङ्गिक है कि इनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव अच्छा पड़ता है जिसका प्रतिरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी के साथ उस जीवन स्तर के सम्बन्ध में हमारे परम्परागत विचार जो उच्च व्यवस्थाओं में शोभा देते हैं और प्रतिफल व लाभ के सम्बन्ध में वे प्रत्याशाएँ जो प्रयत्न व प्रतियोगिता को बनाये रखने के लिए आवश्यक होती हैं—इनमें भी उचित परिवर्तन होना चाहिए। जो प्रतिफल उचित माने जाते हैं उनमें होने वाले परिवर्तनों की इस प्रक्रिया का एक दृष्टान्त उस संक्रमण-काल में भी देखा जा सकता है जब मुद्रास्फीति की अवधि में जल्दी से धनी हो जाने एवं सुगमता-पूर्वक लाभ प्राप्त करने की स्थिति से आर्थिक क्रिया की सामान्य अवस्था के अनुकूल होनेवाले साधारण प्रतिफलों की तरफ गति होती हुई।

7. लेकिन यह तो गलत है कि धान व धन की असमानताएँ अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की उन्नेयनीय विशेषताएँ मानी जानी हैं जो उनकी आर्थिक दशा और संस्थागत ढांचे से उत्पन्न होती हैं और असमानता के कुछ मूलभूत स्रोतों को एक निश्चित उद्देश्य के भीरे-भीरे मिटाकर ही समानता की तरफ काफी प्रयत्न की जा सकती है। कर-प्रणाली इस तथ्य को स्वीकार करके इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से मदद दे सकती है कि आय का वितरण अत्यंत-समतापूर्ण नहीं होता है बल्कि राजस्व-प्रणाली में इस दिशा में निश्चित रूप से बच दिए जाने पर इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह कम इस बात की वास्तविक जांच पर आधारित होना चाहिए कि किसी भी समय में कर-प्रणाली असमानताओं को कम करने की दिशा में क्या कर सकती है और द्वितीय, यह प्रक्रिया निम्नी उत्पादक प्रयत्न व उद्यम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वहाँ तक धाये में आई जा सकती है।

8. जो कर-नीति अपेक्षाकृत ऊँचे स्तरों वाली धाय को कम करके असमानताओं को घटाने का मध्य रणनीति है वह उन राजस्व प्रियाओं (fiscal operations) का नेचल एक रूप होती है जो इस क्षेत्र में सम्भव हो सकते हैं। इसी के एक महत्वपूर्ण घटक पहलू के रूप में आर्थिक विश्वास (उदाहरण के लिए, कृषि व सिंचाई) पर किये जाने वाले सार्वजनिक व्यय और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के विस्तार को माना जा सकता है जो समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की स्थिति को सुदृढ़ करने में भाग लेते हैं।

9. देश में फैली हुई आय व धन की असमानता की मात्रा के सम्बन्ध में इस समय कोई विश्वस्त माप उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह तो ज्ञात है कि भारत में काफी सीमा तक असमानता विद्यमान है। यह भी जाहिर है कि इसमें मुद्राकालीन मुद्रास्फीति और इसकी वजह से विभिन्न वर्गों के बीच आय व धन के वितरण के प्रारूप पर पड़ने वाले प्रभावों के परिणामस्वरूप वृद्धि भी हुई है। मोटे तौर से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण जनता में सामान्य रूप से स्वामी-कृषकों (owner-cultivators), गुजर-बसर करने वाले कृषकों (subsistence farmers) के विशाल वर्ग को छोड़कर, एवं विशेष रूप से बड़े खेतिहर उत्पादकों और ग्रामीण जनता में व्यापारी-व्यवसायी वर्ग और औद्योगिक थमिकों को विभिन्न वर्गों में लाभ पहुँचा है। दूसरी तरफ स्थिर आय वाले वर्गों की आर्थिक दशा में गिरावट आई है। इस वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में साधारणतः मध्यम-वर्ग आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूर आते हैं। मुद्रास्फीति के परिचित प्रभावों के परिणामस्वरूप

व्यावसायिक आय में वृद्धि होने और जिन दलाकों में जमींदारी समाप्त नहीं हुई है उनमें पूँवपिछा ऊँची कृषि-आय हो जाने से असमानता में स्पष्टतया बढ़ोतरी हुई है। साथ में जनसंख्या के विनाश समूहों की वास्तविक आय में गिरावट आई है। ऐसे समूहों में नकद पारिवर्तिक पाने वाले खेतिहर श्रमिक और सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में निम्न वेतन पाने वाले लोग आते हैं।

10. आयकर को काफी घटोही बना देने पर भी व्ययव्यवस्था के कुछ भागों में और आय की कुछ सीमाओं में असमानता बढ़ी है। लेकिन आयकर के अन्तर्गत कुछ राज्यों को छोड़कर, खेतिहर आय नहीं माती है और आयकरदाताओं के महत्वपूर्ण समूहों में यह कर काफी मात्रा में छिपा लिया जाता है। यदि असमानता के प्रश्न को प्रभावपूर्ण ढंग से हल करना है तो प्रत्यक्ष कराधान को अधिक आरोही बनाने के साथ-साथ कर को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने के उपाय भी धरनाने होंगे ताकि करके जाल का क्षेत्र विस्तृत किया जा सके। विलासिता-उपभोग (luxury consumption) की कुछ किस्मों पर अतिरिक्त कर लगाकर कराधान के ढांचे में अधिक विविधता लाने से भी उन वर्गों के कर-प्रदान में वृद्धि करने में मदद मिलेगी जिनको मुद्रास्फीति से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर प्रसंगवश यह कहना उचित होगा कि विलासिताओं के उपभोग पर ऐसा भारी कराधान न केवल उपभोग की असमानताओं को प्रत्यक्षतया कम करने का एक उपयुक्त साधन प्रमाणित होगा बल्कि यह कुछ सीमा तक अधिक आवश्यक उत्पादन के लिए साधन भी उपलब्ध करा सकेगा। सम्पत्ति व आयदाद के कराधान का फैलाव भी असमानताओं को कम करने का एक सम्भावित साधन हो सकता है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए कर-व्यय का पूर्ण उपयोग करने के सम्बन्ध में एक गम्भीर मर्यादा है जिसका हृद उत्प्रेष करना चाहेंगे। यह इस बात से उत्पन्न होती है कि यदि सार्वजनिक आय (public revenues) में काफी वृद्धि करनी है—और हम पहले ही ऐसी वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं—तो आम जनता से भी ऐसे करों के रूप में कुछ प्रदान आना चाहिए जिनका आधार चौड़ा हो। सर्वसाधारण के लिए कराधान में वृद्धि करने की आवश्यकता, बदले में कर-प्रणाली में घटोहीपन की ऐसी वृद्धि को सीमित कर देगी जो अन्यथा प्रत्यक्ष व परीक्ष कराधान के उचित परिवर्तनों से सम्भव हो सकती थी।

11. कराधान में न्याय (Equity in Taxation) :—यहाँ पर यह उचित होगा कि हम कर-प्रणाली के भार-वितरण के सम्बन्धित प्रश्न पर एक

ऐसे धाधार पर विचार करें जिसकी सम्मति: सबसे ज्यादा बर्ना की जाती है। इसे ग्याय कहते हैं। इस सम्मति के सौमित्र विवेचनों में भार के विवरण में ग्याय धारणा औचित्य को प्रायः कर-प्रणाली का उद्गुष्ट नहीं तो भी एक महत्वपूर्ण मापदण्ड धारण माना जाता है, और यह ग्याय का सिद्धान्त सरकार के राजकोषीय धाधार में विश्राम उत्पन्न करने की क्षमता रगता है जिससे जनता का मनोबल बना रहता है और उत्पादक प्रयत्न और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कर-प्रणाली का धाय ही ऐसा कोई दूसरा गुण हो जिसकी परिभाषा धारणा माप हमसे बठिन हो। ग्याय की धारणा को प्रारम्भिक रूप से मापू करने के लिए यह धारणा है कि एक ही आर्थिक दसा वाले व्यक्तियों के साथ समान बर्ना दिया जाय। लेकिन लोगों की आर्थिक दसा एवं परिस्थितियों में काफी अंतर पाये जाने हैं जिसकी वजह से इस धारणा की मापू करने से प्राप्त ग्याय की मात्रा व्यवहार में ज्यादा व्यापक नहीं होती है। आर्थिक परिस्थितियों में अंतर होने पर यह प्रश्न उठता है कि क्यों की दृष्टि से क्या भेद दिया जाय ताकि ग्याय की छतें पूरी हो सकें। ग्याय की बरौटी का सबसे ज्यादा स्वीकृत प्रयोग सापेक्ष करदेय क्षमता के अनुसार करो को लगाने के सिद्धान्त में देखने को मिलता है। यदि असमान साधनों वाले व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले सापेक्ष बर्ना में ग्याय प्राप्त करना है तो करदेय क्षमता स्वयं आरोहीपन के कुछ अंश (Some Degree of Progression) की तरफ इंगित करती है। लेकिन कोई भी ऐसा सिद्धान्त या फार्मूला नहीं है जो आरोहीपन का सतमय ऐसा नमूना प्रस्तुत कर सके जो एक देश की दसाओं के अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त आरोहीपन से बचत, विनियोग एवं फलस्वरूप उत्पादन पर पड़ने वाले प्रेरणाहारी प्रभावों (Disincentive effects) पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अतः विभिन्न आय-सीमाओं (Income-ranges) में बाँटनीय समझे जाने वाले आरोहीपन की मात्रा एक तरफ क्यों के प्रयोग से अधिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य एवं दूसरी तरफ विनियोग के प्रेरक तत्वों को बनाये रखने एवं उनको सुदृढ़ करने और उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

12. ग्याय की धारणा भ्रम में डालने वाली होती है और यह सम्पूर्ण करप्रणाली के मूल्यांकन में, काफी सापेक्ष भी होती है। एक तो यह आवश्यक है कि ग्याय (Equity) पर सम्पूर्ण राजस्व की क्रियाओं में विचार किया जाय, अर्थात् करवाहता के साथ-साथ सार्वजनिक

व्यय से प्राप्त लाभों के वितरण पर भी विचार किया जाय। दूसरी बात यह है कि कर-प्रणाली के बारे में निर्णय कार्य की उस मात्रा को देखकर किया जाय जो इसे अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति, आय के वितरण और समाज के सामान्य संगठन के सम्बन्ध में करना है। इन सबकी वजह से सम्पूर्ण कर-प्रणाली में न्याय की आवश्यकताओं के अनुकूल आरोहीपन की न्यूनतम मात्रा को लागू करना असम्भव हो जायगा। दिये जाने वाले विकास-व्यय की मात्रा के दिये हुए होने पर, करदेय क्षमता के सिद्धान्त के अनुसार कर-प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन करने पर भी सम्पूर्ण कर-प्रणाली में कोई उल्लेखनीय अंश तक आरोहीपन को प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं होगा। अल्पविवक्षित देशों के लिए जो अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहते हैं यह आवश्यक होगा कि उनकी कर-प्रणालियाँ करदेय क्षमता के कठोर आधार से कुछ दूर हटें, क्योंकि सभी आर्थिक विकास के समय जो उनकी राष्ट्रीय नीतियों में आवश्यक तत्त्व माने जाते हैं, ठीक-ठीक अवधि में प्राप्त किये जा सकेंगे। यद्यपि न्याय की कसौटी को सम्पूर्ण कर-प्रणाली पर उचित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि कर-प्रणाली के कुछ अंगों में असमानता या अन्याय के विशेष तत्वों को मिटाना सम्भव न हो। सच पूछा जाय तो कर-प्रणाली में न्याय अथवा औचित्य को आगे बढ़ाने की एक अपेक्षाजनक दिशा बहुधा यह होती है कि एकती स्थिति वाले व्यक्तियों पर कर लगाने में अनौचित्य अथवा अन्याय के तत्वों को मिटाया जाय अथवा कम किया जाय। इनके कूटान्त वैयक्तिक करों से सम्बन्धित अध्यायों में दिये जायेंगे।

13. विकास-कार्यक्रम के अनुकूल कर-प्रणाली :— इस प्रश्न पर कुछ और विचार करने की आवश्यकता है कि एक देश के विकास-कार्यक्रम के लिए किस किस की कर-प्रणाली उपयुक्त होगी, विशेषतया उन साधनों के सदर्भ में जिसकी इसे आवश्यकता होती है। कराधान अपने आप में तो आय में कमी ही लाता है और इस प्रकार निजी उपभोग और विनियोग को भी घटा देता है। लेकिन करों से प्राप्त होने वाली आय सार्वजनिक क्षेत्र को उपलब्ध होती है और सार्वजनिक खर्च यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों को एक साथ लेने पर राजस्व क्रियाओं (Fiscal Operations) का विमुक्त प्रभाव उपभोग व विनियोग के दो उद्देश्यों की दृष्टि से समाज की चालू आय के उपभोग को कम करना होता है अथवा बढ़ाना होता है। सामान्यतया उपभोग की प्रवृत्ति निर्धन एवं सघन समुदायों में तीव्र होती है



घोर परिणामस्वरूप विनियोग मोटा होता है। वह कर-प्रणाली जो कुल मिलाकर विनियोग और बचत के दो पक्षों की दृष्टि से पूँजी-संचय को बढ़ावा देती है, एक अच्छी आवश्यकता को पूरा करती है, क्योंकि ऐसे समुदायों में पूँजी-संचय की दर में वृद्धि की आवश्यकता सर्वत्र विद्यमान होती है। उपभोग अथवा विनियोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सापेक्ष प्राथमिकता आर्थिक स्थिति के साथ बदल सकती है। लेकिन आर्थिक स्थिति के आधार पर मोटा को छोड़कर, कर-प्रणाली का सामान्य और उपभोग को नियमित करने का विनियोग व बचत को प्रोत्साहित करने का अर्थ-व्यवस्था की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विपरीत होना चाहिए।

14. इन प्रश्नों के कई पहलू होते हैं। सर्वप्रथम, कराधान की राशि बहुत कुछ बचत के एक निश्चित-अंश में ही प्राप्त होती है जिसका निर्माण अर्थ-व्यवस्था में उपभोग में ऊँच होने वाले अधिभोग से होता है, और जो सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। कर प्रणाली के लिए बचत को निजी प्रयोग से सार्वजनिक प्रयोग में ले जाना तो अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन विनियोग के लिए उपलब्ध होने वाली बचत की कुल मात्रा में वृद्धि कर सकना अत्यधिक कठिन होता है। कराधान (निजी) उपभोग और विनियोग दोनों में कमी ला देता है। कराधान निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले साधनों में काफी कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले साधनों में वृद्धि कर देता है—इन बातों से यह स्पष्ट नहीं निकलता है कि ऊँची दरों पर भी कराधान कुल विनियोग में कमी कर देगा। यदि कराधान प्रशासनिक व विकासेतर खर्च में वृद्धि न करके सार्वजनिक विनियोग की मात्रा में वृद्धि कर देता है तो कुल विनियोग इस सीमा तक पहले से अधिक हो जायगा कि कराधान की वजह से निजी विनियोग का परित्याग करने के बजाय उपभोग का परित्याग करके प्रतिरिक्त सार्वजनिक विनियोग सम्भव हो सकेगा है। सच पूछा जाय तो कराधान, उस अर्थ-व्यवस्था में जहाँ उपभोग की प्रवृत्ति सामान्यतया ऊँची होती है, बचत व विनियोग की कुल मात्रा में वृद्धि करने का एक सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण साधन हो सकता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-संचय में वृद्धि करने का सम्भवतया एक मात्र प्रभावशाली तरीका यह होगा कि राज्य निजी उपभोग से सार्वजनिक विनियोग में साधनों के हस्तान्तरण की बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कराधान का जो डंका इस उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और उपयोगी होगा वह प्रत्यक्ष व परोक्ष

कराधान का एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें ठीक-ठीक विविधता पाई जायगी और जो उपभोग से सार्वजनिक विनियोग की तरफ शैतिक व वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण ऐसे ढंगों एवं पैमाने पर करने का प्रयत्न करेगा जो विकास कार्यक्रम के अनुकूल होंगे। दूसरे शब्दों में, कर-प्रणाली में गहनता व व्यापकता (Depth and range) दोनों पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सभी विकास की गति तेज की जा सकती है। अतः अनेक विस्म की विलासिता अथवा भव्य-विलासिता की वस्तुओं पर घटिरिक्त कर लगाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत नीची दरों पर जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं पर व्यापक ढंग से कर लगाने का सुझाव दिया गया है। प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में वैयक्तिक आयकर की ऊँची दरों के साथ उस आय पर कुछ छूट दी जानी चाहिए जो बचाई अथवा विनियोजित की जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह कर-प्रणाली जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी और जिसमें विकास-कार्यक्रम और इसके लिए आवश्यक होने वाले साधनों का ध्यान रखा जायगा, ऐसी होगी जो निजी क्षेत्र में होने वाले विनियोग में यथासम्भव कम से कम सभी करके सार्वजनिक क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले विनियोग के साधनों में वृद्धि करेगी। इसी वजह से ऐसी कर-प्रणाली में सभी वर्गों के उपभोग पर यथासम्भव ज्यादा-से-ज्यादा नियंत्रण लगाया जायगा। ऊँची आय वालों के उपभोग पर वास्तव में नीची आय वालों की तुलना में अधिक नियंत्रण लगना चाहिए।

15. यहाँ इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि केवल विलासिता की वस्तुओं पर ऊँचे कर लगाने से ही पर्याप्त आय नहीं मिल जाती है। वस्तु-कराधान से काफी आय प्राप्त करने के लिए और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में उपभोग पर काफी नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक होगा कि निम्न आयवालों के उपभोग पर और उन वस्तुओं पर जो साधारणतया अनिवार्यताओं के वर्ग में शामिल की जाती है (जिन अनेक वस्तुओं के सहित जो सविधान की धारा 286 के अन्तर्गत अनिवार्य वस्तु-अधिनियम में शामिल हैं) उत्पादन और बिक्री करों का विस्तार किया जाय। इनमें से कुछ वस्तुएँ तो वास्तव में पहले से ही काफी ऊँची दरों पर केन्द्रीय कराधान (Central taxation) के अन्तर्गत आती हैं। इनमें से कुछ इस कटोर अर्थ में अनिवार्य वस्तुएँ नहीं हैं कि ये निम्नतम आयवालों के लिए जीवन-रसक अनिवार्यताएँ हों। लेकिन मिट्टी के सेत जैसी वस्तुएँ उस अर्थ में अनिवार्यताएँ हैं, फिर भी उन पर वर्तमान

16. कटाघात की सीमाएँ : करवेय क्षमता :—यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न है कि कटाघात के माध्यम से विकास के लिए साधनों में वृद्धि करने की प्रक्रिया की अवधि/वस्था की नियन्त्रिता को सतरे में डालने बिना किन सीमा तट धारों से बचाया जा सकता है ? विकास-कार्यक्रम के लिए भुट्टाये जा सकने वाले

उत्तरा है कि कल्याण के माध्यम से विज्ञान के लिए साधनों में सुविधा करने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को स्थिरता को सतरे में डालने बिना फिर सोमा तट प्रायः से बाधा जा सकता है ? विज्ञान-कार्यक्रम के लिए जुटाये जा सकने वाले

साधनों के प्रश्न की और फलस्वरूप कराधान की सीमाओं के प्रश्न को प्रायः करदेय क्षमता (taxable capacity) की माप में प्रस्तुत किया जाता है। यह करदेय क्षमता (अ) सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था, (आ) जनसंख्या में विशेष वर्गों, और (इ) कभी-कभी विशेष कर-शीर्षकों के अन्तर्गत अधिकतम उपयोग के लिए होने वाले क्षेत्र के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अन्तिम पहलू पर वैयक्तिक करों के सन्दर्भ में विचार करना होगा, इसीलिए सम्बन्धित अध्यायों में उनका विवेचन किया गया है। दो और पहलुओं की संक्षेप में यहाँ चर्चा की गई है। अ्याय (equity) की तरह करदेय क्षमता की धारणा भी सापेक्ष ही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक अर्थ में, समाज के विभिन्न वर्गों की करदेय क्षमता, मोटे तौर से, कराधान के उस घस की छोटक होती है जिसके पर उत्पादक श्रम और कार्यकुशलता में समग्र रूप से ह्रास होने लगता है। आर्थिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से मर्यादित होती हैं और वे प्रायः जरूरी ही आ जाती हैं, विशेषतया उन समुदायों में जहाँ सबसे ज्यादा विस्तृत मताधिकार की दशा में लोकतांत्रिक आधार पर काम होता है। कुछ परिस्थितियों में इन दोनों सीमाओं पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से मर्यादा लग जाती है। इन दृष्टिकोणों का स्मरण करने की समस्या (Problem of enforcement) से सम्बन्ध होता है।

17. सम्पूर्ण कर-प्रणाली के प्रश्न पर विचार करते समय करों से प्राप्त कुल आय का राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में महत्व हो जाता है। भारत में करों से प्राप्त होने वाली आय राष्ट्रीय आय के सात के आठ प्रतिशत के बीच में ही है; और यह अनुपात कई अन्य देशों से जिनमें दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कुछ देश भी शामिल हैं, कम है। कुछ लोगो का यह सुझाव है कि यह उन विद्याल सम्भावनाओं की सूचक है जो करदेय क्षमता की सीमाओं के घटने से पूर्व अतिरिक्त कराधान के लिए विद्यमान होती है। लेकिन कुछ लोग उलटा निष्कर्ष इस तरह निबालते हैं कि करदेय क्षमता समाप्त हो चुकी है और अतिरिक्त कराधान के लिए कोई गुआइस नहीं रह गई है। यहाँ पर जो प्रश्न उठाये गये हैं वे केवल सैद्धान्तिक महत्व के ही नहीं हैं बल्कि व्यावहारिक पहलू भी रखते हैं, इसलिए इस देश में करों से प्राप्त आय का राष्ट्रीय आय के इतने नीचे प्रतिशत के रूप में होना एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता बनता है।

18. कुल कराधान राष्ट्रीय आय का बहुत नीचा अनुपात होना है — इसका एक मूलकारण लोगों का मामूली जीवन-स्तर है जो प्रति व्यक्ति नीची

आय में भयानकता है। इससे मनुष्य के अधिकांश व्यक्तियों के कराधान पर बड़ी सीमा लग जाती है। बजट कि उपभोग के सामु मितव्ययी स्तरों को नहीं गिराया जाता है। बड़े पैमाने पर व्ययव्यवस्था में एक ऐसे क्षेत्र के होने में जिसमें गुण का प्रयोग नहीं होता है, कराधान के प्रचलित रूपों के माध्यम से करों की आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राश्ट्रीय आय का सीधा अनुपात होता है जो अर्थव्यवस्था के उगी लक्षण का दूसरा पहलू होता है। यह बड़े पैमाने के ऐसे व्यापारिक क्षेत्र के व्यापार को सीमित कर देना है जिससे कराधान प्राप्त करना सुगम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी देश में अतिरिक्त कराधान के क्षेत्र के सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रत्यक्ष निष्कर्ष, जो अधिक विविध देशों के ऐसे ही अनुपातों से की जाने वाली तुलनाओं पर आधारित होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं।

19. लेकिन प्रश्न यह रह जाता है कि यह अनुपात करदेय क्षमता की सीमा के आगने का सूचक है अथवा इसमें वृद्धि की सम्भावना का। इससे हम सम्पूर्ण प्रणाली के सम्बन्ध में करदेय क्षमता के अध्ययन पर आवाते हैं। यदि कर इसलिए लगाये गये थे कि समाज उन कामों को सामूहिक रूप से करे जिनको पहले करदाता व्यक्तिगत रूप से करते थे और यदि करो और उसी बजट से सम्भव होने वाले लाभप्रद खर्च के बीच काफी अंतर तक मेल होता है तो करदेय क्षमता की सीमा अपेक्षाकृत ऊँची होगी। बहुधा यह देखा जाता है कि करो एव इनसे प्राप्त लाभों के बीच सम्बन्ध न तो प्रत्यक्ष होता है और न स्पष्ट होता है और प्राप्त लाभों को स्पष्टतया समझा भी नहीं जाता है। यदि ऐसे लाभ वास्तव में करो से प्राप्त होते हैं, अर्थात् यदि करो से प्राप्त आय वास्तव में सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक विकास में प्रयुक्त की जाती है और इस बात को स्पष्टतः समझा भी जाता है तो करदेय क्षमता अधिक होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि करदेय क्षमता की सीमा का उन उद्देश्यों से सम्बन्ध होता है जिन पर अतिरिक्त करो की आय खर्च की जाती है चूँकि ऐसी सीमा के निर्धारण में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक दृष्टिकोण भी मिले हुए होते हैं, इसलिए उस हद तक यह सीमा लोगों की उस समझ-बूझ पर भी निर्भर करती है जो उन्हें सरकार के द्वारा निमित्त विकास-योजनाओं के लिए होती है। प्रशासन की कुशलता एव सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता जो सार्वजनिक क्षेत्रों के अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग को सफल बनाते हैं और करो से प्राप्त आय के

वित्तियोग पर उत्तम प्रतिफल उपलब्ध कराते हैं, ये दोनों कम-से-कम इतना तो भावश्यक कर सकेंगे कि लोगों की कर-भार की वृद्धि को सहन करने की प्रविच्छा कम हो जाय।

20. प्रशासनिक कुशलता का दूसरा पहलू जिसका कराधान की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता है वह करो के दायित्वों को समान रूप से लागू करना है। जब लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि करों की व्यापक रूप से चोरी हो रही है तो उनका मनोबल कम हो जाता है, ईमानदार कर-दाता के द्वारा करों को चुकाने पर भारी दबाव पड़ता है और इससे निस्संदेह करदेय क्षमता की क्षति पहुँचती है। कुल मिलाकर यह कहना गलत न होगा कि कमजोर व असंयोजित नीतियों एवं अप्रभावपूर्ण शासन से करदेय क्षमता का ह्रास होता है और परोपकारी व कुशल प्रशासन । इसमें वृद्धि होती है। भारत में सार्वजनिक खर्च परोपकारी खर्च की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है लेकिन उसनी ही निश्चितता से हम यह नहीं कह सकते कि यह मिश्रणयिता एवं कार्यकुशलता की तरफ भी बढ़ रहा है। फिर भी भारतीय सार्वजनिक खर्च की सामाजिक व विकास-सेवाओं की तरफ बढ़ती हुई प्रवृत्ति करदेय क्षमता की सीमा को घागे बढ़ाने में मदद दे रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार के प्रति जो एकत्व और उत्तरदायित्व की भावना का उदय हुआ है वह भी उसी दिशा में क्रियाशील हो रहा है। अतः हमें इस बात का तो भरोसा है कि करदेय क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन तथ्य यह है कि करों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में युद्ध-पूर्व काल की तुलना में बिलकुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। इसके लिए वास्तव में कई कारण दिये जा सकते हैं। आगामी अध्यायों में वैयक्तिक करों का विवेचन करने समय हम इन पर सविस्तार चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर यह बतलाना उचित होगा कि इस मत का एक धारणात्मक पक्ष है कि भारतीय कराधान (Indian Taxation) अपने वर्तमान ढाँचे और दरों के आधार पर देश के करदेय साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाया है। जब इस पर प्रतिरिक्त साधनों की विशाल आवश्यक्ता के समर्थ में विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कराधान में थोड़ी वृद्धि करना न्यायोचित ही होगा।

21. कराधान और उधार (Taxation and Borrowing):—इस दृष्टिकोण पर हम बात को लेकर आपत्ति उठाई जा सकती है कि कराधान का उपयोग तो जानू-साने में बजट को संतुलित करने के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए और बजट के पूंजीपट भाग की पूर्ति पूर्वतया उधार से ही की

धाय में भगवता है। इनमें मधुराज के अधिपति व्यक्तियों के करधान पर बड़ीर भीमा लग जाती है। वगैरे कि उद्योग के बाधु मिश्रणी स्त्रों को नहीं दिया जाता है। बड़े पैमाने पर मर्यादस्था में एक ऐसे क्षेत्र के होने से जिनमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, करधान के प्रचलित रूपों के माध्यम से करों की आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय का भीमा अनुपात होता है जो मर्यादस्था के सभी सक्षण का दूसरा पक्ष होता है। यह बड़े पैमाने के ऐसे व्यापारिक क्षेत्र के दायरे को सीमित कर देता है जिनमें करधान प्राप्त करना मुश्किल होता है। इनमें यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी देश में अनिश्चित करधान के क्षेत्र के सम्बन्ध में रिये जाने वाले प्रत्यक्ष निष्कर्ष, जो अधिक विविध देशों के ऐसे ही अनुपातों से की जाने वाली तुलनाओं पर आधारित होने हैं, अनुपात होते हैं।

19. लेखन प्रदान यह रह जाता है कि यह अनुपात करदेय क्षमता की सीमा के आगने का सूचक है अथवा इसमें वृद्धि की सम्भावना का। इससे हम सम्पूर्ण प्रणाली के सम्बन्ध में करदेय क्षमता के अध्ययन पर आगते हैं। यदि कर इसलिए लगाये गये थे कि समाज उन कामों की सामूहिक रूप में करे जिनको पहले करदाता व्यक्तिगत रूप से करते थे और यदि करों और उनकी वजह से सम्भव होने वाले लाभप्रद खर्च के बीच काफी घटा तक मेल होता है तो करदेय क्षमता की सीमा अपेक्षाकृत ऊँची होगी। बहुधा यह देखा जाता है कि करों एवं इनसे प्राप्त लाभों के बीच सम्बन्ध न तो प्रत्यक्ष होता है और न स्पष्ट होता है और प्राप्त लाभों की स्पष्टतया समझ भी नहीं आता है। यदि ऐसे लाभ वास्तव में करों से प्राप्त होते हैं, अर्थात् यदि करों से प्राप्त आय वास्तव में सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक विकास में प्रयुक्त की जाती है और इस बात को स्पष्टतः समझा भी जाता है तो करदेय क्षमता अधिक होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि करदेय क्षमता की सीमा का उन उद्देश्यों से सम्बन्ध होता है जिन पर अतिरिक्त करों की आय खर्च की जाती है चूँकि ऐसी सीमा के निर्धारण में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक दृष्टिकोण भी मिले हुए होते हैं, इसलिए उस हद तक यह सीमा लोगों की उस समझ-बूझ पर भी निर्भर करती है जो उन्हें सरकार के द्वारा निर्मित विकास-योजनाओं के लिए होती है। प्रशासन की कुशलता एवं सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता जो सार्वजनिक कोषों के अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग को सफल बनाते हैं और करों से प्राप्त आय के

विनियोग पर उत्तम प्रतिफल उपलब्ध कराते हैं, ये दोनों कम-से-कम इतना तो भावश्यक कर सकेंगे कि लोगों की कर-भार की वृद्धि को सहन करने की प्रविच्छा कम हो जाय।

20. प्रशासनिक कुशलता का दूसरा पक्ष जिसका कराधान की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता है वह करों के दायित्वों को समान रूप से लागू करना है। जब लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि करों की व्यापक रूप से बोरी हो रही है तो उनका मनोबल कम हो जाता है, ईमानदार कर-दाता के द्वारा करों को चुकाने पर भारी दबाव पड़ता है और इससे निरसदेह करदेय क्षमता की क्षति पहुँचती है। कुल मिलाकर यह कहना गलत न होगा कि कमजोर व धनलोकप्रिय नीतियों एवं अप्रभावपूर्ण शासन से करदेय क्षमता का ह्रास होता है और परोपकारी व कुशल प्रशासन से इसमें वृद्धि होती है। भारत में सार्वजनिक खर्च परोपकारी खर्च की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है लेकिन उतनी ही निश्चितता से हम यह नहीं कह सकते कि यह मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता की तरफ भी बढ़ रहा है। फिर भी भारतीय सार्वजनिक खर्च की सामाजिक व विकास-क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई प्रवृत्ति करदेय क्षमता की सीमा को आगे बढ़ाने में मदद दे रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के प्रति जो एकरा और उत्तरदायित्व की भावना का उदय हुआ है वह भी इसी दिशा में क्रियाशील हो रहा है। अतः हमें इस बात का तो भरोसा है कि करदेय क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन सत्य यह है कि करों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में युद्ध-पूर्व काल की तुलना में किनकुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। इसके लिए वास्तव में कई कारण दिये जा सकते हैं। आगामी अध्यायों में वैयक्तिक करों का विवेचन करते समय हम इन पर सविस्तार चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर यह बतलाना उचित होगा कि इस मसला का एक धारणात्मक पक्ष है कि भारतीय कराधान (Indian Taxation) अपने वर्तमान ढांचे और दरों के आधार पर देश के करदेय साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाया है। जब इस पर अनिश्चित साधनों की विनाश आवश्यकता के सुन्दर्य में विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कराधान में थोड़ी वृद्धि करना न्यायोचित ही होगा।

21. कराधान और उधार (Taxation and Borrowing):—इस दृष्टिकोण पर हम बात को लेकर आपत्ति उत्पन्न न करनी है कि कराधान का उपयोग तो बालू खाने में बजट को संतुलित करने के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए और बजट के पूंजीगत भाग की पूर्ति पूँज्यता उधार से ही की



जानी चाहिए कि बजट-अतिरेक में (Budgetary Surplus)। उर्ध्वक  
संतर्हित बचन का समर्थन करना बर्तन है। चालू और पूर्वगत वर्ष ऐसी  
श्रेणियों में नहीं आते हैं जिनमें इस उद्देश्य के लिए वर्गान्त भाग में स्पष्टता  
घंतर दिया जा सके। वे अनिश्चय त्रिनके जरिए कराधान से पूर्वगत  
वर्ष की पूर्ति की जा सकती है और वे घाटे त्रिनके जरिए उधार  
से चालू वर्ष की पूर्ति की जा सकती है—ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में  
आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में निश्चित स्थान रखते हैं। सार्वजनिक भाग के  
अन्तर्गत विनियोग या निवेश में पूँजी लगाने के लिए बजट-अतिरेक का प्रयोग  
करना सैद्धान्तिक दृष्टि से गलत नहीं होगा। यही नहीं बल्कि दूसरे देशों का  
अनुभव तो निश्चित रूप से यह बतलाता है कि कुछ दशाओं में इसका उपयोग  
वित्त के एक सुगम साधन के रूप में दिया गया है। यदि युद्धोत्तर काल में कई  
देशों के पुनर्निर्माण एवं विवास-कार्यों में पूँजी लगाने के लिए चालू बजटों  
के अतिरेकों का उपयोग नहीं किया जाता, तो इस काल में उनकी अर्थ-  
व्यवस्थाओं में मित्र एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्रतियोगी उपयोग एवं  
विनियोग-भाग के फलस्वरूप गम्भीर विराम के विपरीत परिवर्तन आ जाते।  
एक विशाल विकास-कार्यक्रम में पूँजी लगाने की दृष्टि से उनके अनुभव का  
बड़ा महत्त्व है। इसने हमें यह बतलाया है कि ऐसे कार्यक्रम की मुद्रास्फीति-  
कारी सम्भावना को राजस्व खाते (Revenue Account) में ठीक ढंग का  
बजट-अतिरेक दिखाकर ही परिसीमित किया जा सकता है।

22. अब हम राजस्व और पूँजी खातों के घंतर के आधार पर विचार  
करेंगे। प्रचलित रूप में इसका आधार स्पष्ट नहीं है क्योंकि किसी भी दशा में  
पूँजी खाता वित्तीय दृष्टि से उन उत्पादक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं  
रहता है जिनके लिए ऋण-परिशोध (amortisation) की साधारण पद्धति एवं  
उधार पूँजी निस्संदेह उपयुक्त होते हैं। विराम-खर्च के जो कार्यक्रम पूँजी बजटों  
में दिखाये जाते हैं उनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं  
के विकास के लिए बिये जाने वाले खर्च का भी कुछ अनुपात होता है।  
उसमें शामिल किये जाने वाले विकास के कार्यक्रम भी यद्यपि उत्पादक  
कुशलता को बढ़ाने के इरादे से रखे जाते हैं और इसी वजह से वे काफी लाभप्रद  
भी होते हैं, लेकिन बड़े वित्तीय धर्म में वे सभी उत्पादक नहीं होते हैं। हमें  
इस बात में कोई संशय नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम के बच से हम एक घंटा के  
लिए कराधान का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

23. पूँजीगत खर्च की वित्तीय व्यवस्था के लिए कराधान के प्रयोग के विषय में हमारे समक्ष जो बयान दिये गये हैं उनमें बहुधा यह तर्क रखा गया है कि भावी पीढ़ियों को लाभ पहुँचाने के लिए विकास-कार्यक्रमों की सम्पूर्ण लागत को कराधान के जरिये वर्तमान पीढ़ी पर लादना न्यायोचित नहीं होगा। इस तर्क में यह पुराना भ्रम छिपा हुआ है कि विकास की शालू लागत का एक घंश भावी पीढ़ी पर तितकीया जा सकता है। विनियोग के एक विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में वास्तविक साधनों के रूप में, लागत की स्थिति पर सक्ते का कोई दास्ता नहीं है : इस कार्यक्रम में तो शालू उपयोग के लिए समाज की उपलब्ध होने वाले साधनों में से यही पर कटौती हो जाती है। अतः कराधान और उधार के सापेक्ष उपयोग की समस्या का सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य के बीच भार के वितरण की समस्या का प्रश्न नहीं है बल्कि वर्तमान समय में विनियोग-कार्यक्रम की लागत को पूरा करने की उपयुक्त विधि का प्रश्न है। इस प्रश्न से सम्बन्धित निर्णय केवल विनियोग-कार्यक्रम के द्वारा काले जाने वाले भार के उस वितरण को निर्धारित करता है जो समुदाय के धनवर होता है। लेकिन सम्पूर्ण समुदाय के लिए तो यह भार वास्तविक रूप में वर्तमान में ही वहन करना होता है।

24. हमारा यह सुभाव नहीं है कि सम्पूर्ण विकास-कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था क्यों से की जाय। अन्य दृष्टिकोणों के साथ-साथ मिश्रित धर्मव्यवस्था की दशाओं में ऐसा करना बहुत ही अवास्तविक माना जायगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि ऋणों (loans) का विकास-सम्बन्धी वित्त में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और योजना आयोग में पञ्चवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया है उनमें भी इस बात को स्वीकार किया है। यहाँ पर हम केवल यही मनसताना चाहेंगे कि अजट-अतिरेकों से विकास के एक घटा के लिए वित्त की व्यवस्था करना विकास सम्बन्धी वित्त का एक उचित रूप ही है, और इसमें समुदाय में शालू उपयोग पर उस स्थिति की अपेक्षा अधिक वास्तविक भार नहीं पड़ता है जबकि इसकी ही राशि सार्वजनिक ऋण से प्राप्त की जाती है।

25. घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) :—विकास कार्यक्रम में पूँजी लगाने की एक विधि घाटा उठाकर वित्तीय व्यवस्था करना भी है। घाटे की वित्त-व्यवस्था पर विचार करने समय यह ध्यान सामने आना है कि इसका उपयोग मुद्रा-नवीनीकरण के लिए बिना बंधों लगे हो सकता है, और इसीलिए यह अत्यन्त खतरा पैदा करने में युक्ति करने के एक निम्नरेख अग्रिम

विकल्प की टालने में जिस सीमा तक प्रयुक्त हो सकता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था की उचित मात्रा पर विचार करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि सामान्य आर्थिक दशा में मुद्रा-स्फीति के दबावों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के चिन्ह पहले से कहाँ तक विद्यमान हैं। यदि सामान्य रूप में मुद्रा-स्फीति के दबावों का अस्तित्व नहीं है और यदि कुछ अपस्फीतिकारी चिन्ह दिखाई देते हैं तो सुरक्षित रूप से की जा सकने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था की मात्रा उस स्थिति की तुलना में अधिक होगी जब कि प्रत्येक दिशा की तरफ से जाने वाले तत्वों में ज्यादा समान रूप से संतुलन पाया जाता है। यह मानना तो सही नहीं होगा कि सम्पूर्ण घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रा-स्फीति ही होगी क्योंकि हमें इसकी मात्रा अथवा उन परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई फार्मुला नहीं है जिसके द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था की ठीक मात्रा निर्धारित की जा सके; यह तो अन्ततः एक निर्णय का ही विषय है। जिस सीमा तक घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रा-स्फीति होती है उस सीमा तक इसको अपनाने में कुछ सतर्क होता है और हम इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक अध्याय VI में विचार कर चुके हैं। यहाँ हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि कर-प्रणाली को इस तरह से ढालना होगा कि यदि घाटे की वित्त-व्यवस्था से कभी गतरे उत्पन्न हों तो वह उनका मुकाबला कर सके। कर-प्रणाली को इस उद्देश्य के लिए जिस तरह से अनुकूल बनाया जाय—इस पर हम आगे चलकर इसी अध्याय में विचार करेंगे। लेकिन हम अपने इस मत को पुन दोहराना चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों और प्रचलित दशाओं की रीढ़ानी में घाटे की वित्त-व्यवस्था की एक नाभारण मात्रा अर्थव्यवस्था की शक्ति नहीं पहुँचायेगी।

26. विकास के लिए अर्थसाधन — उपर्युक्त विवेचन का सामर्थ्य विकास कार्यक्रम में पूँजी लगाने के कुछ वैकल्पिक साधनों से रहा है। हमने अभी तक नॉन-लाभ (non-lab) आय के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार नहीं किया है। हम इसका विवेचन अगले करेंगे। हमारे विवेचन में विदेशी पूँजी की कृति की सम्भावनाओं का भी उल्लेख नहीं आया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमारे पास आवश्यक तथ्य नहीं हैं और यह हमारे विचारणीय विषयों में भी नहीं है। इस विवेचन में दो और स्रोतों के सङ्ग्रह का उल्लेख नहीं किया गया है — एक तो करों की चोरी व करों के बचाने की रीढ़ानी और दूसरे स्रोत में विनिष्पत्ति व अविनिश्चितकरण करना। हमने इन विषयों पर कुछ विस्तार के अन्वय इसी रिपोर्ट में विचार दिया है।

27. 'बचत और विनियोग के लिए प्रेरणा प्रदान करने का दृष्टिकोण

(Approach to Incentives for savings and investment) :—हमने अभी तक कर-नीति की समस्याओं का ध्यान व धन की असमानताओं को कम करने के सम्बन्ध में विचार किया है। यह ध्यान और करदेय क्षमता की धारणाओं और करों की आय को शामिल करते हुए सार्वजनिक धाय में वृद्धि करके विधाय के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की दृष्टि से अनुकूल है। अब हम कर-प्रणाली के उन प्रभावों का उल्लेख करेंगे जो बचत व विनियोग के विधेय सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की प्रेरणाओं पर पड़ते हैं।

28. अब तक का हमारा विस्तरेण स्पष्टतया इस बात की आव-

श्यकता को बतलाता है कि भारतीय कर-प्रणाली का क्षेत्र अधिक गहन व व्यापक होना चाहिए। इसका आशय यह है कि प्रत्यक्ष व परोक्ष कराधान दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। वस्तु-कराधान की वृद्धि तो निश्चित रूप से उपभोग को प्रभावित करती है और प्रत्यक्ष करों के आरोहीपन की वृद्धि बचत व विनियोग को प्रभावित कर सकती है। जून निश्चित रूप से ऐसे कराधान के पक्ष में है जो भारत में, विशेषतया ऊँची आय वाले व्यक्तियों के, उपभोग के स्तरों को कम करेगा। इस देश में इस समय उपभोग के स्तरों में जो असमानता पाई जाती है वह सामाजी से देखी जा सकती है और हममें कोई संदेह नहीं कि इसका देश के विद्यालय धर्मिक-वर्ग पर, जहाँ तक उनकी अधिक कर-भार स्वीकार करने और फिर भी अधिक मेहनत से काम करने की इच्छा का प्रदन है, अनैतिक प्रभाव ही पड़ता है। ऊँचे कराधान से ऊँची आय वालों की काम करने की इच्छा पर जो प्रेरणा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको प्रायः बढ़ा-बढ़ा कर कहा जाता है। ऊँची आय वाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे मौद्रिक प्रतिपन की उन कमियों के अनुसार अपने आपको जहाँ से जो देश की अदमनी हुई सामाजिक व आर्थिक दशाओं में आवश्यक बन गई है। अब ऐसे समय में जब कि कर-प्रणाली नीची आय वालों से (जो देश के जन-समुदाय में माने जाते हैं) उनको छल्ले आय का बढ़ता हुआ हिस्सा देने के लिए करनी है, ऊँची आय वालों पर आय-कर के आरोहीपन के प्रेरणा के विपरीत जाने जाने प्रभावों पर और देना अवगच्छित माना जायगा। यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि वर्तमान समय की कर की अनेकाङ्ग ऊँची दरों पर भी लोहे के व्यक्तियों की और अनेक व्यक्तियों की गरीब के साक्ष्य आय (Disposable Income) में असमानता का प्रभाव पड़ता है यहाँ ऊँची आयदरों पर कराधान

की दरें वास्तव में नीची पाई जाती हैं। प्रति व्यक्ति भयवा प्रति परिवार राष्ट्रीय आय के एक उचित गुणन (Multiple) के आधार पर वैयक्तिक आयदणियों पर सीमा-निर्धारण के प्रश्न पर हमने काफी विचार किया और हमारा मत है कि कर के बाद अवशेष (Net) रहने वाली वैयक्तिक आयदणियों पर सीमा लगनी चाहिए जो सामान्यतया देश में पाई जाने वाली प्रति परिवार औसत आय के लगभग 30 गुने से अधिक न हो। हमारा मत कहना नहीं है कि यह तुरन्त ही लागू करने के लायक है बल्कि हम तो यह सोचते हैं कि इसको लागू करने के लिए एक अवधि तक धीरे-धीरे प्रयास करना होगा। कर-परिवर्तन से ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जायेगी बल्कि इसका सम्बन्ध तो कई दिशाओं में अपनाये जाने वाले एक एकीकृत दृष्टिकोण से है। इस दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होगा जिस आर्थिक विकास की गति तेज हो जायगी और रोजगार व उत्पादन के अवसर बढ़ जायेंगे। इसमें राजस्व नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन इस पर किसी भी दिये हुए समय में आर्थिक परिस्थितियों और प्राप्त कर की व्यावहारिक सम्भावनाओं का प्रभाव पड़ता है।

29. दृष्टिकोण इस अर्थ में वास्तविक होना चाहिए कि कर-प्रणाली पर इस सीमा तक दबाव नहीं डाला जाय कि देश की उत्पादन व्यवस्था अतरे में पड़ जाय अथवा निजी क्षेत्र में बचत और विनियोग को प्रभावित करके इसके विस्तार की सम्भावनाओं को ही नष्ट कर दे। इसीलिए हम आयकर प्रणाली में आवश्यक प्रेरणाओं का सुझाव देकर बचत और विनियोग में वृद्धि करने के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान आकषिप्त किया है। विशेषतः हमने औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए करों में रियायतें देने का सुझाव दिया है। उन भीमिष्ठ कोषों का अधिकतम उपयोग करने के लिए जो इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध किये जा सकते हैं, और इस आशा में कि उत्पादन को विनिष्कृत दिशाओं में रियायतों को केन्द्रित करके अधिकतम प्रयोजनकारी प्राप्ति किये जा सकें, हमने औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुझावित कर-सम्बन्धी रियायतों को लागू करने में चुनाव के सिद्धान्त (Selective Principle) को अपनाते की निश्चिन्ता की है। हमने वे उपाय भी सुझाये हैं जिनसे अपनाते में विनियोग के लिए उपलब्ध किये गये कोषों का उपयोग सम्भव इसी उद्देश्य के लिए उपयोग दिया जा सकेगा। हमारे प्रस्तावों में निवेश की बढ़ावा मिलेगा, चाहे वह निर्यात (Corporate) क्षेत्र में निवेश अथवा दीर्घ-निवेश क्षेत्र में और इनमें वैयक्तिक और स्वायत्तिक

(Proprietary) संस्थान शामिल होंगे। इन विषयों पर हमारी विस्तृत सिफारिशें इस रिपोर्ट के दूसरे खंड के सम्बन्धित अध्यायों में दी गई हैं।

30. हमारे विचारणीय विषयों के सन्दर्भ में कर-नीति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बातों पर सोच-विचार करने के बाद अब हम कर-नीति की एक-दो ऐसी विशेषताएँ लेंगे जिनकी चर्चा अनेक प्रतिनिधियों ने हमारे समक्ष की है।

31. प्रत्यक्ष व परोक्ष कर:—कर-प्रणाली के ढांचे पर विचार करते समय प्रायः एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष व परोक्ष करों का सापेक्ष स्थान क्या हो और यह विशेषताया उन संस्थाओं की ध्यान में रखते हुए जिनका इस अध्याय के प्रथम भाग में विवेचन किया गया है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि समय रूप से प्रत्यक्ष व परोक्ष करों के किसी विशेष अनुपात का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। यदि हम कर-प्रणाली से क्या साध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह काफी स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर की ऊँची दरें और करों का अधिक विस्तृत क्षेत्र दोनों समान रूप से आवश्यक हैं और साथ ही वृद्धि प्रत्यक्ष व परोक्ष करों पर फैली हुई होनी चाहिए। परिणाम के अन्दर प्रत्यक्ष व परोक्ष करों की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। मोटे तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर के अन्तर्गत प्रत्यक्ष कराधान ने (और आगे चल कर वृत्त-सम्पत्ति करों में) वृद्धि कर देने के बावजूद भी (जिसे अतिरिक्त साधनों की छान-बीन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए), परोक्ष कराधान पर भी निर्भर रहना होगा और इसके लिए प्रमुखतया वैश्वीय उत्पादन करों व राज्यीय बिजली करों में और विस्तार करना होगा। करों की आय को बढ़ाने की जितनी अधिक आवश्यकता होगी इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए परोक्ष करों के महत्व के बढ़ने की उम्मीद ही अधिक सम्भावना होगी। करेयर आय (non tax revenues) जिसमें राज्यीय व्यापारिक उपकरणों की आय भी शामिल है, कुछ मर्यादों में परोक्ष करों से मिलती-जुलती होती है और इसमें उसी तरह से वृद्धि भी की जा सकती है, हालाँकि इन क्षेत्र में वृद्धि करना सामान्य परोक्ष कराधान की स्थिति की तुलना में ज्यादा कठिन होता है।

32. कराधान में एकस्यता (Uniformity in taxation):—हमने बार बार एक बात पुछा कहा है जिसका सम्बन्ध राज्यीय क्षेत्र में (और कभी कभी स्थानीय क्षेत्र में भी) ढांचे वाले अनेक करों के सम्बन्ध में स्थापना

व दरों में एकत्रता लाने की वांछनीयता से रहा है। हम यहाँ इन प्रश्न के सम्बन्ध में अपना सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और इनका विस्तार सहित उत्तरेय नैयतिज्ञ करों के विवरण में दिया जायगा। हमारा ऐसा विचार है कि एकत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न इसकी ऐसी न्यूनतम सीमा की प्राप्ति करने तक ही सीमित रहे जाँव जो माघनों के सर्वोत्तम घाबंटन की बनाये रखने एवं व्यापारिक व व्यावसायिक जिया की अनर्धित दिशा में जाने से रोकने के लिए आवश्यक हों। लेकिन ऐसा करते समय वित्तीय मामलों में राज्यों की आवश्यक स्वायत्तता कम न होने पाये। यह स्वायत्तता उन जिम्मेदारियों से मेल खाती है जो संविधान के अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कुछ सीमा तक आर्थिक मामलों में उन पर छाती हैं। इस स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए कर-प्रणाली की नैमित्तिक सहायता (Adventitious aid) सेना उचित नहीं होगा।

33. करों से प्राप्त आय के उपयोग को निर्धारित कर देना (Earmarking of tax receipts) :—अब हम एक दूसरा सामान्य प्रश्न लेते हैं जो हमारे समक्ष अनेक प्रतिनिधियों ने उठाया है। इसका सम्बन्ध विभिन्न करों एवं उपकरों (cesses) से प्राप्त आय को विशेष उद्देश्यों के लिए निर्धारित करने के प्रीचिच से है। सारी व हाथ करपा उद्योगों के लाभ के लिए मिल के कपड़े पर लगाये गये उपकर की काफी आलोचना की गई है, विशेषतया मिल उद्योग के प्रतिनिधियों के द्वारा। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न उपकरों के अलावा करों से प्राप्त आय के उपयोग को निर्धारित करने के अन्य दृष्टान्त भी मिलते हैं जिनमें से कुछ काफी पुराने हैं, उदाहरणार्थ पेट्रोल पर आयात व उत्पादन कर से प्राप्त आय के एक अंश को केन्द्रीय सड़क कोष में ले जाना और इसी प्रकार बम्बई राज्य के द्वारा लगाये गये पेट्रोल के प्रतिरिक्त कर की आय को सड़क निर्माण व विकास की तरफ से जाना। ग्रामीण तेल उद्योग के लाभ के लिए मिल के तेल पर उपकर लगाने की सम्भावना का भी जिक्र किया गया है।

34. सर्वप्रथम, इस विषय के सन्दर्भ में 'उपकर' शब्द का प्रयोग बहुत कुछ निश्चित नहीं है। जैसे जो साधारणतया मिल में बने कपड़े पर उपकर माना जाता है और हमने भी जिसे उपकर ही कहा है वह इस कर को लागू करने वाले नियम में प्रतिरिक्त उत्पादन-कर ही माना जाता है। यह वर्णन ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि यह मोटे व मध्यम अंशों के कपड़े पर पहले के कर में काफी वृद्धि कर देता है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों के स्थानीय

क्षेत्रों में गन्ने के प्रवेश पर काफी ऊँची दरों से उपकर लगाया जाता है जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत उपकर कहलाता है जहाँ इस किस्म के शुल्कों (duties) को भारतीय संविधान में 'करों' के स्थान पर 'उपकर' कहा है।

35. वर्तमान विवेचन के उद्देश्य की दृष्टि ॥ हम उपकर का प्राशय उस कर से लेते हैं जो जिस वस्तु पर लगाया जाता है उसके मूल्य का बहुत ही छोटा भाग होता है और जिससे प्राप्त होने वाली आय ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनका सम्बन्ध मोटे तौर से उन्हीं करदाताओं अथवा उद्योग के हितों से अथवा सम्बन्धित वस्तु के उत्पादन या विपणन से होता है। जब विशिष्ट वस्तुओं अथवा उद्योगों पर लगाये गये ऐसे मामूली करों का उपयोग ऐसी खोज व जाँच को प्रोत्साहन देने के विशेष उद्देश्य से किया जाता है जो वाजारों, या कच्चा माल या उत्पादन की विधियों या सूचना के आदान-प्रदान आदि के विकास की तरफ ले जाने वाली होती है, तो उसे हम सम्बन्धित उद्योगों अथवा वस्तुओं के विकास के सामान्य हितों की दृष्टि से एक सहकारी क्रिया का रूप ही मानेंगे। यद्यपि ऐसे उपकरों की आय को संगठित करने और उसको व्यय करने में कुछ दोष बतलाये गये हैं, फिर भी हमारे समक्ष जो मत प्रगट किये गये उनमें किसी में भी इस व्यवस्था की लाभदायकता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। ऐसे उपकरों का प्रयोग करों से प्राप्त आय के उपयोग को निर्धारित करने के सामान्य प्रश्न से भिन्न धेनी में आता है और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस किस्म के उपकरों का उपयोग जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

36. जहाँ तक उपयोग निर्धारित करने के भिन्न एवं अपेक्षाकृत बड़े प्रश्न का सम्बन्ध है हमारे समक्ष जो मत प्रगट किये गये हैं उनमें सश्रम एकलपता भी और यह कि नियम के रूप में करों से प्राप्त आय विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। हमारा भी यह विचार है कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध की दृष्टि से यह उचित होगा कि करों की सम्पूर्ण आय को एक सामान्य कोष में एकत्र कर लिया जाय और इस राशि का सभी प्रकार के व्यय के लिए सामान्य कोष से विशिष्ट मंजूरी लेकर आवंटन किया जाय। प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि करों में और समान भाषा के सम्बन्धित उपयोगों में अनिश्चित समय तक टाल-मेल बना रहे। यदि कर से प्राप्त आय विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यकताओं से अधिक होती है तो फिजूलखर्ची एवं कोषों के दुरुपयोग को प्रोत्साहन



मिलना है, और दूसरी तरफ यदि कर से प्राप्ति मात्र ऐसी आवश्यकता के कम होती है, तो इन दोनों की पूर्ति सामान्य राजस्व से स्वीकृति लेकर करनी होगी। यह भावना महत्वपूर्ण राज्यों के लिए विशिष्ट माली सेने के नियम से काफी दूर जाने पर भी लागू होती है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा खादी एवं हाथ करपा उद्योगों के विकास में पूंजी लगाने के लिए कर्ज़ पर लगाये गये प्रतिरिक्त उत्पादन कर के सम्बन्ध में हम इस तरह के लगाने की आवश्यकता या क्षेत्र पर आपत्ति नहीं उठाते हैं और न हम खादी व हाथ करपा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के भाडन को गलत मानते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाने की प्रथा पर आपत्ति उठाई जा सकती है।

37. संभवतः इस पद्धति के गुण-दोषों को तब ठीक से समझा जा सकेगा जबकि हम उन परिस्थितियों का उत्तेज करें जिनमें हम यह सोचने हों कि विशिष्ट उपकरणों अथवा पूर्व-निर्धारित उपयोग वाले करों ( earmarked taxes ) के प्रयोग का लाभप्रद क्षेत्र विद्यमान है। एक तरह से स्थानीय संस्थाओं का समस्त अथवा अधिकांश कराधान विशिष्ट उद्देश्य वाले कराधान समीप ही होता है और ज्यों-ज्यों हम सरकारी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं त्यो-त्यो करों और लाभ के बीच का सम्बन्ध अधिक घुंघला होता जाता है। इससे ऐसे कराधान का स्पष्ट उद्देश्य सामने आ जाता है जो यह है कि लाभों का करों के साथ संबंध हो जाने से कर या शुल्क ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं और यह सम्बन्ध जितना प्रत्यक्ष होता है, ऐसे 'लाभ' वाले कराधान के प्रयोग का क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाता है। इस सिद्धांत का स्थानीय सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में भी लाभप्रद ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग के रूप में हम पुलों पर लगाये जाने वाले कर ( tolls on bridges ) को ले सकते हैं जिसकी राशि एक वैयक्तिक यात्रा पर तो थोड़ी होती है लेकिन जिसका प्रयोग कई देशों में खर्चीली परियोजनाओं की लागत को अल्पकाल में ही भुका देने के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। करों एवं उनसे प्राप्त धन के प्रयोग में होने वाले सम्बन्ध का मुख्य क्षेत्र उन दिशाओं में मालूम देता है जहाँ इस पद्धति में सम्बन्धित लाभ की वजह से कर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करदाताओं को कम भारस्वरूप प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत, ऊपर के एक उदाहरण में जहाँ मिल-वस्त्र पर लगाये गये प्रतिरिक्त शुल्क की आय का प्रयोग खादी व हाथकरपा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, प्राप्त धन के लाभ और कर के भार का संबंध प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट नहीं जान पड़ता है। बढ़ती हुई संख्या में उत्पादन-

धुल्को को लागू करने में संगठित व असंगठित उद्योगों में भेद किया जाना प्रारम्भ हो गया है। हमारे विचार से यह उन कारणों की वजह से उचित है जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड में उत्पादन करों के अध्याय में किया गया है। ऐसे विभेद के बावजूद (अथवा इसके अन्तर्गत) उद्योग के एक अंश पर आने वाले विशिष्ट भार का दूसरे अंश के लाभ से मेल बैठाना कोई अच्छी पद्धति नहीं प्रतीत होती है क्योंकि इससे सार्वजनिक वित्त के एकीकृत प्रशासन से ध्यान हट जाता है।

38. वह क्षेत्र जिसमें उपयोग को निर्धारित करने (earmarking) की प्रथा का दूसरे देशों में सम्भवतया सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वह मोटरगाड़ियों पर लगे हुए करों का उपयोग सड़क निर्माण व विकास पर करना है। एक ऐसे विकास कार्यक्रम की स्थिति में जो सड़कों सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ हो हम नहीं सोचते कि मोटर गाड़ियों अथवा मोटर स्प्रिंट पर लगे हुए करों से प्राप्त आय के उपयोग को निर्धारित करने की पद्धति सड़क विकास को तीव्र करने में कोई खास मदद कर सकेगी। विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ियों के उपयोग करने वालों से प्राप्त आय और सड़कों पर किये जाने वाले खर्च के बीच काफी अन्तर पाया जाता है। हम इस मत को नहीं मानते कि मोटरगाड़ी के प्रयोग करने वाले का सड़कों के खर्च के अतिरिक्त राज्य के सामान्य खर्चों में भ्रष्टादान देने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। यही नहीं बल्कि सड़क निर्माण के एक विस्तृत कार्यक्रम की स्थिति में यह सम्भव है कि सड़कों पर किया जाने वाला खर्च मोटर गाड़ी के प्रयोगकर्ता पर लगे हुए समस्त करों से प्राप्त आय से भी अधिक हो। लेकिन यहाँ पर यह बतलाया जा सकता है कि केन्द्रीय सड़क बोर्ड उपयोग निर्धारित करने के साधन से कुछ अधिक है। वास्तव में यह तो कर लगी हुई वस्तु के उपयोग के आधार पर राज्यों में केन्द्रीय धुल्क की आय के एक अंश को वितरित करने का साधन है। इसी प्रक्रिया में प्राप्त आय भी सम्बन्धित राज्यों में विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित कर दी जाती है। सच पूछा जाय तो इस साधन का उपयोग राज्य व स्थानीय सम्बन्धों के क्षेत्र में हो सकता है और हमें स्थानीय क्षेत्र में इसके विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं मानूँ देती है। लेकिन हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इसका आवश्यक मर्याद उपयोग निर्धारित करना नहीं है। वास्तव में यह तो स्थानीय संस्थाओं को साधनों में अपेक्षाकृत अधिक भाग देने का एक साधन है। यह सड़क विकास के कार्यक्रमों को हाथ में लेने के सम्बन्ध में उनको अपेक्षाकृत अधिक धारमदिरास दिलाता है।

मिमता है. घोर दुगरी तरफ यदि कर में प्रत्यक्ष आय होगी आवश्यकता में कम होगी है. सो इस कोषों की पुनः गायाम्य राखण है स्वीकृति से करनी होगी है । यह प्रारंभिक महत्वपूर्ण शर्तों के लिए निश्चित मंजूरी लेने के नियम से काफी दूर जाने पर भी लागू होगी है । केन्द्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एवं हाथ करवा उद्योगों के विभाग में पुँजी लगाने ■ लिए कपड़े पर लगाने गये प्रतिरिक्त उत्पादन कर के सम्बन्ध में हम इस कर के लगाने की आवश्यकता या क्षेत्र पर आपत्ति नहीं उठाते हैं और न हम राष्ट्रीय व हाथ करवा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोषों के आरंभ को मनात मानते हैं । लेकिन इन दोनों को मिलाने की प्रथा पर आपत्ति उठाई जा सकती है ।

37. सम्भवतः इस पद्धति के गुण-दोषों को तब ठीक से समझा जा सकेगा जबकि हम उन परिस्थितियों का अन्वेषण करें जिनमें हम यह सोचते हैं कि विशिष्ट उपकरणों अथवा पूर्व-निर्धारित उपयोग वाले करों ( earmarked taxes ) के प्रयोग का लाभप्रद क्षेत्र विद्यमान है । एक तरह से स्थानीय संस्थाओं का समस्त अथवा अधिकांश कराधान विशिष्ट उद्देश्य वाले कराधान के समीप ही होता है और ज्यों-ज्यों हम सरकारी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों करों और लाभ के बीच का सम्बन्ध अधिक घुँघला होता जाता है । इससे ऐसे कराधान का स्पष्ट उद्देश्य सामने आ जाता है जो यह है कि लाभों का करो के साथ संबंध हो जाने से कर या शुल्क ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं और यह सम्बन्ध जितना प्रत्यक्ष होता है, ऐसे 'लाभ' वाले कराधान के प्रयोग का क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाता है । इस सिद्धांत का स्थानीय सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में भी लाभप्रद ढंग से प्रयोग किया जा सकता है । इसके प्रयोग के रूप में हम पुलों पर लगाये जाने वाले कर ( tolls on bridges ) को ले सकते हैं जिसकी राशि एक वैयक्तिक मात्रा पर तो थोड़ी होती है लेकिन जिसका प्रयोग कई देशों में सखीली परिवहनार्थों की लागत को घटपकाल में ही चुका देने के लिए सफलतापूर्वक किया गया है । करो एवं उनसे प्राप्त आय के प्रयोग में होने वाले सम्बन्ध का मुख्य क्षेत्र उन दिशाओं में मानलूम देता है जहाँ इस पद्धति में सम्बन्धित लाभ की बजह से कर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करदाताओं को कम भारस्वरूप प्रतीत होते हैं । इसके विपरीत, ऊपर के एक उदाहरण में जहाँ मिल-वस्त्र पर लगाये गये प्रतिरिक्त शुल्क की आय का प्रयोग खादी व हाथकरवा उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए किया गया है, प्राप्त आय के लाभ और कर के भार का संबंध अथवा स्पष्ट नहीं जान पड़ता है । बढ़ती हुई संख्या में उत्पादन-

शुल्कों की लागू करने में समगठित व असंगठित उद्योगों में भेद किया जाना प्रारम्भ हो गया है। हमारे विचार से यह उन कारणों की वजह से उचित है जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड में उत्पादन करों के अध्याय में किया गया है। ऐसे विभेद के नावजूद (अथवा इसके अन्तर्गत) उद्योग के एक अंश पर आने वाले विशिष्ट भार का दूसरे अंश के लाभ से मेल बैठाना कोई अच्छी पद्धति नहीं प्रतीत होती है क्योंकि इससे सार्वजनिक वित्त के एकीकृत प्रशासन से ध्यान हट जाता है।

38. वह क्षेत्र जिसमें उपयोग को निर्धारित करने (earmarking) की प्रथा का दूसरे देशों में सम्भवतया सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वह मोटरगाड़ियों पर लगे हुए करों का उपयोग सड़क निर्माण व विकास पर करना है। एक ऐसे विकास कार्यक्रम की स्थिति में जो सड़कों सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ हो हम नहीं सोचते कि मोटर गाड़ियों अथवा मोटर स्प्रिट पर लगे हुए करों से प्राप्त आय के उपयोग को निर्धारित करने की पद्धति सड़क विकास को तीव्र करने में कोई खास मदद कर सकेगी। विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ियों के उपयोग करने वालों ■ प्राप्त आय और सड़कों पर किये जाने वाले खर्च के बीच काफी अन्तर पाया जाता है। हम इस बात को नहीं मानते कि मोटरगाड़ी के प्रयोग करने वाले का सड़कों के खर्च के अतिरिक्त राज्य के सामान्य खर्चों में अंशदान देने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। यही नहीं बल्कि सड़क निर्माण के एक विस्तृत कार्यक्रम की स्थिति में यह सम्भव है कि सड़कों पर किया जाने वाला खर्च मोटर गाड़ी के प्रयोगकर्ता पर लगे हुए समस्त करों से प्राप्त आय से भी अधिक हो। लेकिन यहाँ पर यह बतलाया जा सकता है कि केन्द्रीय सड़क बोर्ड उपयोग निर्धारित करने के साधन से कुछ अधिक है। वास्तव में यह तो कर लगी हुई वस्तु के उपयोग के आधार पर राज्यों में केन्द्रीय शुल्क की आय के एक अंश को वितरित करने का साधन है। इसी प्रक्रिया में प्राप्त आय भी सम्बन्धित राज्यों में विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित कर दी जाती है। सब पूछा जाय तो इस साधन का उपयोग राज्य व स्थानीय सम्बन्धों के क्षेत्र में हो सकता है और हमें स्थानीय क्षेत्र में इसके विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं मायूम देती है। लेकिन हम हम बात पर जोर देना चाहेंगे कि इसका आवश्यक सशर्त उपयोग निर्धारित करना नहीं है। वास्तव में यह तो स्थानीय सत्स्थाओं को साधनों में अपेक्षाकृत अधिक भाग देने का एक साधन है। यह सड़क विकास के कार्यक्रमों को हाथ में लेने के सम्बन्ध में उनको अपेक्षाकृत अधिक भारविवश्यास दिनाता है।

39. मुद्रा-स्फीतिकारी व अस्फीतिकारी दशाओं के सम्बन्ध में कर-नीति (Tax policy in relation to inflationary and deflationary situations) :— हमारे विचारणीय विषयों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम कराधान के प्रयोग की भाँति मुद्रास्फीतिकारी अथवा अस्फीतिकारी दशाओं का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतीय साधन के रूप में करें। एक तरह से यह विचारणीय विषय हमारे समक्ष एक कालान्तरिक प्रश्न उपस्थित कर देगा है और हमें कर प्रणाली में ऐसे परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कहता है जो आर्थिक स्थिति के स्पष्टतया स्फीतिकारी या अस्फीतिकारी मोड़ लेने पर उपयुक्त होते हैं।

40. इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने यह बतलाया है कि कर-नीति में आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने के उद्देश्य का बड़ा महत्त्व होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में मोटे तौर से दो तरीकों से मदद मिल सकती है। एक तरीका तो यह है कि ऐसा कर का ढाँचा बनाया जाय जो आर्थिक उतार-चढ़ावों को उनके उत्पन्न होने पर स्वतः ही दूर कर दे; द्वितीय, स्फीतिकारी और अपस्फीतिकारी दशाओं का मुकाबला करने के लिए कर-प्रणाली में परिवर्तन किये जाय। पहले तरीके में आर्थिक उतार-चढ़ाव से मुकाबला करने के लिए कर प्रणाली की स्वचालित क्षमता आरोही प्रत्यक्ष करों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता उत्पन्न करके बढ़ाई जा सकती है। ऐसे करों की आय में मौद्रिक एवं कीमतों के परिवर्तनों के फलस्वरूप कर के आधार (tax base) में होने वाले परिवर्तनों से ज्यादा अनुपात में परिवर्तन होता है। मूलानुसार होने वाले वस्तु-करों के अधिक उपयोग से भी इसी तरह की मदद मिलती है, क्योंकि कीमतों के परिवर्तनों से करो से प्राप्त आय में परिवर्तन उत्पन्न होता है। लेकिन किसी भी समय में कर-प्रणाली का निर्माण सुदृढ़ कर-नीति के समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रख कर करना होता है और इसमें प्रशासनिक कार्यक्षमता एवं सुविधा की आवश्यकताएँ भी शामिल होती हैं। प्रशासनिक कार्यों से ऐसे विशिष्ट शुल्कों (specific duties) को प्राथमिकता देनी पड़ती है जिनसे प्राप्त आय में आर्थिक दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए जिस सीमा तक कर प्रणाली की स्वचालित क्षमता में मुद्रास्फीति व अपस्फीति को दूर करने के लिए सुधार किया जा सकता है उस पर अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः समस्या इस प्रकार है कि कर प्रणाली के सामान्य ढाँचे के दिये हुए होने पर हमें उस समय कौन से सुधार किया जाय जब कि उल्लेखनीय स्फीतिकारी अथवा अपस्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ?

41. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भारत में स्फीतिकारी व अपस्फीतिकारी प्रवृत्तियों के वास्तविक इतिहास के संक्षिप्त विश्लेषण से प्रारम्भ करना लाभप्रद होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले लगभग तीस वर्षों में प्रमुख स्फीतिकारी व अपस्फीतिकारी प्रवृत्तियों की जांच से पता लगता है कि सामान्य आर्थिक स्थिति में आने वाले मोड़ों का प्रमुख स्रोत सदैव बाह्य ही रहा है। उदाहरणार्थ, 1924-25 में कृषिगत पदार्थों के मूल्यों का चरम सीमा को छूने के बाद 1920 से प्रारम्भ होने वाली दसाब्दी के मध्य में घोर अन्तिम भाग में गिरना; 1929 के अंत में कीमतों का गिरना और 1930 से प्रारम्भ होने वाले कुछ के वर्षों में तीव्र मंदी का आना; और उसके बाद 1933 से 1937 तक भावों में धीमे धीमे वृद्धि होना, 1938 में एक अल्पकालीन व तीव्र गिरावट का आना; युद्ध-कालीन चढ़ाव और पुनः युद्धोत्तर काल की तेजी; 1949 में भुगतान संतुलन में संकट, कोरिया की तेजी और धीरे धीरे सामान्य स्थिति का आना—इन सबका उद्गम किसी-न-किसी अन्तर्राष्ट्रीय कारण को लेकर ही हुआ था। लेकिन बाह्य प्रभाव आन्तरिक आर्थिक प्रवृत्तियों पर छा गये जिससे कीमतों में असमानताएँ उत्पन्न हो गईं और इसी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति में समय-समय पर बिचिन्नताएँ पाई गई हैं।

42. महान मंदी जिसमें कीमती अधिकांश धन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक गिरी (हालांकि थोड़ी देर से गिरी), ने प्राथमिक उत्पादन का एक उल्लेखनीय लक्षण स्पष्ट कर दिया जो यह है कि इस तरह के उत्पादन में कीमतों के परिवर्तन के कमस्वरूप पूर्ति की सोच विपरीत पाई जाती है। इपि का उत्पादन न केवल गिरा नहीं बल्कि कीमतों के न्यूनतम स्तर पर आते ही कुछ बढ़ा। गिरती हुई कीमतों की स्थिति में और बिजी-योग्य बचत से प्राप्त आय एवं जीवन-निर्वाह (subsistence) व सागर के बीच घटते हुए अंतर की दशा में कृषक ने मूल्य (value) के रूप में जो कुछ खो दिया था उसकी पूर्ति उसने मात्रा के रूप में करने की कोशिश की। यह दशा लघुभग विद्वग्भाषी थी। इस स्थिति का उल्टा, यर्थात् कीमतों के ऊंचे बिन्दु को पार करते समय प्रयत्न व उद्यम में होने वाली कुछ वृद्धि भी युद्धोत्तरकाल के प्रारम्भ में अल्पविकसित देशों में बड़े पैमाने पर देखने की मिली है। उत्पादन से सम्बन्धित प्राविधिक तत्वों के अभाव का कार्य की पूर्ति में एक किस्म की लोचहीनता भी होती है जो इपक के जीवन-स्तर से निर्धारित होती है। इसी की वजह से सीमान्त भूमि का दुबड़ा अङ्कित पड़ा रह जाता है क्योंकि उपर के अत्यधिक ऊंचे भाव हो जाने पर थोड़ा कम उत्पादन भी जीवन-स्तर को बनाये रखने के

निष्पत्ती रहता है। हमने यह जाहिर होता है कि, सामान्य धारणा के प्रतिरूप, ऊँची कीमतों के स्थान पर गिरा कीमतों ही उद्योग के गुप्त एवं कृपिण उत्पादन की सुसंगतता के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करती है। सामान्य धारणा, जिसमें ऊँचे उत्पादन का सम्बन्ध ऊँची कीमतों से किया जाता है, गैर-कृपिण क्षेत्र के अनुभव के अभाव में हमारे से उत्पन्न होती है कि अलग-अलग पदार्थों के उत्पादन व भावों की गति में सह-सम्बन्ध पाया जाता है। इसमें भ्रम यह है कि अलग-अलग वस्तुओं का अनुभव सम्पूर्ण कृपिण उत्पादन और कीमतों पर लागू कर दिया गया है। लेकिन हमका आशय यह नहीं है कि कृपिण कीमतों की गिरावट कृपक के लिए अच्छी रहती है। इसके विपरीत जब कीमतों में गिरावट होती है तो यह गिरावट कृपिण पदार्थों में अपेक्षाकृत अधिक होती है; इससे अच्छी व अचूकता के सम्बन्धों में गम्भीर व विपरीत परिवर्तन आ जाते हैं और कृपस्वरूप पुनर्समा-योजन (readjustment) की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इससे कृपक के लिए गैर-कृपक के मुकाबले व्यापार की आन्तरिक शक्तें भी बिगड़ जाती हैं, अर्थात् सरल शब्दों में, कृपक की प्रय-शक्ति में गिरावट आ जाती है। भारत में मंदी व मुद्रा-स्फीति दोनों का अनुभव इसी निष्कर्ष की तरफ से जाता है कि कृपक के लिए ऊँचे मूल्यों की नहीं बल्कि स्थिर मूल्यों की आवश्यकता है और विशेषतया गैर-कृपि पदार्थों के मूल्यों से कुछ कुछ साम्य की आवश्यकता भी है।

43. हम यहां पर इस समस्या की सम्भावित प्रकृति एवं क्षेत्र का उल्लेख कर सकते हैं जिनके सम्बन्ध में कर-प्रणाली में किये जाने वाले परिवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए। निकट भविष्य के बारे में विश्वास के साथ कोई भी भविष्यवाणी करना कठिन है। यह विशेषतया बाहरी तत्वों के सम्बन्ध में सही है। लेकिन यह धारणा की जा सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर बड़ी या छोटी हलचलों के अभाव में भूतकाल में सरकारों व प्रशासनों को जो अनुभव आर्थिक उतार-चढ़ावों को दूर करने में हुआ है वह भविष्य में आ सकनेवाली स्थिरता से दूर जाने से उत्पन्न तीव्रता को कम करने में मदद करेगा। जहां तक देश में अस्थिरता के तत्वों का है, अधिक तीव्र सम्भावनाएँ मुद्रा-स्फीति की शक्तियों के जारी रहने की होती हैं जो विनाश आयोजन की गति से उत्पन्न होती हैं और इसी से भी होती हैं। ये शक्तियाँ विकास आयोजन की वित्तीय व्यवस्था के साधनों पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन योजना की अवधि में वास्तव में

होनेवाली घाटे की वित्त-व्यवस्था की मात्रा प्रारम्भिक अनुमानों से कम रही है। विनियोग की मात्रा में तीव्र वृद्धि के होने पर यदि कुछ समय तक सार्वजनिक विनियोग में होने वाली वृद्धि मध्य से कम भी होती रहती है तो भी आन्तरिक समस्या मुद्रा अपस्फीति के बजाय मुद्रा-स्फीति की हो होगी। लेकिन समय-समय पर वास्तविक आर्थिक स्थिति आन्तरिक व बाहरी तत्वों की अन्तर्क्रिया से निर्धारित होगी। जिस सीमा तक अर्थ-व्यवस्था में एक बड़ा गैर-मुद्रा का क्षेत्र (non-monetary sector) होता है, मूल्य-परिवर्तन उन्नत और पूर्ण मुद्राधारित अर्थ-व्यवस्थाओं (completely monetised economies) के जैसा प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन भारत में मुद्राविहीन क्षेत्र का संकुचन हो रहा है। इसका होने पर भी मौद्रिक क्षेत्र इतना विस्तृत है कि यह बढ़ती हुई कीमतों की अवधि में मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति की आवश्यकता के महत्त्व व सीधता को स्पष्ट कर देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में कर-व्यवस्था को भी अपना भाग बढ़ा करना होता है। अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि भारतीय कर-प्रणाली मुद्रा-स्फीतिकारी एवं मुद्रा अपस्फीतिकारी दशाओं का मुकाबला कहा तक कर सकती है।

44. एक अधिक सामान्य विधि जिसके द्वारा कर-प्रणाली स्फीतिकारी अथवा अपस्फीतिकारी दशा के प्रभावों को कम कर सकती है वह निजी व्यय के लिए उपलब्ध होने वाली राष्ट्रीय आय की मात्रा में कमी या वृद्धि करना है। इसके लिए क्रमशः घबराहट का बजट या घाटे का बजट बनाने की नीति अपनानी पड़ती है।

45. जहाँ तक स्फीतिकारी हलचल बाहरी प्रभावों से उत्पन्न होती है निर्णय-कर एक ऐसा सुपरिचित तरीका है जिसके द्वारा हमारी वस्तुओं के लिए तीव्र विदेशी मांग को धरेलू अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी प्रभाव डालने से रोका जा सकता है। जब बाहरी प्रभावों में देश के अन्दर कीमतें गिरती हैं तो कर-प्रणाली में परिवर्तन करके भी इन गिरावट को रोकना कठिन हो जाता है। निर्णय-करों को समाप्त करके और आन्तरिक वस्तु-व्यापान (Commodity taxation) में काफी कमी करके विदेशी मांग की गिरावट को रोका जा सकता है और धरेलू मांग को बनाये रखा जा सकता है और इस प्रकार उत्पादकों की आय में होने वाली गिरावट को कम किया जा सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तु-व्यापान का प्रश्न है, राज्यों के द्वारा पाटा उठाने की असमर्थता के कारण स्थिति जटिल हो जाती है। ऐसा केवल उस समय नहीं होता है जब कि केन्द्रीय सरकार विदेशीय से राज्यों को कर में कमी



करने देने के लिए ऋण व अनुदान (loans and grants) का एक व्यवस्थित कार्यक्रम लागू करती है।

46. राजकोषीय दृष्टि से समुन्नत देशों में भी जहाँ करों से प्राप्त आय उनकी राष्ट्रीय आय का काफी बड़ा अंश होती है, मंदी को दूर करने के उपाय के रूप में करों को घटाने के बजाय सार्वजनिक व्यय के विस्तार पर ज्यादा बल दिया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ करों के रूप में लिया गया राष्ट्रीय आय का अंश 7 या 8 प्रतिशत होता है (जब कि कई अन्य देशों में यह 25 से 40 प्रतिशत तक होता है), मुद्रा-अपस्फीति के प्रभावों को दूर करने में आय-प्रभाव के रूप में कर-प्रणाली बहुत कम काम कर पाती है। जो कुछ घाटे की वित्त-व्यवस्था की सहायता से किये गये सार्वजनिक खर्च के रूप में किया जाता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की ढाँचे की जटिलताओं (structural rigidities) एवं अन्य विशेषताओं के कारण सीमित महत्व का हो जाता है। इतने पर भी भारत में अपस्फीतिकारी दशा के प्रभावों को मिटाने के लिए कराधान की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय की दशा में ज्यादा प्रभावपूर्ण काम किया जा सकता है।

47. मुद्रास्फीति के दिनों में कराधान स्फीति के विपरीत प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भाग ले सकता है। यह केवल इसीलिए सच नहीं है कि इस सम्बन्ध में कर-प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती है बल्कि इसलिए भी है कि ऐसी अवधियों में खर्च में कमी करना ज्यादा कठिन होता है, चाहे जबकि मुद्र की हो जिसमें मौनिक व्यय सामने रहता है, अथवा यह तीव्र प्राथमिक विभाग की हो जिसकी गति बनाये रखनी पड़ती है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी अनुभव से यह पाया गया है कि यदि कर-प्रणाली में उचित परिवर्तन किया जाता है तो वह मुद्रास्फीति की गति को कम करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, हमारे ही देश में कर प्रणाली मुद्रास्फीति एवं इसके मुद्रोन्नत प्रभाव से उत्पन्न आय की कृत्रिम बढ़ी को निरी खर्च से दूर करने में सफल रही है। यह अंशन केन्द्रीय कर प्रणाली की ओष के कारण हुआ है क्योंकि हममें आवश्यक शामिल रहा है और अतः एक नये प्रस्ताव कर—अतिरिक्त मान कर—और लागू की जा सकती है। यह उपाय दुष्प्रभावों के भय से हुआ है। मुद्रास्फीति में प्रणाली केन्द्रित करों की अंश के 65 प्रतिशत तक पहुँच गये थे।

48. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कर जो प्रत्यक्षतः ऊँची अनिश्चित आय पर पड़ते हैं और वे वस्तु-कर जो मुद्रा-स्फीति से उत्पन्न सामान्य क्रय-शक्ति में होने वाली वृद्धि पर पड़ते हैं, वे मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब कर-प्रणाली का स्वाभाविक सोच और करों की अपेक्षाकृत ऊँची दरें दोनों मिलकर भी मुद्रास्फीति की गति को रोकने में असमर्थ रहती हैं तो ऐसी अवधि में विशेष मुद्रास्फीति-विरोधी करों जैसे अनिश्चित लाभ कर और सामान्य व विलासी उपभोग दोनों की वस्तुओं पर वस्तु करों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति एक निश्चित सीमा से आगे निकल आती है तो कराधान प्राधिकार भी प्रस्तुत नहीं कर पाता है। साथमें बढ़ती हुई आय का पीछा करती हैं और सार्वजनिक व्यय अधिकाधिक सार्वजनिक आय से आगे रहने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावपूर्ण इलाज यही है कि या तो सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि को रोक दिया जाय और उसमें तीव्र कमी लाई जाय, अथवा एक तीव्र मौद्रिक मार्जन (Monetary Purge) किया जाय जिसमें मुद्रा की पूर्ति अथवा तरल परिसम्पत्तियों पर पूँजी-कर लागू कर दिया जाय; कभी-कभी इन दोनों की एक साथ भी आवश्यकता हो सकती है।

49. भारतीय कर-प्रणाली पहले ही अपने पास आय-कर व वस्तु-कर के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण साधन रखती है जिनका प्रयोग स्फीतिकारी दशाओं का मुकाबला करने में किया जा सकता है। आपकर एक अत्यधिक घरोही कर है। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, तबो या मुद्रास्फीति की दशाओं में यह अपने आप अधिक आय उत्पन्न करता है और कर के पश्चात् सर्प के लाभक आय की वृद्धि को सीमित करता है। इस कर के इस अन्तर्निहित मुद्रास्फीति विरोधी अक्षण के बावजूद यह मानना होगा कि जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो इस कर की दरों में वृद्धि करके आय-दैनियों में और भी कमी करने में इसकी उपयोगिता सीमित होती है, विशेषतया उस स्थिति में जब कि इसकी दरें अगमाम्य रूप से ऊँची कर दी जाती हैं। लेकिन तीव्र स्फीतिकारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कराधान की ओर कसरने की सम्भावनाएँ अवश्य रहती हैं। इसी प्रकार वस्तु-करों के प्रयोग का क्षेत्र बढ़ा कर एवं उनकी दरों में वृद्धि करके उपभोग-भाग को नियन्त्रित करने में मदद मिलती है। विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में विनिर्मित करों को लागू करना आवश्यक हो सकता है जो विकास-सर्प के स्फीतिकारी भूभाव से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। उपर्युक्त उपाय और साथ में विनिर्मित करों, जैसे

प्रतिरिक्त लाभ कर, के ग्राह्य करने की सम्भावना कर के क्षेत्र में समय-समय पर उत्पन्न हो गइने वाली साधारण स्वीकार्यी दशाओं का मुकाबला करने में बहुत बर्बाद मिट होगी है।

50. मंदी के उत्पन्न होने की अप्रत्याशित स्थिति में कराधान की बर्बाद से विशेष अग्रर नहीं गइना है क्योंकि इसकी वजह से निजी सच के लिए जो आय मुक्त हो जायगी वह राष्ट्रीय आय का एक बहुत छोटा घट होगी; ऐसी स्थिति में राजकोपीय दृष्टि में इनाज यह होगा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाय और इसकी वित्तीय व्यवस्था घाटे के द्वारा उन समय तक की जाय जब तक कि अर्थ-व्यवस्था में पुनः सुधार न हो जाय और कीर्तन व बिक्री मंदी ने पूर्व की प्रवृत्तियाँ प्राप्त न कर लें।

51. दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखने पर अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता बनाये रखने का उद्देश्य आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य में विलीन हो जाता है। अतः प्रश्न इस बात का है कि राजकोपीय व अन्य नीतियों को विकास का मार्ग सरल बनाये रखने की दृष्टि से बनाया जाय, और सार्वजनिक व्यय की गति व वस्तु-सामग्री को, कराधान के स्तर व रूपों को एवं बजट-सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थिति—बचत व घाटे—की आर्थिक दशा के परिवर्तनों के संदर्भ में व्यवस्थित किया जाय। लेकिन यह आवश्यक है कि राजकोपीय नीति के समस्त तत्त्व मूलतः आर्थिक विकास के अनुकूल ही हों।

52. करों से प्रतिरिक्त आय प्राप्त करने के स्रोत (Sources of additional tax revenue):—इस अध्याय में पहले हम मोटे तौर से कर नीति के ढांचे की वह रूपरेखा दे चुके हैं जो हमारे मतानुसार सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में पूँजी-निर्माण व अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने का जटिल कार्य यथा-सम्भव पूरा कर सकती है। उस विवेचन से उन मुख्य दिशाओं की जानकारी हो जाती है जिन पर बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के प्रतिरिक्त साधन प्राप्त किये जा सकते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में ये इस प्रकार हैं : आयकर में वृद्धि जो निगम कर की कुछ कमी से आंशिक रूप से मिट जाती है एवं साथ में बचत व विनियोग के लिए कुछ प्रतिरिक्त छूटें और विलासिताओं, घट-विलासिताओं एवं अनिवार्यताओं पर भी उत्पादन-करों में काफी वृद्धि और ऐसी मूल्य-नीतियों को अपना कर करेतर आय में कुछ वृद्धि करना जिनमें राजस्व को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिरिक्त साधनों की

दिशाएँ इस प्रकार हैं :—भू-राजस्व पर साधारण सरचार्ज लगाकर भाय में कुछ वृद्धि करना—इन सरचार्जों में उस भवधि के अनुसार परिवर्तन करना जब कि पिछले बन्दोबस्त किये गये थे ताकि एक राज्य में एक सामान्य समय-स्तर (Time-standard) के अनुसार एकरूपता आ जाय—कृषि भायकर के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि करना एवं इसकी दरों को बढ़ाना, जायदाद कराधान (Property taxation) एवं स्थानीय सस्वाधो के द्वारा जायदाद के अन्तरण पर करों का अधिक व्यापक प्रयोग करना, और बिजली कर के क्षेत्र को विस्तृत करना एवं धाये बलकर इसकी दरों में वृद्धि करना। राज्तीय क्षेत्र में अन्य छोटे करों के सम्बन्ध में भी हमने उन राज्यों को जो अब तक मुख्यतया कराधान के पुराने रूपों पर निर्भर रहते धाये हैं अपेक्षाकृत कुछ नये करों को अधिक व्यापक रूप से अपनाने की सिफारिश की है। पहले दो अध्यायों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रमुख राजकीय उपक्रमों जैसे सिंचाई व बिजली आदि से भी भाय बढ़ाने का कुछ क्षेत्र है।

53. हमारे विचारणीय विषयों में हमे विद्येपतया कराधान के नये स्रोतों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए कहा गया है। हमने ऊपर भाय की वृद्धि की जिन सम्भावनाओं की चर्चा की है उनका प्रचलित कर-स्रोतों से ही सम्बन्ध है। कराधान की एक महत्वपूर्ण एवं गई दिशा की कल्पना एक ऐसे नये कर के रूप में कर सकता बटिन प्रतीत होता है जो सविधान की सातवीं अनुसूची (Schedule) के अन्तर्गत होने वाली किसी भी सूची में शामिल नहीं है। वास्तव में हमने केन्द्रीय या राज्तीय सूचियों की ऐसी सभी मदों पर विचार किया है जिनका अभी तक अपेक्षाकृत कम उपयोग किया गया है लेकिन भविष्य में अधिक उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अपेक्षाकृत अधिक उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक सुभाव इस रिपोर्ट के विभिन्न स्थलों पर दिये जा चुके हैं। अब हम कराधान के नये रूपों से सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों की चर्चा करेंगे जिन पर हमने विचार किया है लेकिन जिनको लागू करने की हम सिफारिश नहीं करेंगे। इनमें से कुछ का सामग्रद उपयोग भविष्य में किया जा सकेगा।

54. सैद्धान्तिक रूप से भायकर (धीरे मुक्त-सम्पत्ति करों) के पूरक के रूप में कुल धन पर नीची दर से लगाये जाने वाले वाधिक कर के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम की प्रस्ता में काफी कहा जा सकता है क्योंकि इनके जरिए व्यक्तियों के बीच करवाह्यता का ज्यादा धष्टा संतुलन प्राप्त किया जा सकता है बनिस्वत घरेलू भायकर के, क्योंकि भायकर में

तो घोरी हो जाती है। धन का वितरण कराधान का ऐसा आधार है जो आय के वितरण से तो कम उपयुक्त होता है, लेकिन जो इस समय प्रयुक्त किये जाने वाले कई अन्य आधारों से ज्यादा उपयुक्त होता है। व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों व दायित्वों (Assets and Liabilities) के सम्बन्ध में एक की गई सूचना भी करदाताओं के द्वारा रिपोर्ट की गई आय, उत्तराधिकार व उपहार में प्राप्त राशियों की शुद्धता की जांच में काफी महत्व रखती है। लेकिन पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण प्रशासकीय बठानाईयों से भरा हुआ है जिनकी वजह से ऐसा कर कुछ समय तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।

55. नामों से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा के संसाधन की प्राथिक रूप से छोटी धामदनीयों के प्रत्यक्ष कराधान के ही भेद माने जा सकते हैं। चूंकि प्रारम्भिक वर्षों में जब कार्यन्तमों का विस्तार जारी रहता है उस समय संग्रहीत राशि लाभ पर व्यय की गई राशि से अधिक होती है, इसलिए विद्युत प्राप्तियों से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध होने वाले राधनों में लाभप्रद वृद्धि होती है। भारत में इस दिशा में बर्मचारी राज्य बीमा योजना और बर्मचारी प्रोबिटेक्ट कोष योजना के रूप में पहले ही दुरभात की जा चुकी है।

56. आय के कराधान में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाने के लिए बटुया पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की सिफारिश की जाती है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये लाभ आय में होने वाली वृद्धि को सूचित करते हैं और इस प्रकार करदाता की बरदेय क्षमता को बतलाते हैं। इसके अनतिरिक्त ये उन तत्वों में गिने जाते हैं जिनसे धन की असमानता पैदा होती है, और विदेशन्याय एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जिसमें औद्योगीकरण और सहरीकरण निरन्तर बढ़ते जाते हैं। ऊपरवर्णित कारण भारत में पूंजी लाभ कर के लागू करने के पक्ष में जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में दो वर्गों की अलावधि के लिए पूंजी लाभ कर लगाया जा लेकिन यह सन् 1949 में मुख्यतः इस बात को लेकर समझा कर दिया गया कि गिरने हुए मूल्यों के कारण इनके काफी आय नहीं हो रही थी। साथ में यह बात भी बही गई कि इनके वित्तियोग पर विदेशी मनोसंज्ञानिष्ठ प्रभाव पड़ा और इनके हटौक व दीपरी की स्थिति कमिनीय में भी बाधा पड़ी। उस समय पूंजी लाभ कर को समाप्त करने के लिए जो कारण दिये गये थे वे आज भी लागू होते हैं। जब मुदा आय तो विदेशी को असाध्य देने के लिए पहले की अपेक्षा आज ज्यादा संभव है।

वरण की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के महत्त्व के बढ़ने की आशा है। इसके प्रतिरिक्त हम आयकर की दरों में वृद्धि का भी सुझाव दे रहे हैं। यदि इस समय पूँजी लाभ-कर लगा दिया जाता है—और इसकी आकस्मिक (Casual) अथवा अनियमित प्रकृति के कारण यह साधारण आय कर और अधि-कर (Super-tax) की धरेदार नीची दरों पर ही लागू किया जायगा—तो करदेय आय के एक भाग के रूप में मानी जा सकने वाली आय को पूँजी-लाभ बतलाने के प्रयास से कर टालने (tax avoidance) का भय बढ़ जायगा। इसके अलावा मृत सम्पत्ति कर के लागू हो जाने से कर व्यवस्था में अब धन की असमानता और फलस्वरूप बाद में धर्मदानी की असमानता को कम करने का एक प्रत्यक्ष साधन भी उपलब्ध हो गया है। इन परिस्थितियों में हम कुछ समय के लिए पूँजी लाभ पर एक विशिष्ट कर लागू करने की सिफारिश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यह कहना चाहेंगे कि यदि विकास की तीव्र गति के कारण अथवा अन्य किसी कारण से स्थिति बदल जाती है और हम निरंतर बढ़ती हुई कीमतों व मुनाफों एवं पूँजी-मूल्यों (Capital Values) की अवधि में प्रवेश करते हैं, तो पूँजी लाभ कराधान के लिए काफी उपयुक्त साधन बन सकता है और इसे कर के क्षेत्र में ले लेना चाहिए।

57. भूमि और अन्य सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अनाजित वृद्धियाँ, जो चाहे सुधार के विशिष्ट सार्वजनिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुई हों अथवा समान में सामान्य आर्थिक प्रगति के श्रृंग के रूप में हुई हों, इन पर होने वाला कराधान काफी दीर्घकाल से सैद्धांतिक रूप से एक भावार्थ कर माना गया है जो उत्पन्न या उत्पादन को प्रभावित किये बिना आय उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके प्रस्तासन में प्रमुखतया गम्भीर व्यावहारिक कठिनाइयाँ होने से इसे सफलता नहीं मिल पाई है। वास्तविक आयदाद से प्राप्त पूँजीगत लाभों पर राज्यों के द्वारा कुछ सीमा तक परोक्षरूप से कर लगाया जाता है जो बाहरी भूमि व इमारतों पर आनुपातिक आयदाद कर के रूप में, उस भूमि पर जहाँ सिंचाई की नई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं कुछ वर्षों तक बिना वसूल किये गये मुनाफों (unrealised gains) पर सुधार कर (betterment levies) के रूप में और गैर-कृषियुक्त उपयोग में बदली गई कृषियुक्त भूमि पर बढ़ी हुई कर की राशि के रूप में लागू किया गया है। जहाँ तक शहर की वास्तविक आयदाद का प्रश्न है इस पर लगा हुआ अपेक्षाकृत भारी आर्थिक कर और इसके भ्रंश पर लगे हुए कर बढ़ी मात्रा में होने वाली अनाजित वृद्धियों को रोक

सकते हैं। सुधार-कर अथवा विशिष्ट कर-निर्धारण सभी पूंजीगत लाभों को शामिल नहीं कर लेते हैं बल्कि ये उन्हीं को शामिल करते हैं जो विशिष्ट सार्वजनिक सुधारों से उत्पन्न होते हैं। फिर भी ये कर के ढाँचे में काफी मूल्यवान वृद्धि के रूप में माने जा सकते हैं और विशेषतया इसलिए कि ये पूंजीगत लाभों को कुछ वर्षों की एक उपयुक्त अवधि तक व्याप्त कर देते हैं।

58. दूसरा कर जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है वह अतिरिक्त लाभ कर (Excess profits tax) है। यह कर उद्योग और व्यापार के उन लाभों पर लगाया जाता है जो 'सामान्य' अथवा 'उचित' लाभ के स्तर से ऊँचे होते हैं। मुद्रास्फोट के समय यह प्रायः का एक उत्तम साधन हो जाता है। इसी वजह से यह ज्यादातर युद्धकाल और युद्धोत्तर काल में असामान्य व्यावसायिक लाभों पर कर लगाने के सुविधाजनक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह अतिरिक्त लाभ पूंजी पर एक निश्चित प्रतिफल के प्रतिशत के आधार पर (उचित लाभ) निर्धारित किया जा सकता है अथवा एक निश्चित अवधि में प्राप्त किये गये मुनाफों (सामान्य मुनाफों की तुलना के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कई अतिरिक्त लाभ-करों के नियमों में दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रतिशत के स्तर की अपेक्षा से कुछ असमंजस उत्पन्न हो जाती है क्योंकि सभी प्रकार के उप-वर्गों पर समान रूप से लागू करने के लिए लाभ का कोई विशेष अनुपात निर्धारित करना सम्भव नहीं होता है और आधार-अवधि अथवा सामान्य लाभ के स्तर की अपेक्षा इसे लागू करना ज्यादा कठिन होता है। यही कारण है कि अतिरिक्त लाभ कर के विधान में दूसरी विधि का अधिक उपयोग हुआ है और प्रतिशत प्रतिफल का एक विकल्प के रूप में प्रयोग अभी हुआ है जबकि यह निम्नलिखित आवश्यक हुआ है (जैसे नये उपकरणों के सम्बन्ध में) अथवा जहाँ इसकी लागू न करने से काफी असमानता उत्पन्न हो जाती।

59. भारत में अतिरिक्त लाभ कर विधान (1940 का अधिनियम XV संशोधित होने के बाद) बहुत कुछ ब्रिटिश कानून के तमूने पर बन था। इसके अन्तर्गत 36,000 रु० से नीचे के लाभ पर कर नहीं लगना था। अनुसूचित राज्यों में कर की दरें कम थीं। 1. जनवरी 1939 के बाद के अतिरिक्त मुनाफों पर 31 मार्च 1941 तक कर की दर 50 प्रतिशत की। उसके बाद अतिरिक्त लाभों पर यह 66 2/3 प्रतिशत थी। अतिरिक्त लाभ कर-विधान के एक अन्तर्गत के रूप में युद्धोत्तर काल की व्यवस्था विनियमन के अन्तर्गत नहीं थी। इसके पीछे मुख्य विचार यह था कि अतिरिक्त लाभ

एक अंश जो कर के रूप में ले लिया गया है वह युद्ध के पश्चात् करदाता को लौटा दिया जायगा। 31 मार्च 1946 के बाद उत्पन्न होने वाले मुनाफों के सम्बन्ध में भारतीय कर हटा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह कर 1945 के रेवेन्यू अधिनियम के द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया था और संयुक्त राज्य में यह 1946 के अंत में समाप्त किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 जून 1950 के बाद में समाप्त होने वाले करदेय वर्षों (taxable years) के लिए अतिरिक्त लाभ-कर पुनः लागू कर दिया गया था।

60. यहाँ पर यह तर्क दिया जा सकता है कि अतिरिक्त व्यावसायिक लाभ युद्धकालीन अवधि में ही नहीं बल्कि मुद्रास्फीति की किसी अन्य अवधि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस अवधि में विद्यालभा में विकास पर व्यय किया जाता है और भारी मात्रा में मुनाफा प्राप्त हो सकता है। लेकिन युद्धकाल में अतिरिक्त लाभ कर के अनुभव में यह दिखा दिया कि कई दृष्टियों से इसमें स्वेच्छाचारिता का स्वरूप होता है, विशेषतया सामान्य लाभों का स्तर निर्धारित करने में। यदि इसका उपयोग कर-प्रणाली में एक सामान्य अंग के रूप में किया जाना है तो अतिरिक्त मुनाफों के निर्धारण में प्रतिफल प्रतिफल का आधार हो काम भा सकता है। लेकिन व्यवहार में यह भी सतीवप्रद नहीं होगा क्योंकि पूँजी का ब्यवहार करना होगा और विभिन्न व्यवसायों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा। सामान्य अवधि में अतिरिक्त लाभ कर के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व अन्य देशों के अनुभव में प्रायः पर लगाये जाने वाले करों के प्रचलित रूपों की तुलना में कोई विशेष लाभ नहीं दिखाते हैं। भारत में मार्च 1947 में व्यावसायिक लाभ कर 1946-47 के लाभों पर लगाया गया था और इसकी दर पूँजी पर 6 प्रतिशत से अधिक के लाभों अथवा एक लाख रु० के लाभों, इनमें से जो भी अधिक हो, पर 10 प्रतिशत थी। बाद में 1948-49 में दर की दर घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई थी और पूँजी पर प्रतिफल की वह सीमा जिस पर कर लागू नहीं हो सकता था, बढ़ा दी गई थी और अंत में 1950-51 के बजट में यह कर समाप्त कर दिया गया था।

61. अतिरिक्त लाभ कर (E.P.T.) पूँजी-लाभ पर कराधान की तरह, अतिरिक्त मुद्रास्फीति की अवधि में, जब कि बाफो मात्रा में लाभ अतिरिक्त किये जाते हैं, काम में लिये जाने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है; लेकिन हम अतिरिक्त लाभ-कर अथवा व्यावसायिक लाभ-कर को कर-प्रणाली के



सामान्य भत्ता के रूप में लागू करने की विचारिय नहीं करते हैं। भारतीयता में वैयक्तिक आधार और कर्मवी अधिकार (superior right) और व अन्य उद्देश्यों की दृष्टि में पर्याप्त होने हैं।

62. दूसरा कर जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह नमक पर उत्पादन कर है। यह कर प्राचीन समय से देश की राजस्व व्यवस्था का एक अंग रहा है और भारत में ब्रिटिश सरकार ने इसमें बाड़ी वृद्धि भी की थी। इस देश में गोकामहर्षण गोकर्ण में प्रारम्भ करके महात्मा गांधी तक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने सर्वत्र नमक कर का विरोध किया है। इस विरोध की बाव भी सरकारों ने नमक कर में विदेशी सामान के प्रतीक के रूप में एक राजनीतिक महत्व प्राप्त कर दिया था और इसकी समाप्ति स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया था। 1947 में स्वतन्त्रता के आगमन से नमक कर समाप्त कर दिया गया और तब से यह पुनः लागू नहीं किया गया है।

63. नमक कर को फिर से लागू करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए जिस महत्वपूर्ण तत्व पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि वस्तु-कराधान के विस्तृत क्षेत्र की वर्तमान पृष्ठभूमि क्या है। केन्द्रीय उत्पादन करों के दायरे में ऐसी वस्तुएँ आती हैं जैसे तम्बाकू, सूती वस्त्र, चीनी, माचिस, चाय आदि जो साधारण जनता के उपभोग में काम आती हैं। बिक्री करों का विकास विस्तृत क्षेत्र को शामिल करने के लिए किया गया है और उनकी करवाहता नमक कर से ज्यादा भिन्न नहीं है।

64. इस रिपोर्ट में अन्यत्र हमने केन्द्रीय व राज्यीय क्षेत्रों में उपभोग करों के विस्तार के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उनसे उपभोग करों के भार में और भी वृद्धि होगी। अतः यदि हम उपभोग करों के विस्तार एवं इनसे प्राप्त आय की भव्य तक की वृद्धि एवं भविष्य में हो सकने वाली वृद्धि पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उपभोग-करों पर लादा जाने वाला नमक-कर केवल इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि अपने भाग में इसकी करवाहता या करापात अपेक्षाकृत कम होता है।

65. एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व भी होता है जो नमक कर को सामान्य उपभोग को वसी ही अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों पर लगे हुए उसी प्रकार के करों से पृथक् करता है। कर-प्रणाली की सामान्य करवाहता की जाँच

के समय हमने यह बतलाया था कि खाद्य-फसलों का एक बड़ा धरा धरेलू उपभोग के लिए उत्पन्न किया जाता है न कि बिक्री के लिए। इसी वजह से यह वस्तु करो की पहुँच से दूर होता है। इसके विपरीत नमक छोटे रियायती भू-भागों में उत्पन्न किया जाता है, लेकिन यह सीमित मात्रा तक ही निम्नी उपभोग में प्रयुक्त किया जाता है, और इसकी लगभग सम्पूर्ण मात्रा नकद ही बेच दी जाती है। चूँकि नमक शायद ही कभी जीवन-निर्वाह स्तर पर उत्पन्न किया जाता है और ऐसा कुपिगत फसलों में नहीं होता है, इसलिए यह कर से नहीं बच सकता है जिससे यह अपने प्रभाव में अपेक्षाकृत ध्वरोही (regressive) होता है। नमक कर इस कारण से भी ध्वरोही होता है कि मनुष्य की भोजन की वस्तु के रूप में इसका उपभोग अधिष्ठाता रूप में बेलोच होता है। इसी कारण से इसका भार निम्न आयदनी वाले व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त चूँकि धारैरिक धर्म में लगे हुए व्यक्तियों को वैहिक कार्यों से अपनी सुराक में धन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा नमक की आवश्यकता होगी है, इसलिए इस कर का भार ऐसे व्यक्तियों पर न बेलस आय को देखने हुए अधिक होता है बल्कि निरपेक्ष रूप में भी अधिक होता है।

66. नमक कर पर एक राजकीय उपाय के रूप में चर्चा करते समय इसके राजनीतिक पहलू को भी नहीं भुलाया जा सकता है। कर इसलिए लगाये जाते हैं कि आय प्राप्त की जा सके और प्रशासनिक समस्या के रूप में कर के सग्रह में यह मान लिया जाता है कि जिन लोगों को कर देना है वे उचित सीमा तक अपनी प्रतिबन्धना का परिचय देंगे। एक कर में चाहे जो गुण हों लेकिन यदि इससे व्यापक काराङ्गी और आय जनता का विरोध पैदा हो जाता है तो उग सीमा तक यह एक अवाञ्छनीय कर माना जाना चाहिए। हमने अपनी जाँच के दौरान जो कुछ सुना है उगमें यह बात विशेषतया नमक कर पर लागू होती है और हमारा विचार है कि इसको भुलाना निषेध की दृष्टि से एक गम्भीर भुटि ही होगी।

**अन्तर-सरकारी कर सम्बन्ध और कर-सन्तुलन :-**

67. कर-नीति का हमारा विवेचन उग समय तक पूर्ण नहीं माना जायदा जब तक कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच और राज्य विभिन्न राज्यों के बीच कर माधनों के सम्बन्ध के सम्बन्धपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा न करनी जाय।

राजस्व अर्थ के रूप में लाभ करने की निश्चयिता नहीं करते हैं। अतिरिक्त आयकर और कम्पनी अधिकार (super tax) जिन की दृष्टि में अनिश्चित होते हैं।

६२. दूसरा कर दिवस पर विचार करने की आवश्यकता पर उत्पन्न कर है। यह कर प्राचीन समय से देश की राजस्व एक अर्थ रहा है और भारत में ब्रिटिश सरकार ने इसमें बाधा दी। इस देश में योगसङ्गम्य योजन से प्रारम्भ करते हुए सार्वजनिक कार्यालयों में सर्वत्र नमक कर का विरोध किया। को दार की व्यवस्थाओं में नमक कर ने विदेशी शासन के प्रतीक के राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया था और इसकी समाप्ति आन्दोलन से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया था। १९४७ में आन्दोलन से नमक कर समाप्त कर दिया गया और तब से यह पुनः किया गया है।

६३. नमक कर को फिर से लागू करने की बांछनीयता के निर्णय करने के लिए जिस महत्वपूर्ण तत्व पर विचार किया जाना चाहता है कि वस्तु-कराधान के विस्तृत क्षेत्र की वर्तमान पुष्टि केन्द्रीय उत्पादन करों के दायरे में ऐसी वस्तुएं जाती हैं जैसे तांबा, लोहा, चीनी, माचिस, चाय आदि जो साधारण जनता के उपभोग में आती हैं। किसी करों का विकास विस्तृत क्षेत्र को शामिल करने के लिए किया है और उनकी करवायिता समझ कर में अन्तर्गत नहीं है।

के समय हमने यह बतलाया था कि साख-फसलों का एक बड़ा भंडा घरेलू उपभोग के लिए उत्पन्न किया जाता है न कि बिक्री के लिए। इसी वजह से यह वस्तु क़रों की पहुँच से दूर होता है। इसके विपरीत नमक छोटे रिपायती भू-भागों में उत्पन्न किया जाता है, लेकिन यह सीमित मात्रा तक ही निजी उपभोग में प्रयुक्त किया जाता है, और इसकी लगभग सम्पूर्ण मात्रा भवद ही बेच दी जाती है। चूँकि नमक साधारण ही कभी जीवन-निर्वाह स्तर पर उत्पन्न किया जाता है और ऐसा कृषिगत फसलों में नहीं होता है, इसलिए यह कर से नहीं बच सकता है जिससे यह अपने प्रभाव में अपेक्षाकृत अवरोही (regressive) होता है। नमक कर इस कारण से भी अवरोही होता है कि मनुष्य की भोजन की वस्तु के रूप में इसका उपभोग अधिकांश रूप में बेतोज होता है। इसी कारण से इसका भार निम्न आयदनी वाले व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसके प्रतिरिक्त चूँकि सारीरिक श्रम में लगे हुए व्यक्तियों को दैनिक कारणों से अपनी श्रुतक में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा नमक की आवश्यकता होती है, इसलिए इस कर का भार ऐसे व्यक्तियों पर न केवल आय को देखते हुए अधिक होता है बल्कि निरपेक्ष रूप में भी अधिक होता है।

66. नमक कर पर एक राजकोपीय उपाय के रूप में चर्चा करते समय इसके राजनीतिक पहलू को भी नहीं भुलाया जा सकता है। कर इसलिए लगाये जाते हैं कि आय प्राप्त की जा सके और प्रशासनिक समस्या के रूप में कर के संग्रह में यह मान लिया जाता है कि जिन लोगों को कर देना है वे उचित सीमा तक अपनी प्रतिनियता का परिचय देंगे। एक बार में चाहे जो गुण हों लेकिन यदि इससे व्यापक नाराजगी और आम जनता का विरोध पैदा हो जाता है तो उस सीमा तक यह एक अवाञ्छनीय कर माना जाना चाहिए। हमने अपनी जाँच के दौरान जो कुछ सुना है उसमें यह बात विशेषतया नमक कर पर लागू होती है और हमारा विचार है कि इसको भुलाना निर्णय की दृष्टि से एक गम्भीर त्रुटि ही होगी।

**अन्तर-सरकारी कर समन्वय और कर-अनुसंधान :-**

67. कर-नीति का हमारा विवेचन उस समय तक पूर्ण नहीं माना जायगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच और स्वयं विभिन्न राज्यों के बीच कर आयकों के समन्वय के महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा न कर ली जाय।

68. प्रगत कराधान के क्षेत्र में तो समन्वय की कोई समस्या ही नहीं जान पड़ती है क्योंकि भारत में, कुछ अन्य मनीष आस्थाओं के विपरीत, राज्य सरकारों को नैर-कृषि नामदनी पर आधारित लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्हें कृषि-धाय पर आधारित लगाने का हक है। उनमें से कुछ तो पहले से ही इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हमने यह अनुभव किया है कि अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जिस सीमा तक केन्द्रीय आधार की वैयक्तिक दर निर्धारित करने के लिए कृषिगत आय और कृषि आय के साथ मिलाई जाती है और कृषिगत धाय पर राजसीय करों को वैयक्तिक दर को निर्धारित करने के लिए नैर कृषि आय कृषि-गत आय के साथ मिला दी जाती है, उस सीमा तक इनके सकल मंचानन के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों की कर लगाने की मनीसरी के बीच किसी सहयोग का होना आवश्यक है।

69. वस्तु-कराधान के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच सबसे ज्यादा सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। भारत में जिस तरह से बिक्री करों का विकास हुआ है उसमें न केवल सामान्य बिक्री पर लगाये जाने वाले कर शामिल हैं बल्कि उसमें विशिष्ट वस्तुओं पर लगाये जाने वाले विशिष्ट कर भी शामिल हैं जिनमें से अनेक को केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन करों के रूप में कराधान के अन्तर्गत ले रखा है। इससे प्रभावा आर्थिक नीति के उद्देश्य की दृष्टि से राजसीय बिक्री कर-व्यवस्था के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कुछ प्रश्न हैं जिनका राज्यों की परिधि से बाहर के क्षेत्रों व हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। हमने इस रिपोर्ट के भाग के पृष्ठों में विभिन्न स्थानों पर वैयक्तिक करों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है जिस पर कुछ एकीकृत रूप में विचार व कार्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संघ के विभिन्न राज्यों के बीच कर के अनुभव व सूचना के विनिमय का भी बहुत महत्व है।

70. इन सबके अलावा इस बात को देखते हुए कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ रहा है और जिस सीमा तक राजस्व प्रणाली के केन्द्रीय, राजसीय व स्थानीय भाग एक दूसरे के सम्पर्क में आते जा रहे हैं, कराधान व व्यय की समस्याओं के प्रति एक एकीकृत व राष्ट्रीय दृष्टि-कोण के विकसित करने की आवश्यकता हो जाती है चाहे इसका सम्बन्ध केन्द्रीय क्षेत्र से हो अथवा राज्य एवं स्थानीय क्षेत्रों से हो। वैयक्तिक करों की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में भी आंकड़े एकत्र करने की पहले से ज्यादा आवश्यक-

कता है। ऐसा न केवल वित्तीय परिणामों के मूल्यांकन की दृष्टि से किया जाना चाहिए बल्कि विद्युत् धारा के दृष्टिकोण को छोड़कर राजस्व नीति के अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनकी प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए तो और भी ज्यादा भाषा में किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप उस सीमा की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए जहां तक इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा सुझाई गई उत्पादन व विनियोग के लिए दी गई कर-सम्बन्धी प्रेरणाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त करा पाती हैं जिनके लिए ये लागू की गई हैं। औद्योगिक व व्यापारिक जगत में राजकीय उपक्रमों का एक विस्तृत क्षेत्र भी है जिसमें विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार के वैयक्तिक अनुभव को एकत्र करना सर्वाधिक लाभप्रद होगा। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के संपादन होने और द्वितीय योजना के शुरू होने की स्थिति में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर धीमे ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यों के कर-सम्बन्धी प्रयत्नों में भी आयोजित विकास की भांति बड़ी भाषा में समन्वय स्थापित किया जाय।

71. उन मामलों के विस्तार को देखते हुए जिसमें कर-सम्बन्धी प्रयत्न और कर नीतियों में समन्वय की आवश्यकता होती है और एक ऐसे संगठन की आवश्यकता को देखते हुए जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए कर समस्या के विशेष पहलुओं की जांच की जा सकती है, हम संविधान की धारा 263 के अन्तर्गत अखिल भारतीय कषधान परिषद की स्थापना की सिफारिश करते हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार व समस्त राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद् का मुख्य उद्देश्य राज्यों की कर नीतियों, कर विधान एवं कर-प्रशासन में आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना होगा जो स्वयं राज्यों के बीच और साथ व राज्यों के बीच स्थापित किया जाएगा। राज्यों से सम्बन्धित कर के मामलों में वे भी शामिल होंगे जिनका उनकी स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्ध है। राज्यों के बीच पाये जाने वाले विवाद एवं एक या अधिक राज्यों और संघ के बीच होने वाले विचाराधीन विषय जिनकी एक बड़ी संस्था के समक्ष रखना बांछनीय माना जाएगा, परिषद के समक्ष लाये जा सकेंगे। धारा प्रदत्त पर समय-समय पर विवेचन करने के लिए एक संगठित संस्था की व्यवस्था करना साथ व राज्यों एवं स्वयं राज्यों के बीच कर-समन्वय एवं सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

72. यह बांछनीय होगा कि इस संस्था में सम्बन्धित सरकारों का राजनीतिक स्तर पर सर्वानु भवियों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाय। अतएव

होना यह सुझाव है कि परिषद् के सदस्य वित्त व स्थानीय स्वशासन के राष्ट्रीय व राज्तीय स्तरों पर। लेकिन मान में निम्न व्यवस्था भी चाहिए। (क) सरकारी एवं नगर सरकारी समितियों के प्रति प्रतिनिधित्व और (ख) सम्बन्धित दलों का निरन्तर विशेषज्ञों के स्तर पर परामर्श जब कभी आवश्यक हो नगर-सरकारी व सरकारी व्यक्तियों की सलाह (ad hoc) या महाहकार समितियों नियुक्त कर सकती है। परिषद् के अन्तर्गत विषय-व्यवस्था या अन्य सम्बन्धित (जैसे विभिन्न राज्यों के विचारों पर अधिकाधिक का वार्षिक सम्बन्ध) भी दिया जा सकेगा इस संस्था को यह स्वीकार देना सम्भव नहीं होगा कि यह एक ऐसे कार्य के निर्वहन औपचारिक (formal) निर्णय से मंचे प्रस्ताव औपचारिक सिफारिशों प्रस्तुत कर गये जिनके प्रति सभी सदस्य सहमत न हों। प्रस्ताव हो सके परिषद् की कार्य-प्रणाली अनौपचारिक ही रही जाय।

73. परिषद् के प्रतिष्ठित्व का यह अर्थ नहीं है कि संघ और राज्य राज्यों के बीच अथवा विभिन्न राज्यों के बीच द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय अथवा बहुपक्षीय बातचीत आदि की साधारण विधि का उपयोग नहीं हो

74. परिषद् का एक स्थायी सचिवालय कर अनुसंधान ब्यूरो (Research Bureau) होगा जो वित्त-मन्त्रालय से जुड़ा हुआ हो। परिषद् के समक्ष उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रश्नों की जांच के प्रतिरिक्त यह संघ, राज्य, राज्तीय व स्थानीय स्तरों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन सामग्री के सतत् सग्रह व समन्वय का कार्य भी करेगा। हम इस संगठन स्थापना की निम्न कारणों से सिफारिशें करते हैं: सम्पूर्ण कर प्रणाली और मुख्य अंगों—केंद्रीय, राज्तीय एवं स्थानीय स्तरों का अध्ययन किया जा विदेशी कर-प्रणालियों की प्रमुख नई प्रवृत्तियों का ध्यान रखा जाय; सम्बन्धी आंकड़ों के लिए एक समन्वयात्मक एजेंसी का काम करना। राजस्व-विश्लेषण (fiscal analysis) एवं अनुसंधान के लिए आंकड़ों में सुधार करने के लिए कदम उठाना; विशेष करों या कर समूहों के क्रियान्वयन सम्बन्ध में, वृद्ध एवं पूँजी-निर्माण पर प्रत्यक्ष कराधान के प्रभावों के सम्बन्ध में, विशेष उद्योगों पर विशेष करों के भार के बारे में और केंद्रीय व राज्तीय वस्तु-कराधान आदि के बीच उत्पन्न हो सकने वाले प्रतिच्छादन (overlap) व गैर-सम्बन्ध में समय-समय पर विशेष जांच करवाना और साधारणतया सरकारों को वस्तु-सामग्री और प्राविधिक सलाह प्रदान करके कर-नीतियों के निर्माण में मदद पहुँचाना। यह संगठन अलग-अलग राज्य सरकारों की वित्तीय

स्थिति का सतत अध्ययन भी अपने हाथ में ले सकता है जैसा कि वित्त आयोग ने सुझाया था। भारत में सार्वजनिक वित्त की वार्षिक समीक्षा को प्रकाशित करना भी इसके कर्तव्य का एक भाग होगा। इसमें केन्द्रीय व राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय संस्थाएँ भी शामिल होंगी।

75. ऐसे कार्य को सरकार के उत्तरावधान में करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमारा यह मत है कि इन क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों व अन्य गैर-सरकारी अनुसंधान-संस्थाओं में कुछ सक्रिय कदम उठाये जाय। मतएव हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि चुनी हुई अनुसंधान संस्थाओं में सार्वजनिक वित्त व सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में छोटे अनुसंधान केन्द्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाय। ऐसे केन्द्रों व हमारे द्वारा प्रस्तावित कर अनुसंधान ब्यूरो के बीच निकट सम्पर्क की भी व्यवस्था की जाय। यदि विश्वविद्यालयों में स्थापित अनुसंधान केन्द्र ठीक दिशा में प्रगति करते हैं तो समय पाकर कर अनुसंधान ब्यूरो एवं चुने हुए अधिकारियों के सहयोग से इनका उपयोग कर अधिकारियों के लिए प्रबोधन व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (refresher and training courses) की व्यवस्था में सहायता करने में किया जा सकता है।





## करापात

प्रार. ए. मसप्रेव  
(मिनिगन विश्वविद्यालय)

प्रस्तुत लेख का प्रयोजन सामान्य संतुलन की दृष्टिभूमि में उत्पादन-कर एवं आयकर के करापात की तुलना करना है। यह कोई आसान काम नहीं है। हम शुरू में ही भटक न जायें, इसलिए यह लाभप्रद होगा कि हम अपना विश्लेषण एक सम्पूर्ण-उपभोग की अर्थ-व्यवस्था में पाई जाने वाली सरल स्थिति से ही करें। तत्पश्चात् हम मक्कनासिकल मॉडल के अंतर्गत एक अधिक वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे जहाँ पूँजी-निर्माण हो सकता है। अंत में एक तरलता-सदगी मॉडल जैसी अधिक जटिल स्थिति पर विचार किया जायगा, लेकिन इस बार वह संक्षेप में ही होगा।

### 1. सम्पूर्ण-उपभोग वाले मॉडल में करापात

सर्वप्रथम, उन शब्दों की परिभाषा करना उपयुक्त होगा जिनका आगे के विवेचन में उपयोग किया गया है। कराधान के "आपात एवं प्रभावों" के अध्ययन में हम एक संतुलन की स्थिति से प्रारम्भ करते हैं जिसमें करों एवं सार्वजनिक व्ययों का एक दिया हुआ ढाँचा एक बहुस्तरीय भ्रम होता है। बजट-नीति में कुछ परिवर्तन किये जाते हैं और समायोजन होते हैं, एवं एक नया संतुलन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम नई स्थिति की तुलना पुरानी से करते हैं।

सम्पूर्ण परिवर्तन की जाँच करते समय हमें इसके विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर करना होगा। जैसे हमें यह जानना होगा कि क्या साधनों का सार्वजनिक व निजी उपयोगों के बीच हस्तान्तरण हुआ है। यह सार्वजनिक व सेवाओं के व्ययों में होने वाले परिवर्तनों का कार्य है और इसे "साधन-हस्तान्तरण" कह सकते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली वास्तविक आय के वितरण में क्या कोई परिवर्तन हुआ है। मैं इसे "करापात" कहना चाहूँगा। अंत में हम यह जानना चाहेंगे कि क्या कुल आय में कोई परिवर्तन हुआ है। इसे "उत्पत्ति-प्रभाव"

बहा जा सकता है। ये तीनों परस्पर निर्भर होते हैं, लेकिन समग्र परिवर्तन के अलग-अलग मापनीय पहलू माने जाते हैं। इन विविष्ट परिभाषाओं के जो चाहे गुण हों, लेकिन ये कम-से-कम उस भ्रष्टाचार से तो मुक्त हैं जो बहुधा कराधान के "आपात एवं प्रभावों" के साथ जुड़ी हुई होती है।

अब हम बजट सभाओं की विभिन्न किस्मों पर विचार करेंगे और वितरण अथवा करापात में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का माप करेंगे। उदाहरणार्थ, हम सार्वजनिक व्ययों की स्थिर रख कर करो से प्राप्त आय में वृद्धि अथवा कमी कर सकते हैं।<sup>1</sup> मैं इसे "निरपेक्ष करापात"<sup>2</sup> कहना चाहूँगा। अथवा हम एक कर की जगह उतनी ही आय वाला दूसरा कर प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

1. इसमें यह मान्यता निहित है कि आय के रूप में प्राप्त होने वाला लाभ कर-प्रणाली में से वापिस ले लिया जाएगा, अथवा खोई गई आय मुद्रणालय के वित्त से पूरी कर दी जायगी।
2. जैसा कि मूलपाठ में बतलाया गया है, निरपेक्ष करापात आय की दशाधी में होने वाला वह परिवर्तन है जो कराधान के स्तर में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होता है और इस स्थिति में सार्वजनिक व्यय स्थिर रहता है। इसका अंतर भेदात्मक करापात या करवाह्यता से करना होगा जिसमें वितरण के ऐसे परिवर्तन मापे जाते हैं जो उस समय उत्पन्न होते हैं जब कि समान आय देने वाला एक कर हमारे की जगह बदला जाता है। जहाँ तक व्यय के परिवर्तनों का सम्बन्ध है, हम इसी तरह से निरपेक्ष एवं भेदात्मक व्ययपात के बारे में भी कह सकते हैं।

हम पाठक को यहाँ चेतावनी देना चाहते हैं कि "निरपेक्ष" शब्द केवल "भेदात्मक" के विपरीत अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। विशेषतः "निरपेक्ष करापात" शब्द का यह अर्थ कदापि नहीं है कि कर के लागू होने से सम्पूर्ण समूह पर कोई निरपेक्ष भार पड़ेगा, जैसा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए साधनों के हस्तान्तरण से होता है। साधन-हस्तान्तरण कर के परिवर्तनों का नहीं बल्कि व्यय का परिणाम होता है।

इन धारणाओं के अधिक विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—

Papers and Proceedings, Sixty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association, Chicago, 1952

इसको मैं "विभेदात्मक कराधान" कहता हूँ। अथवा हम वितरण के उग परिवर्तन को मापूम कर सकते हैं जो करें एवं सचों को एक-ही मात्रा तक बढ़ाने में उत्पन्न होता है। इसे मैं "मनुविन बजट कराधान" कहता हूँ। इसी प्रकार अन्य मयोगों पर भी विचार किया जा सकता है। इनमें मैं प्रत्येक दृष्टिकोण वांछनीय होगा है और उगका उपयोग दिया जा सकता है, बसतों कि उत्तरो व्यवस्थित रूप से निभाया जाय।

कराधात सापेक्ष कीमत-परिवर्तन के फलन के रूप में

(Incidence—A Function of Relative Price Change)

वितरण की स्थिति में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कर-नीति के परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं, सापेक्ष साधन एवं वस्तु-कीमतों के परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। विनिमय अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति बाजार से दो तरह से सम्बद्ध रहता है :—(1) एक तो उस कीमत के द्वारा जो उसे अपनी सेवाओं की बिज्जी से प्राप्त होती है और (2) उस कीमत के द्वारा जो उसे उन वस्तुओं के लिए देनी होती है जिन्हें वह खरीदता है। जब कर-नीति में कोई परिवर्तन किया जाता है तो हो सकता है कि बजट के स्रोतों और उपयोगों दोनों तरफ ही उसकी सापेक्ष स्थिति बदल जाय।

हो सकता है कि स्रोतों की तरफ उसकी चंस् की जाने वाली भाग में परिवर्तन हो जाय, ऐसा या तो उसकी आमदनी के परिवर्तन के कारण हो सकता है अथवा उसके वैयक्तिक कर सम्बन्धी दायित्वों में परिवर्तन से उपयोग-पक्ष की ओर हो सकता है कि उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बदल जाय, ऐसा या तो मांग के परिवर्तनों से उत्पन्न लागत के परिवर्तनों के कारण होता है, अथवा वस्तुओं के कराधान में होने वाले परिवर्तनों के कारण। किसी भी व्यक्ति की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाते समय हमें स्रोतों एवं उपयोगों दोनों तरफ उसकी स्थिति के परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा।

(*American Economic Review*, Suppl. [1953]) में मेरे लेख "General Equilibrium Aspects of Incidence Theory" का प्रथम खण्ड। नीचे संख्या 24 भी देखें।

3. निरपेक्ष कर और निरपेक्ष व्यय के साधात के साधतों में सम्मिश्रण किया जा सकता है ताकि करव सच के मनुविन म होने वाले सामायोजनों का साधात जाना जा सके।

उदाहरण के लिए, एक ऐसी स्थिति को लीजिए जिसमें दो व्यक्ति क और ख हैं, जो क्रमशः दो साधन घ और झा बेचते हैं और दो वस्तुएं प और फ खरीदते हैं। अब यदि  $\Delta$  की कीमत घा की तुलना में बढ़ती है और/अथवा प की कीमत फ की तुलना में घटती है, तो क की स्थिति ख की तुलना में सुधरेगी; और ख के लिए उलटा सम्बन्ध लागू होगा। हम क की आमदनी में होने वाले परिवर्तन को निम्नांकित ढंग से माप सकते हैं :-

$\Delta R = \Delta E - \Delta T_p - Q_r \Delta P_r + Q_f \Delta P_f$ , जहाँ  $\Delta R$  वास्तविक आय के परिवर्तन को सूचित करना है,  $\Delta E$  आय के परिवर्तन को,  $\Delta T_p$  वैयक्तिक करों के परिवर्तन को,  $Q_r$  और  $Q_f$  उन वस्तुओं की खरीदी गई गई मात्राओं को जिसकी कीमतें क्रमशः बढ़ी या घटी हैं, और  $\Delta P_r$  और  $\Delta P_f$  वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः कमी या बढ़ोतरी को सूचित करते हैं।<sup>14</sup> करापात  $\Delta R$  के द्वारा परिभाषित आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों का माप करता है।

4. वैकल्पिक रूप में हम यो लिख सकते हैं  $\Delta R = (E_1 - T_{p1})/P_1 - (E_0 - T_{p0})/P_0$ , जहाँ  $P_0$  वह कीमत सूचकांक है जिसे प्रथम अवधि के लक्षों के अनुसार भार दिया गया है, और  $P_1$  वह सूचकांक है जिसे कर के परिवर्तन से समायोजन के पदनाशु किये जाने वाले लक्षों के अनुसार भार दिया गया है।

एक कठिन प्रश्न के सम्बन्ध में यह संक्षिप्त बचन कम से कम मोटे तौर से यह दिसाने के लिए दिया गया है कि करापात के माप का क्या भास्य है। प्रस्तावित माप पूर्णता से दूर है। जब एक कर के स्थान पर दूसरा कर लगाया जाता है तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच लाभ-हानि अनिवार्यतः बंट नहीं जाती है, अथवा बंट में वृद्धि करने पर विमुख हानि अनिवार्यतः प्राप्त आय के बराबर नहीं हो जाती है। लगाई जाने वाली सामग्री की हवाइयो के यथास्थिर रहने पर भी ये कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इनको टालना शुभ नहीं होता है। वर्तमान उद्देश्य की दृष्टि से तो यह ध्यान में रखना पर्याप्त होगा कि कर-नीति के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आर्थिक तथ्यों के सारे परिवर्तनों की जानकारी होने पर भी करापात का माप एक कठिन नियम ही बना रहेगा।

## सापेक्ष कीमत-परिवर्तन कर-विभेद का फलन होते हैं

(Relative Price Changes—A Function of Tax Discrimination)

आगे हम यह देखते हैं सापेक्ष कीमतों में होने वाले परिवर्तन (और इसी वजह से करापात में), जो कर-नीति के विशेष परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं, सामान्यता के अन्तर्गत अथवा इसके अभाव (विभेद) पर निर्भर करते हैं जो विशेष करों में निहित होती है। यही एक महत्वपूर्ण तत्त्व है, यह नहीं है हमारा सम्बन्ध आय से है अथवा वस्तु-करों से।

हमारे सम्पूर्ण उपभोग वाले मॉडल की अन्तर्गत प्रवाह की प्रणाली (circular-flow system) में समस्त सौदे साधन-सौदों एवं वस्तु-सौदों को विभाजित किये जा सकते हैं।<sup>5</sup> कोई भी कर किसी-न किसी सौदे पर लगाया जायगा, लेकिन यह विभिन्न पक्षों में सामान्य या विभेदकारी हो सकता है।<sup>6</sup> सारणी 1 का वर्गीकरण नहीं दिया में से जाने की स्थिति प्रस्तुत करता है।

सामान्य कर :—हम सर्वप्रथम सामान्य करों के आपात पर विचार करते हैं। सारणी 1 में दो प्रकार के वास्तविक सामान्य कर दिखावाये गये हैं : मद-गत्या 1 समस्त वस्तु सौदों पर लागू होती है और मद सत्या 3 समस्त साधन सौदों पर लागू होती है।

5. विषय की सरल रखने के लिए हम यह मान लेते हैं कि समस्त वस्तुओं में उत्पादन की एक ही अवस्था होती है।

6. हम यहाँ पर उन दृष्टि राशि वाले करों के विशेष मामले को छोड़ देते हैं जो आर्थिक बाधों पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

**सारणी 1**  
**कर-विभेद की किस्में**

		निम्न पर कर लागू होता है			
		समस्त विक्रेता व समस्त क्रेता	कुछ विक्रेता समस्त क्रेता	कुछ क्रेता समस्त विक्रेता	कुछ क्रेता व कुछ विक्रेता
वस्तुओं पर कर :					
समस्त	...	1	5	9	13
कुछ	...	2	6	10	14
साधनों पर कर :					
समस्त	...	3	7	11	15
कुछ	...	4	8	12	16

प्रथम नियम तो यह है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ऐसा कर बाजार के विक्रेता पक्ष पर लागू किया जाता है अथवा क्रेता पक्ष पर। वस्तुओं के सौदों पर लगाये जाने वाले कर के सम्बन्ध में इस बात से कोई घंटर नहीं पड़ता कि यह कर सामान्य बिजली-बैर का रूप ग्रहण करता है अथवा सामान्य व्याप-कर का। समस्त साधन-सम्बन्धी सौदों पर लगाये जाने वाले कर के बारे में भी इस बात का कोई महत्व नहीं है कि यह व्याप-कर का रूप लेता है, अथवा साधनों की खरीद पर कर का रूप लेता है। बिजली-बैर के बढ़ते में व्याप प्रतिस्थापित कर देने से स्थिति अपरिवर्तित बनी रहनी है जैसे कि व्याप-बैर के लिए साधन की खरीद को प्रतिस्थापित करने से बनी रहती है। यह समानता, जिस पर बढ़ते एजबर्थ ने ध्यान दिया था, विभेदकारी एवं सामान्य करों दोनों पर लागू हो जाती है, लेकिन दूसरी स्थिति में इसका विशेष महत्व होता है।<sup>7</sup>

7. विभेदकारी करों के सम्बन्ध में क्रेत्राओं अथवा विक्रेताओं के लक्षण घंटर का आधार बनाये जा सकते हैं, इस प्रकार इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि कर क्रेता अथवा विक्रेता-पक्ष की ओर झुकाव।

द्वितीय, धीरे भी शक्तिप्रद बात यह है कि हम देखते हैं कि सम्पन्न साधन सम्बन्धी सौदों पर लगाये जाने वाले कर धीरे सम्पन्न वस्तु-मोदों पर लगाये जाने वाले कर में कोई अंतर नहीं होता है। एक को दूसरे से प्रतिस्थापित कर लेने पर भी सापेक्ष वस्तु और साधन-कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं। यद्यपि परिणामस्वरूप सापेक्ष कीमतें बदल सकती हैं, लेकिन सापेक्ष मूल्य धीरे फलस्वरूप करापात अपरिवर्तित बने रहते हैं। अतएव हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक सच्चा सामान्य आय-कर धीरे विन्नी कर सम्पूर्ण उपभोग के माँडल में समान होते हैं। इस बात को स्वीकार कर लेने पर कि वस्तु और साधन-मोदों पर सच्चे सामान्य कर एक से होने हैं ताकि भेदात्मक करापात तटस्थ रह सके, यह प्रश्न उठता है कि ऐसे करों का निरपेक्ष आपात कैसा होता है? जब हम इस तरह से प्रश्न करते हैं तो सार्वजनिक खर्चों के सम्बन्ध में मान्यताएं स्वीकार करने की आवश्यकता हो जाती है। मान लीजिए, इस किस्म का एक सामान्य कर लागू कर दिया जाता है और सार्वजनिक खर्च उतनी ही मात्रा में बढ़ा दिये जाते हैं। यदि हम यह मान लें कि (प्र) साधनों की पूर्ति बेलोच है, (भा) निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली आय में जाने वाली कमी से निजी मांग के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और (इ) सार्वजनिक मांग ठीक उन्हीं साधनों की ओर जाती है जो निजी मांग से मुक्त हो पाते हैं; तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर और व्यय की ऐसी योजना का संतुलित बजट करापात सापेक्ष दशाओं को अपरिवर्तित रहने देगा। ऐसी स्थिति में निरपेक्ष बजट करापात आनुपातिक होगा।

ये मान्यताएँ कहाँ तक वास्तविक हैं? साधनों की बेलोच पूर्ति की मान्यता एक विशेष कर की दशा में लागू नहीं होती है, लेकिन एक सच्चे सामान्य कर की वर्तमान पृष्ठभूमि में यह काफी वास्तविक हो सकती है। यदि विभिन्न साधनों की पूर्ति लगभग सोचदार होती है तो प्रतिफल की सापेक्ष दरें, उदाहरण के लिए, कर से पूर्व विभिन्न प्रकार की दक्षता के लिए दी जाने वाली मजदूरी की दरें, अधिक सोचदार साधन के परा में परिवर्तित हो जाएंगी। इस स्थिति में आय की सापेक्ष दशाएँ बदल जायेंगी। \* मांग के स्थिर

8. ध्यान रहे कि हमारा क्रियाशील माप (operational measure) सच योग्य मौद्रिक आय की कीमतों के अनुसार कम कर देने पर प्राप्त राशि में होने वाले परिवर्तनों के जरिए होता है। इसमें उग भार या लाभ की व्यवस्था नहीं की गई है जो समय के कार्य और अवकाश के बीच किये

प्राप्ति की मान्यता वास्तविक नहीं होती है। निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली आय में परिवर्तन होने से वैयक्तिक प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और सरकार का प्राथमिकता का प्राप्ति निजी क्रेताओं के प्राप्ति से भिन्न होता है। इस प्रकार मांग के प्राप्ति में होने वाले परिवर्तन आय के उपयोगों व स्रोतों दोनों की दृष्टि से व्यक्तिगत दशायों को प्रभावित करेंगे। लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में हम यह आशा कर सकते हैं कि वैयक्तिक दशायों में होने वाले ऐसे परिवर्तन आय के सभी आधार-समूहों वाले व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं। जहाँ तक यह स्थिति पाई जाती है, ऐसे परिवर्तन वैयक्तिक दशायों को तो प्रभावित करते हैं लेकिन आय के समूहों के अनुसार आय के प्रकार-वितरण (size distribution) को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। इस अर्थ में सम्पूर्ण बजट-प्रक्रिया का करापात धानुपातिक बना रहता है।<sup>9</sup>

### भेदात्मक कर (Discriminatory taxes) :—

अब हम विभिन्न भेदात्मक करों के अन्तर्जनित करापात पर आते हैं। हम मद संख्या 2 से प्रारम्भ करते हैं, जिसमें वस्तु-सौदों पर एक कर लगाया जाता है जो समस्त सौदा लेने वालों पर लागू होता है, लेकिन यह कुछ वस्तुओं पर ही लागू होता है।

इस कर के बदले में एक सामान्य कर (चाहे वह सारणी 1 की मद संख्या 1 हो अथवा मद संख्या 3 हो) लगा देने से कर लगी हुई, वस्तुओं की कीमत कर-मुक्त वस्तुओं की तुलना में बढ़ जाती है। और इससे उन साधनों की मांग में कमी हो जाती है जिन्हें कर लगी हुई वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, अतः उन साधनों के जिन्हें कर-मुक्त वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है। कुल मिलाकर इससे उन लोगों की आमदनी की स्थिति में सुधार होगा जिनकी प्राथमिकता कर मुक्त वस्तुओं के

जाने वाले पुनर्वितरण के कारण उत्पन्न होती है। य इसमें उन अद्विष्ट समस्याओं की व्यवस्था की गई है जो परोक्ष करों के "अतिरिक्त भार" से सम्बन्धित होती हैं।

9. यहाँ पर यह मान लिया गया है कि करापात, आधार के अनुसार होने वाले आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से मापा जाता है, अर्थात् मोरेन्ड वक्र से मापा जाता है। इसलिए मेरा मत विमर्श उत्पन्न ऊपर बुटनोट संख्या 2 में मापा है।



पथ में होती है और जिनकी आय उन साधनों से होती है जो प्रमुखतया वर वस्तुओं के उत्पादन में सगाये जाते हैं। यह नहीं बल्कि इसमें उन लोगों की आमदनी की स्थिति भी दिगड़ जायगी जो प्रमुख रूप से कर लगी हुई वस्तुओं के उपभोग या अथवा पूर्ति करने वाले होते हैं। यह आशा करना उचित होगा कि इस स्थिति में करापात प्रमुखतया आय के उपयोग में (सापेक्ष वस्तु-मूल्यों में) होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करेगा, बजाय आय में होने वाले परिवर्तनों के (सापेक्ष साधन-मूल्य)।<sup>10</sup>

ऐसा ही तर्क मद नंख्या 4 पर लगाया जा सकता है जो साधन के सीधों पर एक भेदात्मक कर होता है। यहां पर हम उन लोगों की आय की स्थिति में सुधार देखते हैं जो कर-मुक्त साधनों की पूर्ति करते हैं और जिनके उपभोग सम्बन्धी प्रारूप उन वस्तुओं को सूचित करते हैं जो प्रमुखतया कर-मुक्त साधनों से उत्पादित होती हैं। इस स्थिति में आय-वृद्धि में होने वाले समायोजन काफी महत्वपूर्ण होते हैं।<sup>11</sup>

10. यहां पर पुनः आकार के समूहों के अनुसार आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन के रूप में करापात का उल्लेख आया है। कुछ वस्तुओं पर लागू होने वाला कर ही अन्य वस्तुओं की तुलना में उनकी कीमत में वृद्धि करेगा। चूंकि आय के आकार और बजट के प्रारूपों के बीच एक व्यवस्थित सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिए सापेक्ष कीमत में होने वाला यह परिवर्तन सम्भवतः वास्तविक आय के आकार-वितरण को परिवर्तित कर देगा। इसके विपरीत आय में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन वितरणात्मक दृष्टि से सदृश्य होंगे। असाधारण दशाओं को छोड़कर यह आशा करना सही नहीं होगा कि साधनों के सापेक्ष प्रतिफलों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन प्रमुखतया ऊंची या नीची आय वाले समूहों वाले व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे।

11. इस स्थिति में आय के परिवर्तन और आय के आकार के बीच एक व्यवस्थित सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि विभेदकारी अथवा वसपातपूर्ण वर्तव्य के लिये विभिन्न साधन भुने जा सकते हैं, क्योंकि आय प्रमुखतया ऊंची अथवा नीची आय वाले समूहों को होती है। लेकिन इस स्थिति में इस बात के लिए कोई विशेष कारण नहीं जान पड़ता है कि ऊंची आय वालों के द्वारा सरीरी गई वस्तुओं की कीमतें नीची आय वाले समूहों के द्वारा सरीरी गई वस्तुओं की कीमतों की तुलना में बढ़ेगी या घटेगी।

इस विश्लेषण को इस रूप में फैलाया जा सकता है ताकि इसमें विदेश सौदा करने वालों के विपक्ष में किये जाने वाले विभिन्न किस्म के भेदों का समावेश किया जा सके। समस्त वस्तु-सौदों पर लगाया जाने वाला कर (मद सख्या 5) निम्नोक्त अथवा चैन स्टोरो तक सीमित किया जा सकता है। समस्त साधन-सौदों पर लगाया जाने वाला कर (मद सख्या 7) अपेक्षाकृत ऊँची आय वाले सौदा करने वालों तक सीमित किया जा सकता है जैसा कि घातकर के अन्तर्गत घातकर के साथ होता है। अथवा हम विभिन्न किस्म के भेदों का मिश्रण कर सकते हैं, जैसा कि एक प्रारोही घातकर के अन्तर्गत (जिसमें बड़ी आमदनियों के विपक्ष में भेद किया जाता है) होता है, जो पूँजीगत लाभों पर अपेक्षाकृत नीची दरों की इजाजत देती है (और इस प्रकार अजित आय के विपक्ष में जाती है)। विश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं में समान आय वाले वर्गों के जोड़े अथवा समूह स्थापित किये जा सकते हैं जो कर-निर्धारण के आधार के रूप में भिन्न होने हैं, लेकिन वे करापात की दृष्टि से समान अवस्था लगभग एकल परिणाम देते हैं। यह विधेयक से तब सम्भव होता है जब कि हम करापात की परिभाषा वैयक्तिक दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से न करके आय के समूहों के अनुसार आय (कर के बाद क्षेत्र) के वितरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार करते हैं।<sup>12</sup> जैसे एक विभेदकारी वस्तु-कर जो समस्त सौदा करने वालों पर लागू होता है (उदाहरण के लिए, सिगरेटों पर बिस्की-कर) वह समस्त आय के साधनों पर लागू होने वाले घातकर के बराबर हो सकता है, लेकिन इस पर समाश्रयण-मान (Scale of regression) लागू होता है जो बजट के प्राक्षों में सिगरेट पर किये जाने वाले व्यय के भार के अनुरूप होता है। इसके विपरीत सभी सौदा करने वालों पर लागू होने वाले विभेदकारी वस्तु-कर को सभी सौदा करने वालों पर लागू होने वाले विभेदकारी साधन-कर के बराबर कर सक्ता कठिन या असम्भव होगा। हो सकता है कि कई दशाओं में यह मेल बैठे अथवा न बैठे। यह आय के प्राक्षों और घात के उपयोग के प्राक्षों के प्रचलित अन्तर्सम्बन्धों पर निर्भर करता है।

- 
12. जैसा कि प्रारम्भ में बतलाया गया है, वितरण में होने वाले परिवर्तन की हमारी परिभाषा में न केवल खर्च के योग्य मौद्रिक आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है, बल्कि खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया जाता है।

### बीमारी के निरोध तथा उपचार

सब तरह का गुनै विवेचन मातृश्रम मूल्यों एवं मातृश्रम के रूप में ही किया गया है। मध्यम वृद्ध मध्यमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। लेकिन सामाजिक अंग में करो के समाधानों में निरोध और मातृश्रम दोनों प्रकार के मूल्यों के परिवर्तन शामिल होते हैं। लेकिन यह एक ऐसी दुर्लभता है कि इसके कारण करारान्त के निदान में काफी भ्रम उत्पन्न हुआ है, और इसी वजह से सामाजिक तानों में करो के विवेचन में भी महत्व उत्पन्न हो गया है।

हमारे मध्यम उपचार के मातृश्रम में परिवर्तन-निदान को कार्यशील बनाया जा सकता है। यहाँ पर यह मानना उचित होगा कि मुद्रा की कुल पूर्ति सीधे की मुद्रा के रूप में होती है और मोटे की मुद्रा का भुगतान सामाजिक प्रचलन-वेग स्थिर रहता है। इन प्रकार मुद्रा की पूर्ति की एक ही हुई मात्रा भुगतान की उत कुल मात्रा को तय कर देती है जो किया जा सकता है। जब कल्पना की जाए की सरकारी सौदों में (करोँ अथवा सचों में) भुगतान का वही प्रचलन-वेग निहित होता है जो निजी भुगतानों में होता है अथवा इनके किसी निश्चित अनुपात में होता है। इससे हमें यह निर्धारित करने का अवसर मिल जायेगा कि बजट-नीति में परिवर्तन करने से निरोध बीमारी अथवा मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसे परिवर्तनों से भुगतान का ढाँचा विस्तृत होता है अथवा संकुचित होता है, जब कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, तो अपेक्षाकृत अधिक अथवा कम सौदों की व्यवस्था मुद्रा में भुगतान की उतनी ही मात्रा से होनी चाहिए। इसको सम्भव बनाने के लिए भुगतान की इकाई अथवा कीमत-स्तर को स्वयं की परिस्थिति के अनुसार बदलना होगा। यह सरल सिद्धान्त सारणी 2 में सामान्य करो के लिए और सारणी 3 में विभेदात्मक करो के लिए बतसाया गया है। दोनों ही दृष्टियों में यह मान लिया गया है कि समस्त सौदों के लिए सौदा प्रचलन-वेग (Transaction Velocity) 20 के बराबर होता है।

एक सामान्य कर के लिए हम एक वस्तु की अर्थ-व्यवस्था की कल्पना कर लेते हैं और निजी क्षेत्र पर समग्र रूप से विचार करते हैं। हम बॉलम संख्या 1 में प्रदर्शित बजट-पूर्व की स्थिति से प्रारम्भ करते हैं और बजट का समावेश करते हैं। यह बजट सरकार की कुल उत्पत्ति का लगभग 40 प्रतिशत खरीदने का अवसर देता है और इसकी वित्तीय व्यवस्था विभिन्न प्रकार के करो की जाती है। यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि सरकारी खरीद प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर होती है।



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१. मूल्य-वृद्धि का अनुमान	100.00	83.33	100.00	60.00	100.00	71.40	100.00	60.00
२. वर के रूप में मूल्य प्राप्ति	—	—	—	40.00	66.66	28.56	40.00	24.00
अन्तर्गत लेख								
10. आन्तर-व्ययिनी (हालत में)								
11. अन्तर-व्ययिनी के प्राप्ति	33.33	40.00	—	—	—	—	—	—
12. वर्ष (हालत में)				30.00	66.66	28.56	40.00	24.00
13. अन्तर-व्ययिनी (हालत में)	33.33	40.00	—	30.00	66.66	28.56	40.00	24.00
14. वर्ष की वर्ष-व्ययिनी	0.83	1.00	1.00	1.00	1.66	0.71	1.00	0.60
अन्तर्गत लेख	40	40	40	40	40	40	40	40
15. मूल्य-वृद्धि का अनुमान	100.00	83.33	100.00	100.00	166.66	100.00	140.00	84.00
16. अन्तर-व्ययिनी (हालत में)	200.00	200.00	240.00	200.00	333.33	200.00	280.00	168.00
17. अन्तर-व्ययिनी (वर्ष में)	1.00	0.83	1.00	1.00	1.66	1.00	1.40	0.84
18. मूल्य-वृद्धि का अनुमान	10.00	10.00	12.00	10.00	16.66	10.00	14.00	8.40
19. वर्ष की वर्ष-व्ययिनी	20	20	20	20	20	20	20	20

बौतम 1. स्वनः स्पष्ट है, गौदे का प्रचलन-वेग 20 माना गया है ।

बौतम 2. यह विम्व दशाओं मे निर्धारित होता है : (1)  $E=VM$ ; (2)  $E=W+Ti+P+G$ ; (3)  $Ti=G$ ; (4)  $P=W-Ti$ ; (5)  $G=40p$ ; और (6)  $G+P=100p$ , जहाँ  $E$ =कुल युगतान,  $M$ =मुद्रा की पूर्ति,  $W$ =मजदूरी का युगतान,  $Ti$ = आवश्यक युगतान,  $P$ =निजी खरीद के युगतान,  $G$ =सरकारी खरीद के युगतान, और  $p$ =प्रति इकाई कीमत ।  $M=\$10$  और  $V=20$ , के दिये हुए होने पर हम  $E, W, Ti, P, G$  और  $p$  को निर्धारित कर सकते हैं ।

बौतम 3. भी ऊर्ही दशाओं से निर्धारित होता है जिनमे बौतम 2 होता है लेकिन  $V=20$  और  $P=\$$  । दिया हुआ मानते हैं और  $E, W, Ti, P, G$  व  $M$  का पता लगाने ह ।

बौतम 4. जिन छतों मे निर्धारित होता है वे ये हैं : (1)  $E=VM$ ; (2)  $E=W+P+Ts+G$ ; (3)  $P=W$ ; (4)  $Ts=G$ ; (5)  $G=40p$ ; और (6)  $G+P=100p$ , जहाँ  $Ts$  निजी-कर का युगतान है ।  $M$  और  $V$  के दिये हुए होने पर हम  $E, W, Ts, P, G$  और  $p$  को हल कर सकते हैं ।

बौतम 5. के निर्धारण की सतें हम प्रकार हैं : (1)  $E=VM$ ; (2)  $E=W+P+Ts+G$ ; (3)  $W=P$ ; (4)  $Ts=G$ ; (5)  $G=40p$ ; (6)  $G+P=100p$ ; और (7)  $p=1+Ts/100$ .  $V=20$  दिये हुए होने पर, हम  $E, W, Ts, P, G, p$  और  $M$  का हल निकाल सकते हैं ।

बौतम 6. के निर्धारण की सतें हम प्रकार हैं : (1)  $E=VM$ , (2)  $E=W+P+Ts+G$ ; (3)  $W=P$ ; (4)  $Ts=G$ ; (5)  $G=40pg$ ; (6)  $P=60pg$ ; और (7)  $pg=pp-Ts/60$ , जहाँ  $pg$ =सरकार के द्वारा दी जाने वाली कीमत और  $pp$ =निजी केताओं के



जिस बजट में वित्तीय व्यवस्था एक सामान्य धायकर के जरिए होती है उसमें संतुलित बजट-करापात का मामला बालम 2 व 3 में प्रस्तुत किया गया है। बालम 2 में हम मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति (पंक्ति 18) स्थिर रहती है। इसीलिए मौद्रिक भुगतान का स्तर (पंक्ति 16) भी अपरिवर्तित रहना चाहिये। लेकिन भुगतान के ढांचे की अवधि बढ़ जाती है। पहले की भांति व्यवसाय अपनी सम्पूर्ण आय को मजदूरी के भुगतान में बांट देता है; और, पहले की भांति, मजदूरी की आय चुका दी जाती है। धायकर के भुगतान पहले की शरीर के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं। लेकिन सरकारी शरीर के भुगतान जोड़ दिये जाते हैं। चूंकि कुल मौद्रिक भुगतान ब्याप्यस्थिर रहते हैं हमनिये भुगतान की इकाई—साधन और वस्तु-मूल्यों के स्तर (पंक्ति 1 और 4) अवश्य गिरेंगे।<sup>13</sup> बालम (3) में हम यह मान लेते हैं कि कीमत-स्तर तो स्थिर रहेगा। इसका मास्य यह है कि मौद्रिक भुगतानों के स्तर (पंक्ति 16) में अवश्य वृद्धि होगी और मुद्रा की पूर्ति (पंक्ति 18) इसको सम्भव बनाने के लिए बढ़ाई जाती है।

अब हम यह बतलाना कर लेते हैं कि ऊर्ही शर्तों की वित्तीय व्यवस्था बिबी-नर से भी जाती है जो सरकारी व निजी शरीर पर समान रूप से लागू होगी है। बालम (4) में हम एक ऐसी स्थिति बतलते हैं जिनमें ऐसा कर साधनों के घटाये हुए भुगतानों में लग जाता है और वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। इस स्थिति में बजट का भीमलेश सौदा के ढांचे की अवधि नहीं बढ़ा देता है।<sup>14</sup> अनएक मूल्य-स्तर मुद्रा की पूर्ति के स्थिर रहने पर अपरिवर्तित बना रहता है। बालम (5) में हम एक ऐसी स्थिति बतलते हैं जिनमें कर के लागू होने पर भी साधनों का भुगतान ब्याप्यस्थिर बना रहता

13. यदि हम लोग की बजट मान लेते हैं तो एक भिन्न निष्कर्ष निकलेगा। इस स्थिति में धायकर के भुगतान मजदूरी के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं और सांबन्धित शरीर के भुगतान निजी शरीर के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं। भुगतान के ढांचे की अवधि लम्बी नहीं होती है और मुद्रा की स्थिर पूर्ति मूल्यों को अपरिवर्तित रहने देती है। परिणाम शरीर 2 के बालम 4 के समान ही होगा है।

14. यथे के द्वारा दिये जाने वाले बिबी-नर के भुगतान मजदूरी-भुगतान का स्थान ले लेते हैं और सांबन्धित शरीर के भुगतान निजी शरीर के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं। इसलिए, पूर्ण स्थिति।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

दी जाने वाली कीमत ।  $V=20$  और  $M=100$  के लिये हुए  $W, P, T, G, F, S$  और  $PP$  को प्रतिष्ठित करते हैं ।

घातों से निर्धारित होता है जिससे बर्तमान (6) होता है, किन्तु इसके कि पक्ष  $M$  द्वारा मुक्त नहीं है, और  $PG=1$ , एवं और जोड़ दी जाती है ।

म (7) के लक्ष्य से निर्धारित होता है, किन्तु इसके कि पक्ष (8)  $PP=1$ , होता है ।

जिस बजट में वित्तीय व्यवस्था एक सामान्य आयकर के जरिए होती है उसके संतुलित बजट-करापात का मामला कालम 2 व 3 में प्रस्तुत किया गया है। कालम 2 में हम मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति (पक्ति 18) स्थिर रहती है। इसीलिये मौद्रिक भुगतान का स्तर (पक्ति 16) भी अपरिवर्तित रहना चाहिये। लेकिन भुगतान के ढांचे की अवधि बढ़ जाती है। पहले की भांति व्यवसाय अपनी सम्पूर्ण आय को मजदूरी के भुगतान में बांट देता है; और, पहले की भांति, मजदूरी की आय चुका दी जाती है। आयकर के भुगतान पहले की खरीद के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं। लेकिन सरकारी खरीद के भुगतान जोड़ दिये जाते हैं। चूंकि कुल मौद्रिक भुगतान यथास्थिर रहते हैं, इसलिये भुगतान की इबाई—साधन और वस्तु-मूल्यों के स्तर (पक्ति 1 और 4) अवश्य गिरेये।<sup>13</sup> कालम (3) में हम यह मान लेते हैं कि कीमत-स्तर तो स्थिर रहेगा। इसका आशय यह है कि मौद्रिक भुगतानों के स्तर (पक्ति 16) में अवश्य वृद्धि होगी और मुद्रा की पूर्ति (पक्ति 18) इसको सम्भव बनाने के लिए बढ़ाई जाती है।

अब हम यह कल्पना कर लेते हैं कि उन्हीं तर्कों की वित्तीय व्यवस्था बिना-कर से की जाती है जो सरकारी व निजी खरीद पर समान रूप से लागू होती है। कालम (4) में हम एक ऐसी स्थिति दर्शाते हैं जिसमें ऐसा कर साधनों के घटाये हुए भुगतानों में लग जाता है और वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। इस स्थिति में बजट का योगक्षेप तौंदों के ढांचे की अवधि नहीं बढ़ा देता है।<sup>14</sup> अतएव मूल्य-स्तर मुद्रा की पूर्ति के स्थिर रहने पर अपरिवर्तित बना रहता है। कालम (5) में हम एक ऐसी स्थिति दर्शाते हैं जिसमें कर के लागू होने पर भी साधनों का भुगतान यथास्थिर बना रहता

13. यदि हम खरीद की दबाव मान लेते हैं तो एक भिन्न निष्कर्ष निश्चयेगा। इस स्थिति में आयकर के भुगतान मजदूरी के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं और सार्वजनिक खरीद के भुगतान निजी खरीद के भुगतानों का स्थान ले लेते हैं। भुगतान के ढांचे की अवधि सम्बन्धी नहीं होती है और मुद्रा की स्थिर पूर्ति मूल्यों को अपरिवर्तित रहने देती है। परिणाम सारणी 2 के कालम 4 के समुच्च ही होता है।

14. धर्म के द्वारा किये जाने वाले बिना-कर के भुगतान मजदूरी-भुगतान का स्थान ले लेते हैं और सार्वजनिक खरीद के भुगतानों का

है जबकि मनुष्यों की कीमतों में कम की गति के बराबर वृद्धि होती है। इन स्थिति में कम मनुष्यों में बढ़ोतरी होती है और मुद्रा की पूर्ति में भी घटाव वृद्धि की जाती है।

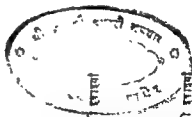
जब विधी-कर्म के बावजूद भी सरकारी महीन कम-मुद्रा बनी रहती है तो स्थिति घोररी भिन्न होती है। यहाँ तीन दशाओं सम्भव हो सकती हैं। सर्वप्रथम हम मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं। जैसा कि कानन (6) में दर्शाया गया है, हमका ध्यान यह है कि मापनों की कीमतें गिरती हैं, निजी कंपनियों के लिए कीमतों में वृद्धि होती है, माध्यमिक कंपनियों के लिए कीमतें गिरती हैं और योग्य कीमत-स्तर स्थापित बना रहता है। द्वितीय, हम मान लेते हैं कि निजी कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली कीमतों में कम की मापन के बराबर वृद्धि होती है जब कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली कीमतें स्थिर रहती हैं। तिसरम् (7) में दिखलाया गया है कि इससे मजदूरी अपरिचित बनी रहती है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होनी आवश्यक हो जाती है। अतः हम यह मान लेते हैं कि निजी कंपनियों के द्वारा बुलाई जाने वाली कीमतें स्थिर रहती हैं। चतुर्थ (8) में दिखाया गया है कि इससे सरकार के द्वारा बुलाई जाने वाली कीमतों में कमी, मजदूरी में गिरावट और द्रव्य की पूर्ति में सकुचन आ जाता है।

विभिन्न दशाओं की तुलना करने से भेदात्मक करापात का रूप स्पष्ट हो जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि निरपेक्ष कीमतों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तनों (अथवा इसके अभाव के) फल होते हैं। वास्तव में हमारे परिमाण-सिद्धान्त की मान्यताओं के फलस्वरूप ऐसा ही होना भी चाहिये। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, हम यह देखते हैं कि उत्पन्न होने वाला करापात निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच वास्तविक उत्पत्ति का बँटवारा, जो पक्ति (5) और (14) में दर्शाया गया है, सर्वथा एक-सा रहता है। विभेदात्मक करापात शटस्थ बना रहता है। यह परिणाम निरपेक्ष कीमत-परिवर्तन के भिन्न-भिन्न प्रारूपों के अंतरों से पूर्णतया अप्रभावित बना रहता है।

सारणी 3 में ऐसे ही समायोजन विभेदकारी करों के एक समूह के लिए दिखलाये गये हैं। इस उद्देश्य की दृष्टि से निजी क्षेत्र 'क' और 'ख' में विभाजित किया जाता है जहाँ 'क' "अ" वस्तु का और 'ख' "आ" का उपभोग करता है। परिस्थिति को सरल बनाने के लिए हम मानते हैं कि 'क' और 'ख' एक ही स्रोत से आय प्राप्त करते हैं और "अ" की प्रति इकाई उत्पादन-लागत समान रहती है।

सारणी 3  
भांनिक करों के मूल्य-समायोजन

कर से पूर्व	आधिक बाय-कर		आधिक विन्नी-कर (सरकारी खरीद कर-मुक्त)					
	मुद्रा की स्विर प्रति	(2)	स्विर बोमले	(3)	मुद्रा की स्विर प्रति	(4)	कर-मुक्त वस्तु का मूल्य स्विर (5)	कर लेगी हुई वस्तु का मूल्य स्विर (6)
उपभोक्ता-संज्ञ 'क'								
1. मजदूरी	50 00	41-66	50 00	35 70	50 00	10 00		
2. पायकर	—	33-33	40 00	—	—	—		
3. वय-भुगान	50 00	8-34	10 00	35 70	50 00	10 00		
4. 'घ' की बीम	1 00	0-83	1 00	3-57	5 00	1 00		
5. गरीदी गई 'घ' की हकाला	50	10	10	10	10	10		
उपभोक्ता-संज्ञ 'ख'								
6. मजदूरी	50 00	41-66	50 00	35-70	50 00	10 00		
7. वय-भुगान	50 00	41-66	50 00	35-70	50 00	10 00		
8. 'घा' की बीम	1 00	0-83	1 00	-71	1 00	0-20		
9. गरीदी गई 'घा' की हकाला	50	30	50	50	50	50		



पञ्च-श्रेष्ठ

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. 14वीं सेव की प्राप्ति	100-00	50-00	60-00	71-40	100-00	20-00
11. सांख्यिक सेव की प्राप्ति	—	33-33	40-00	28-56	40-00	8-00
12. मजदूर का भुगतान	100-00	83-33	100-00	71-40	100-00	20-00
13. कर से प्राप्त हुए	—	—	—	28-56	40-00	8-00
सकल सेव						
14. सावन्तर से प्राप्ति	—	33-33	40-00	—	—	—
15. उभावन-कर से प्राप्ति	—	—	—	28-56	40-00	8-00
16. मजदूर	—	33-33	40-00	28-56	40-00	8-00
17. तरीदी गई इकाइयाँ	—	40	40	40	40	40
सकल सेव						
18. कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति	100-00	83-33	100-00	200-00	140-00	28-00
G.N.P. (10+11) (सकल से)	200-00	200-00	240-00	200-00	280-00	56-00
19. कुल भुगतान, (सकल से)	1-00	0-83	1-00	1-00	1-40	0-28
20. कुल मजदूर, (सकल से)	10-00	10-00	12-00	10-00	14-00	2-80
21. कुल सेव, (सकल से)	20	20	20	20	20	20
22. कुल सेव, (सकल से)						

शेष है निरुद्ध है : भुक्ताना साखी 2 के नीचे ही है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा बटित है।

कालम (1) में हम सारणी 2 की बजट-पूर्व की स्थिति दोहराते हैं, लेकिन अब उपभोक्ता-क्षेत्र को क और ख में विभाजित कर देते हैं। पहले की भांति यहां भी बजट का समावेश कर दिया जाता है और सरकार की उत्पत्ति का 40 प्रतिशत खरीदती है। लेकिन अब सम्पूर्ण भार 'क' पर पड़ेगा। सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि सरकार अ-वस्तु खरीदना चाहती है, इस प्रकार 'क' के द्वारा मुक्त की जाने वाली इकाइया से लेती है।

क पर प्रांशिक रूप से आय-कर लगा कर भी सम्पूर्ण भार ढालने का कार्य पूरा किया जा सकता है। एक प्रांशिक आयकर से वित्त प्राप्त करने वाले बजट का सहूलित बजट करापात कालम (2) और (3) में दिखाया गया है। पहले की भांति, कालम (2) मुद्रा की स्थिर पूर्ति पर, और कालम (3) कीमत के स्थिर स्तर पर आधारित है। कीमतों एवं मुद्रा की पूर्ति में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन वैसे ही होते हैं जैसे कि सामान्य कर के होते हैं। अन्तर केवल इतना है कि अब सम्पूर्ण आयकर क से प्राप्त किया जाता है, जिससे ख की वास्तविक आय बजट से पूर्व की स्थिति के जैसी ही बनी रहती है।

वैकल्पिक रूप में, क पर कर-भार उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु 'घ' पर विक्री-कर लगा कर भी ढाला जा सकता है। यहां पर यह मान लिया जाता है कि सरकारी खरीद कर-मुक्त रहती है। परिणामस्वरूप "घ" का मूल्य "भा" की तुलना में बढ़ सकता है। पहले की भांति हम मुद्रा की स्थिर पूर्ति की मान्यता से प्रारम्भ करते हैं। यह कालम (4) में दिखाया गया है। विक्री-कर से वित्त प्राप्त करने वाले बजट को साफ करने से मजदूरी और "भा" की कीमत दोनों में गिरावट आती है जब कि "घ" की कीमत बढ़ती है। मौलिक रूप से कीमतें और भुगतान की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं। इसके पश्चात् हम "भा" की कीमत स्थिर कर लेते हैं। जैसा कि कालम (5) में दिखाया गया है, मजदूरी अपरिवर्तित रहती है, 'घ' वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कुल भुगतान की राशि और मुद्रा की

15. भूतपाठ के उद्देश्यों की दृष्टि से विवेचन बजट-करापात की भाषा में दिया गया है। प्रत्येक परिणाम की तुलना बिना बजट की स्थिति से की गई है। वैकल्पिक रूप में, कर की विभिन्न दशाओं के बीच भी तुलना की जा सकती है, जो विभेदात्मक करापात की भाषा में परिणाम देती है।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
४						
बी प्राप्तिदा	100-00	50-00	60-00	71-40	100-00	20-00
क्षेत्र की प्राप्तिदा	—	33-33	40-00	28-56	40-00	8-00
सुगमन	100-00	83-33	100-00	71-40	100-00	20-00
एक कुल प्राप्ति	—	—	—	28-56	40-00	8-00
मे प्राप्तिदा	—	33-33	40-00	—	—	—
क्षेत्र मे प्राप्तिदा	—	—	—	28-56	40-00	8-00
यदि दशादा	—	33-33	40-00	28-56	40-00	8-00
	—	40	40	40	40	40
अतः						
1) (मालरों में)	100-00	83-33	100-00	200-00	140-00	23-00
(मालरों में)	200-00	200-00	240-00	200-00	280-00	56-00
अतः	1-00	0-83	1-00	1-00	1-40	0-28
2) (मालरों में)	10-00	10-00	12-00	10-00	14-00	2-80
	20	20	20	20	20	20

1 गणना बारणी 2 के जैसी ही है, लेकिन उगले कुछ व्यापक अटिफ है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में यह भी सम्भव है कि परिणाम प्रारम्भिक समायोजन की दिशा से अप्रभावित न रहे।<sup>16</sup> यदि कर सगी हुई वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है और साधनों की लागत घटा दी जाती है तो सम्भव है कर-मुक्त वस्तुओं की कीमतें उनके अनुरूप नहीं घटें, क्योंकि लागत में होने वाली बचतों का कुछ घटा सम्भवतः एकाधिकारी मुनाफ़ों को बढ़ाने में लग जाय। बसली मजदूरी के परिवर्तनों से सामूहिक सौदाकारी पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कीमतों अथवा मजद मजदूरी का समावेश किया गया है अथवा नहीं, इत्यादि। ऐसी अटिस्तथाएं विशेषतया बाजार की उन दशाओं में उत्पन्न होती हैं जो पूर्णतया अधिकतम साम को तो व्यक्त नहीं करती हैं, लेकिन जहाँ नियन्त्रण लगाया जाता है, अथवा कीमत-उत्पत्ति की दशाओं में संशोधन करने के लिए एक विधम का चक्का-सा आवश्यक होता है।

साथ में यह भी स्मरण रखना होगा कि समायोजन की प्रक्रिया में समय लगता है, जिससे सापेक्ष कीमतों का प्रारम्भिक परिवर्तन बड़े महत्व का होता है। इन सब बातों से महत्वपूर्ण पर्याप्तताओं का समावेश हो जाता है, लेकिन वर्तमान विवेचन की दृष्टि से उनको छोड़ा जा सकता है।

### 11. पूँजी-निर्माण वाली अर्थव्यवस्था में करापात

अब हम दूसरे मॉडल को लेते हैं जिसमें बचत और पूँजी-निर्माण को शामिल किया जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए सरलता-वर्णन की मान्यता का त्याग कर दिया जाता है। पूर्ण रोजगार की आय में से होने वाली बचतें सर्व्व पूँजीगत वस्तुओं की खरीद में लगा दी जाती हैं और मीने की मुद्रा को छोड़ कर और कोई बनाया नहीं रखी जाती है। पहले की प्रांति बचत-नीति के परिवर्तन इस प्रणाली में शामिल कर दिये जाते हैं और हमें यह देखना होता है कि इससे उत्पन्न होने वाले समायोजन सम्पूर्ण-उदभोग के मॉडल से किन दशाओं में भिन्न होते हैं। विशेष रूप से हमें (1) सामान्य और विभेदकारी आयकर के समायोजनों की तुलना करनी चाहिये और (2) हमें इस बात की जाँच करनी चाहिये कि इस स्थिति में एक सामान्य आय-कर और एक सामान्य वस्तु-कर से क्या सम्बन्ध होता है।

16. उपभोग-व्ययन (Consumption function) में दीर्घक भ्रम होने पर भी ज्यादा अंतर पड़ सकता है।



## सागन व कीमन के सम्बन्ध

प्रारम्भ में हमें मन्त्रों में वर्णमान मौड़न में निहित सागन व कीमन के सम्बन्धों पर विचार करना चाहिये। पहले की भाँति हम यहाँ भी एक प्रतिस्पर्धात्मक मापन और वस्तु-बाजार को मान लेते हैं।

सरलता की दृष्टि से हम कल्पना कर लेते हैं कि पूँजीगत वस्तुएं धर्म के प्रयोग से बहुत सीधे उत्पादिता हो सकती हैं। तत्पश्चात् उन्हें उपभोग्य वस्तुओं के रूप में परिपक्व (ripen) का अवसर दिया जाता है। परिपक्व-प्रक्रिया के अंत में पूँजीगत वस्तु में अतिरिक्त धर्म की मात्रा "प्रत्यक्षता" जोड़ी जा सकती है, और उत्पादन जितना अधिक पूँजी-गहन होता जाता है "प्रत्यक्ष" धर्म की सागन कुल सागन की तुलना में उतनी ही कम होती जाती है। इस प्रणाली में अपरिपक्व पूँजीगत मास की सागन पूँजीगत वस्तुओं की उत्पादन करने की धर्म-सागन के बराबर होती है। उपभोग्य वस्तु की सागन पूँजी की धर्म-सागन और उस पर व्याज और साथ में उसमें प्रत्यक्षतः जोड़ी गई धर्म की सागन के बराबर होती है। साथ में यह भी है कि पूँजीगत वस्तु की कीमत उपभोग्य वस्तु के बड़ा कटे हुए मूल्य (discounted value) के बराबर होती है जिसमें प्रत्यक्ष धर्म-सागन<sup>17</sup> नहीं होती है। बदले में साधनों के अंश परिपक्व-प्रक्रिया (ripening process) के लिए आवश्यक धर्म की पूर्ति के लिए चुकाई जाने वाली मजदूरी और बचत की पूर्ति के लिए चुकाये जाने वाले व्याज के बीच विभाजित हो जाते हैं।

## सामान्य आयकर के द्वारा वित्तीय व्यवस्था वाला बजट

हम एक ऐसे बजट के संतुलित बजट-कराधान से प्रारम्भ करते हैं जिसकी वित्तीय व्यवस्था एक आनुपातिक आयकर से होती है। चूँकि यह एक सामान्य आयकर है, इसलिए यह दोनों साधनों (धर्म व कोषों की पूर्ति अथवा प्रतीक्षा) से प्राप्त आय पर समान रूप से लागू होता है। यदि हम यह मान लेते हैं कि दोनों साधनों की पूर्ति प्रतिफल की दर के परिवर्तित हो जाने पर भी बेतुल्य रहती है, तो बजट के समावेश से प्रारम्भ में साधनों की सगाई जाने वाली इकाइयाँ

17. जोखिम की बातों पर ध्यान न देने पर बड़े की दर वह आन्तरिक दर होती है जो मावी लाभदानी के वर्तमान मूल्य की सागन के बराबर कर देती है।

अपरिवर्तित बनी रहेंगी।<sup>18</sup> सीमान्त उत्पत्ति मर्यादास्थिर रहती है ठीक उसी तरह जैसे कि कर से पूर्व मजदूरी व व्याज के बीच घाट का बटवारा हुआ करता है।<sup>19</sup> मजदूरी पाने वाले और व्याज पाने वाले लोगों की संच के योग्य आमदनी में एत-सी कमी आती है। उपभोग-वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें भी अपरिवर्तित रहती हैं। ऐसी हालात में मजदूरी पाने वालों और व्याज पाने वालों की सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित बनी रहती हैं। बजट का करापात अनुपातिक ही निबलता है, और यहाँ तक परिणाम बही होता है जो सम्पूर्ण-उपभोग-मॉडल में पाया जाता है। लेकिन एक पूंजी-निर्माण के मॉडल में यह सम्पूर्ण बिच का एक अंग ही माना जा सकता है। साधनों की सापेक्ष मात्राएँ एक अवधि में अपरिवर्तित नहीं रहती हैं। बजट के समावेश से निजी उपभोग के लिए उपलब्ध होने वाली धन्य घट जाती है और इसी कारण से बचतों की निजी पूर्ति भी घट जाती है। यदि हम यह मान लेते हैं कि व्याज के परिवर्तन से बचतों की पूर्ति बेतोष रहती है तो भी यही स्थिति रहेगी (यदि हम क्लासिकल सदमे में केस की सम्भावना का उपयोग करें तो) हमें केवल यही मानने की आवश्यकता रह जाती है कि संच के योग्य आमदनी में से किये जाने वाले उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति घनात्मक (positive) होती है। यह मानने पर कि सार्वजनिक संच उपभोग्य वस्तुओं पर किया जाता है, बजट के समावेश से पूंजी-निर्माण की दर में कमी आ जाती है।<sup>20</sup>

यदि पूंजी-संचय घटता है तो पूंजीगत स्टॉक और कुल उत्पत्ति भागी समय में कम हो जायेंगे। यहाँ पर पूंजी किसी अन्य स्थिति की अपेक्षा धन्य की तुलना में ज्यादा दुर्लभ होती है। परिणामस्वरूप व्याज की दर अपेक्षावृद्ध

18. यदि मूलभूत के घटने वीरा से वसिष्ठ दीर्घकामीन बहुमुखों पर बिचार न भी करें तो भी यदि साधनों की पूर्ति लोचदार होनी है तो विभिन्न साधनों की पूर्ति की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो जायगा। जैसा कि हमने मर्याद उपभोग के मॉडल के विवेचन में बताया है, अधिक लोचदार साधन की पूर्ति करने वालों की सापेक्ष स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति होती है। इसलिए नीचे फुटनोट संख्या 24।

19. हम यह सरल धारणा भी स्वीकार कर लेते हैं कि अधिक और कम पूंजी-धन बाणुओं के बीच बाँट का प्रारूप नहीं बदलता है।

20. यदि सरकार पूंजीगत वस्तुओं पर कर करती है तो हमारे संच का दम ही कम होगा है, लेकिन निदान बही रहता है।

ऊँची होती है और ध्यान न भ्रष्टाचारी के बीच साधनों के भागों का बंटवारा व  
 रिगनि की गुणना से भिन्न पाया जाता है जब कि बजट नहीं होता है। धृ  
 ध्यान की दर धन ऊँची होती है, इगनिष्ट पूँजीगत वस्तुओं की कीमत उन्मी  
 वस्तुओं की गुणना में भीची होती है। पूँजीगत स्टॉक के परिवर्तन से उत्पन्न  
 होने वाले ये दीर्घकालीन समायोजन हमारे इन अज्ञातमोच निष्कर्षों की बदल  
 देते कि बजट का धारण धातुपानिक होगा। लेकिन यह आभासी से न  
 बतलाया जा सकता कि किमकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी।<sup>21</sup>

### विभेदकारी आय-कर का प्रतिस्थापन

अब हम उस अन्तरजनित आयान (Differential incidence) का  
 वर्णन करते हैं जो सामान्य कर के स्थान पर विभेदकारी आयकर के प्रति-  
 स्थापित करने से उत्पन्न होता है।

मान लीजिए, सामान्य आय-कर की जगह उतनी ही आय देने वाला  
 एक ऐसा आयकर लगा दिया जाता है जो समस्त साधनों की आय पर लागू  
 होता है लेकिन जो कुछ उपयोगों (उद्योगों) के रोजगार तक ही सीमित रहता  
 है।

यहां हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण और परिचित अंतर उपस्थित होता  
 है जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन आयान (incidence) के बीच पाया जाता  
 है। अल्पकाल में विशेष उपयोगों में पूँजी की पूर्ति काफी बेलाच होती है।  
 इसी तरह श्रम की पूर्ति की सोच सामान्य बाजारों की अपेक्षा अधिक बाजारों  
 में अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर समय का तत्व कम प्रबल होता है। इससे  
 कुछ परिचित से निष्कर्ष निकलते हैं जिन पर यहाँ विस्तार से लिखने की  
 आवश्यकता नहीं है।

2. द्वितीय, मान लीजिए, एक सामान्य आयकर की जगह एक ऐसा  
 विभेदकारी आयकर लगा दिया जाता है जो समस्त उद्योगों तक फैला दिया  
 जाता है लेकिन जिसके अन्तर्गत व्याज की आय ही जाती है। यह मामला  
 हमारे बाद के विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, जब कि हम पूँजी-  
 गत वस्तुओं पर लगाये जाने वाले वस्तु-कर की चर्चा करेंगे।

21. देखिए J.R. Hicks "Distribution and Economic Progress : A  
 Revised Version," *Review of Economic Studies*, IV (1936-  
 37).

पुनः कल्पना कीजिए कि बचतों की पूर्ति प्रतिफल की दर के परिवर्तन पर बेलोच बनी रहती है। इस स्थिति में साधनों की मात्राएं अपरिवर्तित रहती हैं।<sup>22</sup> उपभोग्य व पूंजीगत वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं, जैसे कि कर से पूर्व मजदूरी व व्याज की भाव्य रहती है। लेकिन कर के पश्चात् मजदूरी की भाव्य, कर के पश्चात् होने वाली व्याज की भाव्य की तुलना में बढ़ जाती है। चूंकि व्याज से प्राप्त आय कुल पारिवारिक भाव्य के प्रतिशत के रूप में बढ़ती है और मजदूरी की भाव्य आमदनी के पैमाने पर ऊपर चढ़ने समय घटती है, इसलिए हमारा यह निष्कर्ष होगा कि कर-प्रतिस्थापन का अन्तर-जनित घापात (differential incidence) बबरोही होगा।

इस तुलना का सम्बन्ध उन परिवर्तनों से होता है जो भाव्य के पैमाने में विभिन्न बिन्दुओं पर विवेक व्यक्तियों की भाव्य की दत्ता में हुआ करते हैं। लेकिन अब हम विभिन्न व्यक्तियों के बीच की तुलना आय के एक ही स्तर पर करेंगे। यदि हम समस्त व्यक्तियों को "क" श्रेणी (जिसमें वे व्यक्ति आते हैं जो केवल मजदूरी की भाव्य प्राप्त करते हैं और सारी उपभोग पर व्यय कर देते हैं) और "ख" श्रेणी (जिसमें वे व्यक्ति आते हैं जो केवल व्याज की भाव्य प्राप्त करते हैं और इसमें से सारी बचा लेते हैं) में विभाजित कर सकें, तो समस्या अपेक्षाकृत आसान हो जायेगी। इस स्थिति में आंशिक कर का प्रतिस्थापन स्पष्टतया 'क'-समूह के पक्ष में जायेगा और सम्पूर्ण भार 'ख'-समूह पर पड़ेगा।

परिस्थिति उस समय कम स्पष्ट होती है जब कि हम 'ग' श्रेणी के लोगों (जो अधिकतर मजदूरी से भाव्य प्राप्त करते हैं, लेकिन बाकी बचत करते हैं) और 'घ' श्रेणी के लोगों (जिनकी भाव्य ज्यादातर व्याज से होती है, लेकिन जो सारी भाव्य में उपभोग करने हैं) की दत्ताओं की तुलना करते हैं। भाव्य की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन का भार यह बनना है कि बरों के प्रतिस्थापन से ग को लाभ पहुंचता है और ख को हानि होती है,

22. दीर्घकालीन दृष्टिकोण से हमारी भी एक मर्मांत हो सकती है, और वह यह है कि समाज की बचत करने की प्रवृत्ति, और फलस्वरूप पूंजी-निर्माण की दर, कर-प्रतिस्थापन से प्रभावित हो सकती है। ऐसा सम्भव होता है कि या तो बचत विपुल प्रतिफल (कर के पश्चात्) के परिवर्तन पर मोहदार होनी है, अथवा (भाव्य के बिनी भी हिंदे हुए स्तर पर) बचत की प्रवृत्ति व्याज से प्राप्त आय के बिनी दत्त से घुटी हुई होती है।

किर भी यह परिणाम केवल माताशक्ति का मेरी स्पष्ट प्रतीक होगा है। दीर्घ-कालीन दृष्टि से यह विमर्शपूर्ण स्पष्ट नहीं होता है कि, चुनाव का प्रचलन स्थिति जाने पर, एक सामान्य आयकर की जगह ब्याज पर कर का प्रतिस्थापन स्थिति जाने पर 'ग' उगता समर्थन करे और 'घ' उगता विरोध करे। प्रगत में ग तो तब की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। यह भावी वर्षों में ब्याज पर ऊंचे कर के कारण ज्यादा धनि उठाना रहेगा। दूसरी तरफ घ बचन में से घट कर सकता है और इस प्रकार क की स्थिति की तरफ जा सकता है। यदि ऐसा होगा तो ब्याज पर कर लगने से उस पर उत्तरोत्तर कम भार पड़ेगा। इस तरह से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि यह अच्छा होगा कि आपात की धारणा का सम्बन्ध एक विशेष अवधि से ही किया जाय। य को अल्पकाल में लागू हो सक्ता है, लेकिन दीर्घकाल में हानि हो सकती है और घ के लिए हमारे विपरीत होगा। ■

### उपभोग्य वस्तुओं पर सामान्य कर

अब हम उपभोग्य वस्तुओं के सौदों पर लगाये जाने वाले एक सामान्य कर पर आते हैं जो एक सामान्य विक्री-कर कहलाता है और एक सामान्य आयकर की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है। इस विषय की चर्चा ■ हमें दो समस्याओं के बीच स्पष्टतया अंतर करना होया अन्यथा अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हो जायगा।<sup>10</sup> पहली समस्या तो यह है कि एक आनुपातिक आयकर से

23. दूसरे शब्दों में हम ग और घ पर डाले गये भावी कर-भारों के वर्तमान मूल्यों की तुलना सम्बन्धित करों से कर सकते हैं। ये मूल्य ग और घ की भावी बजट-योजनाओं पर निर्भर करते हैं।
24. मेरे पूर्व लेख (देखिये ऊपर का फुटनोट संख्या 2) के दूसरे भाग में मैं इस अंतर के विशेष महत्त्व से परिचित नहीं था। वास्तव में समस्या नं० 1 व नं० 2 में अंतर न करने के कारण ही व्याख्या में एक त्रुटि रह गई थी जिसे यहां ठीक किया जाना चाहिए। मेरा पूर्व निष्कर्ष यह था कि आयकर के स्थान पर उपभोग्य वस्तुओं पर विक्री-कर लगा देने के परिणाम साधनों की सोचों पर निर्भर करते हैं, यदि बचतों की पूर्ति घसीमित रूप से सोचदार होती ■ तो भार अधिक पर पड़ेगा और यदि भ्रम की पूर्ति पूर्णतया सोचदार होती है तो भार ब्याज प्राप्त करने वाले पर पड़ेगा। यह निष्कर्ष दो अवस्थाओं में प्राप्त किया गया था। पहली अवस्था में तो यह तर्क दिया गया था कि आनुपातिक आयकर के

वित्त प्राप्त करने वाले बजट का निरपेक्ष बजट-आपात मालूम किया जाय। इसके बाद दूसरी समस्या यह है कि धानुपातिक आयकर की जगह एक विक्री-कर के प्रतिस्थापित नये जाने पर आपात कैसे परिवर्तित होता है, इसका पता लगाया जाय। प्रथम समस्या का विवेचन पहले किया जा चुका है। अब हम यह कल्पना कर लेते हैं कि साधनों की पूर्ति प्रतिफल की दर के परिवर्तन पर बेलाञ्छ बनी रहती है ताकि कम से कम अल्पकाल में तो आयकर से वित्त प्राप्त बजट का आपात आनुपातिक होगा, अर्थात् यह आय की सापेक्ष दशाओं को अपरिवर्तित रहने देगा। इस समय हमारा सम्बन्ध दूसरी समस्या से ही है।

अब मान लीजिये कि एक सामान्य आयकर के स्थान पर उपभोग्य वस्तुओं पर एक सामान्य विक्री-कर प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसी स्थिति में परम्परागत निष्कर्ष यह होगा कि यह प्रतिस्थापन उनको तो मुक्त कर देता है जो बचाते हैं और सारा भार उपभोक्ताओं पर ही डाल देता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि जब उपभोग्य वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो ऐसी वस्तुओं की कीमतों में कर की राशि के बराबर वृद्धि हो जाती है और

हटा देने से सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित रहती हैं। दूसरी अवस्था में यह तर्क दिया गया था कि विक्री-कर के लागू होने से सापेक्ष दशाएँ बदल जायेंगी और यह साधनों की सोचों पर निर्भर करेगा।

इस तर्क में इस तथ्य को भुला दिया गया है कि, विभिन्न सोच-वाली साधनों की पूर्तियों के दिये हुए होने पर, आय-कर के हटा देने से सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित नहीं रह जायेंगी। प्राप्त निष्कर्ष में जो एक विपरीत मान्यता पर आधारित था, वास्तव में उस विभेदात्मक करापात का वर्णन नहीं किया गया जो आयकर के स्थान पर विक्री-कर के लागू होने से उत्पन्न होता है। इसके बजाय इसने विक्री-कर के निरपेक्ष आपात (absolute incidence) के जैसी किसी चीज का वर्णन किया; यहाँ आयकर के हटाने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इसे वितरणात्मक दृष्टि से तटस्थ माना गया था।

वर्तमान लेख में समस्या नं० 1 और नं० 2, जैसी कि वे मूलपाठ में प्रस्तुत की गई हैं, में ध्यानपूर्वक अंतर करके मैं इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करूँगा। पूर्व तर्क की सुधारी हुई व्याख्या—कि विक्री कर का निरपेक्ष आपात साधनों की पूर्ति-सम्बन्धी सोचों पर निर्भर

गिनिए कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। हालाँकि यह निष्कर्ष तो ज़ा-मुह सही है, लेकिन हम तर्क में दो दोष हैं। सर्वप्रथम, हम यह निश्चय-कि नहीं कह सकते कि उपभोग्य वस्तुओं की कीमते बढ़ जायेंगी। यह भी सकता है कि उपभोग्य-वस्तुओं की कीमते अपरिवर्तित रहें, जब कि साधनों। दिये जाने वाले सागत-सम्बन्धी भुगतान घट जाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला परिणाम मौद्रिक गतिशीलताओं पर निर्भर करता है।<sup>15</sup> द्वितीय यह मानने हुए कि कीमतों में वृद्धि होगी, हम इससे आपात के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निष्कर्ष निकाल सकते। ता कि ऊपर दर्शाया गया है, आपात तो सापेक्ष कीमत में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है, और ये परिवर्तन निरपेक्ष कीमतों अथवा कीमत-तराई के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं।

पहले दोष का पता कई वर्ष पूर्व गुनोसन ब्राउन ने लगाया था और जहाँ ही में थर्ल रोल्फ ने अपने एक महत्वपूर्ण लेख में उस पर धारा विचार दिया है।<sup>16</sup> दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर लगी हुई वस्तुओं

करता है—हमारे वर्तमान तर्क से पूर्णतया मेल खाती है जिसमें यह बतलाया गया है कि (अ) आयकर से वित्त प्राप्त बजट का निरपेक्ष आपात साधनों की लोचों पर निर्भर करता है और (आ) आयकर की जगह एक विक्री-कर के प्रतिस्थापन का परिणाम मूलपाठ के विवेचन में वर्णित बातों पर ही निर्भर करता है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, और यह भी वर्तमान विधि से मेल खाता है, यह होया कि पहले विक्री-कर से वित्त प्राप्त करने वाले बजट का निरपेक्ष आपात निर्धारित किया जाय और तत्पश्चात् आयकर के प्रतिस्थापन की तरफ बढ़ा जाय।

15. वर्तमान मॉडल सम्पूर्ण-उपभोग्य-मॉडल के जैसा ही है, क्योंकि कोई एक बकाया नहीं रखी जाती है। दोनों दशाओं में मुद्रा की पूर्ति, कुल भुगतान और कीमत स्तर के पारस्परिक सम्बन्ध एक से ही रहते हैं। ऊपर तालिका 2 और 3 में बतलाया गया सिद्धांत दोनों मॉडलों में लागू होता है।

16. देखिए Earl R. Rolph, "A Proposed Revision of Excise Tax Theory," *Journal of Political Economy*, LX, No. 2 (April, 1952), 102-17, and Harry Gunnison Brown, "The Incidence of a General output or a General Sales Tax," *Journal of Political Economy*, XLVII, No. 2 (April, 1939), 254-63.

कीमतों का बढ़ना आवश्यक नहीं है। वास्तव में वे तो और भी आगे बढ़ जाते हैं और यह मानते हैं कि समायोजन तो स्थिर कीमतों और घटे साधन-भुगतानों में होना चाहिये।<sup>37</sup>

लेकिन यह एक साधारण-सी बात है। यदि मैं इस समस्या को सही में समझ पाया हूँ तो मेरी राय में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वाउन-क की स्थिति में अभी भी एक दूसरा दोष रह गया है—इसका ध्यान है कि कर उपभोक्ता पर नहीं पड़ता है और यह आपात की दृष्टि से धानुपातिक आयकर के समान ही है क्योंकि प्रारम्भिक समायोजन साधनों-भुगतानों में कमी का रूप ले लेता है। यह निष्कर्ष स्वतः नहीं निकलता यह माग्यता कि साधनों के भुगतान घटा दिये जाते हैं इस बात को नहीं करती है कि कर सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, उसी प्रकार से जैसे की कीमतों की वृद्धि की परम्परागत माग्यता यह नहीं करती है कि कर केवल उपभोक्ता पर ही पड़ता है। समायोजन इस आपात को निर्धारित नहीं करती है और इसे ही आपात नहीं समझ चाहिए।

हमें उपर्युक्त बात को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर पुन विचार चाहिए। उपभोग्य वस्तुओं की कीमत उन उत्पादन के साधनों को जाने वाले लागत-भुगतानों के बराबर होती है जो इन वस्तुओं के निर्माण में लगाये जाते हैं। अतएव यहाँ पर कर लागत-सम्बन्धी-भुगतानों पर पड़ना कर माना जा सकता है। हमारे पूर्व तर्कों के अनुसार समस्त-भुगतानों पर लगाया जाने वाला कर समस्त साधनों की आय पर पड़ने वाले कर के समुदाय होता है। जब एक कर की जगह दूसरा कर प्रतिष्ठ किया जाता है, तो हम केवल साधनों की आय और तर्कों के बीच के बीच की सार्द को पाट देते हैं, और इसकी जगह तर्कों की ओर साधनों के भुगतानों के बीच बँसी ही सार्द बना है। दोनों

यह निष्कर्ष विपुल प्रतियोगिता की माग्यता के आधार पर निजाना जाता है, लेकिन बाजार की अनुरणताओं का समावेश करने पर सम्भवतया यह लागू न भी हो। लेकिन यदि हम इस तरह से तर्क करना चाहते हैं कि अन्तिम जन मोटिव नीति के बजाय मुख्य-निर्धारण का परिणाम होता है तो हम अपने मॉडल पर चले जाते हैं जहाँ सरलता अधिमान पर पदों पर ध्यान दिया जाता है।





मौद्रिक धाय स्थिर बनी रहती है।<sup>29</sup> यदि हम यह मान लेते हैं कि उपभोग्य वस्तुओं की निरपेक्ष कीमत अपरिवर्तित रहती है तो हम देखते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं की कीमत उसी तरह से गिरेगी जैसे कि ब्याज व मजदूरी पाने वालों की खर्च के योग्य मौद्रिक धाय गिरती है।<sup>30</sup> दोनों ही स्थितियों में सापेक्ष दशाओं में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिणाम एक-से होते हैं।

अब हम ब्याख्या के तौर पर एक दूसरे समायोजन पर विचार करेंगे जिसमें पूंजीगत वस्तुओं की कीमत के घटने पर खर्च के योग्य मौद्रिक धाय अपरिवर्तित रहती है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि (अ) खर्च के योग्य मौद्रिक धाय के रूप में सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित रहती हैं, (आ) यदि उपभोक्ताओं और बचत करने वालों की आमदनी वा समान रूप से एक से कीमत सूचना के अपरस्फीतीकरण किया जाता है तो खर्च के योग्य वास्तविक धाय के रूप में सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित बनी रहती हैं, और (इ) यदि हम उपभोक्ताओं की आमदनी वा उपभोग्य अथवा पूंजी-वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अपस्फीतीकरण कर देते हैं तो वे बचतकर्ताओं से ज्यादा क्षति उठाते हैं (यह इस पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन-सी वस्तुएँ किस तम में लचीली जाती हैं)। यदि हम (आ) ब्याख्या को चुनते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि एक धानुपातिक आयकर और उपभोग्य वस्तुओं पर सामान्य कर घापात की दृष्टि से सामान होते हैं। यदि हम (इ) ब्याख्या को चुनते हैं तो हमारा निष्कर्ष यह होगा कि दूसरा कर उपभोक्ता पर पड़ता है।<sup>31</sup> चूंकि

29. साधनों के भुगतान डालर में अपरिवर्तित बने रहते हैं जिससे मजदूरी व ब्याज की धाय स्थिर रहती है। आयकर के हटाये जाने पर मजदूरी व ब्याज के पाने वालों की खर्च के योग्य धाय में एक-सी दर से वृद्धि होती है। (चूंकि साधनों की पूर्ति बेतौष होती जाती है, इसलिए इस स्थिति में आयकर के हटाने से धाय में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। देखिए ऊपर फुटनोट 24) मजदूरी की दर और परिणाम-स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

30. साधनों के भुगतानों व धाय में कर की मात्रा के बराबर कमी आ जाती है, लेकिन आयकर के हटा देने से डालर में खर्च के योग्य धाय अपरिवर्तित रह जाती है। जब मजदूरी की दर के घटने पर पूंजीगत वस्तुओं की बाजार-कीमत गिरती है।

31. हमारे लिए यहाँ उपभोक्ताओं व बचतकर्ताओं की धाय के खर्चों के समन्वय के बरतना आवश्यक नहीं है, जैसा कि विधेयकारी आयकर के माध्यम में

आय के पैमाने पर (Income-scale) ऊपर जाने से आय के घंसे के स्तर पर उपभोग घटता है, इसलिए इसका आभाव यह है कि विभेदकारी घात (Differential incidence) अवरोही ही होगा।

सम्पूर्ण-उपभोग के मॉडल में स्पष्टतः (इ) ही सही दृष्टिकोण बत जायगा। चूंकि सम्पूर्ण आय उपभोग में लगा दी जाती है, इसलिए बाकी सापेक्ष आय की दशाओं को केवल खास उपभोग के माध्यम से ही परिचित किया जा सकता है। अब हम आय के दो सम्भावित घातों के बीच चुनाव कर सकते हैं—इनमें एक घात तो सम्भाव्य उपयोग की शक्ति के रूप में घन का रूप है, और दूसरा खरीदी गई वस्तुओं, चाहे वे उपभोग्य वस्तुएं हों या बचत वस्तुएं हों, के रूप में घन का संचय है।<sup>32</sup> यदि हम पहली धारणा का चुनाव करते हैं तो उपभोक्ताओं और बचतकर्ताओं दोनों की आय का स्तर से उपभोग्य वस्तुओं की कीमत के अनुसार अपस्फीतीकरण होना चाहिए जो हमारे दोनों करों में कराधान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होगा।<sup>33</sup> यदि हम दूसरी धारणा का चुनाव करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उपभोग्य वस्तुओं का कर उपभोक्ता पर पड़ता है।

दोनों धारणाओं के बीच का चुनाव, आय के अधिभाग करने की भाँति, अनिवार्यतः एक सामाजिक दर्शन का विषय है, न कि निष्पक्ष भेदिक जैसा कि मुझे लगता है, दूसरे दृष्टिकोण के पक्ष में बायीं चुनाव का गबना है। यदि हम सम्भाव्य उपभोग की धारणा को स्वीकार करते हैं तो हमारा आभाव यह होता है कि यह ओम्स के लिए तटस्थता का अर्थ

करना आवश्यक था। अब यह जरूरी नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रदान होने वाली वस्तुओं के योग्य सापेक्ष आय अपरिवर्तित रहने से ही यह है। अब हम दीर्घकालीन व्याख्या की उन कठिनाइयों में नहीं जाते हैं जो व्यापक की आय पर एक विभेदकारी कर के सम्बन्ध में देखी गई हैं। हालाँकि वस्तुमान आय के उपयोगों व भावी आय के स्रोतों में एक अंतर करने-कारण का सम्बन्ध हुआ करता है, भेदिक ऐसा कोई स्पष्ट अंतर विवेचन दिया न नहीं देना गया है।

32. बचत बचाव के रूप में हो।

33. ऐसा दीर्घकालीन बर्तनों को ध्यान में रखते हुए होता है कि इन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है।

(Indifference) की स्थिति है, जोन्स अपनी धाय का एक बड़ा भाग बचाता है, चाहे एक सामान्य धाय-कर की जगह उपभोग्य वस्तुओं पर कर का प्रतिस्थापन किया जाय ।<sup>34</sup> लेकिन इससे जोन्स के लिए अपना पहले का उपभोग का स्तर बायम रखना सम्भव हो जाता है और वह अधिक पूजीगत वस्तुओं का भी संग्रह कर पाता है । वास्तव में इस संग्रह का सम्भाव्य उपभोग मूल्य प्रारम्भ में नहीं बढ़ाया जाता है । लेकिन धन का खर्च कुछ सन्तुष्टि देता है; इसके अलावा, व्यवहार और फलस्वरूप, कर का भुगतान शायद कभी न हो पाये । जैसा भी हो, कर का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है और इस पर व्याज अर्जित किया जा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह वाद का पहला एक असली लाभ है जो धाय की धारणाओं की बहस से भी परे है । इसके अलावा सम्भाव्य उपभोग की धारणा का आशय यह है कि स्मिथ के लिए (जो अपनी सम्पूर्ण आय उपभोग में लगाता है) यह एक तटस्थता की स्थिति है, चाहे धाय-कर के स्थान पर उपभोग्य वस्तुओं पर कर का प्रतिस्थापन कर दिया जाय । लेकिन स्मिथ की कर से पहले की अपेक्षा कर के बाद कम उपभोग्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं और उसे ऐसा प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि उसकी स्थिति पहले से खराब हो गई है ।<sup>35</sup> कुल मिला कर मुझे यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि कर उपभोक्ता पर पड़ता है ।<sup>36</sup>

- 
34. पाठक के लिए धायद इस तरह से सोचना उपयुक्त हो कि एक सामान्य धायकर एक सामान्य खर्च-कर (उपभोग्य अथवा पूजीगत वस्तुओं की खरीद पर) की भाँति होता है, ताकि उपभोग्य वस्तुओं पर कर का प्रतिस्थापन (जो उपभोग्य वस्तुओं के ध्येय पर कर के समान होता है) खर्च-कर से पूजीगत वस्तुओं की खरीद को मुक्त करने के बराबर होता है ।
35. मान लीजिए कि क अपनी सम्पूर्ण धाय का उपभोग करता है ख उसको बचा लेता है । सम्भाव्य उपभोग की धारणा के अनुसार सापेक्ष दशाएँ अपरिवर्तित रहती हैं । दोनों की वास्तविक धाय की स्थिति (सम्भाव्य उपभोग के रूप में) एक ही दर से खराब हुई है, क्योंकि दोनों की खर्च के योग्य अपरिवर्तित धाय का अपेक्षाकृत उपभोक्ता-मान के ऊँचे मूल्यों से अपस्फीतीकरण हुआ है । मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई तार नहीं निश्चलता है ।
36. इन दोनों व्याख्याओं के बीच में चिया जाने वाला चुनाव अनिवार्यतः उन्हीं बातों पर घा जाता है जो बचन-सम्बन्धी बहस के पुराने दोहरे-

उत्पत्तिकालीन परिणाम की हमारी व्याख्या जैसी भी हो, यह तो स्पष्ट है कि उपभोग्य वस्तुओं पर कर के प्रतिस्थापन से कुछ समय बाद साधन उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में हस्तान्तरित होने लगेंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि अब बचतकर्ता अपनी बचत के बढ़ने में अधिक पूंजीगत वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जब कि उपभोक्ता कम उद्योग वस्तुएं प्राप्त करते हैं। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त होने वाला बचन पर बढ़ा हुआ प्रतिफल बचत की पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। ज्योंही पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि की जाती है त्योंही आय के स्रोतों और उपयोगों दोनों के सम्बन्ध में सापेक्ष दगाधों में अधिक परिवर्तन घायेंगे। इसके द्वि-द्रीय परिणाम जो भी हों, यह तो स्पष्ट है कि एक कर की जगह दूसरे के प्रतिस्थापित किये जाने पर स्थिति पहले जैसी नहीं रहती है।

### पूंजीगत वस्तुओं पर सामान्य कर

अंत में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि एक सामान्य आय-कर की जगह पूंजीगत वस्तुओं के स्रोतों पर कर लगा दिया जाता है तो क्या परिणाम निकलेंगे।<sup>37</sup>

हम कुछ समय के लिए यह मान लेते हैं कि हमारे प्रतिस्थापन के बादगूर भी धन व बचन की पूर्ति अपरिवर्तित बनी रहती है। उपभोग्य वस्तुओं की बिज्जी से प्राप्त धनराशि प्रत्यक्ष धन की मात्रा के भुगतान एवं पूंजीगत वस्तुओं के भुगतान के बीच पहले के जैसे अनुपातों में ही विभाजित हो जाती है। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से का एक भाग इन पर लगे कर का भुगतान करने में खसा जाता है। ऐसा करने पर पूंजीगत वस्तुओं में लगाई गई धन की मात्रा और बचत की पूर्ति करने वालों को देने के लिए धनि कम ही बच रहती है। पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त धन के प्रतिपन की दर पड़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन

कराधान में निहित है। देखिए "Double Taxation of Savings" in the American Economic Review, September, 1939 में मेरा नोट।

37. हमारे उद्देश्य के लिए विवेचन का मैं यह स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है कि कर प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में पूर्ण निर्धारित किया जाता है यद्यपि हमें पदबद्ध।

में लगे हुए प्रत्यक्ष धन की मात्रा के लिए दो जाने वाली राशि के बरोबर  
 हुआ करती है। इसलिए कर कोषों की पूर्ति करने वालों को कम भुगतान  
 करने में लगाया जाना चाहिए।<sup>38</sup> ब्याज से प्राप्त आय मजदूरी से प्राप्त  
 आय की तुलना में घटती है। मजदूरी पाने वालों और ब्याज पाने वालों  
 दोनों को आयकर के हटने से समान रूप से लाभ होता है, ताकि कुल मिलाकर  
 ब्याज पाने वालों की खर्च के योग्य आय मजदूरी पाने वालों की तुलना में  
 घटती है। हम जानते हैं कि यह परिणाम ब्याज की आय पर लगे विभेदकारी  
 कर जैसा ही होता है।

पूँजीगत वस्तुएं (अपरिवर्त) की विद्युत् कीमत उपभोग्य वस्तुओं की  
 तुलना में अपरिवर्तित रहती हैं, जैसी कि यह ब्याज की आय पर लगे एक  
 विभेदकारी कर के सम्बन्ध में थी। (अपरिवर्त) पूँजीगत वस्तुओं की विद्युत्  
 कीमत मजदूरी की दर से निर्धारित होती है, और उपभोग्य वस्तुओं में लगाई  
 गई प्रत्यक्ष धन की मात्रा की लागत की तुलना में अपरिवर्तित बनी रहती  
 है। लेकिन उपभोग्य वस्तुओं की कुल लागत (अथवा कीमत) के घटा के रूप में  
 प्रत्यक्ष धन की लागत अपरिवर्तित बनी रहती है। इसलिए (अपरिवर्त)  
 पूँजीगत वस्तुओं की विद्युत् कीमत उपभोग्य वस्तुओं की तुलना में अपरिवर्तित  
 बनी रहती है।<sup>39</sup>

38. (कर से पूर्व) बट्टे की आन्तरिक दर अपरिवर्तित रहती है, जब इन  
 प्रतिफल का केवल एक अंश ही कोषों की पूर्ति करने वालों को उपलब्ध  
 हो पाता है।

39. हम ब्याज प्राप्तकर्ताओं अथवा बचत करने वालों के लिये इस रूप में  
 सोच सकते हैं कि वे अपरिवर्त पूँजीगत वस्तुओं को इनके उत्पादक में  
 बरीदते हैं और परिवर्त पूँजीगत वस्तुओं को उपभोग्य वस्तुओं में उत्पा-  
 दन की बेचने हैं। यदि अपरिवर्त पूँजीगत वस्तुओं के विफलता से किसी  
 के समय कर इकट्ठा किया जाता है तो ऐसी वस्तुओं की बाजार-कीमत  
 विद्युत् कीमत की तुलना में बढ़ती है। यदि परिवर्त पूँजीगत वस्तुओं  
 का विफलता मूल्य अपरिवर्त पूँजीगत वस्तुओं के विद्युत् मूल्य की तुलना में  
 अपरिवर्तित रहता है, इसलिए बचतकर्ता को इन अन्तर, जो उसकी  
 ब्याज की आयदानी हैं, में कमी के लिए इन कर को करने ऊपर लेना  
 चाहिए। यदि कर बचतकर्ता से उस समय एकत्र किया जाता है जबकि  
 परिवर्त पूँजीगत वस्तु बेची जाती हैं, तो उसे भी ऐसा ही करना है कि  
 उसकी विद्युत् प्राप्तिवां उसके व्यय की तुलना में घट गई है।

पहले की माँग हम इस तर्क को ग्राह्य के निरोध रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिए, कि उद्योग वस्तुओं की कीमत घट जाती है तो पूँजीगत वस्तुओं की विमुक्त कीमत भी घट जाएगी। मात्र प्रत्यक्ष करने वालों की शर्त के योग्य धारा भी घट जाएगी, लेकिन मजदूरी पाने वालों की शर्त के योग्य धारा में वृद्धि हो जाएगी।

इसमें शीघ्र ही जो परिणाम निकलेगा उसकी व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं होगी है। नये कर का भार व्याज के पाने वालों पर पड़ता है और मजदूरी पाने वाले कर से मुक्त हो जाते हैं। चूँकि आय के रूपांतर पर ऊपर जाने समय आय के घटा के रूप में व्याज बढ़ता है, इसलिए हमारे कर प्रतिस्थापन का अन्तरजनित आपात (Differential incidence) अवरोही ही होगा। शीघ्रमाभी परिणाम तो धारा के उपयोग से स्वतन्त्र होना, लेकिन एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जन के वर्तमान उपयोग इसके भावी खोखों को निर्धारित करने हैं। यहाँ भी उसी किसम की जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं जैसी कि व्याज की आय पर कर लगने से उत्पन्न होती हैं, और जिन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है।<sup>40</sup>

इसके अलावा दीर्घकालीन विश्लेषण में पूँजीगत स्टॉक में परिवर्तन की पुनर्व्यवस्था होनी चाहिए। जब सामान्य धारा-कर की जगह पूँजीगत वस्तुओं (अथवा व्याज की आय) पर कर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सम्भव है कि साधनों का पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन से उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में हस्तान्तरण हो जाय। यह स्थिति अवश्य होगी, क्योंकि समूह के रूप में व्याज-प्राप्तकर्ताओं की बचत करने की प्रवृत्ति मजदूरी पाने वालों की तुलना में ज्यादा दृढ़ होती है,<sup>41</sup> अथवा ऐसी स्थिति के पाये जाने की सम्भावना ही सकती है क्योंकि प्रतिकूल की विमुक्त दर में होने वाली कमी की वजह से हो सकता है कि व्यक्ति बचत के स्थान पर उपभोग करने लगे। विचार

40. देखिए पूर्ण विवरण।

41. सम्भवतः यही स्थिति होगी, क्योंकि व्याज की आय का एक अपेक्षाकृत बड़ा भाग ऊँची धारा वाले लोगों के द्वारा ही प्राप्त किया जायगा। यह स्थिति उस समय भी पाई जायगी जबकि, आय के किसी भी दिये हुए स्तर पर, व्याज व मजदूरी की आय एवं बचत व उपभोग के अनुपात में एक घनात्मक सम्बन्ध होता है।

की दर में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जैसा कि इस विवेचन में सर्वत्र देखा गया है, हमारे अल्पकालीन परिणामों को सीमित बना देंगे।

### समस्त वस्तु-सौदों पर सामान्य कर

अब हम अपने निष्कर्ष समस्त वस्तु-सौदों पर लगाये जाने वाले एक सामान्य कर के अन्तर्गत ले आते हैं। इन सौदों में उपभोग्य और पूँजीगत वस्तुएँ दोनों समान रूप से आ जा जाती हैं।

चूँकि पूँजीगत वस्तुओं का कर व्याज की भाँति पर लगे हुए कर के बराबर होता है, इसलिए यदि उपभोग्य वस्तुओं पर लगाया गया कर मजदूरी की भाँति पर लगे कर के समान होता है तो पूँजीगत वस्तुओं एवं उपभोग्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर एक सामान्य आय-कर के समान ही होगा।

ऐसी स्थिति उस समय आती है जब कि (1) हम यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लेते हैं कि उपभोग्य वस्तुओं पर लगाया गया कर उपभोक्ता पर पड़ता है, और (2) हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें मजदूरी की समस्त आय उपभोग में लगा दी जाती है और व्याज की सम्पूर्ण आय बचायी जाती है। हमारा निष्कर्ष उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा जब कि हम बचत करने वाले श्रमिकों एवं उपभोग करने वाले व्याज प्राप्त-कर्ताओं पर विचार करते हैं। एक सामान्य आय-कर और एक सामान्य वस्तु-कर के बीच जो सरल क्रम की समानता हमने सम्पूर्ण उपभोग के मॉडल में पाई थी, वह वर्तमान मॉडल में लागू नहीं होगी।<sup>42</sup>

### III तरलता-अधिमान मॉडल में करापात

#### (Incidence In The Liquidity Preference Model)

यहाँ स्थानाभाव के कारण हम तरलता-अधिमान-मॉडल की अधिक वास्तविक दशा में इस समस्या पर पुनर्विचार करने की स्थिति में नहीं हैं।

42. यदि हम करापात पर आय के वर्ग-वितरण (Bracket distribution) में होने वाले परिवर्तनों के रूप में विचार करें, तो एक ऐसे कर, जिसका भार विभिन्न वर्गों में मजदूरी की आय के वितरण के अनुसार बँटता है और दूसरे एक ऐसे कर, जिसका भार विभिन्न वर्गों में उपभोग-वर्गों के वितरण के अनुसार बँटता है, इन दोनों के बीच काफी समानता ही देखने को मिलेगी।



हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को लेते हैं जिनके सम्बन्ध में तर्क को मंजूर करने की आवश्यकता है।

1. सरलता-अधिमान या पारदर्शी का समावेश करने पर समारोह की दिशा मोड़ने की नीति ने एक गरम फगन के रूप में नहीं बननाई या सखी है। 'आगे के' समापोत्रों को लेनी से सम्बन्ध करने के लिए आवश्यक बकाया राशि परिणामस्वरूप मुद्रा के रखाव (Holdings) से प्रदान की जा सकती है, अथवा "पीछे के" समापोत्रों से मुक्त दिये गये बीच परिणामस्वरूप मुद्रा में लगाये जा सकते हैं। अब समापोत्रन की दिशा बाजार के आचरण का विषय बन जानी है। मेरे विचार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में बाय-कर के हान पर उत्पादन-कर के लगाने का प्रभाव माघनों के घटे हुए मुफ्तों को बचाव बड़ी हुई कीमतों के रूप में ही होगा, कीमतों की ऊपर की ओर जाने की कठोरता (Rigidity) मजदूरी की नीचे की ओर आने की कठोरता से काफी कम होगी।

परिणामस्वरूप-मुद्रा की पूर्ति में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन व्याज की दर और विनियोग को प्रभावित कर सकते हैं जिससे समापोत्रन की विभिन्न दिशाएँ वस्तुतः विभिन्न अन्तिम परिणाम उत्पन्न करती हैं। हमें इस सम्भावना को स्वीकार करना होगा, लेकिन मुझे इस बात से सदेह है कि इसका कोई बड़ा महत्व है।

2. उपभोग्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर के परिणामों का अध्ययन करते समय हमने सम्भाव्य उपभोग की शक्ति ■ संचय के रूप में होने वाली आय और उपभोग्य एवं/अथवा पूँजीगत वस्तुओं के संचय ■ रूप में होने वाली आय में अंतर किया था। सरलता-अधिमान का समावेश करने पर दूसरे विचार को फँसाकर इसमें मोड़िक बकाया के रूप में होने वाले संचय या संप्रदा को भी शामिल करना होगा। इससे एक विविध समस्या उत्पन्न हो जायगी कि ऐसी बकाया-राशि पर कौन-सा मूल्य-सूचकांक लागू किया जाय।

3. पूर्व विवेचन में निरंतर उन करों का उत्प्रेषण आया था जो बचतों की पूर्ति को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि बचतों की पूर्ति पूँजी-संचय के स्तर और विकास की दर का निर्धारक थी। सरलता-अधिमान का समावेश करने पर बचत और पूँजी-निर्माण की स्पष्ट

कड़ी टूट जाती है। बचत पर कराधान के प्रभाव का महत्त्व अब प्रमुखतया उपभोग, और फलस्वरूप उपभोग-व्यय के स्तर पर प्रभाव न पड़ने के रूप में होगा। विनियोग पर कराधान के प्रभाव अब भी बचत की पूर्ति में गुणात्मक परिवर्तन के जरिए क्रियाशील होते हैं लेकिन उपलब्ध कोषों के विनियोजन या निवेश की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभावों का अब विशेष महत्त्व हो जाता है।

4. इन तत्त्वों के कारण वज्रट-नीति के समायोजनों से बीमारी मध्या राश्वहार के समग्र स्तर में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। ये बदले में वितरण की दशा में और भी परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। अब इस तरह से सर्व प्रस्तुत बिधा जा सकता है कि ऐसे प्रभावों से करापात-वितरण प्रभावहीन हो जाता है। इसमें यह मानना पड़ेगा कि विपरीत प्रभाव को कम करने वाली स्थायीकरण की नीतिमाँ लागू की जाती है। समस्या को इस तरह से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि कर-नीति के निर्धारण में करापात का सम्बन्ध ही हुई आय के वितरण से ही होता है।

लेकिन यदि हम यह मान लेते हैं कि ऐसे स्थायीकरण के कार्य होते हैं, तो प्रश्न उठता है कि स्थायीकरण के बीम से उपाय काम में लिये जाते हैं? यदि मौद्रिक नीति को लेते हैं तो हम वास्तव में मौद्रिक और कर-नीति के मध्यम आपात का विश्लेषण करते हैं। चूंकि समय माँग मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों में निर्धारित होती है, इसलिए हम मौद्रिक नीति को स्थिर रख कर राजकोषीय नीति को दीप्त ही पृथक् नहीं कर सकते हैं। इनके बजाय हमें स्थायीकरण के उपायों के विभिन्न समूहों के अन्तर-जनित आपात पर विचार करना पड़ सकता है, जिसमें कर-नीति का आपात ही नहीं, बल्कि मौद्रिक नीति का आपात भी आता है।

## करापात-सिद्धांत की पद्धति: हाल ही के कुछ योगदानों की आलोचनात्मक समीक्षा\*

जेम्स एम० बुकानन

गिछते पक्षीय वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने क्वांटिटिव अथवा परम्परागत अर्थ में सरकारी वित्त के विद्युत् सिद्धांत के अध्ययन पर अनेकानेक ध्यान दिया है। कुछेक अवसरों को छोड़कर जिन व्यक्तियों ने राजकोपीय सिद्धांत में रुचि दिखाई है उन्होंने बेन्स के बाद अपनाये गये डग के अनुसार राजकोपीय (बजट सम्बन्धी) नीति के सिद्धांत व प्रयोग में आनेवाली समस्याओं पर ही विचार किया है। उन्होंने बराधान व सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों को सापेक्ष रूप में भुलाकर राजकोपीय व मौद्रिक सिद्धांत ■ एकीकृत पहलुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

परम्परागत सिद्धांत की तरफ वापिस जाने की प्रवृत्ति बल पड़ी है और पिछले कुछ वर्षों के सक्षमों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का परिवर्तन होनेवाला है। माजक्स उत्पादन-कर के करापात से सम्बन्धित सिद्धांत में पुनः रुचि बढ़ गई है। यद्यपि इन रुचि के स्वतन्त्र रूप से विकसित होने के भी प्रमाण मिलते हैं, फिर भी इस का अधिकांश श्रेय रॉल रोल्फ (Earl Rolph) को दिया जाना चाहिए जिनके कार्य ने, जो उनकी लेख-मालाओं<sup>2</sup> में एव बाद में इनकी पुस्तक, *The Theory of Fiscal Econo-*

\* (इस निबन्ध में इटैलियन में प्रकाशित एक लेख "La metodologia della teoria dell'incidenza," Studi economici (दिसम्बर, 1955) का काफी परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें मैने पराविचिनी (Parravicini) के विवेचन से सम्बन्धित अनुच्छेद जोड़े हैं और निबन्ध में कुछ अन्य स्थानों पर भी परिवर्तन किये हैं।)

Earl R. Rolph, "A Proposed Revision of Excise Tax Theory," *Journal of Political Economy*, LX (1952), 102-

mies, ३ में प्राया है, काफी वाद-विवाद को प्रोत्साहित किया है। जोन ड्यू, प्रार० ए० मसग्रेव, एच० पी० वी० जेनकिन्स <sup>३</sup> और जी० पराविसिनी ने इस बहस में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

इस लेख के प्रारम्भ में मैं रोलफ के विश्लेषण की संक्षेप में समीक्षा करूँगा। द्वितीय, मैं इस विश्लेषण की उस भालोचना का विवेचन भी करूँगा जो ऊपर वर्णित सामग्री में स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में शामिल है। लेख के तृतीय एवं मूल भाग में मैं सम्पूर्ण बहस को एक ऐसे ढाँचे में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा जिसे मैं एक उचित कार्य-पद्धति का ढाँचा मानता हूँ।

### 1. विश्लेषण

रोल्फ का विश्लेषण शुरू में अमेरिका में एच० जी० ब्राउन <sup>4</sup> द्वारा प्रस्तुत किये गये सिद्धान्त का ही एक परिष्कृत, विस्तृत, व्यापक एवं कुछ

17, "A Theory of Excise Subsidies," *American Economic Review*, XLII (1952), 515-27; "Government Burdens and Benefits: Discussion," *American Economic Review* XLIII (1953), 537-43; "A Theory of Excise Subsidies: Reply," *American Economic Review* XLIII (1953), 895-98.

(2) Berkeley: University of California Press, 1954.

(3) John F. Due, "Toward a General Theory of Sales Tax Incidence," *Quarterly Journal of Economics*, LXVII (1953), 253-66; Richard A. Musgrave, "General Equilibrium Aspects of Incidence Theory," *American Economic Review*, XLIII (1953), 504-17; "On Incidence," *Journal of Political Economy*, LXI (1953), 306-23; H.P.B. Jenkins, "Excise-Tax shifting and Incidence; A Money-Flows Approach," *Journal of Political Economy*, LXIII (1955), 125-49.

लॉरेंस अबोट (Lawrence Abbott) ने श्री रोलफ के विश्लेषण पर एक भालोचनात्मक टिप्पणी लिखी है. "A Theory of Excise Subsidies: Comment," *American Economic Review*, XLIII (1953), 890-95.

(4) H.G. Brown, "The Incidence of a general output or a general Sales Tax," *Journal of Political Economy*, XLVII (1939), 254-62.

धरों में काफी परिमित है। बाउन का यह दावा था कि गन्ने का जो सामान्य उत्पादन कर होता है वह उपभोक्ताओं पर निम्नराश का भार है। इसीलिए ऐसे कर का घनिष्ठ भार साधनों के स्वामियों पर उनकी क्रान्ति के अनुपात में पड़ता है। बाउन का मत तर्क की दृष्टि में सामान्य रूप से सही होने एवं साम्प्रदायिक विश्लेषण में काफी मात्रा में स्वीकार किये जाने पर भी व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहा है। मार्शल की पद्धति में प्रशिक्षण पाये हुए अर्थशास्त्रियों ने आंशिक-संतुलन विश्लेषण को सामान्य उत्पादन-कराधान पर लागू करने का प्रयास किया है जहाँ के लिए यह काल्पनिक में अनुपयुक्त है। इन निष्कर्षों पर शायद ही कभी आगति उठाई जाती है कि उपभोक्ता सामान्य उत्पादन-करों का भार वहन करने हैं। इसका कारण यह है कि इस बात को नहीं पहचाना गया है कि आंशिक उत्पादन-कर और सामान्य उत्पादन-कर के विश्लेषणों में भिन्न-भिन्न सैद्धान्तिक ढाँचों की आवश्यकता होती है।

रोल्फ को यह श्रेय है कि उसने अमेरिका में प्रचलित राजकीय सिद्धांत में इस कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन उसने बाउन के विश्लेषण में भी पड़े जाने और उसके निष्कर्षों को आंशिक उत्पादन-करों पर भी लागू करने का प्रयास किया है। अब मैं रोल्फ के विश्लेषण में पाये जाने वाले अध्ययन के ढाँचे, पद्धति एवं निष्कर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत करूँगा।

रोल्फ कर के प्रभावों का विश्लेषण सरकारी व्यय और/अथवा अन्य करों की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से पृथक् करके करता है। सरकारी व्यय एवं अन्य करों की मात्रा व बनावट को यथास्थिर मान लिया जाता है। वह स्पष्टतः विभेदात्मक कराधान पद्धति (differential incidence approach) को छोड़ देता है जिसमें यह मान लिया जाता है कि अन्य करों में पूरक परिवर्तन हो रहे हैं। इसी तरह वह सतुलित-बजट पद्धति (balanced

- (5) विशेषतया सिकागो विश्वविद्यालय में भूतपूर्व प्रोफेसर हेनरी सी. साइमन्स के द्वारा दिये गये विवेचन में। दुर्भाग्यवश इस विषय पर साइमन्स के द्वारा प्रकाशित एकमात्र विवरण उनके एक लेख के सारांश में दिया गया है जो उन्होंने दिसम्बर 1939 में American Economic Association की एक सभा में प्रस्तुत किया था। देखिए American Economic Review XXX (1940), 242-44.

budget approach) को भी त्याग देता है। जिसमें प्रतिरिक्त कर-भ्राय के बराबर ही प्रतिरिक्त सरकारी खर्च मान लिया जाता है।

कर सिद्धान्त में रोल्फ के दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि केन्स के बाद की अवधि में देखने को मिलती है जब करो पर अपस्फीतिकारी (स्फीति-विरोधी) नीति के रूप में बल दिया गया और फलस्वरूप बजट-संतुलन का राजकोपीय प्रादुर्भाव के रूप में परित्याग कर दिया गया। यदि बजट-नीति के मामलों में करो की भाय-मृजन के उपायों की अपेक्षा मुख्यतया अपस्फीतिकारी उपायों के रूप में ही माना जाना है तो कराधान के विश्लेषण में इस दृष्टिकोण का साधु होना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

पद्धति-सम्बन्धी इस मान्यता से निकट सम्बन्ध रखने वाली और शायद इससे भी ज्यादा मूलभूत है रोल्फ की कर की परिभाषा। उसने कर की परिभाषा इस प्रकार दी है कि यह व्यक्ति ॥ सरकार की तरफ होने वाला मुद्रा का हस्तांतरण (money transfer payment) है। यहाँ पुराना यह विचार कि कर वास्तविक भार डालते हैं बलिप्त घोषित हो जाता है। राज-कोपीय बायों से वास्तविक भार राजकोपीय खाते में कर की तरफ से नहीं बल्कि खर्च की तरफ से उत्पन्न होता है। सरकारी खिचा का समग्र वास्तविक भार पूर्णतया इस बात से निर्धारित होता है कि सरकार के अधिकार में कुल वार्षिक आयों का कितना घटा है। और चूँकि रोल्फ ने सरकारी खर्चों को यथास्थिर मान लिया है, इसलिए सरकार का समग्र वास्तविक भार केवल कर के परिवर्तन से ही नहीं बदल सकता है।

यह आवश्यक भी बात है कि रोल्फ के विश्लेषण में वे स्पष्ट मान्यताएँ नहीं हैं जिनका सम्बन्ध मौद्रिक अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों से होता है। उसने कराधान-सिद्धांत के अपने निरूपण में मौद्रिक सिद्धान्त के आयन्त महत्वपूर्ण स्थान की पूर्णतया स्वीकार किया है, और कम से कम अपनी पुस्तक में तो राजकोपीय सिद्धांत के मौद्रिक आधार पर काफी बल दिया है। लेकिन उसका मौद्रिक विश्लेषण लगभग पूर्णतया प्रक्रिया के रूप में (in terms of process) ही किया गया है। दूसरे शब्दों में, हम यों कह सकते हैं कि वह मौद्रिक विश्लेषण को उच्च वस्तु पुरा मानता है जबकि यह दर्शा दिया जाय कि, उदाहरण के लिए, कर-अंतर्गत अपराधीन व्यक्तियों व जर्मों के व्यय-सम्बन्धी निर्णयों की कितने प्रभावित करनी है। यही भी वह उस मौद्रिक ढाँचे को साफ और से नहीं बतनाता है जिसे अन्तर्गत विश्लेषण बिना जाता है। अन्त में

केवल रोलफ ने ही यह पद्धतीय भूल नहीं की है। मौद्रिक ढांचे की विस्मृति स्पष्ट न कर सकने के कारण ही केस के विश्लेषण की काफी उपयोगिता, सम्भवतया अधिकांश उपयोगिता, घट गई है।<sup>6</sup>

रोलफ के विश्लेषण सम्बन्धी ढांचे में दोष सख्त अधिक परम्परागत हैं। इन लक्षणों में पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक व बंद अर्थ-व्यवस्था की मान्यता भी शामिल है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकाल में साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। विश्लेषण की सरलता के लिये केवल दो वस्तुओं का बिना बचत का मॉडल प्रयुक्त किया गया है। हालांकि इस तरह की सामान्य विस्मृति की मान्यताओं की यह आलोचना की गई है और की भी जा सकती है कि वे विश्लेषण के लागू होने को अनावश्यक रूप से मर्यादित कर देती हैं, फिर भी तृतीय खण्ड के विवेचन में इनको स्वीकार किया जायगा।

अब हम रोलफ के विश्लेषण के कार्य-प्रणाली सम्बन्धी पहलुओं की जांच करेंगे। उसने एक कर के "आय-प्रभाव" और उसके "कीमत-आवटन" ("price-allocation") प्रभाव में काफी अन्तर किया है। कर के लागू होने पर व्यक्तियों की मौद्रिक आय में जो कमी आती है उसे आय-प्रभाव कहते हैं। अब हम कर की यह परिभाषा मानते हैं कि यह एक हस्तान्तरण-भुगतान है तो यह निजी मौद्रिक आय में अवश्य कमी करेगा और सरकार की आयदानी में इतनी ही मात्रा में वृद्धि करेगा। दूसरे शब्दों में, एक कर का आय-प्रभाव सरकार की कर से प्राप्त आय के ठीक बराबर होता है। इसके अनिश्चित कर में अर्थ-व्यवस्था में कीमत-आवटन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं और नहीं भी।

आय-प्रभाव के कारण और इसके माध्यम कर वास्तवीयकारी प्रभाव डालता है। सच कहने की वैयक्तिक शक्ति कम हो जाती है और, सामान्यतः दूसरे अनिश्चित सरकारी व्यय अथवा अन्य करों में कमी के रूप में बराबर

- 6 इस विषय पर हाल ही में प्रस्तुत की गई उत्तम सामग्री के लिये देखिये फ्रिट्ज मैक्लूप (Fritz Machlup), "The Analysis of Devaluation," *American Economic Review*, XLV (1955), 273-75 मैक्लूप का कहना है कि 'नैतिक अर्थशास्त्र' में साध्यतः वय में मुद्रा की पूर्ति को नीति-सम्बन्धी चरमार्थ (policy variable) माने जाने की बजाय एक निर्भर चरमार्थ (dependent variable) माने जाने की ही प्रवृत्ति रही है।

करने वाले स्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं होने दिये जाते हैं। लेकिन कर का अपस्फीतिकारी प्रभाव केवल मौद्रिक ही होता है। कर कोई वास्तविक त्याग नहीं करवाता है। हम यह मान सकते हैं कि जिन व्यक्तियों व समूहों की मौद्रिक आय घट जाती है वे ही कर का भार सहन करते हैं।

एक सच्चे सामान्य उत्पादन-कर की स्थिति में ये सब साधनों के स्वामी होते हैं। कर के भुकाये जाने की शर्त उत्पादन करने वाली फर्मों के द्वारा प्राप्त विद्युद्ध कीमत में कमी कर देती है। प्रत्येक फर्म को उस बिन्दु तक उत्पत्ति के घटाने की प्रेरणा होती है जहां सीमान्त लागत विद्युद्ध कीमत के बराबर हो जाती है। लेकिन चूंकि प्रत्येक फर्म पर एक-सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सब की तरह से उत्पत्ति को सीमित करने की कोशिश से साधनों के बाजारों में बेकारी उत्पन्न हो जाती है। यदि साधन-बाजारों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो साधनों की कीमतें इतनी गिर जायेंगी जिससे बेकारी दूर हो सके। नये सतुलन की स्थिति में प्रत्येक फर्म कर के पूर्व की स्थिति के बराबर ही उत्पादन करेगी और विद्युद्ध कीमत सीमान्त लागत के बराबर होगी। ऐसा समायोजन केवल साधनों की घटी हुई कीमतों के माफंग ही पूरा हो सकेगा। साधनों के स्वामियों की मौद्रिक आय में कर की मात्रा के बराबर कमी आ जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली साधन-आय के भंड के अनुपात में कर भुगतता है। चूंकि प्रत्येक फर्म उतनी ही उत्पत्ति जारी रखती है जितनी कि वह कर से पूर्व करती थी, इसलिए उत्पत्ति की बनावट (वस्तु-मिश्रण) कर के बाद भी अपरिवर्तित ही बना रहता है। समस्त वस्तुओं व सेवाओं पर लगाये जाने वाला सच्चा सामान्य उत्पादन-कर (जो एक-सा होता है) कीमत-आवटन प्रभाव नहीं डालता है।

इसके पश्चात् रोलफ इस विश्लेषण को आसिक उत्पादन कराधान पर लागू करता है। चूंकि आय प्रभाव अब भी विद्यमान रहता है, इसलिए आय प्राप्तकर्ताओं की सरकार की कर से प्राप्त आय में महा भी कर-भार उठाना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में पूरक कीमत-आवटन प्रभाव भी पाये जाते हैं। सब वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ को छोड़कर दोष पर कर के लगाये जाने से बिना कर की वस्तुओं की तुलना में कर सगी हुई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने की अधिक प्रवृत्ति होगी।

रोलफ के ही शब्दों में उसके निष्कर्ष निम्नांकित हैं :

1. "पूर्णतया सामान्य एवं एक-से करों की व्यवस्था उत्पादन की बनावट को अपरिवर्तित बने रहने देती है, वस्तुओं की कीमतों को नहीं बढ़ाती



है, और साधनों के स्वामियों की मौद्रिक आय को घटा देती है और ऐसा वह आनुयायिक रूप में करती है।

2. "घासिक उत्पादन करों की कोई भी अवस्था वस्तु-मिश्रण को बदल देती है, भारी करोंवाली वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देती है, हल्के करों से बिना करों वाली वस्तुओं की कीमतों को कम कर देती है, और साधनों के स्वामियों की मौद्रिक आय को घटा देती है।

3. "उत्पादन कराधान की सभी प्रणालियाँ सरसंप्रतिकारो होती हैं....."

## II. घासोचना

ऊपर रोलफ का जो विस्लेषण प्रस्तुत किया गया है उसकी संक्षेप में घासोचना देना सामग्रद होगा। यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि नीचे जिन चार मतों का विवेचन किया जा रहा है उनमें से प्रत्येक मत वर-सिद्धान्त के क्षेत्र में एक सामान्य योगदान के रूप में देता जा सकता है और वह रोलफ के विचारों की घासोचना तक ही सीमित नहीं है। लेकिन चारों में एक ही बात यह है कि रोलफ के विस्लेषण के कुछ भागों पर आपत्ति उठाई गई है। इससे, कम से कम मेरे प्रयोजन के लिए, एक उपयुक्त ढंग की समरूपता की तरफ ले जाने वाली सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

## रूप का योगदान

रूप ने कराधान की परिभाषा वास्तविक रूप में (real terms) की है। इसे "कर भार के वितरण का प्रारूप समझा गया है; कर-भार का माध्य वास्तविक आय की कमी है (.....) जो कर के लागू होने से उत्पन्न होती है।" उसका रोलफ से मौलिक मतभेद है, क्योंकि रोलफ ने कराधान को मौद्रिक अर्थ में परिभाषित किया है और "कर-भार" की धारणा को स्पष्टता अस्वीकार किया है।

वाउन-रोल्फ के विचारों (जिनको वह एक मानता है) ने अपने विशेष विवेचन में रूप का कहना है कि उसके निष्कर्षों की सत्यता तीन मान्यताओं पर निर्भर करती है। वे इस प्रकार हैं: (1) साधनों की पूर्णतया बेलोव पूँज,

7. "A Proposed Revision of Excise-Tax Theory," p. 102.

8. Due, op. cit., p. 254.

और साथ में द्रव्य की एक दी हुई मात्रा; (2) पूर्ण प्रतिस्पर्धा; और (3) कर से प्राप्त आय का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि कर और आय के उपयोग दोनों पर विचार करने से भी वस्तुओं की समग्र मौद्रिक मांग अपरिवर्तित बनी रहती है।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता रोलफ के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से थी और इस मान्यता के औचित्य के सम्बन्ध में रूयू की आलोचना पर विचार नहीं किया गया। मैं रोलफ से इस बात पर सहमत हूँ कि हमें अपेक्षाकृत बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी कार्यों पर जाने से पूर्व सरल दशाओं में कराधान-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। यूनीय मान्यता ब्राउन के विश्लेषण में निहित मानूम देती है, जिसमें सरकार की करो से प्राप्त आय के उपयोग पर विचार किया गया है। लेकिन यह बात तो ब्राउन और रोलफ के बीच मतभेद की हुई। रोलफ ने स्पष्टतः, सरकारी व्यय को पर्याप्त मान लिया है, और कर के अपस्फीतिकारी प्रभाव पर जोर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूयू ने ब्राउन और रोलफ के बीच पाये जाने वाले इस मतभेद पर ध्यान नहीं दिया है। रूयू की यह आलोचना सही है कि रोलफ के कुछ निष्कर्ष केवल इसी मान्यता से उत्पन्न हो सकते हैं कि समग्र मांग कामचला रही जाती है। अपने गणितीय मॉडलों में रोलफ ने कर का मुद्रास्फीति निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया है जो स्फीतिकारी अंतर (gap) की दशा में लागू किये जाने पर कर सहित समग्र मांग को सम्बन्धित पिछली अवधि में पाई जाने वाली कर रहित समग्र मांग के बराबर कर देता है। यहाँ पर यह माना जा सकता है कि यदि कर लागू नहीं किया जाता तो समग्र मांग में कर की भाँति के बराबर वृद्धि होती, अर्थात् मुद्रास्फीति हो जाती। लेकिन रोलफ के लेखों को ध्यान से पढ़ने पर यह लगता है कि वह अपने विश्लेषण को समस्त राजकोपीय दशाओं पर समान रूप से लागू मानता है। और चूँकि वह करों के सामान्य अपस्फीतिकारी प्रभाव पर जोर देता है, इसलिए मेरा अनुमान है कि यदि उसके निष्कर्ष समग्र मौद्रिक मांग के बने रहने पर निर्भर करते हैं तो ऐसा उसके विश्लेषण की त्रुटि के कारण है, न कि उसकी अन्तर्गत मान्यताओं को स्पष्ट करने की विफलता के कारण।

समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा लगता है कि रूयू रोलफ-ब्राउन के इस मूल निष्कर्ष को अस्वीकार कर देता है कि सामान्य उत्पादन-व्यय साधनों के स्वामियों के द्वारा भुगतें जाते हैं, न कि उपभोक्ताओं के द्वारा। वह इस परिणाम को अनेक स्थितियों में एक सम्भावित स्थिति ही मानता है। रूयू

मे घानी वैज्ञानिक वास्तव में यह मान लिया है कि मुद्रा की पूर्ण मोचदार होती है और मौद्रिक बांधकारी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने में विफल रहती है। अध्ययन के क्रम होने को उगने उगादा पनद किया है उगमें कर की बरत में होने वाली मुद्रा वृद्धि वास्तविक मुद्रा-वृद्धियों के रूप में प्रगट होती है क्योंकि समग्र मौद्रिक मांग में वृद्धि होने की जाती है।

### मसखेव का योगदान

मसखेव के अनुसार कराधान का आभाव उन परिवर्तनों से है जो कर के लगने में किसी उपयोग के लिए उत्पन्न होने वाली वास्तविक आय के वितरण में उत्पन्न होते हैं।<sup>9</sup> उगने कराधान की तीन किस्मों में प्रगट किया है जो बजट सम्बन्धी समाधोजन की असम-समग्र किस्मों से उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम, अन्य करों एवं गावंजनिक व्यय को स्थिर रखने की दशा में एक कर के परिवर्तन से "निरपेक्ष कराधान" ("absolute incidence") उत्पन्न होता है। वस्तुतः यह रोलफ का अध्ययन का ढांचा है। द्वितीय, एक कर में परिवर्तन कर दिया जाय, लेकिन साथ में दूसरे कर में इसको बराबर कर देने वाले का मिटा देने वाले ऐसे परिवर्तन कर दिये जाय कि कुल सरकारी आय वयास्थिर बनी रहे। इन करों का जो वितरण-सम्बन्धी परिणाम निकलता है उसे "भेदात्मक कराधान" ("differential incidence") की श्रेणी में रखा गया है। अतः में एक कर में परिवर्तन किया जा सकता है और साथ में सार्वजनिक व्यय में भी उसी मात्रा में परिवर्तन कर दिये जाते हैं। यह परिणाम "संतुलित बजट कराधान" ("balanced budget incidence") कहलाता है। मसखेव ने राजकोपीय सिद्धान्त में "भेदात्मक कराधान" के दृष्टिकोण का प्रथम समर्थन किया है, लेकिन उसने तीनों दृष्टिकोणों को पद्धति की दृष्टि से स्वीकार किया है।

मसखेव का विश्लेषण, जो केवल भेदात्मक और संतुलित बजट के माध्यम से ही किया गया है, यह दर्शाता है कि जिस विशिष्ट मौद्रिक ढांचे की वरूपता की गई है वह उन निरपेक्ष कीमतों में समाधोजन की दिशा को निर्धारित करने में पूरी तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है जो कर के परिवर्तन से उत्पन्न हुई है। प्रारम्भ में विभिन्न किस्म की मान्यताओं, जैसे मुद्रा की स्थिर प्रति की नीति, स्थिर मूल्य-स्तर अथवा अन्य विवरण, के स्वीकार करने से विभिन्न

वित्त के निष्कर्ष निकल सकते हैं। उसने यह दृष्टि का प्रकाश किया है कि निरपेक्ष कीमतों अथवा कीमत-स्तर में समायोजन की दशा का कराधान के प्रारूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निरपेक्ष कीमतों में समायोजन की दशा पूर्णरूप से एक मौद्रिक वस्तु है जो कर-भार के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। "कराधान का सिद्धान्त मूलतः सापेक्ष कीमतों का ही सिद्धान्त है जब कि इस स्थिति में किये जाने वाले मौद्रिक परिवर्तनों का प्रभाव केवल मूल्य-स्तर पर ही पड़ता है।" 10

ममघेव वित्तलेपण की परम्परागत पद्धति में निहित दो भ्रमों को स्वीकार करता है जिनके द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि उपभोक्ता उपभोग्य वस्तुओं पर लगाने जाने वाले सामान्य उत्पादन करों का भार वहन करते हैं। वह छाउन और रोटफ दोनों को इस भ्रम को दूर निवारण का श्रेय देता है, और वह यह है कि व्यक्तिगत व्ययों के समायोजनों के कारण मूल्य-वृद्धि हो सकती है। लेकिन वह उनको इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि वे हमारे भ्रम से नहीं बच सके। यह भ्रम इस प्रकार है कि उन्होंने निरपेक्ष कीमतों में समायोजन की दशा को ही करापात समझ लिया है। यह दर्शा कर कि, कुछ दशाओं में, साधनों की कीमतों में कर की मात्रा के बराबर गिरावट आती है, ममघेव ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि छाउन और रोटफ ने यह नहीं समझाया है कि साधनों के स्वामी कर का भार वहन करते हैं। ममघेव यह बतलाता है कि यदि समायोजन की दशा ऐसी हो कि इससे मूल्य बढ़ जाय, घट जाय, अथवा स्थिर बने रहें तो भी करापात का प्रारूप (incidence pattern) एक जैसा रह सकता है।

उपभोग-व्ययव्यवस्था के अनेक विवेचन के बाद ममघेव एक ऐसी व्यवस्था पर विचार करता है जिनमें उपभोग की वस्तुएँ और पूंजीगत वस्तुएँ दोनों पाई जाती हैं। उपभोग्य वस्तुओं पर कर का समावेश करने से यह दर्शाता है कि पूंजीगत वस्तुओं की कीमतें उपभोग्य वस्तुओं की तुलना में घट जाती हैं और कर का वास्तविक भार उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के बीच पाये जाने वाले व्यय के वित्तीय प्रारूप (individual purchase pattern) पर निर्भर करता है। यहाँ पर उनका विवेचन रोल्फ कपला जेनकिन्स से बेहतर हम सब से अधिक है कि यह पूंजीगत वस्तुओं का समावेश कर देना है।

उपभोग्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले सामान्य उत्पादन कर के जाने विवेक्षण के बाद (जो वाउन-रोल्फ के अर्थ में एक सामान्य उत्पादन कर मही है), मसग्रैव समझन पूँजीगत वस्तुओं पर सामान्य रूप से एवं समान रूप से लगाये जाने वाले कर के प्रभावों की जाँच करता है और ऐसा करने समय यह उपभोग्य वस्तुओं को बिना कर मगे हुए ही छोड़ देता है। यह इन निष्कर्षों पर पहुँचता है कि ऐसा कर पूर्णरूप से बचन की पूर्ति करने वालों के द्वारा ही भुगता जायगा। यह इन परिणाम पर उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को पूँजीगत वस्तुओं से भूतंतया घटक करके पहुँचना है, प्रथम श्रेणी की वस्तुओं प्रत्यक्ष अथवा और पहले से उत्पन्न की गई पूँजीगत वस्तुओं की सहायता से उत्पादित होती है और द्वितीय श्रेणी की वस्तुओं प्रत्यक्ष अथवा "प्रतीक्षा" से उत्पादित होती है। उपभोग्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले सामान्य कर और पूँजीगत वस्तुओं पर लगाये जाने वाले सामान्य कर के भार का विश्लेषण करने के बाद मसग्रैव इन दोनों को सच्चे सामान्य उत्पादन-कर के अपने विश्लेषण में शामिल करने का प्रयास करता है। चूँकि यह मान लिया जाता है कि पूँजीगत वस्तुओं पर लगाये जाने वाला कर बचत की पूर्ति करने वालों के द्वारा ही भुगता जाता है, इसलिए यदि करापात की दृष्टि से सामान्य उत्पादन-कर को साधनों के प्रतिफल पर लगाये जाने वाले सामान्य आय-कर के समान होना है, तो उपभोग्य वस्तुओं पर पड़ने वाला कर पूर्णरूप से उपभोक्ताओं के द्वारा ही भुगता जाना चाहिए (यही वाउन-रोल्फ निष्कर्ष है)। उपभोक्ता उपभोग्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले उत्पादन-कर का पूरा भार तभी वहन करते हैं जब कि मजदूरी से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण आय उपभोग में खर्च की जाती है, और ब्याज की सम्पूर्ण आय बचा ली जाती है। चूँकि ये बातें अवास्तविक हैं, इसलिए मसग्रैव का यह निष्कर्ष है कि व्यवहार में बहुत कम पाये जाने वाले सम्पूर्ण उपभोग के मॉडल को छोड़कर रोल्फ का सामान्य प्रतिपादन कहीं भी लागू नहीं होता है।

मसग्रैव के विश्लेषण के अधिकांश भाग को चुनौती देना सम्भव नहीं होगा वशतः कि हम पूँजी के उस सिद्धान्त को स्वीकार करें जिस पर कि यह आधारित है। वह बिना किसी मर्यादा या शर्त के पूँजी के माँस्ट्रियन सिद्धान्त को स्वीकार कर लेता है जिसमें पूँजीगत वस्तुएँ उत्पादन के साधनों की सूचक होती हैं। उसने अर्थव्यवस्था के पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्रों के क्षेत्र में, धारणा की दृष्टि से, जो सीधे अंतर किया है इस पूँजीगत सिद्धान्त के आधार पर ही सम्भव प्रतीत होता है। इसके

विपरीत यदि हम ऑस्ट्रियन सिद्धान्त को मसखेव का विश्लेषण करके उसके स्थान पर माइट का सिद्धान्त रख लें तो मसखेव का विश्लेषण सही नहीं रह जायगा। उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में बिना जाने वाला स्पष्ट अंतर घिट जायगा और जो निष्कर्ष सम्पूर्ण उपभोग-वस्तुओं के माँदल की मांगता के आधार पर निकाले गये थे वे इसमें पूंजीगत वस्तुओं के समावेद से, कम-से-कम स्थैतिक विश्लेषण में तो अपरिवर्तित ही बने रहेंगे।

### जेनकिन्स का योगदान

भव में उत्पादन-कर के भार-सम्बन्धी विवाद में एच० पी० डी० जेनकिन्स के योगदान का विवेचन करेंगे। उसका विश्लेषण अत्यधिक जटिल है और उसके गणितीय विश्लेषणात्मक माँदलों के ढाँचे से बाहर विवेचन कर सकना कठिन है। फिर भी उसकी पद्धति व उसके निष्कर्षों का सारांश दिया जा सकता है।

जेनकिन्स की पद्धति में मुद्रा-प्रवाह (Money flow) पर कर के प्रभावों के जरिए कराधान के प्राप्ति को जानने का प्रयास किया गया है। यद्यपि उसका विशिष्ट विश्लेषण भेदात्मक कराधान की भाषा में हुआ है, फिर भी उसका मत है कि उसके निष्कर्ष सरकारी व्यय की मात्रा, अन्य कर एवं मौद्रिक नीति के बारे में स्वीकार की जाने वाली मांगताओं से असम्बन्धित किये जाने पर भी लागू होते हैं। जेनकिन्स के अनुसार नीति-सम्बन्धी इन तीन परिवर्तनशील तत्त्वों से सम्बन्धित स्पष्ट मांगताएँ केवल विश्लेषण की स्पष्टता व सुविधा के लिए ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये मुद्रा-प्रवाह की निरपेक्ष मात्राओं को ही प्रभावित करती हैं।

जेनकिन्स का मत है कि रोलफ ने मौद्रिक अपस्फीति को गलती से कर का सिद्धकाम मान लिया है। इस बात पर वह और मसखेव एक दूसरे से सहमत हैं। लेकिन जेनकिन्स मसखेव की भी आलोचना करता है और कहता है कि उसने करों के झूठे और सच्चे करापात में टीक से अंतर स्पष्ट नहीं किया है। जेनकिन्स के अनुसार करापात की परिभाषा इस प्रकार है : "यह वह प्राप्ति है जिसमें राज्य के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली (सेवाओं) का आरोप्य या सपाया गया सुदरा वस्तु-मूल्य अन्तिम बाजार-भुगतानों के ढाँचे में शामिल होता है।"<sup>11</sup> चूँकि यह परिभाषा अनिवार्यतः मौद्रिक है, इसीलिए

11. जेनकिन्स, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ० 131

जेनकिन्स की करापात को धारणा मसदेव अपना दू के बराब रीयक के अपरा ममीन मान्य देनी है लेकिन यह समानता वास्तविक होने के बराब ऊपरी जगह है क्योंकि इन मीट्रिक परिभाषा के बावजूद भी जेनकिन्स का करापात का विशेषण अनिवार्य वास्तविक या प्रमीट्रिक रूप में ही किया गया है ।

रीयक का मत है कि कर के धार-प्रभाव (जिन्हें वह स्पष्टतः "करापात" कह कर नहीं पुकारता है लेकिन जिनको वह स्पष्टा प्रमीट्रिक परिभाषा के रूप में स्वीकार करता है) सरकार की कर में प्राप्त आय में अधिक नहीं हो सकते हैं, और यदि बीमा-आइटम प्रभाव शामिल होते हैं तो इन प्राथमिक भाषा के पूरक के रूप में ही होते हैं । जेनकिन्स भी लगभग ऐसा ही तर्क प्रस्तुत करता है कि कर-भार का वास्तविक अपना सच्चा मीट्रिक मूल्य बाहुओं व नेवाओं की सरकारी खरीद के मात निम्न गये या धारोप्य मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है । कर के कारण इनके पूरक के रूप में वास्तविक आय में जो कमियाँ आती हैं उन्हें सच्चा करापात नहीं कहा जा सकता है । वह उन्हें झूठा करापात कहता है, अर्थात्, अधिक विविष्ट रूप में, दुबरा वस्तु-मूल्य में शक्तिमयी परिवर्तन मानता है । मसदेव जेनकिन्स के "सच्चे" करापात और वस्तु-मूल्य के इन परिवर्तनों दोनों को ही अपनी व्यापक परिभाषा में शामिल करता है ।

जेनकिन्स के विश्लेषण में विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र का विवेचन शामिल किया गया है और वह रीयक व मसदेव दोनों की इस बात के लिए आलोचना करता है कि उन्होंने सरकार के द्वारा की गई खरीद की ध्यान से छानबीन नहीं की है । सर्वप्रथम, जेनकिन्स ने यह बतलाया है कि एक कर अपने प्रभाव में सही अर्थ में सामान्य सभी हो सकता है जब कि यह सरकारी खरीद और सम्पूर्ण निजी खरीद दोनों पर फैल जाय । इस स्थिति में प्राउन-रीयक का पूर्ण रूप से पीछे की ओर खिसकाने का निष्कर्ष लायु होता है; कर का पूरा भार साधनों के स्वामियों पर पड़ता है । लेकिन यदि कर सरकारी खरीद तक नहीं फैलाया जाकर केवल निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाता है तो विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि, उत्पादन को दी जाने वाली अर्थिक सहायता की दशा को छोड़कर जिसमें कर-भार को आपे खिसकाना सम्भव होता है, कर अंततः साधनों के स्वामियों के द्वारा और अंततः उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान जायेगा ।

## करापात-सिद्धांत की पद्धति

यह यह दर्शाता है कि जब सरकारी मरीद को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, तो साधनों के स्वामियों पर पड़ने का भार वास्तविक मूल्य सदैव सरकार की उत्पादन-कर की धारा में होगा। इसमें रोलफ के प्रारम्भिक निष्कर्ष का समर्थन हो जाता है। उसका मत है कि रोलफ ने इसी बिन्दु पर रुक कर गलती की। जेतन विवेचन से यह प्रगट होता है कि सरकार की कर में प्राप्त आय के मूल्य से भी अधिक मात्रा में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है। अनिर्दिष्ट या पूरा भार सदैव पीछे ठकेली जाने वाली मात्रा के समान ही होता है, और यह अनुपात अर्थव्यवस्था में कुल कर-भार की मात्रा निर्धारित किया करता है।

विवेचन की भविष्य के लिए जेतनिय यह मान लेता है कि मॉडलों में कर केवल इतना ही होता है कि यह वस्तु-रूप में सरकारी की एक ही हुई मात्रा की वित्तीय व्यवस्था के लिए पर्याप्त सिद्ध हो। व्यवस्था में उत्पादन के उन साधनों के अनुपात की मापना बाध होता है जो सरकार के द्वारा लगी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन करते हैं। उसके मॉडलों में यह अनुपात सदैव पांचवा भाग होता है। यद्यपि यह है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन-वृद्धि का १ भाग निजी के द्वारा लगी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगता है। इसमें जेतनिय को उस प्रारम्भिक दया का ज्ञान हो जाता है। उपभोक्ताओं की स्थिति मापी जा सकती है। यदि निजी तीर प जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता सुदरा पदार्थों के रूप का १ से ज्यादा भाग कर मरी हुई वस्तुओं के लगी देने में लगाते हैं। ऊपर का भाग कर-भार का अर्थ माना जायगा, और उपभोक्ताओं भुगतान जायगा। वास्तव में इस विवेचन में यह अनुपात दया है। साधनों के भाव कुछ घटा दिये जाते हैं और सरकारी मरीद पर लगता है। इसलिए सरकार को अपनी मरीद में छोड़े की दृष्टि से जाता है। भुगतानों के रूप में होने वाली यह विवृति कर के समान लग दिलाई देने वाले भार से अधिक बना देनी है जो कर की सीमित रहता है।

समय के साथ जेतनिय का सम्बन्ध ज्यादा सुदृढ़ है और वास्तविक उत्पादन-कर के विवेचन में ही प्रगट होता है। जेतनिय व्यवस्था का सुझाव है यह व्यवस्था की परिभाषा के मादानी-में जेतनिय



ही उत्पन्न होता है। उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले मौद्रिक भार को मापने के सम्बन्ध में जेनकिन्स के द्वारा स्वीकार की गई प्रारम्भिक दशा में साधनों की लागतों का वह भ्रम थाता है जो उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में निहित होता है। खुदरा खरीद में किये गये कुल भुगतानों का जो अंश साधनों की लागतों के इस भ्रम से ऊपर होता है वह उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार का माप माना जाता है। लेकिन उसका विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जब उत्पादन-कर एक ही वस्तु पर लगाया जाता है (अथवा कुल वस्तुओं से कम पर लगाया जाता है) तो कर लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं के द्वारा खुदरा वस्तु के मूल्य के रूप में चुकाई जाने वाली जो राशि "माने गये या आरोपित खुदरा मूल्य" से अधिक होती है, वह कर के वास्तविक भार से अधिक होती है। यह स्मरण रखना होगा कि जेनकिन्स के अनुसार करापात के भी दो भ्रम होते हैं, एक तो सरकार की कर की आय और दूसरे, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वास्तविक भार का अतिरिक्त खुदरा मूल्य। लेकिन इससे ऊपर एक राशि और होती है जो आंशिक उत्पादन-कर की स्थिति में कर लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं के द्वारा चुकाई जाती है। एक स्थिति यह होती है जहाँ खुदरा वस्तु-मूल्य अतिरिक्त अथवा पूरक रूप में हस्तान्तरित किया जाता है; यह स्थिति कर के लागू होने से उत्पन्न होती है। जेनकिन्स मसब्रेव को इस बात के लिए गलत ठहराता है कि उसने इसे करापात में शामिल कर लिया है।

खुदरा वस्तु-मूल्य में जिस तरह से यह पूरक अन्तरण होता है उसका निक्षिप्त विवरण भी दे दिया जाता है। एक ही वस्तु पर लगाया गया कर अन्य समस्त वस्तुओं व सेवाओं की लागतों को कम कर देता है। इस प्रकार कर न लगी हुई वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं को उत्पादन-कर के लागू होने से ठीक उमी तरह से वास्तविक लाभ प्राप्त हो जाता है जिस तरह कि सरकार को सामान्य उत्पादन-कर और आंशिक उत्पादन-कर की स्थिति होता है। लेकिन कर न लगी हुई वस्तुओं के उपभोक्ताओं को यह लाभ पर लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं को क्षति पहुँचा कर ही होता है। जेनकिन्स के अनुसार कर लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं के द्वारा उठाये जाने वाले भार को अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले "लाभों" के सबर करने के लिए कराधान में जोड़ना अनुचित होगा। कर लगी हुई वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों का परिवर्तन कर लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं के द्वारा उठाये जाने वाले सबर कराधान की भांति की आवश्यकता से अधिक उल्लासित है। विवेक की यह भांति जो अन्य उपभोक्ताओं को दी जाने वाली

## करापात-सिद्धान्त की श्रद्धाति

छिपी हुई आर्थिक सहायता से बराबर हो जाती है, एक हस्तान्तरण-होती है, जिससे कर लगी हुई वस्तुओं के उपभोक्ता कर लगी हुई और कर लगी हुई वस्तुओं का उपभोग उसी अनुपात में वरके सदैव बच सकें जिस अनुपात में एक औसत घन्यवा प्रतिनिधि व्यक्ति इनका उपभोग करता

### पराविसिनी का योगदान

#### (The Parravicini Contribution)

गिमानिनो पराविसिनी ने करापात की इस सहस्र 12 में इटली प्रतिनिधित्व किया है। उसके तर्क में, जो वाउम रोलफ सिद्धांत की आलोच के रूप में स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है कुछ ऐसे सर्व हैं जो मसग्रैव 3 जैनकिन्स दोनों के तर्कों से कुछ अर्थों में मिलते जुलते हैं। यद्यपि पराविसिनी विवेचन अधिक परिष्कृत प्रतीत होता है, फिर भी यह ऊँ के विवेचन सबसे अधिक निकट है।

अपने मॉडल की सर्व के रूप में वह यह कल्पना कर लेता है कि मु की मात्रा और मुद्रा का प्रचलन-वेग स्थिर रहते हैं। उसके बाद वह दर्शाता है कि उत्पादन-कर के लागू होने से यह प्रतिजिया होती है कि मु का आय-वेग बढ़ जाता है। यह प्रभाव मुद्रा के "कार्य-भार" में कमी माध्यम से प्रगट होता है। "कार्य-भार" की यह कमी वर-घन्य की जि से उत्पन्न होती है। सामान्य उत्पादन-कर जो प्रायः वितरण के अन्तिम सोपा पर लगाया जाता है एक ऐसे राजकोपीय आय-वृत्त के मार्फत कोप एक कर लेता है जिसमें अधिक सामान्य निजी आय-वृत्त की तुलना में अपेक्षाक कम सम्बद्ध सोपान होते हैं। अतएव यदि मुद्रा की मात्रा और प्रचलन-वे दोनों स्थिर रखे जाते हैं तो सामान्य उत्पादन-कर के फलस्वरूप कीमतों सामान्य रूप से अवश्य ही वृद्धि हो जाती है।

### III आलोचना

पीछे करापात-सिद्धांत के जिन विभिन्न योगदानों का विवेचन किया गया है वह इतना सक्षिप्त है कि उसके जरिए पृथक्-पृथक् विश्लेषणों की

- 
12. Giannino Parravicini, "Imposte indirette su merce e livello generale dei prezzi," *Moneta e credito* (1954), 144-64; 298-312; "Imposte, moneta, e prezzi," *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, XV (1956), 111-36.

जिन्होंने भीर अटिलताओं को स्पष्ट कर गवना कठिन है। मैंने प्रयोग करने वाले के प्रमुख योगदानों का ही विवरण देने का प्रयाग किया है। कुछ सम्पादक यह गया है वह इन अनुभाग में स्पष्ट किया जायगा और मैं इस विषय पर मैं अपने विचार भी प्रकट करूँगा।

इस दृष्टि में जो प्रश्न सामिल हैं वे विस्लेषणात्मक होने की बजाय पद्धति में सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। कुछ पद्धतीय प्रश्न घुनाव के हैं जैसे जा गये हैं। ब्राउन, मगपेंस और जेनरिन्स के विस्लेषणों में जाने वाले अंतर उनकी परिभाषाओं व गैर-साम्यताओं के अन्तर्गत होने वाले अंतरों में बदले जा सकते हैं। इसके विपरीत कुछ विभिन्न दोनों के निष्कर्ष वस्तुतः उस मोड़ित ढाँचे पर निर्भर करने हैं। वे अपने विस्लेषणार्थ उपयुक्त मान लेते हैं। लेकिन पद्धतीय त्रुटियाँ भी हो सकती हैं और जहाँ तक रोलफ का सम्बन्ध है उसकी तरफ से इस सम्पूर्ण पाठ की बहस में इस तरह की भी त्रुटि हुई है, और उसके आलोचक त्रुटि को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं, हालाँकि प्रत्येक ने इसकी उप-ति तो स्वीकार की है।<sup>13</sup>

आगे के विवेचन में मैं निम्न कथनों का समर्थन करने का प्रयास करता हूँ :—

1. ब्राउन-रोल्फ का यह निष्कर्ष कि एक सच्चा सामान्य उत्पादन-प्रक्रिया की ओर हस्तान्तरित किया जाता है और कराधान उत्पादन के घनों के स्वामियों पर ही आता है, काफी सही है।

2. रोलफ का यह कथन गलत है कि ऐसा कर वस्तु-मिश्रण को प्रेरित नहीं करता है। लेकिन इस विषय पर ब्राउन, अपने विस्लेषण के अन्तिम सर्ग में, अपने कथनों में सावधान एवं सही है।

3. एक प्रांशिक उत्पादन-कर सामान्यतः साधनों के स्वामियों एवं र लगी हुई वस्तु के उपभोक्ताओं के द्वारा वहन किया जाता है; हालाँकि भारत का अधिकांश भाग साधारणतया साधनों के स्वामियों के द्वारा ही वहन किया जाता है।

3. अब्बोट ने इसे काफी स्पष्ट रूप से देखा है, लेकिन उसने भी इस प्रश्न को पूर्ण सामान्य ढंग से व्यक्त नहीं किया है। अब्बोट, पूर्वोद्धृत।

4. रोलफ अपनी पद्धतीय त्रुटि उस समय कर बैठता है जबकि वह एक कर का स्वतंत्र विश्लेषण करने का प्रयास करता है। उसकी त्रुटि एक आधारभूत विस्म की है क्योंकि इसमें अभ्यंशास्त्री के 'अन्य बातें पूर्ववत् रहें' नामक अस्त्र का अनुचित प्रयोग किया गया है।

5. प्रत्येक कर वास्तविक भार ढासता है क्योंकि यदि ऐसा भार नहीं डाले तो वह कार्यात्मक दृष्टि से व्यर्थ होता है।

6. मसग्रैव और जेनकिन्स के बीच अंतर करने के लिए हमें उनके विश्लेषणों में कर की निहित प्रकृति को स्पष्ट करना होगा।

7. जेनकिन्स की कर की धारणा परम्परागत विचार के ज्यादा अनुकूल है और यह करापात सिद्धांत के अर्थों को सीखा करने में सहायक होती है। लेकिन यदि मसग्रैव की धारणा का ठीक से उपयोग किया जाता है, तो यह अधिक सामान्य रूप से लागू की जा सकती है और इसी कारण से यह कुछ उद्देश्यों के लिए पद्धतीय दृष्टि से ज्यादा अच्छी मानी जाती है।

8. करापात-सिद्धांत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मौद्रिक मान्यता यह है कि अन्तिम वस्तुओं की कीमतों के किसी सूचकांक को स्थिर करने के लिए सरकारी हस्त उठाया जाय। केवल इस मान्यता की सहायता से ही करापात की धारणा की दृष्टि से मौद्रिक नीति के भार से पृथक् किया जा सकता है।

चूंकि ऊपर के कथन एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक का विवेचन स्वतंत्र ढंग से नहीं किया जायगा। लेकिन इन कथनों का प्रयोग सुविधाजनक रूपरेखा के तौर पर करना लाभप्रद होगा।

1. इस बात के सम्बन्ध में काफी सहमति प्रतीत होती है कि एक पूरे सामान्य उत्पादन-कर के आपात के बारे में डाउन-रोलफ निष्कर्ष सही है। यदि कीमतों को एक से बढ़ कर की राशि के बराबर भी बढ़ने दिया जाता है, जैसा कि रूबिन के स्फीतिकारी मॉडल में होता है, तो भी साधनों के स्वामी गैर-साधन स्वामियों की तुलना में ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाते हैं; लेकिन इसमें यह भान लिया जाता है कि कर के बिना भी मुद्रास्फीति होती। साथ में यह भी सही है कि हमें मौद्रिक अधिकारियों की स्फीतिकारी नीतियों के लिए कर को उत्तरदाई नहीं ठहराना चाहिए। मसग्रैव अपने सम्पूर्ण-उपभोग के मॉडल में सामान्य वस्तु-कर और साधनों की माप पर घाय-कर के बीच

कारीशियों और जटिलताओं को स्पष्ट कर गचना कठिन है। मैंने प्रत्येक भाग लेने वाले के प्रमुख योगदानों का ही विवरण देने का प्रयाग किया है। जो कुछ सम्पष्ट रह गया है वह इस अनुभाग में स्पष्ट किया जायगा और साथ में इस विषय पर मैं अपने विचार भी प्रकट करूँगा।

इस दृष्टि में जो प्रश्न सामान्य हैं वे विश्लेषणात्मक होने की बजाय मूलतः पद्धति में सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। कुछ पद्धतीय प्रश्न चुनाव के दृष्टियों में बदलते जा सकते हैं। बाउन, मगसेव और जेनरिंग्स के विश्लेषणों में पाये जाने वाले अन्तर उन्हीं परिभाषाओं व संर-राजकीय पूर्वमान्यताओं के चुनाव में होने वाले अन्तरों में बदलते जा सकते हैं। इसके विपरीत ह्यू व पराविसिनी दोनों के निष्कर्ष वस्तुतः उस मौद्रिक दृष्टि पर निर्भर करते हैं जिसे वे अपने विश्लेषणार्थ उपयुक्त मान लेते हैं। लेकिन पद्धतीय त्रुटियाँ भी हो सकती हैं और जहाँ तक रोलफ का सम्बन्ध है उन्हीं तरफ से इन सम्पूर्ण कराधात की बहस में इस तरह की भी त्रुटि हुई है, और उसके आलोचक इस त्रुटि को स्पष्ट करने में अमफल रहे हैं, हालांकि प्रत्येक ने इसकी उपस्थिति तो स्वीकार की है।<sup>13</sup>

आगे के विवेचन में मैं निम्न कथनों का समर्थन करने का प्रयास करूँगा :—

1. बाउन-रोल्फ का यह निष्कर्ष कि एक सच्चा सामान्य उत्पादन-कर पीछे की ओर हस्तांतरित किया जाता है और कराधात उत्पादन के साधनों के स्वामियों पर ही आता है, काफी सही है।

2. रोलफ का यह कथन गलत है कि ऐसा कर वस्तु-मिश्रण को परिवर्तित नहीं करता है। लेकिन इस विषय पर बाउन, अपने विश्लेषण के सीमित संदर्भ में, अपने कथनों में सावधान एवं सही है।

3. एक प्राथमिक उत्पादन-कर सामान्यतः साधनों के स्वामियों एवं लगी हुई धरतु के उपभोक्ताओं के द्वारा वहन किया जाता है; हालांकि मार का अधिकांश भाग साधारणतया साधनों के स्वामियों के द्वारा ही किया जाता है।

अब्वोट ने इसे काफी स्पष्ट रूप से देखा है, लेकिन उसने भी इस प्रश्न को पूर्ण सामान्य ढंग से व्यक्त नहीं किया है। अब्वोट, पूर्वोद्धृत।

4. रोल्ट अपनी पद्धतीय त्रुटि उस समय कर बैठता है जबकि यह एक कर का समतल विश्लेषण करने का प्रयास करता है। उसकी त्रुटि एक आधारभूत त्रुटि की है, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्री के 'अन्य बातें पूर्ववत् रहें' नामक अर्थ का अनुचित प्रयोग किया गया है।

5. प्रत्येक कर वास्तविक भार डालता है क्योंकि यदि ऐसा भार नहीं डाले तो वह कार्यात्मक दृष्टि से व्यर्थ होता है।

6. मसरोव और जेनकिन्स के बीच भ्रंतर करने के लिए हमें उनके विश्लेषणों में कर की निहित प्रकृति को स्पष्ट करना होगा।

7. जेनकिन्स की कर की धारणा परम्परागत विचार के ज्यादा अनुकूल है और यह करापात सिद्धांत के अर्थो को तीखा करने में सहायक होती है। लेकिन यदि मसरोव की धारणा का ठीक से उपयोग किया जाता है, तो यह अधिक सामान्य रूप से लागू की जा सकती है और इसी कारण से यह कुछ उद्देश्यों के लिए पद्धतीय दृष्टि से ज्यादा अच्छी मानी जाती है।

8. करापात-सिद्धांत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मौद्रिक मान्यता यह है कि अन्तिम वस्तुओं की कीमतों के किसी सूचकांक को स्थिर करने के लिए सरकारी बंदम उठाया जाय। केवल इस मान्यता की सहायता से ही करापात की धारणा की दृष्टि से मौद्रिक नीति के भार से पृथक् किया जा सकता है।

चूंकि ऊपर के कथन एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक का विवेचन स्वतन्त्र ढंग से नहीं किया जायगा। लेकिन इन कथनों का प्रयोग सुविधाजनक रूपरेखा के तौर पर करना लाभप्रद होगा।

1. इस बात के सम्बन्ध में काफी सहमति प्रतीत होती है कि एक पूरे सामान्य उत्पादन-कर के आपात के बारे में वाउन-रोल्ट निष्कर्ष सही है। यदि कीमतों को एक से कर की राशि के बराबर भी बढ़ने दिया जाता है, जैसा कि हमारे स्थितिकारी मॉडल में होता है, तो भी साधनों के स्वामी गैर-साधन स्वामियों की तुलना में ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाते हैं; लेकिन इसमें यह मान लिया जाता है कि कर के बिना भी मुदास्फीति होती। साथ में यह भी सही है कि हमें मौद्रिक अधिचारियों को स्थितिकारी नीतियों के लिए कर को उत्तरदाई नहीं ढहराना चाहिए। मसरोव अपने सम्पूर्ण-उपभोग के मॉडल में सामान्य वस्तु-कर और साधनों की आय पर आय-कर के बीच

समानता स्वीकार करना है, और जैसा कि हम बना चुके हैं, वैयक्तिक पूंजी-सिद्धांत की स्थिति में सम्पूर्ण-उत्पन्न का मौल्य तुलनात्मक स्थिति में विश्लेषण के लिए एक सामान्य ढांचा बन जाता है । वास्तव में यह स्थान ऐसा नहीं है जहां पूंजी-सिद्धांत के महान और घात भी जारी अज्ञात समझे जाने वाले घातों के विवेचन में प्रवेश किया जाय, लेकिन मैं यह बनाना चाहता हूँ कि मैं मास्ट के सिद्धांत को पसन्द करता हूँ जो रोलफ के विश्लेषण में निहित है । जैनकिन्स रोलफ के निष्कर्ष से कम स्थिति में सहमत होता है जब कि कर सरकार के द्वारा शरीदी गई वस्तुओं और निजी व्यक्तियों के द्वारा शरीदी गई वस्तुओं दोनों पर लगाये जाने हैं । इस विनिष्ट स्थिति में जैनकिन्स का योगदान इस बात को दर्शाने में है कि एक कर उस समय तक सामान्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उनमें सरकारी शरीद शामिल नहीं करली जाय ।

विश्लेषण की आरीकियाँ एवं पद्धति की बातें चाहे जितनी महत्वपूर्ण हों, लेकिन इनके बारे में होने वाली बहस से वह मूलभूत सहमति नहीं छिप जानी चाहिए जो सामान्य उत्पादन करों के आपात के स्थान में सम्बन्ध में पाई जाती है । आर्थिक समुलन के घात काफी सरसदा से ऐसी परिस्थितियों पर लागू किये गये हैं और अब भी किये जा रहे हैं जहां वे काम नहीं करते हैं और, यदि प्रयुक्त किये गये, तो गसत परिणामों की तरफ से जायेंगे । और यदि अर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में पेचीदा दृष्टिकोण अपना लेते हैं, तो समाज में साधारण रूप से इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले नीति-निर्धारक समूहों एवं राजनीतियों को यह जानना चाहिए कि एक सामान्य उत्पादन-कर प्रथम आर्थिक उत्पादन-करों के एक पूरे समूह में, और एक आनुपातिक आय-कर में वास्तव में मामूली-सा अन्तर ही है ।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान बहस में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने, केवल जैनकिन्स को छोड़कर, लेकिन स्वयं रोलफ को शामिल करते हुए, इस तथ्य को भुला दिया है कि सामान्य उत्पादन-करों के सम्बन्ध में ब्राउन व रोलफ के विश्लेषणों में मूलभूत अन्तर है । अन्तर इस प्रकार है कि ब्राउन का विश्लेषण तो निश्चित रूप से संतुलित-बजट करापात के सन्धि में डला है जिसमें सरकार की तरफ से कर से नई आय के प्राप्त करने एवं व्यय करने पर विशेष ध्यान दिया गया है । ब्राउन इस बात को स्पष्टतः स्वीकार करता है कि कर के फलस्वरूप सरकार के पास व्यय के लिए अधिक राशि हो जायगी

और व्यक्ति के पास कम हो जायगी। "वैयक्तिक रूप से लोगों के पास व्यय के लिए कम मुद्रा होगी। सामूहिक रूप से, बिक्री-कर से प्राप्त आय के रूप में जो सरकार के द्वारा खर्च की जानी है, उनके पास व्यय के लिए अधिक राशि होगी।"<sup>14</sup> इसकी वजह से ब्राउन यह कहते समय बहुत सावधान हो जाता है कि कर के फलस्वरूप उत्पत्ति की बनावट अपरिवर्तित रह जाती है। जल्दी से पढ़ने पर ऐसा लग सकता है कि उसने उत्पत्ति की बनावट को अपरिवर्तित माना था, लेकिन उसने एक फुटनोट में विशेषरूप से यह स्वीकार किया है कि यदि सरकारी मांग का ग्राह्य व्यक्तिगत मांग से भिन्न होता है, तो यह निष्कर्ष लागू नहीं होगा।<sup>15</sup> यह एक रुचिप्रद बात है कि रीस्क, ब्राउन के धितोपण का जिक्र करते हुए तो उनमें निहित विभेदात्मक करापात के पहलुओं की स्वीकार करता है, लेकिन वह यह पहचानने में विफल रहता है कि वस्तु-निर्धन के सम्बन्ध में ब्राउन का प्रारम्भिक निष्कर्ष अपनी आर्थिक सत्यता के लिए इस पूर्वानुमानित ढाँचे पर ही निर्भर करता है।<sup>16</sup> यदि सरकारी व्यय धनदाता धन्य करों में पूरक परिवर्तन नहीं होने दिये जाते हैं तो सामान्य उत्पादन-कर के लागू होने से ऐसी शक्तिशाली उत्पन्न हो जायेंगी जो उत्पत्ति की बनावट को परिवर्तित कर देंगी।

यह निम्न विधि से दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर एक सामान्य उत्पादन-कर लागू किया जाता है और साथ में सरकार की तरफ से भी जाने वाली धन्य करों की द्रव्य के रूप में वसूली

14. ब्राउन, पूर्वोद्धृत,

15. "यह तो सम्भव है कि कम व्यक्तिगत व्यय और अधिक सामूहिक व्यय विभिन्न चिह्न की वस्तुओं की सापेक्ष भावों और उनकी सीमात सागत को परिवर्तित कर दें और इस प्रकार उनकी सापेक्ष कीमतों पर कुछ प्रभाव डाल सकें।"

16. "ब्राउन के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन-कराधान की एक सामान्य प्रणाली उत्पत्ति की बनावट व वस्तु-मूल्यों को कराधान की उस प्रणाली की तुलना में निरपेक्ष व सापेक्ष रूप में अपरिवर्तित रहने देती है जो समान भाग देती है और योग के अर्थ में जिसके घोषणा सम्बन्धी प्रभाव कुछ भी नहीं होते हैं।"

"A Proposed Revision of Excise-Tax Theory," *Journal of Political Economy*, LX (1952), 107.



और द्रव्य के रूप में सरकारी व्यय अपरिवर्तित बने रहते हैं। (रोल्फ की मान्यताएं ये ही हैं।) सरकार के सम्बन्ध में यह मान्यता स्वीकार करनी होगी कि वह एकत्र आय का संचय कर लेती है, हालांकि रोल्फ ने वहीं भी इसकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं की है। कर-संग्रह अर्थव्यवस्था पर अपस्फीतिकारी प्रभाव डालेगा, साधनों के स्वामियों की आमदनी घट जायगी, कुछ समूहों की आमदनी और अन्य स्रोतों से सरकार की आमदनी (मुद्रा में) अपरिवर्तित बनी रहेगी। जहां तक अन्तिम दोनों की मांग का प्रारूप साधनों के स्वामियों की मांग के प्रारूप से भिन्न होगा, वहां तक वस्तु-मिश्रण में परिवर्तन करना होगा।

अन्य दशाओं में जहां पुराने कर की जगह नया कर लगा दिया जाता है, अथवा एकत्र की गई नई आय अतिरिक्त सरकारी खरीद में पूंजी लगाने में प्रयुक्त होती है, वहां राजकोपीय प्रक्रिया के फलस्वरूप वस्तु-मिश्रण स्पष्टतः बदल जायगा।

3. रोल्फ का बड़ा योगदान सम्भवतः इस बात में है कि उसने सामान्य उत्पादन-करों के विक्षेपण को घासिक उत्पादन-करों पर लागू किया है और उसने यह बतलाया है कि घासिक उत्पादन-करों के आपात का एक भंश कर लगी हुई वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर घाने की बजाय साधनों के स्वामियों पर घायेगा। आउन का विक्षेपण इतना विस्तृत नहीं है, और घासिक-मनुष्य के निष्कर्ष लगभग व्यापक रूप से घासिक उत्पादन-करों पर भी लागू किये गये हैं। कुछ उद्देश्यों के लिए घासिक मनुष्य-विक्षेपण उपयुक्त रहता है, लेकिन धारणात्मक दृष्टि से सामान्य-मनुष्य का डोचा सदैव ज्यादा गहरी होता है। घासिक-मनुष्य पर जोर देने का कारण यह प्रतीत होता है कि उपभोक्ताओं पर इकट्ठा कराया जाता है जो बिना कर लगी हुई वस्तुओं की तुलना में कर लगी हुई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से उत्पन्न होता है। जिनके लिए घासिक उत्पादन कर के मांडल में साधनों के स्वामियों एवं उपभोक्ताओं के सापेक्ष भार को घटाने में अत्यधिक मदद करना है।

4. रोल्फ उस समय एक मूलभूत पड़ोसी चुटि कर देता है जबकि वह एक नये कर का विक्षेपण अन्य करों अथवा सांख्यिक व्यय में होने वाले परिवर्तनों से घटकर करके करने का प्रयास करता है और कर-वैलि मोडिफ़ाइंग का मनुष्य के पुरे परिवारों तक पड़ने में अग्रसर रहता है। उपर्युक्त प्रकार है कि सांख्यिक व्यय और अन्य करों को यथास्थित मान कर एक भव्य

इस तरह के प्रभावों का विश्लेषण करना पूर्णतया उचित होगा। लेकिन इस दृष्टि-कोण के घपनाने पर कर के अपरस्फीतिकारी प्रभावों पर पूर्णतया विचार किया जाना चाहिये। मौद्रिक दशाओं को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में यथास्थिर नहीं माना जा सकता है। जब रोलफ सभी सम्भव पुरक प्रभावों को स्पष्टतया अथवा इन्हें मुलाकर यथास्थिर मान लेता है, तो वह एक ऐसे प्रश्न का एकदम सतत प्रयोग करता है जो अर्थशास्त्रियों के लिए काफी उपयोगी रहा है और ठीक से प्रयुक्त होने पर जिससे काफी सहायता मिल सकती है। हमारे लिए उन चल-राशियों को यथास्थिर मानना उचित होगा जो या तो उस चल-राशि (variable) की गति से पूर्णतया अप्रभावित रहती है जिस पर हमारा विश्लेषण कार्य करता है, अथवा यदि प्रभावित होती है, तो ये इतनी कम मात्रा में बदलती है कि स्थिरता की मान्यता हमारे निष्कर्षों को व्यर्थ सिद्ध नहीं कर देती है। लेकिन उन चीजों को स्थिर मानना अनुचित होगा जो हमारे विश्लेषण की प्रक्रिया के कारण अवश्य बदलती हैं। दूसरे शब्दों में, उन मात्राओं को स्थिर मानना अनुचित होगा जो सक्रिय चल-राशि (action variable) के साथ अवश्य बदलती हैं। कीमत-सिद्धान्त में हम एक वस्तु की कीमत को बदलते हैं और मौद्रिक आय के अपरिवर्तित रहने की मान्यता के आधार पर इसके प्रभावों की छानबीन करते हैं। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन मौद्रिक आय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन यदि हम एक ऐसे संस्थागत ढाँचे का अध्ययन करते हैं जिसमें मजदूरी की दरें एक ही कीमत से बांध दी जाती हैं, तो हम किसी महत्वपूर्ण (जैसे गले में घण्टी वाली घगली भेड़) वस्तु की मांग की जाव में मौद्रिक आय के स्थिर रहने की प्रचलित मान्यता का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अथवा, यदि हम अर्थशास्त्र के बाहर से कोई उदाहरण लें तो मान लीजिये कि हम एक जलाशय में जल की सतह को नीचे लाने के प्रभावों का विश्लेषण करना चाहते हैं। यहाँ, तापक्रम आदि जैसी चीजों को 'अन्य बातों के पूर्ववत्' रहने में शामिल करना नामुमकिन होगा, लेकिन हम इसके अन्तर्गत सम्बन्धित जलधारा के अन्य सभी घातकों (receptacles) के जल के स्तर को शामिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रोलफ ने यही करने का प्रयास किया है। उसने बिना आवश्यक पूर्व प्रभावों का पता लगाये एक कर के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। वास्तव में यह एक चुनाव का विषय है कि तीन शस्तों में से किसका चुनाव लिया जाय। कोई चाहे तो मतपत्र की पसन्द के अनुसार अन्य कर में कमी का मार्ग चुन सकता है। अथवा संतुलित-बजट-विधि प्रयुक्त की जा सकती है। अथवा, यदि कोई चाहे

तो एक कर में परिवर्तन कर सकता है, और सरकारी खर्च घटाना अन्य करों को बढ़ाते बिना उत्पन्न होने वाले मौद्रिक असन्तुति के पूरे प्रभावों का पना लगा सकता है। यदि रोकफ़ ऐसा कर लेता तो उसका विस्तारण बहुत मुश्किल होता। लेकिन आगिर का चुनाव तो तीनों में सबसे कम उपयुक्त प्रतीत होता है। यही मुख्य बात यह है कि इन तीनों में से एक का चुनाव करना होगा और जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो, एक विस्तृत अर्थ में, निरीक्षण करारगत की धारणा को छोड़ना पड़ता है। अन्य वन-राशियों में पूरक परिवर्तन होने चाहिये। विस्तारणकर्ता तो बेवम यही कर सकता है कि वह उन पूरक वन-राशियों का चुनाव कर सके जिन्हें वह बढ़ाना चाहेगा।

यहाँ पर रोकफ़ के साथ व्यापक करने के लिए यह स्मरण रखना होगा कि केवल उसी में अन्य बातें पूर्ववत् रहें का दुरुपयोग नहीं किया जा। इस तरह की व्यापक अर्थशास्त्रियों में आम तौर से पाई जाती है, और यह विशेष रूप से उनमें देखने को मिलती है जिन्होंने मार्शल के माग-वक्र के सम्बन्ध में दिये गये हिवस के वर्णन को स्वीकार किया है और काम में लिया है। इस विषय पर मिल्टन फ्रीडमैन (Milton Friedman) का पद्धतीय योगदान वास्तव में इस बात को दर्शाने में है कि परम्परागत माग-वक्र की मान्यताएँ परस्पर कैसे असंगत हैं, अर्थात्, उनमें किस तरह से 'अन्य बातें पूर्ववत् रहें' का दुरुपयोग किया गया है और उनसे किस प्रकार विस्तारण की दृष्टि से गलत परिणाम निकलते हैं।<sup>17</sup>

17. Milton Friedman, "The Marshallian Demand Curve," *Journal of Political Economy*, LVII (1949), 463-95; "The 'Welfare' Effects of an Income Tax and an Excise Tax," *Journal of Political Economy*, LX (1952), 25-33. उसका निबन्ध "The Methodology of Positive Economics," भी देखिये जो *Essays in positive Economics* में अन्य दो निबन्धों के साथ शामिल किया गया है (Chicago : University of Chicago Press, 1953).

अन्य बातें पूर्ववत् रहें के उपयोग से सम्बन्धित सामान्य विवेचन के लिए मेरा लेख देखिए "Ceteris Paribus : Some Notes on Methodology," *Southern Economic Journal*, XXIV (1958), 259-70.

5. रोलफ ने कर की परिभाषा में इसे एक भौद्रिक वस्तु बतलाया है, अर्थात् यह व्यक्ति से सरकार की तरफ किया जाने वाला एक हस्तान्तरण भुगतान है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इससे कोई वास्तविक भार नहीं पड़ता है। यह राजकोषीय सिद्धांत में परम्परा से काफी दूर जाने का सूचक है और इस पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिये। चूंकि एक कर का उपयोग केवल मुद्रास्फीति-निरोधक अस्त्र के रूप में किया जा सकता है, यहाँ इसका सांख्यिकीय ध्येय की भाँसा से कोई सम्बन्ध न हो, इसलिए रोलफ ने कर का इस विशुद्ध भौद्रिक साधन के रूप में विश्लेषण करना ही पसन्द किया है। वास्तव में ऐसा करना बिलकुल सही है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पद्धति-सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा।

अब हम कर के सम्बन्ध में उसका ऐसा उदाहरण लेते हैं जिससे कोई वास्तविक भार नहीं पड़ता है। यह एक ऐसा कर होता है जो एकमात्र मुद्रा-स्फीति को रोकने के प्रयोजन से ही लगाया जाता है और जो इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल होता है।<sup>18</sup> वस्तुओं की कीमतें औसत रूप से कर से पूर्व और कर के पश्चात् एव-सी ही रहती हैं। निजी उपयोग के लिए वास्तविक पदार्थों का वही समूह उत्पादित होता है क्योंकि कर के कारण सरकार की तरफ से किया जाने वाला साधनों का उपयोग परिवर्तित नहीं होता है। यह समझना आसान है कि यह निष्कर्ष कैसे निकाला गया है कि ऐसे कर का कोई वास्तविक भार नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रोलफ का ध्वनि-विश्लेषण दोषपूर्ण हो जाता है और वह कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। कर से पूर्व एव बाद में व्यक्तियों की सापेक्ष स्थितियाँ समान हो सकती हैं। लेकिन सही तुलना पूर्व एव पश्चात् की नहीं होती है। यह तो कर के बिना और कर के साथ की होती है। सामान्य आर्थिक विश्लेषण में जो असुलन की दशाओं से प्रारम्भ होता है, इस अन्तर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि विश्लेषण अस्तुत्तन की दशा से प्रारम्भ होता है तो यह महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। यदि करारोपण मुद्रास्फीति को रोकने भर में सफल होता है, जो अन्यथा भी हो सकता था, तो यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक स्थिति असुलन की है। ऐसी स्थिति में कर के प्रभावों की तुलना मुद्रास्फीति के प्रभावों से की जानी चाहिए जो कर के अभाव में उत्पन्न होती। स्थितिक विश्लेषण में सर्वदा एक ही समय में वैकल्पिक दशाओं की तुलना की जाती

18. Rolph, "Government Burdens and Benefits: Comment,"  
American Economic Review, XLIII (1953), 539.

है, न कि एक अवधि में उत्तरोत्तर दशाओं की। यह तो स्पष्ट है कि यदि प्रभाव की दृष्टि से कर की तुलना मुद्रास्फीति से की जाती है तो कर के लगने से वास्तविक भार बहुत पड़ता है। जो व्यक्ति और समूह मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते उन पर कर के कारण वास्तविक भार पड़ता है। जिन समूहों की हानि उठानी पड़ती वे बदले में लाभ प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। एक विस्तृत अर्थ में, मुद्रास्फीति को एक तरह का कर माना जा सकता है और रोलफ का विश्लेषण वास्तव में विभेदात्मक करापात का रूप ले लेता है।

लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या यह आवश्यक है कि एक कर जो केवल मुद्रास्फीति को रोकने के लिए लगाया गया है, ऊपर-बाँटित धन में कुछ समूहों पर वास्तविक भार डाले और कुछ को लाभ पहुँचावे? क्या कुछ व्यक्तियों पर डाला जाने वाला वास्तविक भार ऐसे कर के साधू होने का आवश्यक परिणाम माना जायगा? इसका प्रारम्भिक उत्तर नकारात्मक मासूम देगा। धारणा की दृष्टि से यह सम्भव है कि एक कर इस तरह से साधू किया जाय ताकि इसका भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़े जिन्हें मुद्रास्फीति से हानि होती और यह भार उन पर मुद्रास्फीति की स्थिति में पड़ने वाले वास्तविक भारों के अनुपात में ही हो। इससे सभी व्यक्ति ठीक उसी सापेक्ष स्थिति में आ जायेंगे जिसमें कि वे मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने पर होते। लेकिन यह सम्भावना तो केवल धारणा की दृष्टि से ही है क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा कर कभी लागू नहीं करेगी। और इस बात को दशानि के लिए हथारे लिए ऐसे कर की राजनीतिक दृष्टि से अभ्यावहारिकता पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर कार्यात्मक दृष्टि से व्यर्थ (functionally useless) होगा। यदि कर का प्रयोजन मुद्रास्फीति को रोकना है तो यह सफल होगा। इसलिए ऐसा लगेगा कि इसका कोई प्रयोजन है। लेकिन हमें इसके पीछे जाकर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकारी दृष्टि को देखना होगा। यदि व्यक्तियों व समूहों को उनी सापेक्ष स्थिति में रहने देना जिसमें कि वे मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने पर होते, तो प्रश्न उठता है कि सरकार की मुद्रास्फीति को रोकने में सचि क्यों होंगी? मुद्रास्फीति तो इसलिए अवांछनीय है कि यह आय का पुनर्वितरण करती है और ऐसा यह एक अवांछनीय ढंग से करती है। यदि मुद्रास्फीति ऐसा नहीं करती तो यह सम्भवता बर्तन होगा कि बाह्य सरकार निरपेक्ष क्रियमों के तहत की बरी बरबाद करती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक

ऐसे कर से जो केवल मुद्रास्फीति को ही रोकने वाला है, कुछ व्यक्तियों व समूहों पर अवश्य ही वास्तविक भार पड़ेगा। यह तो निश्चय है कि वास्तविक भार पूर्णतः अथवा अंशतः वास्तविक लाभ से सन्तुलित हो जाता है, लेकिन यह स्थिति उन करों से भिन्न नहीं है जो गई सरकारी सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए सपाये जाते हैं।

रोल्फ सम्भवतः पिछले पैरा के तर्क को स्वीकार करेगा। वह मानता है कि ऐसे कर से भ्रष्ट या पुनर्वितरण हो जाएगा। लेकिन वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि समग्र पहुँचों पर ध्यान केन्द्रित करने से कोई वास्तविक भार नहीं पड़ता है। यदि निजी कार्यों के लिए उपलब्ध होने वाले वास्तविक साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या यह कहना उचित होगा कि समाज पर वास्तविक भार पड़ रहा है? यह कहना कि ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन पुनर्वितरण अवश्य होता है, वस्तुतः यह कहने के समान है कि व्यक्तियों के बीच उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है। जहाँ तक पुनर्वितरण का प्रश्न है हाँ उठाने वाली पर पड़ने वाला वास्तविक भार लाभ प्राप्तकर्ताओं को पिसने वाले वास्तविक लाभ से अधिक या कम हो सकता है। केवल इसी मान्यता के आधार पर कि किसी भी विद्या में होने वाले भ्रष्ट के शीघ्र परिवर्तन सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, हम इन विचार का समर्थन कर सकते हैं कि समग्र वास्तविक भार शून्य होगा। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह परम्परागत विचार कि सभी करों से वास्तविक भार पड़ता है—रोल्फ के प्रहार से कोई बुरी तरह से विचलित नहीं हो पाया है।

6. यद्यपि ममत्रेव और जैनविन्स दोनों में से किसी ने भी अपनी कर की सम्यक्त परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी मेरा विचार है कि यदि हम उनके वर्णन में ऐसी परिभाषाओं को 'बुझने का' प्रयास करें तो उनके विरूपण प्रविष्ट स्पष्ट हो सकेंगे। ममत्रेव कर की परिभाषा सम्भवतः इस तरह में 'करेगा' कि 'यह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से दूर सामाजिक साधनों के उपयोग के स्वाभाविक वा हन्तान्तरण है' जो सरकार की राजकोषीय विद्या से उत्पन्न होता है। जैनविन्स कर की परिभाषा सम्भवतः यों 'करेगा' कि "यह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की तरफ से सरकार की ओर दिया जाने वाला सामाजिक साधनों के उपयोग के स्वाभाविक वा हन्तान्तरण है" जो सरकार की राजकोषीय विद्या में उत्पन्न होता है। स्पष्ट रहे कि ये परिभाषाएँ समान हैं। और केवल "सरकार की ओर" के शब्दों का है जो जैनविन्स की

परिभाषा के लिए मगधेय की अवस्था परिभाषा में जोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार के कारण मगधेय गुदरा वस्तु-मूल्यों के धार्मिक प्रसारण को अपने विद्वेषण में शामिल कर पाना है जो जैनकिन्स के वगधान-विद्वेषण में रह गया है। जैनकिन्स की परिभाषा इनको कराधान से अलग कर देगी और यह इन भारों को "भूटा वगधान" बहेगा। वास्तव में यह स्मरण रखना होगा कि यदि कर के सम्बन्ध में मगधेय की प्रस्तावित धारणा स्वीकार कर ली जाती है जो कर से उत्पन्न होने वाली वास्तविक आय की कमी को उग दूँगी भी शामिल करती है जबकि इन कमी का धारणा यह होता है कि व्यक्तियों के बीच ऐसे हस्तान्तरण हुए हैं जो सरकार के जरिए सम्पन्न नहीं किये गये। तो इसके अनुकूल ही सरकारों लाभ की धारणा को भी स्वीकार करना होगा। यदि करों की परिभाषा में गुदरा वस्तु-मूल्यों के धार्मिक हस्तान्तरणों को शामिल किया जाता है, तो सरकारी लाभों की परिभाषा में इन हस्तान्तरणों के पास वालों को मिलने वाले लाभ भी शामिल करने होंगे।

7. अब प्रश्न यह रह जाता है कि कर की इन दो धारणाओं में से कौन-सी ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी। (यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि दोनों परिभाषाएँ सम्बन्धित लेखकों पर उनके विद्वेषण के परिणामस्वरूप "आरोपित" की गई हैं। वास्तव में प्रत्येक लेखक उस परिभाषा को अस्वीकार कर सकता है जो उस पर आरोपित की गई है। जैनकिन्स की धारणा स्पष्टतः परम्परागत राजकोपीय सिद्धान्त से अधिक मेलाती है। यदि व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच वास्तविक आय के हस्तान्तरण सरकार की राजकोपीय क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं तो भी वे धारणा कभी करों अथवा लाभों में शामिल किये जाते हैं। अनेक उद्देश्यों की दृष्टि से यही रचना उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि जैनकिन्स का विद्वेषण बतलाता है, इसकी वजह से कर के लागू होने से सरकार और अन्य समूहों को प्रदान किये जाने वाले वास्तविक साधनों के बीच एक तीव्र अंतर पैदा करना सम्भव होता है। जब समग्र कर-प्रणाली की कार्यकुशलता का अध्ययन करना होता है तो इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं।

लेकिन जैनकिन्स की धारणा उस समय कुछ कमजोर प्रतीत होती है जब कि हम उसके विद्वेषण को रोलफ के द्वारा स्वीकार की गई दशायों में लागू करते हैं। यदि कर विषुद्ध रूप से मौद्रिक होता है, धर्मानु यह मुद्रा स्फीति को रोकने मात्र में सफल होता है, तो सरकार की तरफ वास्तविक साधनों का हस्तान्तरण नहीं होता है। कर के फलस्वरूप होने वाले वास्तविक

धर्म के हस्तान्तरण केवल व्यक्तियों एवं समूहों के बीच ही होते हैं, और ये राजकोप के जरिए वास्तविक साधनों को ले जाये बिना ही सम्पन्न हो जाते हैं। यदि जैनकिन्स का विश्लेषण रोल्फ के उपर्युक्त भाषणे पर विशेष रूप से साधु किया जाय तो कर के सम्बन्ध में मसग्रैव का विचार स्वीकार करना आवश्यक हो जायगा। जैनकिन्स की धारणा उस समय तो ठीक कार्य करती है जब कि हम विभेदात्मक अथवा सदुत्तित-बबट-करापात के क्षेत्र में रहते हैं। मेरे विचार में कई उपयुक्त कारणों से राजकोपीय सिद्धान्त की इन्हीं सीमाओं में रचना उचित होया और विश्लेषण में सम्पूर्ण मौद्रिक सिद्धान्त का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कुछ विश्लेषणकर्त्ता इस अधिक परम्परागत सीमाओं से परे जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ तक "मसग्रैव" की कर-सम्बन्धी धारणा एक लाभप्रद पद्धति के अनुकूल अस्त्र भवश्य प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत हम किसी भी सम्भव होने वाली राजकोपीय क्रिया को लेकर उसके प्रभावों की जाँच कर सकते हैं और जो प्रभाव व्यक्तियों की वास्तविक आय को घटाते हैं उनको 'कर' और जो व्यक्तियों की वास्तविक आय को बढ़ाते हैं उनको 'लाभ' कह सकते हैं। ऐसा करते समय हमें विश्लेषण की कुछ सीधता का परिचय करना पड़ेगा जो जैनकिन्स के वर्णन में विद्यमान है, लेकिन सभी परिस्थितियों का अध्ययन कर सकने की अतिरिक्त क्षमता मिल जाने से यह त्याग करना उचित कहा जा सकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दो धारणाओं का होना उचित है। दोनों ही उपयोगी हैं, और विश्लेषक को, सदैव की भाँति, अपने विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त अस्त्रों का चुनाव करना चाहिए।

8. यदि वर्तमान बहुसंख्यक भाग लेने वाले उस मौद्रिक ढाँचे की स्पष्ट परिभाषा करने पर ध्यान देते जिममें कि विश्लेषण किया गया है, तो इस बहुसंख्यक का अधिकांश अंश काफी स्पष्ट हो जाता। वास्तव में कोई घबरेली ऐसी विशिष्ट मौद्रिक मान्यता नहीं है जो "सही" कही जा सके। प्रश्न चुनाव का है और चुने गये मौद्रिक ढाँचे का करापात के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी यह उचित कि अधिकांश विवाद करापात और "मौद्रिक नीति के अभाव" के बीच अंतर करने की विफलता के कारण हुआ है, इस बात को बतताता है कि "उत्तम" और "निष्ठ" मौद्रिक मान्यताएँ अवश्य होती हैं।

मेरी राय में विश्लेषण के प्रारम्भ में इस बात को ध्यान लेने के पक्ष में प्रबल तर्क दिया जा सकता है कि मौद्रिक अधिकारी एक ठोस नियम को लागू



करने में सफल होते हैं जो अन्तिम वस्तु-मूल्यों के ठीक से परिभाषित सूचकांक की समग्र रूप से होने वाली स्थिरता की गारंटी देता है। मितव्ययिता के आधार पर इस मौद्रिक मान्यता का समर्थन किया जा सकता है; यह सामान्य मुद्रास्फीति अथवा अपस्फीति के आपात और साथ में ऐसे आपात को स्वयं करापात से पृथक करने की समस्या पर विचार करने की सम्पूर्ण आवश्यकता को मिटा देता है। इस मॉडल में सामान्य बिजली या उत्पादन-कर के लागू होने से उत्पन्न होने वाली वास्तविक आय की कमियाँ करापात के ग्राह्य का निर्माण करती हैं। और यह काफी स्पष्ट है कि वस्तु-मूल्यों और साधन-मूल्यों में कोई भी "जोड़" साधन-मूल्यों को नीचे खिंचकर ही ढाला जाता है। यह निष्कर्ष सही होता है, चाहे आवश्यक क्षतिपूर्क परिवर्तन बड़े हुए सार्वजनिक व्यय के रूप में हो, अथवा घटे हुए "धन्य" करों के रूप में, अथवा कर से प्राप्त आय के निराकरण (neutralization) के रूप में हो। प्रत्येक दशा में उत्पादन कर के लागू होने से साधनों के निजी स्वामी अपनी उस स्थिति की तुलना में बुरी स्थिति में आ जाते हैं जो उत्पादन-कर के हटाये जाने पर अन्य समस्त बातें क्षतिपूर्क परिवर्तन के व्यक्तिगत रूप में परिणत होती (individualized shares) रहित, स्थिर रहने पर पाई जाती है। इन राजकोषीय मॉडलों या प्रतिमानों में प्रत्येक में एक तरह सामान्य उत्पादन-कर होता है और दूसरी तरह कुछ उपयुक्त विरम या क्षतिपूर्क परिवर्तन होता है, लेकिन साथ में मूल्य-स्तर की स्थिरता को बनाये रखने के लिए कुछ पूरक विरम या मौद्रिक राजकोषीय कार्य आवश्यक हो सकता है। लेकिन ऐसे पूरक कार्य के प्रभावों को कर के प्रभावों से अच्छी तरह से पृथक करना होगा।

यहाँ पर मुझाई गई इस मौद्रिक मान्यता के लाभों को क्यूँ और पराबिनिती के मॉडलों में पृथक करके स्पष्ट किया जा सकता है। इस स्पष्ट-तया उग हावे को स्वीकार करना है जिसमें मौद्रिक अधिपतारी वस्तु-मूल्यों में वृद्धि करने के कर-वैरिन् प्रणालियों के माध्यम से अपनी प्रतिनिधिता या तो मुद्रा की पुंति में वृद्धि करने बनाने हैं अथवा उन मूल्य-वृद्धियों को स्वीकार करके बनाने हैं जो कर के कारण अपने में ही जाने वाली बचन से सम्भव हो जाती हैं। इन मॉडल की अजह न वह इन निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि सामान्य उत्पादन-कर के कारण वस्तु-मूल्यों के निरन्तर स्तर में वृद्धि हो जाती है, इसलिए कर का "अर्थ" उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। कर का प्रभावपूर्ण आगमन साथ ही कई मौद्रिक नीति की दिग्ध पर निर्भर करता है। स्पष्टतः सही पर मूल्य के लिए सावधान्य विद्वानों की जाय करने में दिव्यता रही है। यदि कर

के सहित अथवा इसके बिना वस्तु-कीमत (product-price) मुद्रास्फीति की एक-सी ही मात्रा मान ली जाती है, तो यह स्पष्ट है कि साधनों के स्वामियों की स्थिति घर के साथ कम अनुकूल होगी बनिस्बत इसके अभाव में। करापात का प्रारूप वही रहता है जो अन्य मौद्रिक मान्यताओं के अन्तर्गत पाया जाता है।

पराविसिनी एक ऐसा मौद्रिक ढांचा मान लेता है जिसमें मुद्रा की मात्रा और इसका प्रचलन-वेग स्थिर रहते हैं। उसका तर्क यह दर्शाता है कि सामान्य उत्पादन-कर वस्तु-मूल्यों के स्तर में वृद्धि कर देता है क्योंकि कर के कारण मुद्रा के उपयोग में अपेक्षाकृत अधिक किफायत हो जाती है। आर्थिक मॉडलों में स्थिर मात्रा की मान्यता के काफी दृष्टान्त पाये जाते हैं, और कुछ सीमा तक कीमतों की वृद्धि को कर पर आरोपित करना उचित माना जा सकता है। लेकिन यहाँ भी यह ज्यादा उचित होगा कि समग्र मूल्य-स्तर की वृद्धि (यदि यह होती है) के लिए मौद्रिक नीति को उत्तरदायी ठहराया जाय और मुद्रास्फीति के आपात को करापात से पृथक् किया जाय। केवल इसी तरह से करापात के प्रारूप को पूर्वकल्पित मौद्रिक ढांचे से पूर्णतया मुक्त किया जा सकेगा।

रूढ़ि का विश्लेषण, और कुछ सीमा तक पराविसिनी का भी, उस विश्लेषण के समान है जो अल्प सम्बन्धों में हास ही में प्रस्तुत किया गया है। मुद्रास्फीति की तथाकथित "लागत या मजदूरी जनित" ("cost or wage-push") व्याख्याओं में लागत-मूल्य वृद्धियों को मुद्रास्फीति का कारण बता कर द्रव्य की पूर्ति को लोचदार मान लिया गया है। इस मत के विरोधी यह तर्क रखते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण स्वयं मुद्रा की पूर्ति में विस्तार का होना है, इसके लिए लागत अन्य तत्त्व उत्तरदायी नहीं हैं। मेरा विचार है कि इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच किया जाने वाला चुनाव उन "मौद्रिक नियमों" पर निर्भर करता है जो एक "उत्तम समाज" के सम्बन्ध में एक विश्लेषणकर्ता की धारणा में निहित होते हैं। "लागत जनित" (मुद्रास्फीति) के जो समर्थक हैं (अथवा उत्पादन-करापात के रूढ़ि के रूप के) वे आर्थिक दृष्टि से उत्तम समाज का चित्र इस प्रकार से खींचते हैं कि इसमें मुद्रा की पूर्ति में काफी लोच होती है और/अथवा आय के वेग में काफी अल्पकालीन परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अतः एक "घादस" व्यवस्था में भी सामान्य वस्तु-मूल्य स्तर एक आश्रित चल-राशि ही होती है। इसके विपरीत एक विरोधी मत जो बहुत कुछ भयभीत से "शिफायी विचारधारा" के नाम से चला है, के समर्थक आर्थिक

ष्टि से उत्तम समाज उसको मानते हैं जिसमें या तो स्पष्टतः परिभाषित नियम एक पूर्णरूप से स्वचालित मान, अथवा सर्वज्ञ विवेकशील अधिकारी इस तरह के कार्य करते हैं ताकि अन्तिम वस्तु अथवा साधनों के मूल्यों के स्तर में स्थिरता आई जा सके। कम-से-कम इस अर्थ में तो "तटस्थ मुद्रा" एक सार्यक धारणा ही मानी जायगी। निरपेक्ष मूल्य-स्तर एक चत्तराशि होता है जिस पर ठीक ढंग से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तत्पश्चात् यह एक बाधित चत्तराशि न रह कर एक निषण्णित राशि हो जाता है।

#### IV निष्कर्ष

सामान्य उत्पादन करों के आपात पर वर्तमान बहस अभी तक समाप्त नहीं हुई है। कई प्रश्नों का स्पष्टीकरण होना बाकी है जिनमें कुछ विश्लेषण सम्बन्धी हैं और कुछ पद्धति-सम्बन्धी। यह बहस आर्थिक सिद्धान्त में सामान्य रूप से होने वाले व्यापक विकास को एवं उन समस्याओं पर सामान्य संतुलन-सिद्धान्त के प्रयोग की सूचित करती है जिन पर पहले केवल आंशिक-संतुलन के षट्कोणों से ही प्रहार किया गया था, जो अनुचित था।

## भारत के लिए कराधान का सर्वोत्तम ढांचा

डा० राजा जे० चेलैया

3. करदेय सामर्थ्य के अनुसार कराधान का सिद्धान्त (The Principle of Taxation According to Ability to Pay) :—जब कर-नीति का प्रमुख उद्देश्य निजी और सार्वजनिक विनियोग को प्रोत्साहन देना होता है तो कर के ढांचे को पाठ्याय अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकसित किए गए कराधान के कुछ परम्परागत नियमों से छोटे भिन्न सिद्धांतों की पुष्टि करनी होती है। जैसा कि श्रीमती हिक्स ने कहा है, 'यह तो स्वाभाविक है कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कर के ढांचे की रूपरेखा एक परम्परागत अल्पविकसित देश में हमारे जैसी काफी सामुद्रिक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा बहुत भिन्न होगी।' लेकिन मुख्य रूप से परम्परागत धारणाएँ और सिद्धांत तो आज भी काममें हैं। यह सत्य है, 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन-अभाव' की ही बात है। अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त होने वाली धारणाएँ जमी-जमी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं पर भी लागू कर दी जाती हैं। ऐसी एक धारणा करदेय सामर्थ्य के अनुसार कर लगाने की है। आय और धन पर काफी आगेही कराधान (highly progressive taxation) के बिना भी प्रस्ताव हैं। समर्थन के परिचय की तरह भारत में भी इस धारणा का सुगमतापूर्वक प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, मई 1957 में भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में धन पर लगाये जाने वाले अपने नये कर को करदेय सामर्थ्य के आधार पर स्वीकारित कहा था। उन्होंने कहा था कि 'यह स्वीकार किया जाता है कि प्रचलित आयकर कानून और व्यवहार हैं अनुसार आय की ओ परिभाषा दी गई है वह करदेय सामर्थ्य का पर्याप्त माप नहीं है और आय

2. Ursula K. Hicks, 'Direct Taxation and Economic Growth,' Oxford Economic Papers, Vol. VIII, No. 3, October 1956, P. 303.

पर कर लगाने की प्रणाली के माध्य-माध्य धन पर आधारित कराधान भी होना चाहिए।<sup>1</sup> लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठता जा सकता है कि क्या यह इतना स्पष्ट है कि माध्य में कर का ढाँचा लोगों की आय और धन के द्वारा मापी जा करने वाली 'करदेय सामर्थ्य' पर ही आधारित हो।

कराधान के सिद्धान्त में कर को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह सार्वजनिक अधिकारी को दिया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में करदाता को कोई मायनीय प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरह यह सरकारी बायों से मिलने वाले सामान्य लाभों की लागत को भुक्ताने में योगदान करता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यह योगदान लोगों की करदेय सामर्थ्य अथवा करदेय दायता के अनुरूप होना चाहिये। यह भी कहा जाता है कि करदेय सामर्थ्य का सिद्धांत प्रायः पर लागू होने वाले किसी भी त्याग-सिद्धांत और सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर कराधान में आरोहीपन की तरफ से जाता है।

प्रायः इस अन्तिम निष्कर्ष की सत्यता पर सदेह प्रगट किया गया है और इसको अस्वीकार भी किया गया है। वास्तव में यह दर्शाया गया है कि करदेय सामर्थ्य का सिद्धांत स्पष्टतया कराधान के किसी विशेष स्तर (scale) तक नहीं पहुँचाता है। प्रत्येक व्यक्ति सीमान्त उपयोगिता के घटने की दर के सम्बन्ध में अपने राजनीतिक भुक्तानों के अनुसार एक सुविधाजनक मान्यता स्वीकार कर सकता है और उसके बाद कराधान के आनुपातिक या आरोही पैमाने का समर्थन कर सकता है। इसके अलावा हम "समान त्याग" के अर्थ को भी स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अर्थ दूसरे के जैसा ही अच्छा या बुरा हो सकता है।<sup>2</sup> इस प्रकार करदेय सामर्थ्य के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया सिद्धान्तिक ढाँचा जो आरोही कराधान को उचित ठहराता है लगभग पूर्णतया

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री का भाषण, मई 15, 1957, पृ० 11-12.

2. Gunnar Myrdal, *The Political Element in the Development of Economic Theory*, tr. Paul Streeten, Harvard University Press, Cambridge, Mass; 1954, P. 174.

इस प्रश्न के पूर्ण विवेचन के लिए इस ग्रन्थ के सातवें अध्याय 'सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत' को देखिए।

असंतोषजनक माना जायगा। फिर भी वैयक्तिक आय के सम्बन्ध में कराधान की काफी आरोही प्रणाली व्यापक रूप से कराधान का सबसे अधिक वांछनीय रूप माना जाता है। ऐसे कराधान के समर्थन में दिये गए परिभाषित सैद्धान्तिक तर्कों के बावजूद भी केल्डॉर का यह मत सही जान पड़ता है कि आमदनी पर पड़ने वाले भार के रूप में काफी आरोही कर-प्रणाली को अपनाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य और औचित्य आर्थिक असमानताओं को कम करने की इच्छा ही है।<sup>1</sup> युद्ध के संचालन के लिए अथवा तैयारी के लिए सरकारी आय की बढ़ती हुई आवश्यकता ने भी सरकारों को जहाँ से मुद्रा प्राप्त हो सकती है वहीं से उठे लेने के लिए बाध्य किया है। फिर भी सिद्धान्त के क्षेत्र में करदेय सामर्थ्य का सिद्धांत आज भी कराधान के सिद्धांतों में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है और एडम स्मिथ व उसके पहले के अर्थ-शास्त्रियों के समर्थन से इसको प्रतिष्ठित मिली है। इसीलिए अल्प विवक्षित देशों में सार्वजनिक वित्त के अभ्यापक करदेय सामर्थ्य के सिद्धान्त को सार्वजनिक वित्त का मूलभूत सिद्धांत मानते हैं और इसके आधार पर कर के ढाँचे के निर्माण का समर्थन करते हैं।<sup>2</sup> हो सकता है कि ऐसा करते समय ये अर्थ-शास्त्री आय पर आरोही कराधान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्ट सैद्धान्तिक औचित्य से प्रभावित हों और वे इसके पीछे पाये जाने वाले वास्तविक उद्देश्य—असमानता को कम करना—को भुला बैठें।

यदि विवक्षित अर्थव्यवस्थाओं में आय के काफी आरोही कराधान को अपनाने का वास्तविक औचित्य असमानताओं को कम करने में है तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसी तरह की प्रणाली की अल्प विवक्षित देशों में क्यों नकल की जाय जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि इन देशों में भी असमानताओं को कम करने की यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। दूसरे शब्दों में, असमानताओं को कम करने के प्रश्न पर पृथक् से विचार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय अल्प विवक्षित देशों में पाई जाने वाली विशेष दशाओं और विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

### 3. निकोलस केल्डॉर, पूर्व उद्धृत रचना में, पृ० 26-27

1. इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय उदाहरण श्री आर० एन० भागेंव का है जिनका यहाँ तक कहना है कि 'आधुनिक खोजों ने मनु से धीमे प्रगति की है और आरोही कराधान की सत्यता का सैद्धान्तिक प्रमाण प्रस्तुत किया है।' (The Theory and Working of Union Finance in 1898, P. 21)

ये चतुर्धर यह बनाने का प्रयास किया जायगा कि अन्य निश्चित देशों में समानताओं के प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि वास्तव में कुन आसानी पर जारी ऊँचा घाटीही कराधान (Steeply progressive taxation) लगाना नहीं है।

जो भी हो हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि करदेय सामर्थ्य का सिद्धान्त जैसा कि बहुत से लोग जोर देते हैं, आयदनी पर भारीही कराधान की तरफ से आता है। इतना होने पर भी यह सिद्धान्त कड़ाई में सभी मामलों में ठीक से आता है। जब कि हम यह मान लें कि कराधान तो कुछ सामान्य क्रिया का सञ्चालन है जब कि हम यह मान लें कि कराधान तो कुछ सामान्य लाभों की लागतों को पूरा करने में केवल योगदान-मात्र है। लेकिन कार्यात्मक वित्त के दृष्टिकोण (functional finance approach) में कराधान को इतने सरल तरीके से नहीं लिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक अल्पविकसित देश में कराधान सरकारी सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था में केवल योगदान देने से भी ज्यादा विमुक्त विनियोग की दर को बढ़ाने का एक दृष्टि-शाली अस्त्र माना जायगा। यह तो स्पष्ट है कि सरकारी सेवाओं की बहुत सी मदें ऐसी होती हैं जिनकी किसी भी तरह से वित्तीय व्यवस्था करनी होती है, लेकिन इनकी वह मात्रा जो प्रविष्टि में कार्यान्वित की जा सकेगी स्वयं भी विनियोग की दर और आर्थिक प्रगति पर निर्भर करेगी। अतः प्राथमिकता की दृष्टि से विनियोग की दर को ही प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि करदेय सामर्थ्य का सिद्धान्त अल्पविकसित देशों में कराधान की समस्याओं पर आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है और इन देशों में यह कर के ढाँचे का केन्द्र बिन्दु भी नहीं बनाया जा सकता है।

यह एक दृष्टिप्रद बात है कि यद्यपि करदेय सामर्थ्य का सिद्धान्त केवल इस तथ्य के सन्दर्भ में लागू करके दिखाया जा सकता है कि कम से कम अनिवार्य सरकारी सेवाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था तो करों के प्रत्यक्ष से अवश्य करनी होती है, फिर भी व्यवहार में यही तथ्य इस सिद्धान्त से दूर भी ले जाया जा सकता है। अल्पविकसित देशों में आवश्यक वित्त मुख्यतः आय और धन पर प्रत्यक्ष कर लगाकर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में तो मुख्यरूप से परोक्ष कराधान पर आश्रित रहना पड़ता है जिससे कर का ढाँचा अवरोही हो जाता है। इस विषय के लेखक और वित्तमंत्री जब इस सिद्धान्त को व्यवहार में लागू करने के लिए उत्पन्न होते हैं तो उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक उपभोग एवं विनियोग के खर्च की वित्तीय व्यवस्था करने हेतु कराधान का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए लेकिन

यदि ऐसा मुख्यतया भारोही प्रत्यक्ष कराधान के जरिये से ही किया जाता है तो आदित्य प्रेरणाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मतः जब कभी कराधान में कुछ सीमा तक वृद्धि होती है तो परोक्ष कराधान का भार अधिक बढ़ता है, कर का ढाँचा खरबोही बना रहता है और निजी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, या यों कहिए कि कोई विशेष काम नहीं किया जाता है। ऊपर बतताई गई दुविधा तभी दूर की जा सकती है जब कि हम करदेय सामर्थ्य के तत्त्वनिमित्त सिद्धान्त का परम्परागत अर्थ भुला दें।

#### 4. कराधान और आर्थिक बचत (Taxation and Economic Surplus)

अल्पविवक्षित क्षेत्रों के संसार बहुधा इन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बचत के नीचे स्तर पर ध्यान आकर्षित किया करते हैं। इस स्तर में वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि ऐसा किसी बड़ी सीमा तक कर सवना सम्भव नहीं होगा क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होता है जो बचत व विनियोग के नीचे स्तर का कारण माना जाता है। इससे जो विचार सामने आता है वह गरीबी का कुचक्र (vicious circle) कहलाता है। लेकिन इसमें सन्देह है कि अर्ध-व्यवस्था में बचत की दर अथवा कम से कम सम्भाव्य बचत (potential savings) प्रत्यक्षतया प्रति व्यक्ति आय के स्तर से सम्बद्ध की जा सकती है अथवा नहीं। बचत की सम्भाव्य दर के अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व सम्भवतया ये हैं कि राष्ट्रीय आय का नितना अंश आय के ऊपरी समूहों के पास जाता है और कुल आय में सम्पत्ति से प्राप्त आय का अंश कितना होता है।

श्री एस० जे० पटेल के द्वारा लगाये गये कुछ छोटे अनुमानों से यह पता चलता है कि भारत और अमेरिका में सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय के अंश में ज्यादा अंतर नहीं है। श्री पटेल ने भारत में 1950-51 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय के वितरण का हिसाब लगाया है।<sup>1</sup> इससे उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले हैं :—(अ) राष्ट्रीय आय का आधे से ज्यादा अंश स्वयं का रोजगार करने वालों की आय से प्राप्त होता है; (आ) मजदूरी व वेतन कुल का लगभग 23 प्रतिशत है जो अमेरिका में मजदूरी व वेतन पाने वालों को मिलने वाले अंश से काफी कम है; (इ) भारत में सम्पत्ति के स्वामित्व

1. S. J. Patel, 'The Distribution of the National Income of India, 1950-51', *The Indian Economic Review*, Vol. III, No. 1, February 1956, P. 8.



से जिस सकल आय (gross income) का सम्बन्ध है वह कुल आय के 23 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है।<sup>1</sup> अन्तिम निष्कर्ष हमारे उद्देश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर संयुक्त राज्य और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पिछले लगभग दस वर्षों में सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय कुल आय के 20 से 25 प्रतिशत के बीच में परिवर्तित होती रही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो वर्ग आय के इस भंश को प्राप्त करते हैं वे इसका काफी भाग बचा लेते हैं जब कि भारत में इन्हीं वर्गों के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक भारत में आय प्राप्तकर्ताओं के वर्गों के अनुसार अपनी आमदनी के वितरण का प्रश्न है क्यूजेनेट (Kuznet) के द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार इस देश में चोटी के बीस प्रतिशत लोगों की आय राष्ट्रीय आय का लगभग 55 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के अन्य देशों में भी यही स्थिति पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संका, जापान एवं फिलिपाइन में इनके के तत्वाधान में किये गये आय के वितरण के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि इसके दायरे में शामिल किये गये देशों में असमानता का भंश लगभग एक-सा ही था।<sup>2</sup> इससे यह भी पता चला कि संका में 10.6 प्रतिशत आय प्राप्तकर्ताओं ने आय का 37.0 प्रतिशत प्राप्त किया और फिलिपाइन में 10 प्रतिशत ने आय का 33.3 प्रतिशत प्राप्त किया था।<sup>3</sup> इन आंकड़ों पर दृष्टि डालने से इस तर्क को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है कि ये देश अपनी आय के केवल 5 प्रतिशत से ज्यादा अंश को बचत व विनियोग में नहीं लगा सकते हैं।

यह तो स्पष्ट है कि इन देशों में बचत की सम्भाव्य दर इसकी वास्तविक दर से ऊँची पाई जाती है। इन दोनों के बीच पाये जाने वाले उल्लेखनीय अंतर का एक तर्कमुक्त स्पष्टीकरण भी पटेल ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है : 'यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति आय नीची है तथापि यह आवश्यक नहीं है कि विकसित देशों की तुलना में यहाँ बचत की सम्भाव्य दर काफी नीची ही हो, क्योंकि दोनों तरह के देशों में बचत को उत्पन्न करने वाला घाय का अनुपात अपना सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली कुल आय लगभग समान ही पाये

1. पूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पृ० 9।

2. Economic Bulletin for Asia and Far East, Vol. III, Nos. 1-2, November 1952, P. 23.

3. वही ग्रन्थ, पृ० 22.

जाते हैं। अतः भारत में उत्पादक विनियोग की नीची दर नीची औसत आय के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती है बल्कि यह 'सामन्ती' आय (सम्पत्ति की आय में) की प्रचुरता से समझाई जा सकती है जो इस समय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में कुछ विफल सिद्ध हुई है।<sup>14</sup>

समस्त प्रायोजिक (Pre-industrial) समाज व्यवस्थाओं में कृषि का राष्ट्रीय उत्पत्ति में आधे से भी ज्यादा योगदान पाया जाता है और इसका काफी बड़ा भाग उन लोगों को मिलता है जिनको हम 'सामन्ती' भासिक और मध्यस्थ कह कर पुकारते हैं। यदि इस 'अतिरेक' या 'बचत' का बड़ा भाग उत्पादक विनियोग के लिए उपलब्ध हो जाय तो आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। ऐसा अतिरेक अर्थव्यवस्था के अन्य भागों में भी पाया जा सकता है। राजकीय नीति का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि ऐसे अतिरेक को आर्थिक विकास के लिए जुटाया जाय।

यही कारण है कि अल्प विकसित देशों में सार्वजनिक वित्त के वास्तविक सिद्धान्त का प्रारम्भ अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले आर्थिक अतिरेक की धारणा से होना चाहिए। यद्यपि आर्थिक अतिरेक की धारणा बहुत कुछ भ्रामक है, फिर भी हमारे कार्य की दृष्टि से यह सही और लाभप्रद मानी जा सकती है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के लिए सम्पत्ता सभी वायम रह पाती है जब कि अर्थव्यवस्था अनिवार्य उपभोग के स्तर से ऊपर अतिरेक या बचत उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दे।<sup>15</sup> प्रोफेसर बरान का अनुसरण करते हुए हम वास्तविक आर्थिक अतिरेक और सम्भाव्य आर्थिक अतिरेक के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।<sup>16</sup> वास्तविक आर्थिक अतिरेक वास्तविक भ्राम उत्पत्ति

4. एच० जे० पटेल पूर्वउद्धृत, पृ० 11 गहरे अक्षर भूतपाठ के अनुसार।

1. वास्तव में 'अनिवार्य उपभोग' की सही परिभाषा करना असम्भव जान पड़ता है। यह सर्वत्र के लिए स्थिर नहीं होता है और न सभी देशों व वर्गों के लिए समान होता है। फिर भी किसी भी समाज में एक ही हुई अवधि में अनिवार्य उपभोग के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के बारे में एक साधारण-सा विचार बना लेना सम्भव होगा। अर्थशास्त्र में कई अन्य धारणाएँ भी प्रयुक्त होती हैं जिनकी परिभाषा बढ़ाई से कर सकना सम्भव नहीं है, जैसे मूल्य-ह्रास (depreciation)।

2. Paul A. Baran, The Political Economy of Growth, Monthly Review Press, New York, 1957, Pp. 22-23.

और वास्तविक चानू उपयोग के आधार को कहते हैं । इस प्रकार यह विभिन्न विद्यमानियों के वास्तविक संघटन के समान होता है । सम्मान्य आर्थिक विनियम तो उक्त उद्योग, जो काम में लगाने जा सकने वाले उत्पादक साधनों की महायन्त्रा में एक दिने हुए प्राकृतिक व प्रायोगिक बलावरण में उत्पन्न की जा सकती है, और जिसे अनिवार्य उपयोग कहा जा सकता है, इन दोनों के संतर को कहते हैं ।<sup>13</sup> यह भी संभव है कि इस अतिरेक का कुछ भाग वास्तव में प्राप्त भी न हो क्योंकि सामान्य बेकार पड़े रहने एवं गणत उपयोग से व्यर्थ में ही मरट हो सकते हैं । इस अतिरेक का तेज भाग विभिन्न उद्देश्यों में प्रयुक्त किया जाता है । किसी भी देश की सम्पत्ता की प्रकृति एवं इसकी मापी प्रगति उन उद्देश्यों पर निर्भर करती है जिनके लिए एवं किस ढंग में इस अतिरेक का उपयोग किया जाता है । इस अतिरेक का उपयोग जिस काम के लिए किया जा सकता है उसे कृतात्मिक संस्करणों ने अनुत्पादक उपयोग कहा है । संश्लेष इसका उपयोग 'अनुत्पादक विनियोग' (महत्त और विरामित), अथवा उत्पादक विनियोग के लिए भी किया जा सकता है । आर्थिक प्रगति की यह मांग है कि कम से कम प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो इस अतिरेक का बड़ा भाग उत्पादक विनियोग में लगाया जाय । भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में अतिरेक का बड़ा भाग कृषि के क्षेत्र से उत्पन्न होता है और इस पर सूत्रात्मिक, साहूकारों एवं व्यापारियों का अधिकार हो जाता है जिनमें प्रायः उत्पादक विनियोग की भावना नहीं पाई जाती है । कुछ विचारकों के अनुसार भारत सर्वसाधारण के उपयोग में बची बिक्री बिना अपनी आमदनी का 15 प्रतिशत विनियोग में लगा सकता है ।<sup>14</sup> इस उद्देश्य की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है कि पर्याप्तवस्था में वर्तमान समय में उत्पन्न होने वाले आर्थिक अतिरेक का व्यापक रूप से संचय किया जाय । यह कार्य साम्यवादी उद्योग का समन्वयिकरण एवं कृषि का समूहीकरण करके करने का प्रयास करते हैं । सैक्युलर समाज ऐंग्लिक सचल और इसको न अपनाते पर, कराधान इसके विकल्प होते हैं । अतः आर्थिक विकास के लिए कर-नीति का कार्य इस अतिरेक का संग्रह करना, इसको उत्पादक दिशाओं में भेजना एवं निरंतर इसके आकार में वृद्धि करना होना चाहिए ।

## 5. भारत के लिए कराधान के नियम (Canons of Taxation for India) :—

उपर्युक्त बातों को स्वीकार करने पर यह प्रश्न उठता है कि कर के देने के पीछे मूलभूत सिद्धांत क्या हो ? यह आर्थिक अतिरेक के संपर्क का सिद्धांत होना चाहिए । कराधान के जरिये अतिरेक का बड़ा भाग प्राप्त कर लिया जाना चाहिये जो इस समय उत्पादक विनियोग में प्रयुक्त नहीं हो रहा है । अतः समस्या इस बात की है कि इस अतिरेक का पता लगाया जाय और इसको इस तरह से विनियोग की तरफ ले जाया जाय कि इस प्रक्रिया में इसका उत्पन्न होना न तो गप्ट हो और न गम्भीर रूप से सीमित ही हो ।

दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कराधान में जो योगदान करे वह आर्थिक विकास में संयोजन करने की उसकी अप्रयुक्त क्षमता या योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए । यह योग्यता आर्थिक अतिरेक के उस भण्ड (अथवा उसके प्रति दावे) के रूप में मापी जा सकती है जो उसके हिसते में आता है और जिसे वह पहले से अपनी इच्छा से उत्पादक विनियोग में नहीं लगा रहा है । किसी भी व्यक्ति की भाव में अतिरेक का भण्ड उस समय समझा जाता है जब कि यह उस स्तर से ऊपर होता है जो कार्यकुशलता और प्रेरणाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले न्यूनतम उपभोग को बनाये रखने की दृष्टि से जरूरी समझा जाता है । यह तो स्पष्ट है कि इस न्यूनतम उपभोग की मात्रा विभिन्न देशों में और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न होगी ।

कराधान के जरिए अतिरेक की वे वृद्धियाँ भी एकत्र की जानी चाहिए जो विकास की दिशा में उठाये गये प्रारम्भिक प्रयत्नों के कलस्वरूप उत्पन्न होती हैं । इसे ही हम अक्षत वृद्धि-अनुपात (incremental saving ratio) में बड़ीतरी का होना कहते हैं । अतः कराधान का तीसरा नियम यह है कि इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाय कि विकास के प्रारम्भिक चरणों में उपभोग में आय के अनुपात में वृद्धि न हो सके । आगे चलकर यह बतलाया जायगा कि वस्तु-कराधान का इस उद्देश्य के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से उपभोग किया जा सकता है ।

भारत में कराधान का चौथा महत्वपूर्ण नियम कराधान में आय-लोच का नियम (Canon of income-elasticity) कहा जायगा । आय की वृद्धि के साथ-साथ कुल आय में कराधान का भण्ड बढ़ना चाहिए । इस समय भारत में समस्त सरकारी इकाइयाँ मिलकर कराधान के रूप में राष्ट्रीय आय का

मदमद ३ मिनट ही चलाने के लिये है। यदि यह ही मरणाधीन चम है मुँह  
कमला मरणाधीन न ही लगे भी लेना कठिन वर मरणाधीन होना वर वि  
रागीन भाव उन्मेषनीय मुँह विमानावा अस्वस्थ कर दे। तैरा हि चीज  
ही मरणाधीन मरणाधीन इसके निम्न कर-मरणाधीन ॥ विद्वान् मोक्ष (Vishnu-  
Hiranyaksha) की आकाशवाणी होनी है। मरणाधीन को आकाशवाणी मोक्ष प्रदान  
करने के निम्न यह कहती है कि उन मरणाधीन पर कर मरणाधीन आकाश विमान  
मरणाधीन मोक्ष अर्थात् होनी है और मरणाधीन में आकाशवाणी का मरणाधीन  
कर भी मरणाधीन माना जाईगा। मुँह मोक्षवाणी कर मरणाधीन ॥ में अर्थात् होनी  
हमनिम्न मरणाधीन का अर्थ आकाश के वरने के मरणाधीन मरणाधीन में मरणाधीन  
होना।

अनिष्ट धान विनष्टा महत्त्व कम नहीं है वह समानता का ध्यान का नियम है। अर्थात् कलापान का उपयोग आर्थिक विभाग के साधन के रूप में किया जाता है, इसलिए ध्यान के नियम की महत्त्व होती है कि तीव्र आर्थिक विभाग में आने वाले भार प्रभाव के विभिन्न वर्गों में समान रूप से बाँटे जाय। जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त का बड़ा भाग विनियोग में लगाना जाता है तो ठीक ऐसा ही किया जाता है। यदि समाज के अतिरिक्त गरीब वर्गों को उमरी आमदनी में होने वाली वृद्धि की पूरी मात्रा तक उद्योग में वृद्धि करने से रोका जाता है, तो दूसरी तरफ अतिरिक्त वर्गों को अपने अतिरिक्त का उपयोग अतिरिक्त उपभोग में करने से रोका जाता है। उपभोग सम्बन्धी त्याग समाज के सभी सदस्यों के द्वारा समान रूप से किये जाते हैं। इस सामान्य नियम से स्वाभाविक परिणाम के रूप में क्षैतिज समानता (horizontal equity) का नियम निरवस्था है जिसे बहुधा भुला दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों एवं एक ही ढंग से आचरण करने वाले व्यक्तियों (अपने अतिरिक्त का उपयोग करने के सम्बन्ध में) से कर के उद्देश्यों की दृष्टि से समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह समानता का एक स्पष्ट नियम है, फिर भी भारतीय कर-प्रणाली इसका पालन नहीं कर पाई है।

(आ) आय और धन पर करारोपण या कराधान

1. भाग्य कराधान से बचतों को प्राणिक रूप से छुट देने के पक्ष में विचार

ऊपर यह सुझाया जा चुका है कि आर्थिक विकास के लिए कराधान का भार आर्थिक अतिरेक पर पड़ना चाहिए और इसे विनियोग के लिए

एकत्र किया जाना चाहिए। कराधान का रूप ऐसा होना चाहिए कि यह अतिरेक से निरंतर वृद्धि करने में मदद दे सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कराधान राय के उस भंश पर (जो एक निश्चित सीमा से ऊपर है) आरोही दर से लगाया जाना चाहिए जो स्वीकृत विनियोगों के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है और कराधान का ढंग भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दूसरे शब्दों में, उन बचतों को आय-कराधान से मुक्त करा जा सकता है जिनका विनियोजन समाज के लिए आवश्यक समझी जाने वाली दिशाओं में किया जाता है।

ऐसी सम्पूर्ण छूट को तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब कि म कराधान को केवल आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही देखें। किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि कराधान से सरकारी सेवाओं के लिए वित्त प्राप्त होता है। इसके अलावा इस अतिरेक का एक भाग सामाजिक ऊपरी व्यय (social overheads) में सार्वजनिक विनियोग के लिए आवश्यक होता है। अतः बीष का हल तो यह होगा कि एक आशिक, सेविंग पर्याप्त, छूट दान की जाय। यदि हम अर्थव्यवस्था में बचत की दर को बढ़ाने की अधिक अनिवार्यता पर ध्यान दें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह देना नितान्त आवश्यक है।

ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के विशेष संस्थानगत वातावरण में सार्वजनिक विनियोग के साधन निजी बचत को प्रोत्साहन देने के ऊपर के कार्यक्रम का समर्थन किया जाता है। सर्वप्रथम, अतिरेक के अधिकांश भाग को सार्वजनिक विनियोग में लगाना वाछनीय नहीं होगा। सार्वजनिक और निजी विनियोग दोनों को एक-साथ चलना होता है क्योंकि सार्वजनिक विनियोग का अधिकांश भाग भी विनियोग की सीमागत उत्पादनता में वृद्धि करने के लक्ष्य से ही किया जाता है।<sup>1</sup> द्वितीय, भारत में भी जिसका आदर्श 'समाजवादी ढंग का समाज' प्रतिष्ठित करना है, अर्थव्यवस्था का अपेक्षाकृत बड़ा भाग, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित हो चुका हो, निजी उपक्रम के लिए छोड़ा जाता है। यह भारत सरकार के अग्रेष्ठ 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है। प्रस्ताव के अनुसार केवल वे उद्योग जो प्राथमिक व सामयिक महत्त्व हैं, एवं जो सार्वजनिक सेवाओं में आते हैं, और जिनमें विनियोग का पैमाना

सा होता है कि केवल सरकार ही उसकी व्यवस्था कर पाती है—सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे।<sup>2</sup> अन्य सभी उद्योगों का विवास निजी उपक्रम के लिए छोड़ दिया गया है। इस संस्थानगत घृष्ठभूमि में निजी उपक्रम पर रोक लगाने से आर्थिक विकास पर रोक लग जायगी। तृतीय, सरकार ज्यादातर ऐसे उपक्रम अपने हाथ में लेती है जो सापेक्षिक रूप में भलाभकारी होते हैं। बहुत से सरकारी उपक्रमों से प्रत्यक्ष रूप में मौद्रिक प्रतिफल तो मिल सकते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं होते हैं कि उनसे बड़ी मात्रा में लाभ मिल सके। इसीलिए अर्थ-व्यवस्था में प्रतिरेक की वृद्धि सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के बाहर लाभकारी क्षेत्रों की वृद्धि पर ही निर्भर करेगी। अतः में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है कि बचत और उपक्रम की प्रेरणाओं को दुर्बल होने से रोका जाय बल्कि यदि तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो और भी प्रागे जाकर प्रेरणाओं को भी सुदृढ़ करना होगा। ऊपरी पूंजी (overhead capital) की व्यवस्था करने की तुलना में राज्य के लिए यह कोई कम दबाव डालने वाला कर्तव्य नहीं है।

ये वे प्रबल कारण हैं जो बचतों को आय-कराधान से आर्थिक रूप से मुक्त रखवाने के हमारे पूर्ववर्णित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं। लेकिन यह भी प्राप्ति उठाई जा सकती है कि जब हम करदेय सामर्थ्य के सिद्धान्त और कुल आमदनीयों के आरोही कराधान से दूर जाते हैं तो हम ग्याय या समानता को तिलांजलि दे देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम पहले देख चुके हैं कि करदेय सामर्थ्य का सिद्धान्त निश्चयारमक रूप से कराधान के किसी विशेष रूप की तरफ नहीं से जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जो कराधान आय के तदर्थ में थोड़ा अवरोही (Slightly regressive) होगा वह अनिवार्यतः ग्याय के विपरीत होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक विकास के लिए उपभोग में त्याग करने की आवश्यकता होती है और ये त्याग जनता के सभी वर्गों में समान रूप से वितरित होने चाहिए। जो कर-प्रणाली उपभोग करने के लिए भारी सजा देती है और विनियोग में लिए पारितोषिक देती है, वह प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग का परित्याग करने के लिए प्रेरित करती है। जगम में एक विभागशील अर्थव्यवस्था में ग्याय (equity) को एक सार्वजनिक रूप में ही देखना होगा। आर्थिक प्रगति करके ही संस्थापारण का जीवन-स्तर काफ़ी ऊचा निया जा सकता है। जो कर-प्रणाली करवाहता (incidence of taxation) को एक परम्परागत

‘समान’ ढंग से वितरित करती है वह लोगों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती है। डा० बोल्डिंग ने बताया है कि यदि पुनर्वितरणकारी उपायों से आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ जाती है तो कुछ समय के बाद पुनर्वितरण के फलस्वरूप विशेषरूप से लाभान्वित होने वाले समूह को प्राप्त होने वाला निरपेक्ष घाटा उस स्थिति की तुलना में कम हो जायगा जो विकास की दर के असेवाहत ऊँचा होने पर प्राप्त होता है।<sup>1</sup> इसका आशय यह है कि विमी भी समूह के हित में यह नहीं होगा कि वह ऐसा पुनर्वितरण अपने पक्ष में स्वीकार करे जो विकास की दर को कम करता हो। मार्बजनिन वित्त का प्रचलित कल्याणकारी अर्थशास्त्र स्थिर मान्यताओं से बड़ा हुआ है। “न्याय” का आशय ज्यादातर स्थिर राशि के विभाजन के रूप में लगाया गया है न कि अधिक राशि को प्रोत्साहन देने के रूप में।<sup>2</sup> एक अल्पविकसित देश में कराधान में न्याय का आशय इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता कि पूँजी-निर्माण में निहित भार का वितरण समान किया जाए और विकास की सर्वोच्च सम्भव हो सके वाली दर को प्रोत्साहन दिया जाए।

पहले बताया जा चुका है कि आर्थिक विकास के ‘भार’ के समान वितरण में शैतिज न्याय या समानता के नियम को लागू करने की बात शामिल होती है। भारत में विपरीत परिस्थितियों में पाये जाने वाले लोगों पर लागू करने के लिए एक नियम को तलाश करने के हमारे प्रयत्नों में हमने समानता के इस घनापत्तिजनक नियम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। बेतनभोगी कर्मचारियों पर कर लगा दिया जाता है जब कि दुकानदार इससे बच जाते हैं, मुनाफो एवं बेतनो से प्राप्त आय से एकसा बरताव नहीं किया जाता क्योंकि पहली स्थिति में पढाने साधक सबों से सम्बन्धित शर्तें उदार होती हैं; बेतिह्र आय के प्रति उदार बरताव किया जाता है और घट में, पूँजीगत लाभ के रूप में प्राप्त आय भी अब तक कराधान से बची हुई थी और आज भी इस पर रियायती दर से ही कर वसूल किया जाता है।

हमारी योजना में पूँजीगत लाभ इस आधार पर कराधान में शामिल दिये जा सकते हैं कि ये उन लाभकारी शक्तियों में माने जाते हैं जो व्यक्तियों

1. Kenneth E. Boulding, ‘Fruits of Progress and the Dynamics of Distribution, *American Economic Review*, Vol XLIII No. 2, May 1953, pp 481-482.

2. वही, पृ० 483.



के हाथों में अतिरिक्त का ही धंसा होगी है और वे उनके द्वारा उपभोग प्रयास विनियोग के लिए प्रयुक्त हो सकती हैं। पूँजीगत लाभों पर कराधान न केवल विभिन्न व्यक्तियों के बीच अधिक ग्याप का सम्यादन कर मोगा बनि करों को टानने के संबंधित गुरागों में से एक को बंद भी कर देगा। लेकिन पूँजीगत लाभों पर कराधान के साथ बचनों के पत्र में अधिक छूट भी दी जानी चाहिये।

यहां पर हमारा इरादा आरोही कराधान के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करना नहीं है, बनि हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इसका मापार नून आय को नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका मापार यह भी हो सरता है कि कर-प्रणाली आय के सम्बन्ध में कुछ अवरोही हो जाय। लेकिन यह प्रणाली आय के उत अथ के सम्बन्ध में काफी आरोही होगी जो उत्पादन ढंग से विनियोजित नहीं किया जाता है। यह योजना दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है : यदि बड़ी राशि वाली आमदनी बचाई नहीं जाती है तो इसका काफी भाग सरकार के द्वारा ले लिया जायगा, और इसके विपरीत, यदि आमदनी को भारी कराधान से बचाना है तो इसे विनियोग में समाना होगा। दोनों ही विधियों से यह अतिरिक्त अधिक विकास के लिए एकत्र हो जायगा। इस तरह से यह योजना हमको कर-नीति में पाये जाने वाले मूलभूत उभयपारा (dilemma) से मुक्त कराने में मदद देती है जो इस प्रकार है : कराधान से अधिक राशि प्राप्त की जानी चाहिए लेकिन ऐसा प्रेरणाओं को नष्ट करने के भय से नहीं किया जा सकता है। हम यहां पर जिस योजना का विवेचन कर रहे हैं उसमें यदि सरकार कर के रूप में कुछ आय लो भी देती है तो भी यह बचत को प्रोत्साहन देने में सफल हो जायगी जिससे से यह अपना कुछ भय से सक्ती है।

अतः आवश्यकता एक ऐसे व्यावहारिक कार्यक्रम की है जिसके द्वारा विशेष दिशाओं में विनियोजित की जाने वाली बचतों के लिए अधिक छूटें दी जा सकें। ऐसी छूटों से केवल लाभार्थ प्राप्त करने वालों एवं निगमों के स्वामियों को ही नहीं बल्कि सभी किस्म के आयकरदाताओं को लाभ पहुंचना चाहिए। चूंकि विनियोग को मिलने वाला प्रोत्साहन वैयक्तिक व व्यावसायिक स्तर पर दिया जाना चाहिये, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक व व्यावसायिक दोनों तरह की आय के कराधान में सम्योचन करने होंगे। यहां पर प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि उन सब लोगों को जो आयकर नहीं देते हैं, स्वतः अपनी बचतों पर कर की छूट प्राप्त हो जाती है क्योंकि वे अपने उपभोग पर ही कर चुकाते हैं।

छूट की यह योजना कोई क्रान्तिकारी नहीं है। भारत में एवं अन्य देशों में ये छूटें चर्माथे अछादानों, वीमा व प्रोविडेंट कोष के भुगतानों एवं निगमों के द्वारा किये जाने वाले कुछ पूंजीगत विनियोगों के लिए दी गई हैं। दान की अनिवार्य विनियोग को प्रोत्साहित करने का ज्यादा महत्व होता है और ऐसा विशेषरूप से एक अल्पविकसित देश में होता है। और जब एक व्यक्ति अपनी आमदनी वैयक्तिक उपयोग में न लगाकर ऐसे विनियोगों में लगाता है जिनमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ती है तो स्पष्ट रूप से सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में केन्स के उन शब्दों को स्मरण करना होगा जो उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम अर्द्धशतक में पाई जाने वाली यूरोप की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में कहे थे :

‘इस प्रकार यह उत्सर्जनीय व्यवस्था अपने विकास के लिए दोहरे दबाव या धोखे पर निर्भर करती थी। एक तरफ श्रमिक वर्ग ने अज्ञानतावश या शक्तिहीनता के कारण एक ऐसी स्थिति स्वीकार कर ली अथवा समाज की प्रथा, परिपाटी, सत्ता एवं सु-स्थापित व्यवस्था के कारण मजबूर एक ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए विवश हो गये, प्रेरित हो गये अथवा धोखे में आ गये जिसमें उस बहुत छोटे से भाग को, जो उन्होंने प्रकृति व पूंजीपतियों के सहयोग से उत्पन्न किया था, अपना कहने लग गये थे। दूसरी तरफ, पूंजीपति वर्ग को भी इस बात की इजाजत दे दी गई कि वे इस माल के अधिकांश भाग को अपना बतला सकें और वे सिद्धांततः इसका उपयोग करने के लिए इस अव्यक्त अन्तर्निहित शर्त पर स्वतन्त्र थे कि व्यवहार में इसका बहुत मोटा भाग उपयोग में लगाया जायगा।’<sup>1</sup>

ऊपर प्रस्तावित कर-प्रणाली में पतिव वर्ग कर-मुक्त आय की स्वयं की बतलाने के लिए ‘सिद्धांतिक रूप से स्वतन्त्र’ होगा, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकेगा। एक ‘अव्यक्त अन्तर्निहित शर्त’ पर निर्भर करने के बजाय हम पतिव वर्ग को कराधान की एक सुव्यवस्थित योजना के जरिए उपयोग का परित्याग करने के लिए ‘फुललावेये’ और ‘प्रेरित करेंगे’।

यह तो सच है कि यदि हम बच्चों को आशिक छूट प्रदान करते हैं तो आयकर धन की अनुमानजामों को कम करने में कम प्रभावशाली सिद्ध होता है। लेकिन चूंकि इस योजना में आयकर की दरें बढ़ाई जा सकती हैं इसलिए

1. J.M. Keynes, *The Economic Consequences of the Peace*, Harcourt, Brace and Howe, New York, 1920, pp. 19-20.

उपभोग के स्तरों में पाई जाने वाली असमानताएँ भी कम की जा सकेंगी। अल्पकाल में सर्वसाधारण के लिए यही सर्वश्रेष्ठ बात की जा सकती है। धन की असमानताओं को कम करने के लिए और असमानताओं को चिरस्थायी होने से रोकने के लिए धन एवं उत्तराधिकार के कराधान पर निर्भर करना होगा। यदि कोई देश निजी उत्पन्न पर ही निर्भर करता चाहता है तो इसे धन-संग्रह को एक सीमा तक प्रोत्साहित करना होगा। लोगों के लिए बड़ी फर्मों को स्थापित करने एवं चलाने के लिए धन की विशाल मात्रा पर अधिकार रखना आवश्यक होगा। जितनी जल्दी यह महसूस कर लिया जाता है कि एक आदर्शवादी मुधारक जिस असमानता की इजाजत देता है उससे अधिक असमानता की मात्रा का होना अनिवार्य है, आर्थिक विकास की दृष्टि से यह उतना ही अधिक अच्छा माना जाएगा। यदि एक देश धन की असमानताएँ नहीं रखना चाहता है और साथ में तीव्र आर्थिक प्रगति का भी इच्छुक है तो इसके लिए प्रमुख रूप से समाजवादी व्यवस्था का अपनाना सम्भवतया ठीक रहेगा। लेकिन इस तरह की व्यवस्था में भी आमदनी में असमानता का भारी घट बना रहेगा।

---

## 1. परोक्ष कराधान का महत्व

यह तो सब जानते ही हैं कि परोक्ष करों का अल्पविकसित देशों की वित्तीय व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन देशों में परोक्ष कराधान का खांचा प्रत्यक्ष कराधान के उद्देश्यों के आधार पर ही बनाया जाता है। इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि यह सर्वव्यवस्था में पूँजी-निर्माण की दर को बढ़ा सके और साथ में सार्वजनिक उपभोग और विनियोग के लिए आय प्रदान कर सके। यहाँ पर भी हमें केवल यही प्रश्न भरी पूछना है कि सरकार के लिए अधिक आय कैसे जुटाई जाय, बल्कि हमें यह जानना है कि विनियोग की दर में कैसे वृद्धि की जा सकती है और साथ में सरकार से अधिक आय कैसे प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर बचत वृद्धि-अनुपात पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करना आवश्यक होगा।

जिन वस्तुओं का व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है उनके कराधान का एक औचित्य यह है कि यह कम से कम अनिवार्य सरकारी सेवाओं के लिए तो पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए आवश्यक होता है। अल्पविकसित देशों में यह आवश्यक होता है कि करों की आय के अधिकांश भाग को वस्तु-कराधान के जरिए प्राप्त किया जाय। इस तरह से विचार करने पर वस्तु-कराधान सामान्य साम की लागत को पूरा करने में योगदान देता है और इसे मर्यादाबद्ध समान ढंग से लगाया जाना चाहिए। व्यापक रूप से स्वीकृत नियमों के अनुसार तो वित्तिलाभों पर ऊँची दरों से और सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर नीची दरों से कर लगाये जाने चाहिए। दरों का यह भेद भारोद्घोषन के एक मोटे तत्त्व का समावेश कर देता है।

जब हम वस्तु-कराधान की धार्मिक विधास के साधन के रूप में देखते हैं तो इसका औचित्य यह होता है कि हमें उपभोग की नियन्त्रित करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसका अधिक प्रयोग सर्वसाधारण के सामूहिक

उपभोग में लगी करने के बजाय उपभोग की सम्भाव्य वृद्धि को रोकने में रियाजाना चाहिए। कराधान को इस रूप में उचित ठहराना सामान्य होता है कि समाज उद्देश्य विभागिताओं के उपभोग और स्वास्थ्य व कार्यक्षमता के लिए आवश्यक न होने वाली अन्य वस्तुओं के उपभोग में बंसी करना है। लेकिन एक गरीब व अल्पविकसित देश में आम जनता के उपभोग में घटने वाली वस्तुओं पर पर लगाने से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह हमारे इस सिद्धान्त के विपरीत है कि अतिरिक्त या घाघिक्य के सत्व (element of surplus) पर ही प्रहार रियाज जाय। अतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या आम जनता के उपभोग पर लगाये जाने वाले करों का विकास के लिए की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था में कोई स्थान हो सकता है? चूंकि आम लोगों की आमदनी में अतिरिक्त का अंश मुश्किल से ही पाया जाता है, इसलिए उनकी अपनी मामूली आमदनी में से घाघिक विकास के लिए योगदान देने के लिए बाध्य करना स्पष्टतया अवांछनीय व अनुचित माना जायगा। यह कहना तो एक बात है कि अनिवार्य सरकारी सेवाओं को समयम रसने के लिए ऐसा कराधान आवश्यक है; लेकिन यह बात वित्तकुल भिन्न है कि विनियोग की चामू दर को ऊंचा करने के लिए इस स्रोत से ही कर की आय बढ़ाई जानी चाहिए। आगे चलकर यह बतलाया जायगा कि सम्भवतः यह नीति सफल न हो।

इस प्रन्थ में प्रस्तुत किये गये कार्यात्मक वित्त (functional finance) के दृष्टिकोण से आम वस्तुओं पर लगाये गये करों का कार्य एक दिए हुए समय में विनियोग की दर में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि उपयोग को उस सीमा तक बढ़ने से रोकना है जहाँ तक भूतकाल के विनियोग के फलस्वरूप आय बढ़ती है। इसी कारण से आम वस्तु-कराधान अल्पविकसित देशों में घाघिक विकास के दृष्टिकोण से भी आवश्यक हो जाता है।

अल्पविकसित देशों में एक अत्यधिक अटिल समस्या बचत वृद्धि-अनुपात (incremental saving ratio) को ऊंचा करने की है। यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल घनिक वर्ष को ही बचत व विनियोग के लिए प्रेरित करना अपवा फुसलाना पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ तक आय में होने वाली वृद्धि का अधिकांश भाग जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के हिस्से में आता है, वहाँ तक वे पहले से ज्यादा उपभोग करने की स्थिति में आ जाते हैं। उनके उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति इकाई के काफी नजदीक होती है, इसलिये उनके उपभोग में लगभग उनकी आय के अनुकूल ही वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि ऐसा होने दिया जाता है तो उत्पादनता में होने वाली वृद्धि बड़े हुए

उपभोग के रूप में ही लगभग पूर्णतया समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में बड़ा हुआ वस्तु-कराधान उपभोग की वृद्धि को नियन्त्रित करने में प्रयुक्त हो सकता है ताकि विनियोग के लिए कुछ साधन उपलब्ध किये जा सकें।

यही बात कृषि पर भी लागू होती है। जब कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है तो कृषक फार्म की वस्तुओं, विशेषतया भोजन, का अपना उपभोग बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसके अलावा जब मर्द्ध-रोजगार की दशा से श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक रोजगार की तरफ जाते हैं तो खेतों पर रह जाने वाले व्यक्तियों को अपने उपभोग में वृद्धि करने का अवसर मिल जाता है। दूसरी तरफ औद्योगिक रोजगार की निरन्तर वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि कृषिगत पदार्थों की बिभ्रीयोग्य बचत में वृद्धि हो। अतः हो सकता है कि बढ़ते हुए अतिरेक के एक घस को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में ले जाने के लिए कराधान का उपभोग करना पड़े।

असल में हमारा यह मत नहीं है कि उपभोग्य वस्तुओं की उत्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं हो, बल्कि हम तो यह सुझाना चाहते हैं कि उत्पादकता की वृद्धियाँ पूर्णतया उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में ही समाप्त न हो जाय। सच पूछा जाय तो मानवीय अथवा राजनीतिक कारणों के अलावा भी छिपी हुई बेकारी की स्थिति में कुछ उपभोग्य वस्तुओं की पूति में तो तीव्र गति से वृद्धि करना काफी वांछनीय होगा। यह उस समय स्पष्ट हो जायगा जब हम 'बचत वृद्धि-अनुपात को बढ़ाने' के आशय की सही रूप में जाँच करेंगे।

इस विश्लेषण की दृष्टि से हम उपभोग्य वस्तुओं की तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित कर लेते हैं (अ) अनिवार्यताएँ : जिनकी सबसे आवश्यकता होती है, लेकिन जो जीवन-निर्वाह की सीमा पर होते हैं उनको तो केवल ये वस्तुएँ ही उपलब्ध होती हैं, (आ) गैर-अनिवार्यताएँ : ये उस विद्याल जन-समुदाय के द्वारा काम में ली जा सकती हैं एवं ली जाते हैं जो विभिन्न संशो तक जीवन-निर्वाह के स्तर से ऊपर होता है; और (इ) वित्ताश्रितार्थः यह मुख्यतया धनिक वर्ग के द्वारा ही प्रयुक्त की जाती है।

मान लीजिए, जनमर्या स्थिर रहती है और छिपी हुई बेकारी नहीं पाई जाती है। विस्तृत विनियोग से जनता की वास्तविक आय में बढ़ोतरी होती है। इसका आशय यह है कि लोगों की मौद्रिक आय कीमतों के लगभग उसी स्तर पर अपेक्षाकृत ऊँची होगी अथवा कीमतों के अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर मौद्रिक आय लगभग उतनी ही होगी। जब एक व्यक्ति की वास्तविक आय बढ़ती

है तो यह धरने उपभोग के पैमाने में अनिवार्यताओं से विनियमितताओं की तरफ जाने का प्रयास करता है। यदि हम यति पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो गैर-प्रतिबन्धित वस्तुओं व विनियमितताओं के उत्पादन में वृद्धि होने के बजाय विनियोग-पराधी के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जीवन-स्तर स्थिर रहता है धनवा माधुनी-ता बढ़ता है, लेकिन विनियोग का प्राय के प्रति अनुपात बढ़ता है।

अब हम यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेकारी है और इसे बालांतर में कम किया जाना है। अर्थ-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को औद्योगिक रोजगार की तरफ ले जाने से गुजरिचन 'मजदूरी-वस्तु अंतर' ('wage-goods gap') उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यों कहा जा सकता है कि यद्यपि ये लोग अर्थ-रोजगार की अपनी पहले की दशा में कुछ वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे, लेकिन उनको औद्योगिक रोजगार के मिल जाने पर अर्थव्यवस्था में मजदूरी-वस्तुओं की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसा दो कारणों से होता है : (अ) उनको जो वास्तविक मजदूरी देनी होती है वह उनके आंशिक बेकारी के दिनों के औसत उपभोग से अधिक होती है; और (आ) जो खेतों में रह जाते हैं एवं अपने प्राथित्यों से मुक्त हो जाते हैं वे अपने उपभोग में वृद्धि करने लगते हैं। इन परिस्थितियों में छिपी हुई बेकारी की मात्रा में उस समय तक कमी नहीं हो सकती जब तक कि मजदूरी-वस्तुओं की उत्पत्ति में थोड़ी वृद्धि न हो जाय। दूसरे शब्दों में, यदि हम छिपी हुई बेकारी की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसी अनिवार्यताओं एवं कुछ गैर-अनिवार्य वस्तुओं की उत्पत्ति में वृद्धि करनी होगी जो विशेषरूप से धमिकों के काम आती हैं।

अब हम यह मान लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है और यह स्थिति वस्तुतः अल्पविकसित देशों में पाई जाती है। जब इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इन देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग निर्वाह-स्तर पर गुजर करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनिवार्यताओं की उत्पत्ति एवं कुछ गैर-अनिवार्य वस्तुओं की उत्पत्ति में भी तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए। अतः परोक्ष कराधान का कार्य अनिवार्यताओं की उत्पत्ति में कमी करना नहीं है, बल्कि सचत वृद्धि-अनुपात को बढ़ाना है। इस काम के लिए इसका उपयोग दो भिन्न-भिन्न तरीकों से करना होता है। सर्व प्रथम, इसका उपयोग धनवा गैर-अनिवार्य एवं वित्तासिता की वस्तुओं की उत्पत्ति में तीव्र वृद्धि पर रोक लगाने (अथवा उत्पत्ति को कम करने में भी) के लिए किया जाता है।

द्वितीय, इसका उपयोग मजदूरी-वस्तुओं की बढ़ी हुई उत्पात्ति के एक भाग को विनियोग और/प्रत्यवा औद्योगिक क्षेत्र में भेजने में करना होता है । आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सर्वसाधारण के उपयोग पर कर लगाने का पुष्ति-संगत कारण अतः यही होता है ।

यह स्मरण रखना होगा कि उपयोग की बढ़ती अपवा नियंत्रण की बात विनाशिताओं एवं गैर-अनिवार्य वस्तुओं पर ही लागू होती है । अनिवार्यताओं के सम्बन्ध में तो केवल इतना ही आवश्यक है कि इनकी उत्पात्ति में होने वाली वृद्धि का एक अंश विनियोग के क्षेत्र के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए । यह तो स्पष्ट है कि इस दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्यताओं पर ही कर लगाना आवश्यक नहीं है । उदाहरण के लिए, साध की द्विती घोष वस्तु के बढ़ाने के प्रयत्न को सीजिए । सर्वसाधारण के उपयोग में काम आने वाली मूलभूत वस्तुओं पर कर लगाना कृषकों को किसी भी तरह से इस बात के लिए प्रेरित करने अपवा बाध्य करने में सहायक नहीं होगा कि वे क्षेत्र की उपज के अपेक्षाकृत बड़े भाग का परिचालन करें । कृषकों के विपक्ष में विनिमय की शर्तों (*terms of exchange*) को बदलकर, अर्थात्, उन गैर-अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को करण के लिए बढ़ाकर जिन्हें कृषक अपनी आमदनी की वृद्धि के साथ-साथ बढ़नी हुई मात्रा में उपयोग में लगाना चाहेंगे, गैर-वृषि मास की एक दो हुई मात्रा के बदले में वृषि का अधिक मास प्राप्त किया जा सकता है । कर के उपायों को अपना कर यह भी आवश्यक नहीं है कि जनता के कुछ वर्गों के अनिवार्यताओं के उपयोग को उन लोगों के लिए नियन्त्रित किया जाए जिन्हें विनियोग के क्षेत्र में काम मिला हुआ है; क्योंकि ऐसे लोगों की ही जाने वाली मजदूरी स्वन, उन्हें इस बात के लिए सशम कर देगी कि वे अव्यवस्था में मजदूरी-वस्तुओं की उपलब्ध पुष्टि का एक अंश मांग सकें ।

अल्पविकसित देशों में राजकीय नीति पर निम्नलिखित बातें ध्यातियों में सामान्यतया इस बात पर केन्द्रित की जा है कि सर्वसाधारण को प्रोत्साहन देने करण के लिए अधिक विकास में योगदान करने के लिए क्या किया है लेकिन उनका बहुत यह निष्कर्ष रहा है कि ऐसा करण अव्यवस्थाकारी होता है । जब प्रश्न यह है कि जब हम प्रोत्साहन देने के लिए सर्वसाधारण को बाध्य करने को क्या करते हैं तो हमने सही आशय बना निश्चयता है ? किसी भी दिने हुए, समय में मजदूरी-वस्तुओं की पूर्ण निरर रहती है और यह उपरो-



तो यह धारणा प्रयोग के नीचे से अमान्यताओं से विनाशितों की  
 उत्पत्ति का प्रमाण बनता है। यदि इन गति पर प्रत्यक्ष ध्यान रखा  
 जाये तो गैर-अनिवार्य वस्तुओं के विनाशितों के उत्पादन में वृद्धि होने के  
 बजाय विनाशितों-उत्पत्ति के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और यह धारणा  
 सही है धारणा अमान्यता बनता है, लेकिन विनाशितों का ध्यान के नीचे  
 अमान्य बनता है।

अब हम यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेकारी है और  
 इन कारणों से यह धारणा बनता है। अर्थ-रोकथाम वाले स्थितियों को  
 औद्योगिक रोकथाम की मर्यादा के नीचे से गुजराना 'मजदूरी-वस्तु धार' ('wage-good trap') उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यों कहा जा  
 सकता है कि मर्यादा से लोग अर्थ-रोकथाम की अपनी पट्टे की धारा में कुछ  
 वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनको औद्योगिक रोकथाम के बिना  
 जाने पर अर्थव्यवस्था में मजदूरी-वस्तुओं की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है।  
 ऐसा दो कारणों से होता है : (अ) उनको जो वास्तविक मजदूरी देनी होती है  
 वह उनके आगिक बेकारी के दिनों के औसत उपयोग से अधिक होती है;  
 और (आ) जो लोगों में रह जाते हैं अब अपने व्ययों में मुक्त हो जाते हैं  
 वे अपने उपयोग में वृद्धि करने लगते हैं। इन परिस्थितियों में छिपी हुई  
 बेकारी की मात्रा में उस समय तक बची नहीं हो सकती जब तक कि मजदूरी-  
 वस्तुओं की उत्पत्ति में कोई वृद्धि न हो जाय। दूसरे शब्दों में, यदि हम  
 छिपी हुई बेकारी की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसी अनिवार्य-  
 ताओं एवं कुछ गैर-अनिवार्य वस्तुओं की उत्पत्ति में वृद्धि करनी होगी जो  
 विशेषरूप से धर्मिकों के काम आती हैं।

अब हम यह मान लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है और यह स्थिति  
 वस्तुतः अल्पविकसित देशों में पाई जाती है। जब इस बात पर ध्यान दिया  
 जाता है कि इन देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग निर्वाह-स्तर पर गुजर  
 करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनिवार्यताओं की उत्पत्ति एवं कुछ  
 गैर-अनिवार्य वस्तुओं की उत्पत्ति में भी तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए।  
 परीक्षा करारपान का कार्य अनिवार्यताओं की उत्पत्ति में बची करना नहीं  
 बल्कि वचन वृद्धि-अनुपात को बढ़ाना है। इस काम के लिए इसका उपयोग  
 भिन्न-भिन्न तरीकों से करना होता है। सर्व प्रथम, इसका उपयोग धनेक  
 एवं वित्तव्यय की वस्तुओं की उत्पत्ति में तीव्र वृद्धि पर रोक  
 (यों-ही-उत्पत्ति को कम करने में भी) के लिए किया जाता है।

द्वितीय, इसका उपयोग मजदूरी-वस्तुओं की बढ़ी हुई उत्पत्ति के एक भाग को विनियोग और/अथवा औद्योगिक क्षेत्र में भेजने में करना होता है। प्रादिक विकास के दृष्टिकोण से सर्वसाधारण के उपयोग पर कर लगाने का युक्ति-संगत कारण अतः यही होता है।

यह स्मरण रखना होगा कि उपयोग की बढ़ती अथवा नियंत्रण की बात विलासिताओं एवं गैर-अनिवार्य वस्तुओं पर ही लागू होती है। अनिवार्यताओं के सम्बन्ध में तो केवल इतना ही आवश्यक है कि इनकी उत्पत्ति में होने वाली वृद्धि का एक बड़ा विनियोग के क्षेत्र के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि इस दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्यताओं पर ही कर लगाना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, खाद्य की किसी योग्य वृद्धि के बढ़ाने के प्रश्न को लीजिए। सर्वसाधारण के उपयोग में काम आने वाली मूलभूत वस्तुओं पर कर लगाना कृषकों को किसी भी तरह से इस बात के लिए प्रेरित करने अथवा बाध्य करने में सहायक नहीं होगा कि वे खेत की उपज के अपेक्षाकृत बड़े भाग का परित्याग करें। कृषकों के विपक्ष में विनिमय की शर्तों (terms of exchange) को बदलकर, अर्थात्, उन गैर-अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को कराधान के जरिए बढ़ाकर जिन्हें कृषक अपनी आमदनी की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हुई मात्रा में उपयोग में लगाना चाहेंगे, गैर-कृषि भाग की एक दी हुई मात्रा के बदले में कृषि का अधिक भाग प्राप्त किया जा सकता है। कर के उपायों को अपना कर यह भी आवश्यक नहीं है कि जनता के कुछ वर्गों के अनिवार्यताओं के उपयोग को उन लोगों के लिए नियंत्रित किया जाय जिन्हें विनियोग के क्षेत्र में काम मिला हुआ है; क्योंकि ऐसे लोगों को दी जाने वाली मजदूरी स्वतः उन्हें इस बात के लिए सक्षम कर देगी कि वे अर्थात्-वस्तुओं में मजदूरी-वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति का एक बड़ा भाग सकें।

अल्पविकसित देशों में राजकीय नीति पर लिखने वाले व्यक्तियों ने सामान्यतया इस बात पर खेद तो प्रकट किया है कि सर्वसाधारण को अपेक्षाकृत ऊँचे कराधान के जरिए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए कहा जाता है लेकिन उनका बहुधा यह निष्कर्ष रहा है कि ऐसा कराधान अक्षमभावी होता है। अब प्रश्न यह है कि जब हम अपेक्षाकृत ऊँचे कराधान के जरिए आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सर्वसाधारण को बाध्य करने की चर्चा करते हैं तो इससे सही आशय क्या निकलता है? किसी भी दिने हुए समय में मजदूरी-वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है और यह उपयोग

के लिए उपलब्ध होती है। अपेक्षाकृत ऊँचे कराधान से वास्तविक उपभोग में घीघ्र ही बमी नहो हो सकती है। उपभोग में काफी बमी तभी आती है जब कि कराधान से उपभोग्य वस्तुओं की उत्पत्ति में बमी होने लग जाती है। लेकिन ऐसा समस्त उपभोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में नहीं होने दिया जाता है। भावी उत्पत्ति की बनावट वर्तमान विनियोग के प्रारूप पर ही निर्भर किया करती है। इस समय विनियोग की जो अधिकांश योजनाएँ चल रही हैं उनमें मजदूरी-वस्तुओं की उत्पत्ति में काफी वृद्धि की व्यवस्था की गई है। वास्तव में ज्यों-ज्यों विकास की योजनाएँ आगे बढ़ेंगी त्यों-त्यों कई तरह की उपभोग की वस्तुओं की उत्पत्ति में वृद्धि होगी। उपभोग-वस्तुओं की उत्पत्ति वित्तनी तेजी से बढ़ेगी और वित्त किसम की वस्तुएँ बढ़ती हुई मात्रा में उत्पन्न की जायेंगी यह सब जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विनियोग के ढंग पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जितना अधिक विनियोग देश क पूँजीगत ढाँचे को गहन करने में किया जाता है, उपभोग-वस्तुओं की उत्पत्ति उसनी ही कम तेजी से बढ़ती है। चूँकि सभी किसम के विकास में कुछ-न-कुछ पूँजी-गहनता की आवश्यकता होती है, इसलिए विनियोग का प्रारूप सम्भवतः गैर-अनिवार्यताओं व विलासिताओं की उत्पत्ति में तीव्र वृद्धि नहीं होने देगा। इस नीति के अन्तर्गत आम जनता के लिए यह तो आवश्यक होगा कि वह अपने जीवन-स्तर में अपेक्षाकृत घीमी वृद्धि को ही सहन करे, लेकिन इससे अनिवार्यताओं के उपभोग में कोई बमी नहीं आयेगी।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम जनता के काम की वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों का मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण के उपभोग में तीव्र वृद्धि को रोकना होता है। इस निष्कर्ष के नीति की दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। सर्वप्रथम, अनिवार्यताओं पर कर लगाने के पक्ष में कोई ठर्क नहीं दिया जा सकता है। द्वितीय, गैर-अनिवार्यताओं एवं सर्वसाधारण की विलासिताओं पर प्रारम्भ में काफी नीधी दरों से कर लगाया जा सकता है। सर्वसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर कर की दरें तभी बढ़ाई जानी चाहिए जब कि इस बात का स्पष्ट सबेद मिल जाय कि ऐसी वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उत्पत्ति बढ़ रही है। यहाँ पर यह बतलाना भी आवश्यक होगा कि जहाँ तक विनियोग का प्रारूप योजना-अधिकारी के द्वारा निर्धारित होता है वहाँ तक कराधान का कार्य केवल भावी उपभोग के प्रारूप को विनियोग के प्रकार के अनुरूप ही माना होगा है। अनिवार्यताओं पर कर लगाना और साथ में सरकारी विनियोग और आर्थिक सहायता के

जरिए उनकी उत्पत्ति को बढ़ाना स्पष्टतया एक परस्पर विरोधी नीति ही मानी जायगी ।

कराधान-जीव-आयोग (TEC) ने एक सिफारिश की है जो हमारे उपर्युक्त निष्कर्षों के विपरीत है । भारत के लिए वस्तु-कराधान के सर्वोत्तम ढांचे का विवेचन करते हुए उसने निम्नांकित बात कही है : 'भ्रत हमारा मत है कि कई किस्म की विलासिता एवं भ्रद्ध-विलासिता की वस्तुओं पर काफी ऊँची दरों से अतिरिक्त कर लगाये जाय और साथ में सर्वसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर अपेक्षाकृत नीची दरों से विस्तृत रूप से कर लगाये जाय ।<sup>1</sup> यह एक ऐसा कदम है जिसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता । लेकिन इससे भागे चल कर यह कहा गया है . 'वस्तु-कराधान से काफी आय प्राप्त करने के लिए और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में उपभोग पर उत्प्रेक्षणीय नियंत्रण करने के लिए उत्पादन एवं विप्री करो को नीची आय वाले लोगों तक फैलाना होगा और इनके अन्तर्गत उन वस्तुओं को भी लेना होगा जो साधारणतया अनिवार्य-ताएँ कहलाती हैं और जिनमें ऐसी कई वस्तुएँ भी आ जाती हैं जो सविधान की धारा 286 के अन्तर्गत अनिवार्य वस्तु-अधिनियम में शामिल की गई हैं ।

..... यदि सार्वजनिक विनियोग की वित्तीय व्यवस्था के लिए साधनों को मोड़ (Diversion) देकर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने हैं तो अनिवार्य-ताओं पर कराधान का विस्तार करना अवश्यम्भावी प्रतीत होता है ।<sup>2</sup> अनिवार्य वस्तु-अधिनियम में शामिल होने वाली कुछ वस्तुएँ नीची आय वाले व्यक्तियों के लिए इस कठोर अर्थ में अनिवार्य नहीं हैं कि वे उनके लिए जीवन की अनिवार्यताओं हों । लेकिन जीवन की अनिवार्यताओं के सम्बन्ध में तो प्रायोग की सिफारिश बिलकुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है । यह विश्वास सम्बन्धी वित्त के प्रश्न पर केवल 'आय-दृष्टिकोण' ('revenue approach') पर आधारित है और प्राप्त किये जा सकने वाले मोड़ों की प्रकृति का गलत अर्थ लगाती है ।

यदि यह सच है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्वाह-स्तर पर जी रहा है तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अनिवार्यताओं की उत्पत्ति में बमी करने के लिए बनायी गई कोई भी नीति कैसे उचित टहपाई जा सकती

1. TEC Report, Vol I, P. 149.

2. वही ।

है। इनके विपरीत वेतन कि ऊपर बताया जा चुका है जनसंख्या की वृद्धि और ज़िन्दा हुई बेकारी को कम करने की आवश्यकता के दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक विनियोगों की प्रगति में तीव्र वृद्धि की ही बात कानी है। प्रथम एक द्वितीय व्यवस्थागत मोडलों में इन परिवर्तन अनुपातों की प्रगति में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता की गई है। धन: आयोग का यह समझ कि 'सार्वजनिक विनियोग की विशेष आवश्यकता के लिए साधनों के मोड़ या व्यवस्थापन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता करने हैं तो परिवर्तनों पर कराधान का विचार आवश्यकताओं परीक्षा होता है', एवं आयोगकर्तव्यों के द्वारा के ही व्यवस्था विपरीत है और मांग में यह धार्मिक विवेकन में प्राप्त निष्कर्षों के भी विपरीत है। (विदेश और देश के लिए गहरे अर्थों में पैसा की ओर से दिया गया है।)

## 2. परोक्ष कराधान के प्रभावों का विश्लेषण (Analysis of the Effects of Indirect Taxation) :-

ऊपर यह बताया जा चुका है कि धार्मिक विवेक के दृष्टिकोण से परोक्ष कराधान के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं, यथा (अ) सार्वजनिक विनियोग के लिए साधन जुटाना; (आ) विलासिताओं के उपयोग में बनी बचत अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर को बढ़ाना; और (इ) बचत वृद्धि-अनुपात (incremental saving ratio) को ऊंचा करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को इस बात में रुचि होगी है कि वह साधनों एवं अर्थ-शक्ति को कुछ विधियों से एक कुछ दिशाओं में मोड़ प्रदान करे। ऐसे तीन किस्म के मोड़ हैं जो इस स्थिति में आवश्यक माने जायेंगे: (अ) साधनों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ से जाना; (आ) निजी क्षेत्र में ही उपभोग-वस्तुओं के उपयोग से विनियोग-वस्तुओं के उपयोगों में साधनों को से जाना और (इ) मांग की आयातों की तरफ से घर में निर्मित माल की तरफ मोड़ देना।

द्वितीय किस्म का मोड़ भेदात्मक कराधान (differential taxation) के माफ़त प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, विलासिताओं पर दर लगाने से एवं पूजनीय माल को छूट देने से इस किस्म का कुछ मोड़ प्रवर्त प्राप्त होगा। हम पिछले अनुच्छेद में पहले ही इस बात का विवेचन कर चुके हैं कि यही उद्देश्य किस प्रकार आय पर आरोही कराधान और साथ में बचत पर आधिक छूट की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकता है। मोड़ की तृतीय किस्म आयात-करों से उत्पन्न होती है। आयात-कर विकास-कार्यक्रम

के धन के रूप में सगाये जा सकते हैं ताकि घरेलू उद्योगों (domestic industries) को अधिक विवसित विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में प्रारम्भिक सहाय दिया जा सके। ये आयात की जाने वाली वित्तागिता की वस्तुओं के उपयोग को सीमित करने के लिए भी सगाये जा सकते हैं। ऐसा कराधान उसी सीमा तक प्रभावपूर्ण हो सकता है जहाँ तक कि वित्तागिता की वस्तुओं का घरेलू उत्पादन भी साथ में बच बचाया जाता है। अंत में, आयात-कर मुद्रा-स्फीति एवं भुगतान-संतुलन के संकट के समय में भी लगाये जा सकते हैं ताकि आयातों को नियंत्रित रखा जा सके और जनता से उसकी अतिरिक्त क्रय-शक्ति का एक अंश लिया जा सके। लेकिन यह स्मरण रक्खना होगा कि अन्य देशों के द्वारा सगाये जाने वाले प्रतिस्पर्धात्मक आयात-कर भुगतान-संतुलन सम्बन्धी इन संकटों को दूर करने की इस विशेष विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए।

जहाँ तक प्रथम किस्म के भौद का सम्बन्ध है राज्य को चाहिए कि वह अपनी तरफ साधनों का हस्तान्तरण इस तरह से करे कि कम से कम स्फीतिकारी अथवा अवांछनीय प्रभाव ही पड़े। इस हस्तान्तरण में दो भिन्न भिन्न कार्य शामिल हैं। प्रथम तो राज्य के द्वारा क्रय शक्ति का प्राप्त किया जाना है और द्वितीय राज्य के द्वारा उत्पादन के साधनों का खरीदा जाना है जिससे क्रय शक्ति स्वतः निजी हाथों में वापिस आ जाती है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यदि पूर्ण रोजगार की दशाओं में क्रय-शक्ति साख सृजन के जरिए प्राप्त की जाती है तो कुछ मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा कराधान के जरिए किया जाता है तो इस तरह का कोई मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि कराधान उत्पादन के साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में, सरकार की तरफ साधन हस्तान्तरित करने का साख सृजन की तुलना में साधारणतया ज्यादा अच्छा उपाय माना जाता है। लेकिन वस्तुओं पर परोक्ष रूप से कर लगाये जाने से अवि-काश दशाओं में कीमतों में कुछ वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि की मात्रा और प्रभावित वस्तुएं जमना: इस बात पर निर्भर करती हैं कि सरकार ने कौन-सी वस्तुओं पर कर लगाया है और कौन-सी वस्तुएं खरीदी हैं। कुछ परिस्थितियों में परोक्ष कराधान की बड़े पैमाने पर होने वाली वृद्धि से कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो जाती है जिससे मजदूरी में भी वृद्धि हो सकती है। यह परिणाम उस सीमा तक परोक्ष कराधान के प्रभावों को मिटा देता है जहाँ तक कि इसका लोगों की क्रय शक्ति में कमी करने से सम्बन्ध होता है।

करों के अन्तिम आर्थिक प्रभाव केवल करों की प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि वे इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि क्या करों से प्राप्त आय सच की जायगी, और यदि सच की जायगी, तो किन दिशाओं में। नीचे के वर्णन में हमने यह मान लिया है कि संप्रद की गई सम्पूर्ण आय बिना विशेष विलम्ब के सच कर दी जाती है। साथ में यह भी मान लिया गया है कि श्रम और प्राकृतिक साधनों के अलावा अन्य समस्त साधन समस्त पूर्णरूप से काम में लिये जा रहे हैं। यह विस्तरेषण, जहां कोई अन्य निर्देश नहीं है, विशुद्ध प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि में ही किया जा रहा है।

परोक्ष कराधान के प्रभावों का विस्तरेषण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत सुविधापूर्वक किया जा सकता है : (अ) आय-प्रभाव (revenue effect); (आ) मोड़-प्रभाव (diversion effect); (इ) कीमत-प्रभाव (price effect); और (ई) वितरण-प्रभाव (distribution effect); (ए) आय या राजस्व प्रभाव (Revenue effect):—जब कर एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसका उत्पादन होता रहता है और जो बिकती जाती है तो सरकार के लिए आय का एक प्रवाह-सा बना रहता है। वास्तव से हम एक ऐसे कर की कल्पना कर सकते हैं जो सरकार को अरा भी आमदनी नहीं देता है, जैसे एक ऊँचा संरक्षारमक कर। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि कर-प्रणाली में कम-से-कम कुछ महत्वपूर्ण कर तो ऐसे अवश्य हों जो सरकार के लिए काफी आय जुटा सकें। ऐसी वस्तुओं पर कर होते हैं जिनकी मांग की सोच (कीमत के सन्दर्भ में) नीची होती है। विभिन्न वर्गों के लिए एक ही वस्तु की मांग की कीमत-सोच प्रायः काफी भिन्न होती है। एक व्यक्ति की आय के बढ़ने पर यह सम्भव है कि कुछ वस्तुओं के लिए उसकी मांग कम सोचदार हो जाय। जिन वस्तुओं की मांग की भाव-सोच ऊँची होती है उन पर कर लगाने का यही प्रभाव होता है क्योंकि आमदनी के बढ़ते जाने पर ऐसे करों से प्राप्त होने वाली आय में अनुपात से अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।

(आ) मोड़-प्रभाव (Diversion effect):—विशेष वस्तुओं पर कर लगाने से सम्बन्धित उद्योगों से साधनों के मोड़ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रायः यह सकं दिया जाता है कि मोड़ की मात्रा मांग व पूर्ति की तापेता मोड़ों पर निर्भर करती है। मांग घटवा पूर्ति जितनी ज्यादा बेमोव होती है कर के परिवर्तन में उत्पन्न होने वाला मोड़ उतना ही कम होगा है। लेकिन यह भी सम्भव है कि सच सम्बन्धी प्रभाव कर के प्रभावों में परिवर्तन उत्पन्न कर दें। कर से प्राप्त आय इस तरह से व्यय की जा सकती है ताकि उन वस्तुओं की

प्रतिरिक्त मांग उत्पन्न हो जाय जिनकी विधी कर की वृद्धि के कारण घट गई है। उदाहरणार्थ, यदि वर मजदूरी-वस्तुओं पर लगाये जाते हैं अथवा प्रचलित कर की दरों में वृद्धि की जाती है और प्रतिरिक्त आय प्रमुखतया उस धन को वाम पर लगाने में व्यय हो जाती है जिसको इस समय अल्प रोजगार मिला हुआ है तो यह सम्भव है कि मजदूरी-वस्तुओं की मांग में कोई विशुद्ध कमी न आवे। दूसरे शब्दों में, कीमत के बढ़ने पर भी खरीदी गई वस्तु की कुल मात्रा स्थिर रह सकती है अथवा सम्भवतः कुछ बढ़ भी सकती है। मोड़ तो रोजगार के क्षेत्र में हुआ है।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना होगा कि पूति की सोच से हमारा टीका प्राशय क्या है। जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उत्पादन की सीमान्त सागत में वृद्धि हो जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में कीमत में प्रत्यक्षरूप से वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी वजह से उत्पादकों की प्रवृत्ति उत्पादन को घटाने की हो जाती है जिससे साधनों के लिए उनके द्वारा की जाने वाली मांग भी घट जाती है। इससे साधनों की आय में गिरावट आ जाती है। जब साधनों के स्वामियों की प्रतिफल की दर इस तरह से घट जाती है तो वे साधनों की अपनी पूति को घटा देते हैं और ऐसी स्थिति में पूति सोचदार मानी जा सकती है। वे ऐसा निम्न दशाओं में कर सकते हैं (अ) यदि वे यह निश्चय करते हैं कि प्रतिफल की अपेक्षाकृत नीची दर पर पहले जितनी मात्रा में अपनी सेवाएँ या साधन उपलब्ध करना उचित नहीं है, अथवा (आ) यदि वे अपने साधनों के कुछ प्रस के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रतिफल की अपेक्षाकृत ऊँची दर प्राप्त कर सकते हैं। हम यह निश्चितरूप से मान सकते हैं कि अधि-वास बसाओ में केवल दूसरे कारण का ही महत्त्व होता है।

अब हमें यह देखना है कि वे तीन ही दशाएँ हैं जिनमें साधनों के स्वामी कर लगे हुए उद्योग की अपेक्षा अन्य उद्योगों में प्रतिफल की अपेक्षाकृत ऊँची दर प्राप्त कर सकेंगे। वे अन्यत्र ऊँचा प्रतिफल सभी प्राप्त कर सकेंगे जब कि (अ) साधन विशिष्ट न हों और अन्य कई उद्योगों में प्रयुक्त हो सकें, और (आ) बड़ा हुआ सरकारी उद्योगों में अथवा उनके द्वारा उत्पन्न कर सकें। यदि इनमें से दोष न टहरना होगा और यह यह करते हैं कि यह है। आने के विवेचन में ... में पूति देनी



हो सकती है। लेकिन दीर्घकाल में थानु गाणनों के सम्बन्ध हो जाने पर धरणा उनकी हटाने के लिए करने में पर्याप्त साधन कर सके हुए उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे जिससे उद्योग में गाणनों की कुल पूर्ति कम हो जायेगी। इस प्रकार दीर्घकाल में गाणनों की पूर्ति कर सके हुए उद्योग के लिए काफी मोचदार हो जायेगी।

अब इस विशेष सम्बन्धों पर सके हुए वनों के मोड़-प्रकारों पर विचार करेंगे जो उनकी मांग व पूर्ति की मोचों के विभिन्न धनों की स्थिति में उत्पन्न होते हैं (यही हम निरन्तर मोच और बेचोच को छोड़ देते हैं)।

(i) सापेक्ष रूप से मोचदार पूर्ति और सापेक्ष रूप से मोचदार मांग—

चूंकि पूर्ति मोचदार है इसलिए उत्पाति पर रोक लग जाती है और कुछ साधन कर सके हुए क्षेत्र को छोड़ देते हैं। इस स्थिति में साधनों के मोड़ का उद्देश्य अधिकतम सीमा तक प्राप्ति हो जाना है। चूंकि मांग मोचदार है, इसलिए उपभोक्ता ऊंची कीमत पर इस वस्तु पर अपेक्षाकृत कम राशि व्यय करते हैं। इससे वे अन्य वस्तुओं पर अधिक व्यय करने में और/अथवा (अधिक) बचाने में समर्थ हो जाते हैं। अन्य वस्तुओं पर अधिक खर्च हो जाने से कुछ साधन अन्य निजी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं।

(ii) सापेक्ष रूप से मोचदार पूर्ति और सापेक्ष रूप से बेचोच मांग—

इन दशाओं में कर सके हुए उद्योग से मोड़ उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता है जितनी में कि यह प्रथम स्थिति में होता है। उपभोक्ता इस वस्तु पर अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर पहले से अधिक व्यय करेंगे और इसीलिए उन्हें अन्यत्र बचत या व्यय में कटौती करनी होगी। इसलिए अधिकतर मोड़ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होता है।

(iii) सापेक्ष रूप से बेचोच पूर्ति और सापेक्ष रूप से मोचदार मांग—

इन दशाओं में, तुलनात्मक मोचों को उत्पन्न देने पर, कर सके हुए उद्योग से मोड़ लगभग पिछले जितना ही होता है। कीमत में कुछ वृद्धि हो जाती है और उपभोक्ता इस वस्तु पर कम और अन्य वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। इस दशा में जो कर प्राप्त होता है वह साधनों की प्राप्ति में कटौती के रूप में ज्यादा होता है, वनिस्वत कीमत में वृद्धि के रूप में। इस बात से भी साधनों का मोड़ होने लगता है। चूंकि हमने यह मान लिया है कि पूर्ति पूर्णतया बेचोच नहीं है, इसलिए मांग की मोच की मात्रा से कुछ

प्रतर प्रवश्य पड़ेगा। लोचदार माँग की स्थिति में उपभोक्ताओं के पास अन्य वस्तुओं पर व्यय करने के लिए अधिक राशि रहेगी और बेलोच माँग की स्थिति में यह कम हो जायेगी।

(iv) सापेक्ष रूप से बेलोच पूर्ति और सापेक्ष रूप से बेलोच माँग :—

चारों परिस्थितियों में से केवल इसी परिस्थिति में उत्पत्ति की कमी सबसे कम होगी। यद्यपि माँग बेलोच है फिर भी कीमत की वृद्धि अत्यधिक नहीं होगी क्योंकि पूर्ति भी बेलोच है और साधनों के स्वामियों को अपनी आमदनी में कटौती स्वीकार करनी होगी। उपभोक्ता अन्य वस्तुओं पर थोड़ा कम खर्च करेंगे। यहाँ भी साधनों का मोड़ अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में ही उत्पन्न होगा।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निश्चयता है कि अल्पकाल में कर की एक ही हुई वृद्धि से एक विशेष उद्योग में उत्पत्ति में सबसे कम गिरावट तभी आती है जब कि माँग व पूर्ति दोनों बेलोच होती हैं। अतः यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार को तो सबसे अधिक आमदनी प्राप्त होती है लेकिन कर लगे हुए उद्योग से मोड़ न्यूनतम होता है। जब माँग व पूर्ति दोनों लोचदार होती हैं तो उत्पन्न मोड़ सबसे अधिक होता है, लेकिन आमदनी (राजस्व की धारा) सबसे कम होती है। दीर्घकाल में पूर्ति लोचदार होती है क्योंकि साधनों की विविधता तो अनिवार्यतः एक अल्पकालीन विषय ही है। अतएव दीर्घकाल में (i) और (ii) परिस्थितियों का ज्यादा महत्त्व हुआ करता है। इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जब माँग लोचदार होती है तो अधिकांश मोड़ कर लगे हुए उद्योग से उत्पन्न होता है; और जब माँग बेलोच होती है तो अधिकांश मोड़ अन्य उद्योगों से उत्पन्न होता है। इसके अलावा दूसरी दशा में वस्तु-कर से उत्पन्न होने वाला राजस्व पहली दशा की तुलना में अधिक होता है।

(v) कीमत-प्रभाव (Price Effect)—यह स्मरण रखना होगा कि सरकार की वास्तव में रवि इन बातों में होनी है कि कुछ साधन सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा निजी विनियोग के क्षेत्र में हस्तान्तरित किये जायें। इन साधनों में विशेषतया मध्यवर्ती वस्तुओं की विभिन्न किस्में और थप—दस और परस—दोनों शामिल होने हैं। हमें इस बात की जाँच करनी है कि विभिन्न मान्यताओं के अन्तर्गत हस्तान्तरण की प्रक्रिया कीमत-वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है।

जब एक वस्तु पर अधिक कर लगाया जाता है जो समस्त वस्तुओं पर लगे हुए कर के बराबर नहीं होता है, तो इसकी उत्पत्ति में घटने की प्रवृत्ति होती है (ऐसा केवल उस समय नहीं होता है जब कि व्यय का परिवर्तन इस प्रभाव को मिटा देता है)। उत्पत्ति में होने वाली कमी जिस सीमा तक इसकी कीमत को बढ़ायेगी अथवा इस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधनों की आमदनी को कम करेगी, यह उस वस्तु की माँग व पूर्ति की सापेक्षताओं पर निर्भर करेगा। हम मान लेते हैं कि माँग की सोच इकाई के बराबर है और हम पूर्ति-पक्ष की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। यदि उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं और कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पन्न करने में प्रयुक्त विधे जा सकते हैं जिन पर कर के परिवर्तनों का कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो साधनों की कुछ इकाइयाँ इन वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों में चली जायेंगी और उनकी पूर्ति में वृद्धि हो जायेगी। उनकी कीमतों में गिरावट आयेगी और सम्बन्धित साधनों की कीमतें भी घटेंगी। इसके विपरीत पर लगी हुई वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जिन उद्योगों में साधन प्रयुक्त विधे जा सकते हैं उनकी सहायता जितनी अधिक होगी उनकी आय में उतनी ही कम गिरावट आयेगी और कर लगी हुई वस्तु की कीमत में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इसके विपरीत, कर के अन्तर्गत वस्तुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, साधनों की आमदनी में उतनी ही अधिक गिरावट आने की सम्भावना होगी, और कर लगी हुई वस्तुओं की कीमतों में उतनी ही कम वृद्धि होगी।

ये परिणाम तो उस स्थिति में आते हैं जब कि हम यह मान लेते हैं कि कर की आय लक्ष्य नहीं की जाती है। लेकिन हमारी सामान्य मान्यता यह है कि कर की सम्पूर्ण आय लक्ष्य कर दी जाती है। यदि सार्वजनिक व्यय से कर लगे हुए उद्योग में प्रयुक्त होने वाले साधनों के लिए कुछ माँग उत्पन्न होगी है, अथवा इन साधनों की सहायता से उत्पन्न हो करने वाली वस्तुओं के लिए माँग उत्पन्न होगी है तो साधनों की आय एवं इन साधनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली वैयक्तिक वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट कुछ सीमा तक रक जायेगी है। धन: कर लगी हुई वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि अनेकानेक अधिक होती है। जब सम्बन्धित साधन पूर्णतया विनिम्न होते हैं और सरकारी लक्ष्य उनके लिए कोई माँग उत्पन्न नहीं करता है तो समायोजन (adjustment) केवल साधनों की आय में होने वाली गिरावट के रूप में ही हो जाता है। यह निम्न पूर्ति की पूर्ण बेरोजगारी की है जो अपने अर्थव्यवस्था के कारणों से उत्पन्न होती है। उन सब परिस्थितियों में जहाँ पूर्ति में पूर्ण



कीमतों को भी प्रभावित कर सकती है। तम्बाकू के भत्तावा कई अनिवार्य वस्तुओं जैसे नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, सूती वस्त्र, आदि पर भी कर लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक साधारण उपभोक्ता को इस बात से सतुष्टि नहीं होती है कि बाह्यर सिनेमा व पत्रिकाओं के भाव तो गिर गये हैं।

उपयुक्त विवेचन से एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी सामने आती है कि विशेष वस्तुओं पर लगने वाले करों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हलचल उत्पन्न हो जाती है। यदि मूल्य-वृद्धि और हलचल को न्यूनतम रखना है तो आवश्यकता पड़ने पर उन उद्योगों पर प्रतिरिक्त कर लगाये जा सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम आने वाले सीमित साधनों के लिए प्रतिबोधी होते हैं। जब सार्वजनिक विनियोग में वृद्धि करनी होती है और इसकी वित्तीय व्यवस्था बढ़े हुए वस्तु-कराधान के माध्यम से की जाती है तो एक नये कर के चुनाव का आधार मुख्यतया माँग की वेलोच का भ्रम न होकर उत्पादन के साधनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता का भ्रम होना चाहिए। वेलोच माँग वाली वस्तुएँ कराधान की दृष्टि से काफी पसंद की जाती हैं क्योंकि इन वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों से सरकार को सापेक्ष रूप से अधिक मौद्रिक आय प्राप्त होती है। यह तो सच है कि, अन्य बातों के समान रहने पर, वेलोच माँग वाली वस्तु पर एक ही हुई दर से कर लगाने पर निजी आय में उस स्थिति की अपेक्षा अधिक कमी आती है जबकि यह कर सापेक्ष रूप से सोचदार माँग वाली वस्तु पर लगाया जाता है। अतः यदि मुद्रा-स्थिरता के विरुद्ध में कदम उठाना है तो वेलोच माँग वाली वस्तुओं पर कर लगाना ज्यादा उचित होगा। लेकिन यदि प्राथमिक उद्देश्य विनियोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ साधनों का हस्तांतरण करना है तो उन उद्योगों पर कर लगाना ज्यादा उचित होगा जो उन्हीं साधनों के लिए प्रति-स्पर्धी हैं। यदि उद्योगों के समस्त माँग सापेक्ष रूप से सोचदार होती है तो सरकार माधनों की अपेक्षाकृत भीषण कीमतों पर प्राप्त करने में समर्थ हो पायेगी, बनिस्वन उस स्थिति के जबकि माधनों का कर-प्रेरित (tax-induced) हस्तांतरण नहीं होता है। अतः प्रतिरिक्त कराधान के लिए वस्तुओं के चुनाव में यह आवश्यक नहीं है कि माँग की सोच का भ्रम एक निर्णायक तत्व हो।

अब हम एक सामान्य कर के मुख्य-प्रभावों पर आते हैं। हाल के वर्षों में सामान्य बिजली कर के भार बढ़ाने करने एवं इनके प्रभावों की सही प्रकृति के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ विवाद व अनिश्चितता बनी रही है। विशेष



है तो समस्त मापनों की आय में आनुपातिक कमी आ जाती है। वस्तु-मिश्रण (product mix) के सम्बन्ध में समान कर गठन होगा। रोल्ट का निष्कर्ष इस प्रकार है: 'विद्यमान विवेचन में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक पूर्णतया सामान्य क्रिसम की उत्पादन-करों की एकात्मिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नहीं बढ़ती हैं, इससे उत्पादों की बनावट में परिवर्तन नहीं होता है और यह व्यवस्था साधनों के स्वामियों की मौद्रिक आय में आनुपातिक कमी उत्पन्न करती है।'<sup>4</sup>

रोल्ट अपने विश्लेषण में कर की अतिरिक्त आय को व्यय करने से उत्पन्न होने वाले प्रभावों में शामिल नहीं करता है। चूंकि हमने यह मान लिया है कि कर की आय संचय की जाती है तो हमें कर व व्यय के कार्यक्रम पर सम्पूर्णरूप से विचार करना होगा। इस कार्यक्रम का अंतिम परिणाम उन मान्यताओं पर निर्भर करेगा जो हम समग्र मौद्रिक मांग के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में स्वीकार करते हैं। अतः हम सामान्य विभिन्न कर के भूस्थ-प्रभावों का विवेचन मौद्रिक मांग के स्तर से सम्बन्धित विभिन्न मान्यताओं के अन्तर्गत करेंगे।

समग्र मांग पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है: (अ) कर के परिणामस्वरूप निजी उपभोग और निविद्योग किम सीमा तक कम होते हैं, (आ) कर से प्राप्त आय के प्रयोग का विस्तार की तरफ से जाने वाला प्रभाव, और (इ) चालू मौद्रिक नीतियाँ<sup>5</sup> यह मान लेने पर कि मुद्रास्फीतिकारी और मुद्रा-अपस्फीतिकारी दशाओं में से कोई भी वद्यमान नहीं है, हम यह पता लगा सकते हैं कि कब और किन परिस्थितियों में समग्र मौद्रिक मांग स्थिर रहेगी और यह कब बढ़ेगी।

विशुद्ध प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक सामान्य कर का अथवा उत्तम होने वाली वृद्धि का प्रारम्भिक प्रभाव समस्त साधनों की धार में कमी करना होता है। हम यह मान लेते हैं कि बस्तुओं की कुल निजी मांग में साधनों की आय में होने वाली कमी के बराबर ही कमी हो जाती है। अब यदि कर की

4. अर्ल रोल्ट, पूर्वउद्धृत, पृ० 116.

5. cf. John F. Due, 'Toward a General Theory of Sales Tax Incidence', *Quarterly Journal of Economics*, Vol. LXVII, No. 2, P.258.

आय बंद हो जाती है तो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।<sup>1</sup> इस प्रकार एक मुद्रा-अपस्फीतिकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में समग्र मौद्रिक माग में गिरावट आ जाती है।

इसके विपरीत, यदि संयोगवश सरकार प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे के जहाँ वस्तुओं की उसी मात्रा में खरीदती है जिनकी साधनों के स्वामियों ने अपनी आय में होने वाली गिरावट के कारण खरीदना बंद कर दिया है तो मूल्य-स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। इस स्थिति में समग्र मौद्रिक मांग उतनी ही रहेगी जितनी कि पहले थी और वस्तु-मिथण अथवा उत्पाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्मों की तरफ होने वाला द्रव्य का प्रवाह तो स्थिर रहेगा लेकिन हमना एक अलग सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा। फलस्वरूप साधनों की आय उनके कर के पूर्व के स्तर तक नहीं आ सकेगी। केवल इस अत्यन्त विविष्ट स्थिति में ही, जो ऊपरवर्णित समस्त मांगताओं पर निर्भर करती है, समग्र मौद्रिक मांग और मूल्य-स्तर स्थिर रहेगे।

यह भी काफी सम्भव है कि सरकार बड़ी हुई कर की आय से उन उपभोग्य वस्तुओं की नहीं खरीदेगी जिनकी निजी मांग कर के परिवर्तन से कम हो गई है। विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए तो यह ज्यादातर उत्तरादन साधनों की ही अपनी खरीद में कृति करना चाहेगी। जहाँ तक कर की आय इस तरह से व्यय की जाती है वहाँ तक सरकार अर्थव्यवस्था में साधनों की मांग में प्रत्यक्षतया कृति करती है। निजी फर्मों के लिए साधनों के मूल्य नहीं गिरते हैं (अथवा यदि वे शुरू में गिरते हैं तो अब बढ़ जाते हैं), और साधनों की आय अपने कर से पूर्व के स्तरों के अन्दर ही बनी रहती है (अथवा उन तक पहुँच जाती है)। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह ध्यान देने की है कि सरकार की तरफ से होने वाली साधनों की मांग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में उनके मूल्यों की उस गिरावट को रोकती है जो कर की कृति से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती। परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। इस स्थिति में समग्र मौद्रिक मांग में कृति हो जाती है क्योंकि साधनों के स्वामी कर के पहले जितनी राशि ही खर्च करने की स्थिति में होते हैं और इसके अतिरिक्त, सरकार भी अपनी कर की आय खर्च कर रही है।

1. रोचक साधनों की आय से होने वाली गिरावट के प्रभावों को बहुताने में ध्यान रहे।



है तो गमन साधनों की भाव में आनुपातिक कमी आ जाती है। वस्तु-मिश्रण (product mix) के सम्बन्ध में गमन कर सटकर होगा। रोल्फ का निष्कर्ष इस प्रकार है: 'विद्ये विवेचन में यह दिगमाने का प्रयोग किया गया है कि एक पूर्णतया सामान्य बिन्दु की उत्पादन-करों की एक-ही व्यवस्था में उन्-भोक्तारों के लिए कीमतें नहीं बढ़ती हैं, इससे उत्पत्ति की बनावट में परिवर्तन नहीं होता है और यह व्यवस्था साधनों के स्वामियों की मौद्रिक आय में आनु-पातिक कमी उत्पन्न करती है।'<sup>4</sup>

रोल्फ अपने विस्लेषण में कर की अतिरिक्त आय को व्यय करने से उत्पन्न होने वाले प्रभावों में शामिल नहीं करता है।<sup>5</sup> चूँकि हमने यह मान लिया है कि कर की आय शर्च की जाती है तो हमें कर व व्यय के कार्यक्रम पर सम्पूर्णतया से विचार करना होगा। इस कार्यक्रम का अन्तिम परिणाम उन मान्यताओं पर निर्भर करेगा जो हम समग्र मौद्रिक मांग के स्तर पर पढ़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में स्वीकार करते हैं। अतः हम सामान्य बिन्दु कर के मूल्य-प्रभावों का विवेचन मौद्रिक मांग के स्तर से सम्बन्धित विभिन्न मान्यताओं के अन्तर्गत करेंगे।

समग्र मांग पर पढ़ने वाला वास्तविक प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है : (अ) कर के परिणामस्वरूप निजी उपभोग और विनियोग वित्त सीमा तक कम होते हैं, (आ) कर से प्राप्त आय के प्रयोग का विस्तार की तरह से जाने वाला प्रभाव, और (इ) चालू मौद्रिक नीतियाँ<sup>6</sup> यह मान लेने पर कि मुद्रास्फीतिकारी और मुद्रा-अपस्फीतिकारी दशाओं में से कोई भी वद्यमान नहीं है, हम यह पता लगा सकते हैं कि कब और किन परिस्थितियों में समग्र मौद्रिक मांग स्थिर रहेगी और यह कब बढ़ेगी।

विधुद्ध प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक सामान्य कर का अथवा उत्तम होने वाली वृद्धि का प्रारम्भिक प्रभाव समस्त साधनों की भाव में कमी करता होता है। हम यह मान लेते हैं कि वस्तुओं की कुल निजी मांग में साधनों की भाव में होने वाली कमी के बराबर ही कमी हो जाती है। अब यदि कर की

4. अर्ल रोल्फ, पूर्वउद्धृत, पृ० 116.

5. cf. John F. Due, 'Toward a General Theory of Sales Tax Incidence', *Quarterly Journal of Economics*, Vol. LXVII, No. 2, P.258.

उत्पादन के साधनों में कुछ बेकारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस तरह से जो साधन निजी उद्योगों से हटा दिये जाते हैं वे कर की धार के व्यय किये जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र में लग सकते हैं। इस प्रकार अंतिम परिणाम तो अपूर्ण प्रतियोगिता में भी वही होता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, सिवाय इसके कि कर के एक अंश को अतिरिक्त लाभ में शामिल किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्थिर समय मौद्रिक मांग की स्थिति काफी विविष्ट ढंग की होती है। अधिक प्रचलित और वास्तविक स्थिति तो यह है कि बड़ी हुई समय मौद्रिक मांग साधनों की समय वास्तविक मांग के साथ या तो स्थिर रहती है अथवा अत्यधिक ढँची भी रह सकती है। इसलिए यह परम्परागत निष्कर्ष काफी नहीं जान पड़ता है कि सामान्य बिन्दी कर के लागू होने से बीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, इसी तरह की परिस्थितियों में आयकर की आमदनी से सार्वजनिक व्यय में होने वाली बढ़ोतरी से सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाने की सम्भावना नहीं होती है। जिस सीमा तक साधनों की निजी मांग उत्तनी नहीं घटती है जितनी कि सरकारी मांग बढ़ती है वहां तक तो कुछ विस्तारशील प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन आयकर के मामले में तो साधनों की आय का एक अंश प्रत्यक्ष रूप में ही से लिया जाता है और इसके लिए उद्योगीताओं के द्वारा ही जाने वाली बीमतों और उत्पादकों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय में कोई बेल बँटाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सामान्य मूल्य-स्तर में सामान्य बिन्दी कर की भांति वृद्धि की जाया न करना ही उचित होगा।

सामान्य बिन्दी कर के प्रभाव के सम्बन्ध में उपर्युक्त निष्कर्ष एक सीमा तक ही सही माना जा सकता है। मूल्य-स्तर पर जो और प्रभाव पड़ते हैं उनको जाँच करना भी आवश्यक होगा। पिछले तर्क में कर की आय का व्यय साधनों की मांग व इनके मूल्यों को प्रारम्भिक स्तर पर पुनः स्थापित करने की दृष्टि से किया गया था। साधनों के लिए समय वास्तविक मांग उत्तनी ही रहेगी जितनी कि वह कर से पूर्व की, जब कि निजी आय कम होनी और सरकारी मांग अत्यधिक अधिक होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अतिरिक्त

1. ऐसे ही निष्कर्ष के लिए देखिए—Richard Goode, 'Anti-inflationary Implications of Alternative Forms of Taxation', *Papers and Proceedings of the American Economic Association*, May 1952, P. 157.

जब एक बार वस्तुओं की कीमों बढ़ने लग जाती हैं तो विभिन्न वस्तुओं की मांग की सोच का महत्व हो जाता है। बेमोच मांग वाली वस्तुओं की कीमों मोचदार मांगवाली वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ता प्रथम थोड़ी सी वस्तुओं पर पहले से ज्यादा व्यय खर्च करते हैं और दूसरी थोड़ी सी वस्तुओं पर कम करते हैं। यह आसानी से उचित होगा कि अनिवार्यताओं की कीमतों, जिन पर अन्य-व्ययित व्ययव्यवस्था में सम्पूर्ण अवस्था अधिकांश मजदूरी व्यय की जाती है, सामान्य मूल्य-स्तर की वृद्धि की तुलना में ज्यादा बढ़ती हैं।

कीमत-स्तर एवं समग्र मौद्रिक मांग की वृद्धि से अनिवार्यतः इस बात की आवश्यकता हो जायेगी कि द्रव्य की पूर्ति (MV) में वृद्धि की जाय। यदि हम द्रव्य की पूर्ति को मोचदार मान लेंगे हैं, तो आवश्यकता के मुताबिक M में सुगमतापूर्वक वृद्धि की जा सकती है। और सरकार के इस कार्य से मुद्रा के प्रचलन-वेग में वृद्धि हो सकती है कि यह उपभोक्ताओं के व्यय में से कर की राशि लेती है और साधनों को खजाने से पूर्व इसे दूसरी बार खर्च कर देती है। अतः जब तक प्रतिव्ययतात्मक मौद्रिक नीतियों का पालन नहीं किया जाता तब तक व्ययव्यवस्था में द्रव्य की पूर्ति में इतनी वृद्धि होती रहेगी जो कीमतों में वृद्धि कर सकने की दृष्टि से आवश्यक होगी।

पहले की कुछ मान्यताओं को अब चिथित किया जा सकता है। एक मान्यता तो यह थी कि निजी मांग में कर की पूरी राशि के बराबर गिरावट आयेगी। ऐसा उस स्थिति में नहीं होगा जब कि कर का एक घंटा घबरा में कमी करके प्राप्त किया जाता है और साथ में विनियोग ॥ कमी नहीं की जाती है। इस स्थिति में कर का अपेक्षाकृत अधिक विस्तारशील प्रभाव होगा। दूसरी मान्यता यह थी कि समस्त साधनों के मूल्य मोचदार होते हैं। वास्तव में इनमें से अनेक यथास्थिर रहते हैं। जिस सीमा तक कुछ साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं और नीचे नहीं लाये जा सकते हैं वहां तक उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में कर की आय के व्यय करने के बावजूद भयवा इसके पूर्व भी बढ़ने की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। विशुद्ध प्रतियोगिता की मान्यता को छोड़ देने पर भी वही परिणाम निकलता है जैसा कि प्रोफेटर ह्यू ने बतलाया है, <sup>1</sup> अल्पविक्रेताधिकार की दशाओं में कर के तात्पर्य होते ही फर्म मूल्यों में प्रत्यक्षरूप से वृद्धि कर सकती हैं और कर भी देती हैं। इससे

बिये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में समूह (इ) के सबसे बड़े होने की सम्भावना होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसी काफी विकसित अर्थव्यवस्था में तो स्पष्टतया यह स्थिति देखने की नहीं मिलती है जहाँ केवल लगभग 10 प्रतिशत परिवारों को ही 1000 एव इससे कम वार्षिक आय प्राप्त होती है।

समस्त उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर समूह (घ), यदि चाहे तो, अपने पहले वाले उपभोग के स्तर को कायम रख सकता है लेकिन इसके लिए बचत में कटौती करनी होगी। व्यवहार में सम्भवतः इसे प्राशिक रूप से विलासिताओं व गैर-आवश्यक वस्तुओं के उपभोग में कमी करनी पड़ सकती है। समूह (घा) को भी अपने उपभोग में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह सम्भवतः इतना न्यूनतम उपभोग कर सके जो जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक हो। लेकिन समूह (इ) जीवन-निर्वाह व कार्यकुशलता के लिए आवश्यक होने वाले न्यूनतम उपभोग को भी कायम नहीं रख सकेगा। अतः उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर समूह (घ) और (घा) के लिए मजदूरी व वेतन की वृद्धि पर जोर देने की प्रेरणा अपेक्षा-कृत कम होती है। उनको वास्तविक मजदूरी में कटौती स्वीकार करने के लिए तैयार करना सम्भव होता है क्योंकि पहले वे जीवन-निर्वाह स्तर से ऊपर थे। लेकिन (इ) समूह के जो सदस्य मजदूरी पर श्रम करते हैं अथवा किसी तरह के औद्योगिक रोजगार में सहे हुए हैं उनकी नकद मजदूरी में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए। सभी वे जीवन-निर्वाह व कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग को बनाये रख सकेंगे। ऐसा होने पर नकद मजदूरी बढ़ती है जिससे कीमतों में और भी वृद्धि होती है। सम्भव है कि इससे निजी माँग बराधान से पूर्व के अपने प्रारम्भिक स्तर पर पुनः स्थापित हो जाय।

अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह सहज में ही स्वीकार कर लिया जाता है कि सर्वसाधारण के उपभोग पर बढ़ने वाले कराधान से जीवन-व्यय में वृद्धि होती है जिससे मजदूरी को बढ़ाने की माँग उत्पन्न हो सकती है।<sup>1</sup> लेकिन कभी-कभी यह मत प्रगट किया जाता है कि ऐसी सम्भावना केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ही मुद्द होती है जहाँ अधिक शक्तिशाली संघों में संगठित होते हैं। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रायः यह तर्क दिया

1. उदाहरण के लिए देखिए, *Agricultural Taxation and Economic Development*, ed., Haskell P. Wald, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, 1954, P. 94.

सरकारी माँग उन्हीं मापनों के लिए होगी जो निजी माँग में होने वाली कमी से मुक्त हुए हैं ? यदि ऐसा नहीं होगा है तो मूल्यों की वृद्धि कम-से-कम अल्पकाल में तो अपेक्ष्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही केन्द्रित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अतिरिक्त बिजली कराधान के जरिए सार्वजनिक विनियोग में वृद्धि करने का निश्चय लिया जाता है और अतिरिक्त धन का उपयोग ऐसी विभाग-परियोजना में पूंजी सगाने के लिए किया जाता है जिसमें लगाये गये अन्य मापनों में धन का अनुपात काफी ऊँचा है। ऐसी स्थिति में यदि उन उद्योगों में (जिनके मान जो निजी माँग घट जाती है) अन्य साधनों के मुकाबले धन का वही ऊँचा अनुपात प्रयुक्त नहीं होता है तो धन-व्यवस्था में मजदूरी-वस्तुओं की माँग में विघुट रूप से वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि सरकार के द्वारा काम पर लगाये गये अतिरिक्त धन की मात्रा निजी उद्योगों में हटाये जाने वाले धन की मात्रा से अधिक होती है।<sup>1</sup> इस स्थिति में मजदूरी-वस्तुओं की कीमत में सामान्य मूल्य-स्तर की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि होती है। अल्पविकसित व अनाधिक्य वाले देशों में जहाँ विकास-परियोजनाएँ प्रायः रोजगारोन्मुख (employment-oriented) होती हैं, यह बात बहुत महत्व रखती है।

अब हम सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाली वृद्धि से उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों पर होने वाली प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। एक गरीब देश में बहुत सी उपभोग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो जीवन-निर्वाह और कार्य-कुशलता की दृष्टि से आवश्यक होती हैं। हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए अल्पविकसित देश के उपभोक्ताओं को तीन समूहों में बाँटा जा सकता है : (अ) वे उपभोक्ता जो जीवन-निर्वाह और कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा में अधिक उपभोग करते हैं और कुछ बचाते भी हैं; (आ) जो उपर्युक्त न्यूनतम से अधिक उपभोग तो करते हैं लेकिन बचाते नहीं हैं; और (इ) वे उपभोक्ता जिनकी आय केवल इतनी सी होती है कि वे लगभग न्यूनतम मात्रा का ही उपभोग कर पाते हैं। कुछ समय के लिए हम उन छिपे हुए बेकारों पर भी ध्यान नहीं देते हैं जो उस राशि से भी कम उपभोग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता एक नियमित व सतत रूप से चलने वाले कार्य के लिए हुआ करती है। ये तीनों समूह यहाँ अपने सापेक्ष भावहारों के उल्टे क्रम में सूचीबद्ध

1. यह भी मान लिया गया है कि कुछ धन छिपी हुई बेकारी के समूह से आयेगा।

सेविन हय सर्वसाधारण के काम जानेसानी वस्तुओं के बरों में होने वाली आर्थिक वृद्धि के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बर विभाग के महासचिवी कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए लगाये जाते हैं। बाहर से आने वाले विशेषतः प्रायः अन्तराष्ट्रिय देशों के लिए बर की आय में वृद्धि की गिरावट बिना करते हैं। सेविन यह कभी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि यह वृद्धि इन तरह के की जानी चाहिए किन्तु कि मुख्य-तः में होने वाली बढ़ोतरी रकम गने अथवा कम-से-कम ग्युलनम तो की जा सके। पूर्णिक प्रत्यक्ष कराधान के विभाग में अनेक कटिमादवां होती है, इनलिए एक महाविश्वविद्यालय में सरकार सर्वसाधारण के उपयोग पर कराधान की कमाने के लिए तीव्र रूप से सामाजिक चर्चा है। सम्भावित मुद्रा-नफीतिवारी प्रभावों का विश्लेषण तो समझना चाहते की वित्त-व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाता है। यह स्पष्ट अथवा स्पष्ट रूप से मान लिया जाता है कि जब तक बड़े हुए राष्ट्र की पूर्ण बढ़े हुए करारोगम में हो जाती है तब तक कोई मुद्रा-नफीति-वारी प्रभाव उत्पन्न नहीं होने। सेविन वास्तव में सभी परिस्थितियों में यह सही नहीं निश्चयता है।

हाम ही के वर्षों में सामान्य विधी-नर में विधायन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा-नफीति विरोधी उपाय के रूप में सौकरप्रियता प्राप्त करती है। यदि मकर मजदूरी को बढ़ाने से रोजा जा सजा तो बड़ा हुआ विधी-नराधान निश्चित रूप से अन्य व्यक्ति को घटा देगा और व्यय को कम कर देगा। और वहाँ जनसंख्या के विभाग समूह का जीवन-नतर केवल निर्वाह-नतर से ऊपर होता है वहाँ कम से कम नैदानिक रूप से तो जनता को उपभोग में बढ़ोती रोजवार करने के लिए तीव्र करना सम्भव हो सकना। सेविन वहाँ जन-गुलन का अधिर्वाच भाग अथवा एक बड़ा भाग भी जीवन-निर्वाह की सीमा पर रहता है, वहाँ सामान्य विधी कर के मुद्रा-नफीति विरोधी उपाय के रूप में उठने ही प्रभावपूर्ण होने की सम्भावना नहीं होती है।

(ई) वितरण-प्रभाव (Distribution Effect) :—हम अंत में वस्तु कराधान के वितरण-प्रभाव पर आते हैं। एक साधारण नागरिक की भाँति अर्थशास्त्री भी कराधान के वितरणकारी प्रभावों में काफी समय से रुचि लेते रहे हैं। परम्परा से यह माना गया है कि ये प्रभाव कर के विशेष उपायों के भार को सहन करने पर निर्भर करते हैं। करवाह्यता का आशय करों के उस 'भार' (वास्तविक या मौद्रिक) से लगाया गया है जो विभिन्न व्यक्तियों या आय-समूहों पर पड़ता है। इसी वजह से अर्थशास्त्री करवाह्यता-विश्लेषण

जाता है कि इसमें श्रम का एक छोटा भंश ही संगठित होता है और उसी की मोलभाव करने की शक्ति होती है, इसलिए वास्तविक मजदूरी की कटौती को श्रमिकों के विशाल माँग पर साग्न करना अधिक सुगम होता है। उपर्युक्त विश्लेषण की रोशनी में इस तरह का तर्क भ्रमात्मक प्रतीत होता है। जो लोग जीवन-निर्वाह की सीमा पर रहते हैं उनकी मोलभाव करने की शक्ति एक अलग किस्म की होती है ! यह तो सब जानते ही हैं कि भारत जैसे देश में श्रम-शक्ति का एक बड़ा भाग जीवन-निर्वाह की सीमा पर गुजर-बसर करता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिक, सभी किस्म के अर्ध-कुशल एवं शारीरिक श्रमिक और स्वयं के रोजगार में लगे हुए व्यक्ति जैसे दस्तकार आदि आते हैं। अधिकांश गैर-खेतिहर श्रमिक पहरी व अर्ध-पहरी क्षेत्रों में काम में लगे हुए होते हैं। लेकिन उनमें से बहुत से गाँवों में रहते हैं और गहरों में काम करने के लिए आते हैं। इन परिस्थितियों में नगरों में जीवन-निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति प्रायः बहुत ही सोचवार होती है। यदि जीवन-निर्वाह से कम मजदूरी दी जाती है तो अधिक काम को स्वीकार नहीं करता है और गाँव को लौट आता है। बहुधा उसका एक पारिवारिक सेत होता है जहाँ पर वह लौट सकता है।<sup>1</sup> भारत में द्वितीय महायुद्ध की अवधि में एवं उसके पश्चात् इस तरह का श्रम धीरे-धीरे बढ़ने वाली गति मजदूरी को प्राप्त करने में सफल हुआ, हालांकि वास्तव में मजदूरी मूल्यों से पीछे ही रही। फिर भी ऐसे श्रमिक सघों में संघटित नहीं किये गये। वे श्रमिक अपनी मजदूरी को निर्वाह-स्तर से काफी ऊपर ले जाने की स्थिति में तो नहीं होते हैं, लेकिन स्वयं प्रकृति ही सतत मजदूरी को निर्वाह-स्तर से नीचे के लिए प्रयत्न बना कर उतारी रखा करती है। अतः यह निष्कर्ष अवश्यमावी प्रतीत होता है कि यदि सर्वसाधारण के काम आने वाली वस्तुओं पर कर लगा कर आय में वृद्धि करने का वांछी प्रयास लिया गया तो नगर मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप बीमारी में और भी वृद्धि होगी।

यह तर्क दिया जा सकता है कि वस्तु-कराधान में होने वाली आय वृद्धि, अपवा कई वर्षों पर फैला कर की जाने वाली थोड़ी-थोड़ी वृद्धियों के उपर्युक्त निष्कर्षों पर नहीं पड़ना आ सकेगा। यह सच हो सकता है।

1. भारतीय श्रमिक वर्ग की दशा के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—  
राधाकृष्ण मुखर्जी, *The Indian Working Class*, 3rd edition,  
Hind Kutch Ltd, Bombay, 1951.

लेकिन हम सर्वसाधारण के काम आनेवाली वस्तुओं के करो में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये कर विनाश के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए लगाये जाते हैं। बाहर से आने वाले विनोद प्रायः अल्पविवक्षित देशों के लिए कर की आय में वृद्धि की सिफारिश किया करते हैं। लेकिन यह कभी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि यह वृद्धि इस तरह से की जानी चाहिए जिससे कि मूल्य-स्तर में होने वाली बढ़ोतरी रुक सके अथवा कम-से-कम न्यूनतम तो की जा सके। चूंकि प्रत्यक्ष कराधान के विस्तार में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए एक अल्पविवक्षित देश में सरकार सर्वसाधारण के उपभोग पर कराधान की फैलाने के लिए तीव्र रूप से साक्षात्कृत रहती है। सम्भावित मुद्रा-स्फीतिबारी प्रभावों का विवेचन तो लगभग घाटे की वित्त-व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाता है। यह अस्पष्ट अथवा स्पष्ट रूप से मान लिया जाता है कि जब तक बड़े हुए खर्च की पूर्ति बड़े हुए करारोपण से हो जाती है तब तक कोई मुद्रा-स्फीति-बारी प्रभाव उत्पन्न नहीं होवे। लेकिन वास्तव में सभी परिस्थितियों में यह सही नहीं निकलता है।

हाल ही के वर्षों में सामान्य बिजली-बंद में विरहित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय के रूप में सौकरप्रियता प्राप्त करली है। यदि नफ़ाद भजदूरी को बढ़ने से रोका जा सके तो बड़ा हुआ बिजली-कराधान निश्चित रूप से क्रय शक्ति को घटा देगा और व्यय को कम कर देगा। और जहाँ जनसंख्या के विशाल समूह का जीवन-स्तर बेवस निर्वाह-स्तर से ऊपर होता है वहाँ कम से कम मंदान्तिक रूप से तो जनता को रबीवार करने के लिए तैयार करना सम्भव हो सकेगा।

जन-संख्या का अधिकांश भाग पर रहता है, में उतने

टीवी  
जन-  
सीमा  
क रूप

में वस्तु  
की भाँति  
लेते  
उपायों के  
करो के  
मित्र व्यक्तियों



में काफी लगे रहे हैं। मेरिन थूटि यह निरूपण प्रारंभ: सार्वजनिक मनुष्य विज्ञान के दृष्टि का रहा है, जिसमें अन्य सब बातें समान रणी जाती हैं, इसलिए इसमें सार्वजनिक व्यय के भार व प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है। परन्तु भारत का केवल यही धारणा है कि कर के समन्वय विभिन्न लोग घानी वास्तविक आय में सभी का सामना करते हैं और साथ में सार्वजनिक व्यय के 'लाभों' की गिनती नहीं की जाती है। श्रीमती द्विग जैसे कुछ लेखकों ने कराधान के भार को मानने में सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को भुना देने पर आपत्ति उठाई है क्योंकि सार्वजनिक व्यय न केवल करवाहता को परिचित कर सकता है (मान व प्रति की अनुसूचियों को विनष्ट कर) बल्कि यह समुदाय की वास्तविक आय के अंतिम वितरण को भी परिचित कर सकता है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय के लाभों को उपभोग में शामिल करना होता है। इतना होने पर भी कर और सरकारी बायों के व्यय के वितरणकारी प्रभावों को सैद्धान्तिक ढाँचों में मिला सकना सम्भव नहीं हो सता है। करवाहता पर हाल ही के एक अध्ययन में रिषाहं ए० मसपेव ने कहा है 'सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष शुल्क से मुक्त प्रदान की जाने वाली उपभोक्ता-सेवाओं का वितरणकारी प्रभाव एक भिन्न बात है जिसके पृथक् निरूपण की आवश्यकता है।'<sup>1</sup>

यदि सार्वजनिक व्यय के लाभों को भुना दिया जाता है तो यह ठीक देना उचित होगा कि सामान्य विज्ञान कर का भार अवरोही होता है। यह पहले बतलाया जा चुका है कि वास्तविक माम्यताओं के अन्तर्गत सामान्य विज्ञान कर को लागू करने से कीमतों में वृद्धि होगी। यदि कीमतों की वृद्धि एकसी होती है और साधनों की भाय में कोई गिरावट नहीं आती है तो करवाहता उपभोक्ताओं पर आती है और वे अपने उपभोग पर किये गये व्यय के अनुपात में कर चुकाते हैं। व्यवहार में कीमतों की वृद्धि एकसी नहीं होती है, कुछ साधनों की भाय घटती है और सम्भव है कि कर का एक प्रभं प्रतिरिक्त लाभ में ही सचिलीन हो जाय। जहाँ तक ये बातें पाई जाती हैं, कर ठीक उपभोग-व्यय के अनुपात में नहीं भुगतान जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त विज्ञान कर के ढाँचे में विभेदात्मक दरों का समावेश करके कर के भार को उपभोग-व्यय के सम्बन्ध में कुछ आरोही बनाया जा सकता है। विलासिताओं की विज्ञान पर ऊँची दरों से और अनिवार्यताओं पर नीची दरों से कर लगाया जा सकता है। ऐसी योजना उपभोग पर खर्च की जाने वाली आमदनी के सम्बन्ध में कर

1. 'General Equilibrium Aspect of Incidence Theory', American Economic Review, May 1953, P. 506.

को मोटे तौर से धनवानों व गरीबों के बीच में व्धारोही बना देती है। (वास्तव में सभी धनिक भारी कर वाली वित्तासिता की वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे।) फिर भी कुल आय के सम्बन्ध में वित्ती कर का भार अवरोही होता है, क्योंकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आय के बढ़ने पर साधारणतया इसका एक अपेक्षाकृत बड़ा भाग बचाया जाता है।

वित्ती-कर के अवरोहीपन के निपट में सार्वजनिक व्यय के लाभ रहे जाने चाहिए। जब कराधान आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो लाभ का अन्तिम प्रभाव अवरोही हो सकता है। लाभ का अन्तिम प्रभाव विनियोग के ग्राह्य पर निर्भर करेगा। यदि प्राथमिकता मजदूरी-वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने के लिए दी जाती है तो कालान्तर में निर्धन वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है और रोजगार की मात्रा निरंतर रूप से बढ़ सकती है। वास्तव में यदि विनियोग के ग्राह्य पर समूचा नियंत्रण सरकार रखती है, जो साथ में भारी मात्रा में विनियोग भी करती है, तो दीर्घकाल में विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशाएँ कर-नीतियों की अपेक्षा विनियोग-नीतियों पर अधिक निर्भर करेंगी। सच पूछा जाय तो इस किस्म की चरम स्थिति सोवियत संघ में देखने को मिलती है। वहाँ पर जनता का जीवन-स्तर विक्रय-कर (turnover tax) के कारण नीचा नहीं रहा है, बल्कि वह गोस्प्लान के द्वारा निर्धारित विनियोग के ग्राह्य के अनुसार वास्तविक साधनों के मूलभूत आवंटन के कारण ही नीचा रहा है। विक्रय-कर तो केवल वह साधन है जिसके द्वारा उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति के मौद्रिक मूल्य को बढ़ाकर उनकी प्रत्याक्षित मौद्रिक माँग तक पहुँचाया जाता है।

दूसरी चरम सीमा एक व्यवस्था की है जिसमें सरकार से कर

निर्वाह नीति वाली सर्व-सभी प्रकार के हस्तक्षेप की ही व्यवस्था करती बाजार की शक्तियों पर ता के उन अधिमानों के ने वाली मौद्रिक माँग से आर्थिक दशाएँ, जहाँ एक के लिए यह निर्भर है मौद्रिक बाजारनिर्वाह

वास्तुतः सामाजिक महत्त्व हो जाता है। लेकिन जब सरकार, बाजार की प्रतिक्रिया को धुमाकर, सामाजिक हित में विनियोग के प्रावण को नियंत्रित करने लगती है अथवा इसमें मजबूत करने लगती है, तो क्यों के वास्तव्य का मौद्रिक प्राय के विवरण का प्रावण विभिन्न वर्गों की भावी मांगेयिक वास्तविक प्राय की दशाओं का एक मात्र निर्धारक तत्व नहीं रह जाता है। एक दिने हुए समय में मांगेय सामाजिक दशाएँ मौद्रिक आमदनियों पर निर्भर करेंगी, लेकिन एक अवधि-विशेष में ऐसी दशाएँ (such positions over a period of time) सरकार के द्वारा निर्धारित विनियोग के प्रावण पर ही निर्भर करेंगी। हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक उचित विनियोग सम्बन्धी नीति वस्तु-कराधान के अवरोहीयता (regressivity) का कम-से-कम कुछ सीमा तक ही प्रवर्धन प्रतिकार कर सकती है। इसीलिए विनियोग सम्बन्धी नीतियों की ध्यान से की जाने वाली छानबीन भी जरूरी है। अध्ययन इतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

## वैयक्तिक कराधान में व्यापक सुधार के पक्ष में

प्रोफेसर निकोलस केल्डॉर

### 1. भूमिका

वैयक्तिक (अथवा 'प्रत्यक्ष') कराधान का उद्देश्य समुदाय में कर-भार के वितरण में ग्यायोचितता लाना होता है। यदि इस प्रश्न पर केवल आय के पहलू से देखा जाय तो आय की एक ही हुई मात्रा को बित्री-करी, उत्पादन-करीं आदि सौदों पर लगाये गये करों से, अथवा विभिन्न किस्म के सूर्यानुसार करों (ad rem taxes) से एकाग्र करना प्रशासनिक दृष्टि से ज्यादा सरल होगा, अनिवार्य इसके कि व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले कर 'करदेय क्षमता' के किसी समूचे आधार (अथवा आधारों) के अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरों से लगाये जाय। लेकिन एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ निजी स्वामित्व में धन तेजी से एवं असमान रूप से बढ़ता है वह स्थिति सामाजिक दृष्टि से अपहनीय मानी जाती है जिसमें विनाश जन-समुदाय पर डाले जाने वाले भार के साथ अल्पसंख्यक वनाध्य व्यक्तियों पर आरोही कराधान की कुशल व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अतः वैयक्तिक कराधान के प्रशासन के क्षेत्र, व्यापकता एवं कार्यकुशलता में सुधारों की आवश्यकता के प्रश्न पर केवल आय के संकीर्ण दृष्टिकोण से ही निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कुछ सुधारों के सम्बन्ध में यह दर्शाया जा सके कि वे समस्त समुदाय पर अपेक्षा-रहित अधिक भार डालने की पूर्व-घर्ष के रूप में आवश्यक होने हैं, और समाज में ग्याय व गमानता की प्रचलित धारणा से मेल खाते हैं, तो वे धारण्यक समझे जाते हैं, चाहे उनसे निकट भविष्य में आय की सम्भावना कम हो क्यों न हो।

2. यह प्रश्न विद्येयता भारत के लिए महत्वपूर्ण है जो तीव्र गति से होने वाले आर्थिक विकास के द्वार पर खड़ा है और जहाँ के लोग पारम्पर्य बुरी-राज और पूर्वी समाजवाद के 'बीच का रास्ता' अपनाते की इच्छुक हैं। भारत में राष्ट्रीय धन का बड़ा भाग निजी हाथों में है और भविष्य में भी

रहेगा—सरकार की ओर से उद्योगों अथवा भू-सम्पत्ति के ले लिए जाने पर इस स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आ जायगा, बस तो कि स्वामियों को उचित मुआवजा दे दिया जाता है। क्योंकि ऐसा होने से सार्वजनिक सम्पत्ति की वृद्धि सार्वजनिक ऋण<sup>1</sup> की वृद्धि के कारण समाप्त हो जायगी इसलिए यह अवश्यम्भावी प्रतीत होता है कि निजी स्वामित्व के अन्तर्गत धन की मात्रा और (प्रभावपूर्ण कर के उपायों के अभाव में) उस धन के स्वामित्व के वितरण का वैषम्य (Skewness) आर्थिक विकास के साथ-साथ बढ़ते जायेंगे। चूंकि समाज में वृद्धि का वितरण आय से ज्यादा असमान होता है, इसलिए जब तक कर-व्यवस्था अथवा सार्वजनिक नीति के अन्य साधनों द्वारा प्रभावशाली ढंग से नहीं रोका जायगा तब तक यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से पाई जायगी कि सबसे अधिक सम्पत्तिवासी व्यक्तियों के पास धन की मात्रा सामान्य धन की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अतः आय और धन में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी व्यक्तियों के बीच धन की असमानता में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी।

3. राजनीतिक दृष्टि से बड़े-बड़े सभी लोकतन्त्रीय देशों में किसी न किसी किस्म का आरोही वैयक्तिक कराधान (progressive personal taxation) पाया जाता है जो सामान्यतया 'आय' पर आधारित होता है। लेकिन स्वीडेन के सम्भावित भ्रमवाद को छोड़कर कोई भी देश धन व आय के पुनर्वितरण के उस घस को साने में सफल नहीं हुआ है जिसको प्राप्त करना उनकी कराधान-नीतियों का स्पष्ट उद्देश्य रहा है। उदाहरण के लिए, समस्त राज्य में पिछले पंद्रह वर्षों से उच्च समूहों में आय और अधिक (surtax) की मिली-जुली दरें 90% से अधिक रही हैं और मूल-सम्पत्ति-कर 80% की अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है, फिर भी आय भी वित्तस मात्रा में नई सम्पत्ति प्राप्त की जाती है और धन के स्वामित्व में केन्द्रीकरण का घंटा, जो राष्ट्रीय धन के एक-तिहाई का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों के प्रति-धन बँटवृद्ध से मापा जाता है, कम नहीं हो पाया है। ये सामग्री हैं कि समस्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों के सम्मन्य में भी यह बात सही है। हम निम्नलिखित कारण दिये जा सकते हैं वे ये हैं कि कई तरह से उद्योगों को विधान-मन्त्रिम सहन करते रहने हैं (और कुछ मामलों में उनका जान-बूझकर पोषण भी करने हैं) और साथ ही धन की पूरी तरह से बचाने के

1. ऋण की विन-व्यवस्था अथवा सार्वजनिक ऋण-व्यय (loan-expenditure) की सामान्य में निजी धन में वृद्धि होती है।

सम्बन्ध में दबाव डालने में कर-प्रशासन की विफलता से भी सम्पत्ति के स्वामियों पर कराधान का वास्तविक भार “घाय” पर कराधान की नाममात्र बो दलों से काफी कम होता है। दूसरी तरफ, कार्यालय, रोजगार, भ्रष्टाचार से प्राप्त आय, जैसे वेतन व मजदूरी को मुद्रनाल में एवं उसके पश्चात् लागू की जाने वाली व्यापक रिपोर्ट देने की प्रणालियाँ लगभग शत प्रतिशत रूप से बक लेती हैं। यहां पर “करदेय आय” की परिभाषा भी उस किस्म के प्रयोग का भोका नहीं देती है जो व्यावसायिक लाभ अथवा पूँजी के स्वामित्व से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में किया जा सकता है। वेतन की आय के सम्बन्ध में तो महत्वपूर्ण छिद्र केवल ये ही होते हैं, जैसे स्वर्ण के लिए दी जाने वाली छूटें और मालिक के द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तु के रूप में सुविधाएँ। लेकिन इन छिद्रों को विशेष वैधानिक व्यवस्थामें के द्वारा बंद किया जा सकता है और रिया भी जा रहा है। हाल ही में समुक्त राज्य, भारत एवं कुछ अन्य देशों ने इस तरह की व्यवस्थाएँ लागू की हैं। वे सार्वजनिक कर्मचारी जैसे ग्यायाधीश अथवा उच्च श्रेणी के सिविल कर्मचारी जो अपने नियोक्ता (employer) से ऐसे “लाभ” (“perks”) प्राप्त नहीं करते हैं और जिनके पास कर से बचने के लिए और छिद्र नहीं रह जाते हैं—वे ऐसी दण्डार्थक दलों के पूरे झोंके के सामने जा जाते हैं जबकि समाज के अन्य वर्ग इनसे लगभग बच जाते हैं।

निम्न की राशिगी इतने घटाव रही गई है (जिनमें पूँजीगत मान एवं सभी निरम के पूँजीगत मुनाफ़े अगम्य गहरापूर्ण हैं); एतद्वरुण अनेक निरम के ऐसे उपायों की रोकना अमम्भव रहा है जिनका उद्देश्य जानदार के स्वामित्व अथवा अावगाधित निगा से प्राप्त होने वाले मामों की करदेय राशिगी की अाव गैर-करदेय पूँजीगत मुनाफ़ों अथवा मामों के रूप में प्रकट करना रहा है ।

(घा) इस धान को नहीं पहचाना गया है कि प्रयोग्य परिसम्पत्तियों (disposable assets) का स्वामित्व उनके मामिरी की आयदाद की धान के अतावा अन्य माम भी प्रदान करता है । यही नहीं बल्कि धाय पर लगाने जाने वाले करों के साथ विभुद्ध परिसम्पत्ति (net worth) पर कर लगाने के सम्बन्ध में भी असफलता ही मिली है ।

(इ) व्यापारिक मामों का हिसाब सवाते समय प्राप्तिर्यो (receipts) में से जिन राशियों के घटाने की स्वीकृति दी जाती है उनकी परिमाया लोचदार रही है और माय में "पाटो" की धारणा को अधिक उदार रूप से मान्यता दी गई है और इनकी पूर्ति के लिए ज्यादा उदार रूप से व्यवस्था की गई है जिसका परिणाम यह निकला है कि एक व्यापारी कर के प्रयोजनार्थ "पाटों" का निर्माण कर सकता है और ऐसा करके धाय (revenue) की बलि देकर परिसम्पत्तिर्यो का निर्माण कर लेता है जिससे उसे अपने मामों पर कुछ भी कर नहीं देना पड़ता है ।

(ई) कर के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति (अथवा एक परिवार) की कुल आयदाद अथवा आय के सच्चे योग को प्राप्त करने में असफलता मिली है । इसका कारण (अंशतः) तो यह है कि पारिवारिक धाय के अनिवार्य रूप से किये जाने वाले योग के सम्बन्ध में दोषपूर्ण व्यवस्थाएँ रही हैं, और धाय अथवा आयदाद को ट्रस्टों व अस्तियों की सरफ हस्तान्तरित करने की व्यवस्थाएँ, आदि भी दोषपूर्ण रही हैं (आय को गैर-कायूमी ढग से छिपाने से विलकुल अलग) ।

(उ) आय अथवा सम्पत्ति की पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने में असफलता के कारण निम्नांकित हैं : (i) आयदाद की आय और आयदाद के सौदों के लिए स्वतः रिपोर्ट देने की व्यवस्था का अभाव रहा है जबकि रोजगार से प्राप्त धाय के लिए इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है; (ii) करदाता से (return) इतना व्यापक नहीं बनाया गया है कि

यह स्वतः जाँच या परीक्षण का साधन बन सके; (iii) सामान्य नियम में इस बात की सुविधाएँ रही हैं कि मिथ्या नामों (बेनामी धृत या होल्डिंग) में जायदाद के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के जरिए अथवा बिना नाम की धृत या होल्डिंग के जरिए (जैसे वाहक बांड, अथवा शेयरों के सम्बन्ध में कोरे हस्तान्तरण की प्रणाली) घाय और जायदाद को छिपाया जा सके।

6. (घ) से (ई) तक जो बातें बही गई हैं वे (कानूनी रूप से) कर को टालने के छोट बटलाती हैं, लेकिन (उ) के अन्तर्गत (गैर-कानूनी रूप से) कर से बचने की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। भारत और अधिकांश पारिचात्य देशों की स्थिति में अंतर केवल यह है कि भारत में (उ) सम्भवतया ज्यादा महत्वपूर्ण है, और परिणामस्वरूप (घ) से (ई) पारिचात्य देशों की तुलना में सापेक्ष रूप में कम महत्व रखते हैं।

7. मेरा ऐसा विश्वास है कि कर-प्रणाली में ऐसे सुधार करना प्राविधिक दृष्टि से सम्भव हो सक्ता है जिससे कि कर-टालने के कानूनी तरीकों एवं बड़े पैमाने पर कर की चोरी के क्षेत्र की या तो पूर्णतया समाप्त किया जा सके अथवा उसे काफी मात्रा में घटाया जा सके। निम्नांकित कारणों से ऐसा करने की प्रशासनिक सम्भावना आर्थिक अथवा दुबड़ों में किये जाने वाले सुधार के उपायों की अपेक्षा की अनिवार्य व्यापक सुधार में ज्यादा प्रतीत होती है। न तो संयुक्त राज्य या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों में, और न भारत में बड़े पैमाने पर कर को टालना और इसकी चोरी करना मानवीय या प्रशासनिक अपूर्णताओं या मूर्खता, अथवा निजी उद्यम प्रणाली या समाज के और किसी स्थाई संधान का अनिवार्य परिणाम माने जा सकते हैं। पारिचात्य सोवियत देशों अथवा भारत में सामान्य व पुरी पर कराधान की प्रभावपूर्ण स्थापना की स्थापना में जो साधन रोज़ा घटकाता रहा है वह एक व्यापक और निरंतर प्रणाली की योजना बनाने की 'प्राविधिक' असम्भावना नहीं है, बल्कि निहित रूढ़ियों का विरोध ही है।

## II. तीन महत्वपूर्ण विचारणीय बातें

8. एक प्रभावशाली कर-प्रणाली के निर्माण में तीन प्रमुख बातों का समायोजित किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं : न्याय (equity), आर्थिक प्रभाव (economic effects) और प्रशासनिक कार्यकुशलता (administrative efficiency)।



9. न्याय के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर-प्रणाली में करदाताओं के विशेष वर्गों के पक्ष में एवं अन्य के विपक्ष में कोई निश्चित झुकाव नहीं होना चाहिए। कार्य से प्राप्त आय और जायदाद की आय के बीच कराधान में न्याय उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि (i) "आय" की धारणा इतनी व्यापक नहीं बन जाती कि यह उन समस्त लाभप्रद प्राप्तियों को शामिल न करले जो करदाता की व्यय करने की शक्ति को बढ़ाती हैं, और यह केवल आय के परम्परागत रूपों को ही शामिल करते तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए; (ii) आयकर के साथ पूंजीगत धन पर व्यापक कर इस तथ्य को मान कर नहीं लगाया जाता कि करदेय क्षमता केवल आमदनी अथवा केवल पूंजीगत धन से ही पर्याप्त रूप से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह मान कर लगाया जाता है कि यह दोनों के सम्मिश्रण से ही मापी जा सकती है, (iii) करदेय आय के हिसाब में, लाभ अथवा प्राप्ति, एवं जिन कटौतियों की इजाजत दी जाती है वे आय की विभिन्न किस्मों और रूपों के बीच में एक-से एवं बिना भेदभाव के नियमों के आधार पर नहीं बनती हैं। इन सबके कारणों का विवेचन मैंने कुछ विस्तार से अपनी पुस्तक<sup>1</sup> में किया है जिनको यहां दोहराना आवश्यक होया। व्यवहार में हमारा मान्य यह है कि केवल ऐसे सर्वे ही प्राप्तियों में से घटाये जाने चाहिए जो विचारणीय वर्ष की प्राप्तियों (receipts) को उत्पन्न करने से अनिवार्यतः सम्बन्धित होते हैं।

10. कराधान के व्यापक प्रभावों के दृष्टिकोण से प्रमुख विचारणीय बात यह है कि कर-प्रणाली प्रयत्न, बहुत अथवा उद्यम के लिए आर्थिक रूप से प्रेरणा के विरुद्ध न चलती जाय। आमदनी पर लगाये जाने वाले कर काम करने को अथवा उत्पादक उपक्रम में पूंजी की जोखिम उठाने को कम आकर्षक बना देते हैं और बचत पर "दोहरे कराधान" के जरिए बचत को हतोत्साहित करने हैं और व्यय को प्रोत्साहित करते हैं। इन सब प्रभावों का महत्व कराधान की सामान्य दरों पर निर्भर करता है। मेरा यह दृढ़ मन है कि पिछले 15-20 वर्षों में कर की जो (नाममात्र की) अत्यधिक ऊँची सामान्य दरें लागू की गई हैं वे बड़ी चानच मिट हुई हैं क्योंकि उनसे कर टांगने के बड़े उद्योग को रूने दिया गया है। हेनरी माइमन् ने मुझ से पहले कहा था कि सामान्य दरों में "एक बारीक क्रिम की नैतिक एवं बीडिक बेईमानी की प्रतीति"

1. An Expenditure Tax. ch. I, pp. 25-42.

2. Personal Income Taxation (Chicago 1933), pp. 219.

है।" "इसमें घोसायड़ी का एक ऐसा विशाल कार्यक्रम दिखाई देता है जिसमें बड़े पैमाने पर बतिकरों (surtaxes) को लगा दिया जाता है और बदले में ऐसे वायदे कर दिये जाते हैं कि उन्हें व्यवहार में प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जायगा। इस प्रकार राजनीतिज्ञ वर्ग के साथ कर की दरो की तरफ तो इशारा कर सकते हैं, लेकिन वे चुपके-चुपके अपने पक्ष के धनी व्यक्तियों को उन करों के छिद्रों (loopholes) की भी याद दिलाते रहते हैं।"

11. करों की इतनी ऊँची सीमान्त दरें जो 80 से 90% तक पहुँच गई थीं (संयुक्त राज्य में तो एक समय ये 97.5% हो गई थी) कभी भी लागू नहीं की जाती यदि ये वस्तुतः सही रूप में प्राप्त होने वाले धन पर ही लागू होतीं जैसा कि इनके पीछे बहाना था। बहुधा देखा जाता है कि ये लूट-लसोट की कर की दरें वास्तव में थोड़े से व्यक्तियों पर ही लागू होती हैं जो इनके भार से मुक्त नहीं हो सकते हैं और इनका दीर्घकालीन प्रभाव बहुत घातक होता है क्योंकि इनकी वजह से कुछ ऐसे वर्गों की सम्भावनाओं को क्षति पहुँचती है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और दूसरे ये लोगों की नैतिकता को भी समाप्त कर देती हैं। 2

2. मुझे यह बहना पड़ता है कि मैं भारत में धाय पर "सीमा-निर्धारण" के वर्तमान प्रस्तावों में उपर्युक्त प्रवृत्तियों को अपनी अन्तिम तार्किक असंगति पर धावे हुए पाता हूँ। इन प्रस्तावों के समर्थक कभी इस बात की जाँच नहीं करते कि उस "भाय" शब्द की परिभाषा व भावय क्या हैं जिस पर ये इतनी आसानी से निरपेक्ष ऊपरी सीमा लगाना चाहते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन प्रस्तावों से सामाजिक असमानता उस समय तक कितने कम हो सकेगी जब तक कि धन निजी हाथों में बना रहता है। जिस अर्थ में (संयुक्त राज्य में), उदाहरणार्थ, आय पर सीमान्त दर पहले ही 1946-51 की अवधि में 97.5% तक पहुँच चुकी थी, यह दर स्पष्ट: 100% तक बढ़ाई जा सकती थी लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कोई सम्भीरतापूर्वक इस बात पर विश्वास कर सकता है कि यह साधन, बांछनीय सामाजिक प्रेरणाओं को छोड़ कर, और निजी धन को मिटाने में मदद दे सकता है? इससे प्रतिस्पर्धिता व प्रतिनिधित्व समाप्त नहीं हो जायगी। इसका सरल कारण यह है कि यहाँ तक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध है पूँजी से प्राप्त होने वाले लाभ केवल इतिहास समाप्त नहीं हो जायेंगे कि वे "भाय" के अलावा और कोई रूप धारण कर लेंगे। (जैसा कि इंग्लैण्ड में कहा जाता है कि भारी कराधान

12. यदि हम कर का एक व्यापक आधार मान कर चलें तो, मेरे विचार से, आयकर की सीमान्त दर कभी भी अजित और बचाई गई दोनों तरह की आय पर 40—50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। (यदि अधिक की अपेक्षाकृत ऊँची सीमाओं के बढ़ते में आयकर के साथ भारोही या प्रगामी खर्च-कर जोड़ दिया जाता है, तो खर्च की गई आमदनी पर प्रभावपूर्ण दर वास्तव में काफी ऊँची भी की जा सकती है।) अनजित आय (ध्वस्त आय या जायदाद की आय) के लिए घन पर वार्षिक कर के रूप में एक भेदात्मक कर लगाया जाना चाहिए (आय पर कर के प्रतिरक्त) जिसका पूँजी के उत्पादक उपयोग पर (अर्थात् जोखिम उठाने पर) प्रेरणा के विपरीत जाने वाला ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है जैसा कि आयकर का पड़ता है। लेकिन इस कर का भी आयकर की भांति बचत पर वैसा ही निरुत्साहित करने वाला प्रभाव

करदेय आय को एक विलासिता में परिवर्तित कर देता है जिसे "घनी लोग रखने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं।") यहाँ पर हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि "आय पर सीमा-निर्धारण" की वर्तमान हलचल सर्वोच्च नैतिक व सामाजिक उद्देश्यों के असावा और किसी उद्देश्य से चल रही है, और मेरा यह विश्वास है कि इस हलचल के समर्थक इनको (उद्देश्यों को) जायदाद के स्वामित्व से प्राप्त वास्तविक लाभों पर भी उसी तरह लागू करना चाहते हैं जिस तरह से वे इनको कार्य से प्राप्त आय पर लागू करते हैं। लेकिन उनका यह विचार गलत है कि "आय" पर सीमा लगाना इन भाकांशाओं को पूरा करने का एक उपयुक्त साधन है। ऐसा उम समय तक नहीं हो सकता जब तक कि "आय" की धारणा इस धारणा की प्रचलित वास्तविक परिभाषा के अनुरूप काफी विस्तृत नहीं की जाय और सीमा-निर्धारण के आशय में न केवल वार्षिक प्राप्त-राशि पर वार्षिक घन के स्वामित्व पर भी सीमा न मान ली जाय। लेकिन इस प्रकार का व्यापक अर्थ लगाने पर, यह प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिसे भारत के देश अपने विकास व सुधार की भाँती सम्भावनाओं अथवा प्रचलित रूढ़ि-गहन के स्तरों के बचाये रखने को गम्भीर रूप से लड़ने में मदद देना स्वीकार कर सके। सोवियत रूस ने अपने बहुत अनुभव से यह सीखा है कि वार्षिक प्रेरणाएँ धानक परिणामों के बिना सामान्य नहीं की जा सकती हैं। इसका अन्वय यह है कि जब देश वार्षिक वार्षिक की दृष्टि से एक ऐसी धारणा में हो जो, धारण तो क्या, गवने घनी रूप (जैसे बहुत बड़ा धर्म/विद्या) में भी काफी ऊँची हो।

पड़ता है और इसी कारण से घन पर वापिक कर, आरोही कर के रूप में माने जाने पर, 1—1½% प्रति वर्ष की सर्वोच्च सीमान्त दर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

13. प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से प्रमुख आवश्यकताएँ निम्नांकित हैं :—

(1) सरसता :—कर सरल परिभाषाओं पर आधारित होने चाहिए और यथासम्भव विभिन्न किस्म की छूटें अथवा विशिष्ट श्रेणियों के लिए विशिष्ट किस्म के व्यवहार टाले जाने चाहिए, क्योंकि इन सब जटिलताओं का दुरुपयोग हो सकता है (उदाहरण के लिए, विभिन्न किस्म की कम्पनियों के बीच, अथवा कम्पनियों व व्यक्तियों के बीच, अथवा व्यावसायिक "लाभों" एवं "पूजीगत लाभों" के बीच कर लगाने के सम्बन्ध में प्रचलित प्रंतर) ।

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारत में आर्थिक असमानता की वर्तमान मात्रा को कम करने के पक्ष में प्रबल तर्क दिये जा सकते हैं । लेकिन ऐसा निरपेक्षरूप से "सीमा-निर्धारण" लागू करके नहीं, बल्कि कर-व्यवस्था को व्यापक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रभावपूर्ण बनाकर ही किया जा सकता है । (भू-जोतों पर सीमा-निर्धारण के पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं लेकिन मेरे विचार से इससे आय और पूँजी पर सीमा-निर्धारण के लिए कोई मुलता नहीं मिल जाती है । चूँकि भारत में धेतों का प्रभावपूर्ण आकार अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए एक निश्चित सीमा से ऊपर भू-स्वामित्व से कोई आर्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता है । यह कृषक वर्ग के शोषण का एक साधन-मान रह जाता है और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के मार्ग में निश्चित रूप से एक रोक बन जाता है लेकिन यह उन ऊँची आयदलियों के सम्बन्ध में बिलकुल भी सही नहीं है जो एक सफल व्यवसाय अथवा पेजेंवर यथा अथवा सफल उद्यम करके घन-संग्रह के जरिए प्राप्त की गई हैं ।)

मुझे पक्का विश्वास है "आय पर सीमा-निर्धारण" के प्रस्तावों का मत न तो कर की 100% सीमान्त दरों के लागू करने में होगा और न एक निश्चित अधिकतम सीमा से ऊपर आयदली के मुगदान पर शानुनो निपेध के रूप में होगा । लेकिन यदि इस हलचल के कारण नये सरकारी उपक्रमों में छोटी व अधिनासी कर्मचारियों को उच्च श्रेणी में नीचे वेतन-मान दिये जाने लगते हैं तो इससे काफी क्षति हो जायगी । मैं

(ii) व्यापकता :—घायबों के अन्तर्गत सभी विस्म की लाभ के रूप मिलने वाली राशिवां एवं पूंजीगत धन पर लगाये जाने वाले करों में सभी करों की सम्पत्ति या जायदाद घानी चाहिए। इनके लिए व्यापक वेतन प्रशासनिक व्यापार पर ही चिये जाने चाहिए। (जिसे विचारणीय मामलों की संख्या को सीमित करने के लिए दी जाने वाली छूट)।

(iii) एक ही व्यापक प्रविवरण-पत्र, कराधान की स्वतः जाँच की प्रणाली, और रिपोर्ट भेजने की स्वचाहित प्रणाली :—मेरा ऐसा विचार है कि प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं।

(घ) एक व्यापक प्रविवरण-पत्र (A Comprehensive Return) :—

इस समय तो करदाता को केवल अपनी आमदनी का प्रविवरण भेजने के लिए कहा जाता है और चूंकि यह प्रश्न प्रायः काफी संदेहास्पद होता है कि एक विशेष राशि "आय" की धोनी में घाती है अथवा नहीं, इसलिए व्यवहार में करदाता को ही यह निर्णय करना होता है कि विशेष राशि प्रविवरण पत्र में दिखलानी है अथवा नहीं। राजस्व अधिकारियों को पूंजीगत परि-सम्पत्तियों व अन्य विवरणों के बारे में जानने का अधिकार होता है, लेकिन इन अधिकारों का बहुत कम उपयोग किया जाता है क्योंकि वास्तव में करदाताओं को ऐसे मामलों के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य करना सम्भव नहीं होता है जिसका कर-दायित्वों के निर्धारण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। यदि पूरा हिसाब दिखाया जाता है, जैसे वर्ष के प्रारम्भ में कुल

सम्भ्रमा है कि जहाँ तक भारत के भावी विवास के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण — 'समाजवादी ढंग के समाज' — की सफलता का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योग सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध निपुण व्यक्तियों को आकर्षित कर सकें। इसका आशय यह है कि वे उनको ऐसे वेतन-मान प्रदान कर सकें जो निजी उद्योग के द्वारा प्रदत्त मानों से पूरी तरह प्रतिस्पर्धात्मक हों। अतः मेरे विचार से यह अधिक राष्ट्रीय हित में होगा कि इस विषय पर जल्दी ही सार्वजनिक रूप से इस तरह की घोषणाएँ कर दी जायं कि धन पर व्यापक एवं प्रभावपूर्ण कर लगाकर ही धन की असमानताओं में कमी करने के उद्देश्य की तरफ बढ़ा जायगा, न कि "आय पर सीमा-निर्धारण" की दिखाने लायक लेनिन व्यर्थ की (और परीक्षा रूप से हानिप्रद) धारणा के द्वारा।"

पन का विवरण वर्ष भर में मिलने वाली समस्त राशियाँ—भेंट, उत्तराधिकार, जीत के रूप में प्राप्त होने वाली करदेय आय और लाभ के समस्त रूप, इन सबका वैयक्तिक खर्चों और विनियोगों में उपयोग और वर्ष के अंत में उत्पन्न होने वाली परिसम्पत्ति की स्थिति, तो आय भ्रष्टाचार या अपराध की विशेष मदों को छिपाना, भ्रष्टाचार मूठे खाते तैयार करना स्पष्टतः और भी मुश्किल हो जाता है। (यहाँ पर कहने का यह भाव्य नहीं है कि बहीखातों का पूर्णतया रोहरा सेंट रखना भ्रष्टाचार व्यापक खातों का “नाममात्र” का सेंट बनाना असम्भव है। लेकिन यह आंशिक प्रविवरण की स्थिति में प्राप्त-राशियों को छिपाने की अपेक्षा एक ज्यादा कठिन काम है।)

### (घा) कराधान की स्वतः जाँच की प्रणाली

#### (A self-checking system of taxation)

कराधान की वर्तमान प्रणाली में वस्तुतः कुछ स्वतः जाँच के तत्व होते हैं। लेकिन विधान की कुछ कमियों, करदेय और गैर-करदेय प्राप्तियों के अंतर की स्पष्टता और अन्य कारणों से इस प्रणाली की कुशलता सीमित हो जाती है और यह कुछ दिशाओं में ही ले जाती है। लेकिन यह मान लेने पर कि आय पर वर्तमान करों के अतिरिक्त समस्त प्राप्त पूंजीगत लाभ भी कर के अन्तर्गत ले लिये जाते हैं (उपहार, उत्तराधिकार एवं वायदान (legacy) के जरिए होने वाला परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण भी उसी तरह से ‘प्राप्ति’ में शामिल कर लिया जाता है जिस तरह से बिक्री के जरिए होने वाला हस्तान्तरण शामिल किया जाता है), उपहार-कर सम्पदा-कर या मृत-सम्पत्ति-कर के साथ-साथ (और अंत में इसके बदले में) लागू कर दिया जाता है, और अंत में एक वैयक्तिक व्यय-कर लागू कर दिया जाता है, तो कर-प्रणाली इस अर्थ में पूर्णतया स्वतः जाँच वाली हो जाती है कि ‘क’ का इस बात का प्रयास कि स्वयं के कर-दायित्वों के सम्बन्ध में ऊँची राशि निर्धारित नहीं हो आय, ‘ख’ के लाभों एवं प्राप्तियों को स्वतः प्रकाश में ला देता है, इत्यादि। यदि आय पर वर्तमान कर पूंजीगत लाभों एवं पूंजी की प्रकृति की अन्य प्राप्तियों पर लागू कर दिये जाते हैं और साथ में घन पर वार्षिक कर और एक उपहार-कर लगा दिया जाता है, यदि व्यय के आधार पर एक अधि-कर (super tax) लगा दिया जाता है (नीचे देखिए) और यदि इन सब करों का निर्धारण एवं ही समय में, एक ही अधिकारी और करदाता के द्वारा प्रस्तुत किये गये एक ही व्यापक खाते के आधार पर किया जाता है (जिसमें वर्ष भर की सारी प्राप्तियाँ, कर से मुक्त सभी व्यय, सभी पूंजीगत सौदों का ध्वारा, और अपने

सम्पत्ति में होने वाली समस्त सम्पत्ति का पूरा विवरण होता है) तो कर को चोरी करना और कर को छिपाना और भी मुश्किल हो जायगा, और यह केवल इस कारण से नहीं कि वैयक्तिक करदाता विशेष प्राप्तियों अथवा सम्पत्ति की मदों को बराबर छिपाने में कठिनाई महसूस करेगा बल्कि इस कारण से कि एक करदाता के द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण (अपने स्वयं के आयित्व को कम करने के हित में) दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण की जाँच में प्रत्यक्षतः मदद देते हैं। उदाहरण के लिए, वैयक्तिक सर्व-कर के लिए 'क' के आयित्व का हिसाब लगाने के लिए समस्त "करमुक्त व्यय" विवरण न दिलाये जाने चाहिएँ और ये ही करमुक्त व्यय 'ख' के लिए किसी-न-किसी अरदेय प्राप्ति को सूचित करते हैं (जैसे लाभ, पूंजीगत लाभ, उपहार, इत्यादि)। इसी प्रकार से चूँकि इस प्रणाली में पूंजीगत सौदों पर समस्त लाभ या हानि की राशियाँ लाते में दिसलाई जाती हैं, इसलिए विक्री के हिसाब के जरिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों की समस्त नई खरीद की स्वतः जाँच हो जाती है और यह जेता के हित में होगा कि वह जिस कीमत पर परिसम्पत्ति खरीदी गई है उससे कम कीमत न दिलावे, क्योंकि इससे पूंजीगत लाभ पर कर के रूप में उसकी भावी देयता और वैयक्तिक सर्व-कर के रूप में उसकी देयता बढ़ जायगी।

(इ) समस्त सम्पत्ति को शामिल करने वाली स्वतः रिपोर्ट की प्रणाली (An Automatic Reporting System extending to All Property):—

समस्त सम्पत्ति सम्बन्धी सौदों और एक निश्चित राशि से ऊपर के समस्त महत्व भूगठानों को शामिल करने वाली प्रणाली की रूपरेखा अध्याय 6 में दी गई है। जैसा कि वहाँ बताया गया है, कुछ समस्याओं और कर के बाउंडरी की प्रणाली के द्वारा वजीवन की आवश्यकता वाले एक स्टाम्प शुल्क को धारण करने वाले समस्त सम्पत्ति-सम्बन्धी सौदों के लिए स्वतः रिपोर्ट देने की प्रणाली को लागू करना (प्रशासनिक दृष्टि से) अपेक्षाकृत सरल होगा। जैसा कि मुझसे कहा है, यदि कर वैयक्तिक सर्व एवं आय पर लगाये जाने हैं तो यह प्रणाली अन्य कई तरह के सौदों पर लागू की जा सकती है।

### III. प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा

14. उद्घुष्ट मुद्दों के अनुसार होने वाली प्रभावशाली प्रणाली में

(अ) आयकर; (ब) पूंजीगत लाभ; (इ) निम्नलिखित; (ई) वैयक्तिक सर्व; और (उ) उपहारों पर लगाये जाने चाहिए। ये सब एक ही बार में

निर्धारित किये जा सकते हैं और करदाता के द्वारा प्रस्तुत किये गये एक ही व्यापक प्रविवरण के आधार पर लगाये जा सकते हैं।

(घ) आयकर:—वर्तमान आयकर और अधि-कर के स्थान पर एक ही आयकर होना चाहिए जो व्यक्तियों और संभेदारियों आदि के लिए 25,000 रु० तक की वार्षिक आय के लिए तो आरोही (progressive) हो और इसके ऊपर समस्त आय पर प्रति रुपये 7 आने की समान दर से लगाया जाय। प्रतः आमदनी पर उस सीमा से ऊपर सर्वोच्च सीमान्त दर 43½% (अथवा अधिभार सहित 45%) हो जाती है। कम्पनियों से आयकर नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उनको अपनी सम्पूर्ण आय पर प्रति रुपये 7 आने वार्षिक न किया जाने वाला कर देना चाहिए (वर्तमान आय व निगम करों की एवज में)। उद्गम स्थान पर ही संग्रह कर लेने के लिए व्यापक व लाभदायक भुगतान करते समय 7 आने की अधिकतम राशि आयकर के रूप में घटा कर प्राप्तकर्ता के आयकर-खाते में जमा कर देनी चाहिए।

(आ) पूंजीगत लाभ कर:—बमुनी करने पर प्राप्त समस्त पूंजीगत लाभों और समस्त आकस्मिक लाभों और ऐसी पूंजीगत प्राप्तियों जिन पर वर्तमान समय में कर नहीं लगाया जाता है, (जैसे समाप्त होने लायक अधि-कारों की बिक्री, पट्टे आदि पर प्रीमियम) पर आयकर लगाया जाना चाहिए, जिसका आशय यह है कि निजी-मुनी आय (पूंजीगत लाभ सहित) के 25,000 रु० से अधिक होने ही एक रुपये में 7 आने की सीधी दर लागू हो जायगी। कम्पनियों के पूंजीगत लाभों पर भी व्यापारिक लाभों की तरह से ही कर लगाया जाना चाहिए।

इसका आशय यह है कि समस्त लाभकारी प्राप्तियों (beneficial receipts) (आटे के व्यापारिक लाभ हों अथवा पूंजीगत लाभ, अन्य विरम की आय, वैयक्तिक अथवा कम्पनी की आय, अथवा सार्वजनिक या निजी कम्पनियों की आय) पर एक रुपये में 7 आने की एक ही दर से कर वसूल बिना बायपास (वर्तमान विविध दरों एवं छूटों की एवज में)। इसका अर्थवाद केवल यह होगा कि वह व्यक्तियों की सबसे लाभकारी प्राप्तियें 25,000 रु० से कम होती तो उन पर कम दरों के अनुसार कर लगाया जायगा। व्यापारिक लाभों और कम की योगी एवं अभी तरह की व्यक्तियों को रोके देने के लिए इन दरों के व्यापारिक लाभ पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।



सम्पत्ति में होने वाली समस्त सम्पत्ति का पूरा विवरण होगा है) तो कर को पूरी करना और कर को छिपाना और भी मुश्किल हो जाएगा, और न केवल इन कारण से नहीं की वैयक्तिक करदाता विशेष प्राप्ति को प्रत्यक्ष कर के माध्यम से बचाकर छिपाने में कठिनाई महसूस करेगा बल्कि इन कारण से कि एक करदाता के द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण (जाने स्वयं के विवरण को कम करने के हित में) दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण के साथ ही प्रत्यक्ष कर दे दे। उदाहरण के लिए, वैयक्तिक संच-कर के लिए 'क' के विवरण का दिनांक लगाने के लिए समस्त "करमुक्त व्यय" विवरण दिनांक के लिए आदि और ये ही करमुक्त व्यय 'ख' के लिए किसी-न-किसी करदेय प्राप्ति को सूचित करने हैं (जैसे नाम, पंजीगत लाभ, उपहार, इत्यादि)। इसी प्रकार से बूझिए इस प्रणाली में पंजीगत सौदों पर समस्त लाभ या हानि की राशिवां गांठें में दिखाई जाती हैं, इसलिए किसी के दिनांक के लिए पंजीगत परिसम्पत्तियों की समस्त नई गरीब की स्वतः जांच हो जाती है और यह प्रणाली के हित में होगा कि वह जिस क्रम पर परिसम्पत्ति सौदी गई है उससे कम क्रम में दिनांक, क्योंकि इसमें पंजीगत लाभ पर कर के रूप में उसकी भावी देयता और वैयक्तिक संच-कर के रूप में उसकी देयता का जायगी।

(इ) समस्त सम्पत्ति को शामिल करने वाली स्वतः रिपोर्ट की प्रणाली (An Automatic Reporting System extending to All Property):—

समस्त सम्पत्ति सम्बन्धी सौदों और एक निश्चित राशि से ऊपर के समस्त नकद भुगतानों को शामिल करने वाली प्रणाली की रूपरेखा अग्रे 6 में दी गई है। जैसा कि वही बतलाया गया है, कुछ संस्थाओं और कर के वाजबर्तों की प्रणाली के द्वारा पंजीगत की आवश्यकता वाले एवं स्टाम्प शुल्क को भागवित करने वाले समस्त सम्पत्ति-सम्बन्धी सौदों के लिए स्वतः रिपोर्ट देने की प्रणाली को लागू करना (प्रशासनिक दृष्टि से) अपेक्षाकृत सरल होगा। जैसा कि सुझाया गया है, यदि कर वैयक्तिक संच एवं आय पर लगाये जाने हैं तो यह प्रणाली अन्य कई तरह के सौदों पर लागू की जा सकती है।

### III. प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा

14. उपर्युक्त सुझावों के अनुसार होने वाली प्रभावशाली प्रणाली में कर (अ) सामदनी; (आ) पंजीगत लाभ; (इ) विधुद धन; (ई) वैयक्तिक संच; (उ) उपहारों पर लगाये जाने चाहिए। ये सब एक ही बार में

निर्धारित किये जा सकते हैं और करदाता के द्वारा प्रस्तुत किये गये एक ही व्यापक प्रविवरण के आधार पर लगाये जा सकते हैं ।

(घ) आयकर:—वर्तमान आयकर और अधि-कर के स्थान पर एक ही आयकर होना चाहिए जो व्यक्तियों और संभेदारियों आदि के लिए 25,000 रु० तक की वार्षिक आय के लिए तो आरोही (progressive) हो और इसके ऊपर समस्त आय पर प्रति रुपये 7 आने की समान दर से लगाया जाय । घट: आमदनी पर उस सीमा से ऊपर सर्वोच्च सीमान्त दर 43½% (अथवा अधिमार् सहित 45%) हो जाती है । कम्पनियों से आयकर नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उनको अपनी सम्पूर्ण आय पर प्रति रुपये 7 आने का वार्षिक न किया जाने वाला कर देना चाहिए (वर्तमान आय व निगम करों की एकर में) । उद्गम स्थान पर ही संग्रह कर लेने के लिए व्यापक व लाभदायक व भुगतान करते समय 7 आने की अधिकतम राशि आयकर के रूप में घटा कर प्राप्ति के आयकर-लाभ में जमा कर देनी चाहिए ।

(आ) पूँजीगत लाभ कर :—बनूनी करने पर प्राप्त समस्त पूँजीगत लाभों और समस्त प्राप्तिगत लाभों और ऐसी पूँजीगत प्राप्तिपों जिन पर वर्तमान समय में कर नहीं लगाया जाना है (जैसे मुभापत होने लायक अधि-कारों की बिजो, पट्टे आदि पर प्रीमियम) पर आयकर लगाया जाना चाहिए, जिसका आधे यह है कि मिनी-जुनी आय (पूँजीगत लाभ सहित) के 25,000 रु० से अधिक होने ही एक रुपये में 7 आने की सीधी दर लागू हो जायगी । कम्पनियों के पूँजीगत लाभों पर भी व्यापारिक लाभों की तरह से ही कर लगाया जाना चाहिए ।

इसका आधे यह ॥ कि समस्त लाभकारी गतिपों (beneficial receipts) (आहे के व्यापारिक लाभ हों अथवा पूँजीगत लाभ, अन्य विधाय की आय, वैयक्तिक अथवा कम्पनी की आय, अथवा कार्बनिक या निजी कम्पनियों की आय) पर एक रुपये में 7 आने की एक ही दर से कर वसूल किया जायगा (वर्तमान विविध दरों एवं छूटों की एकर में) । इसका कारण यह है कि यह कम्पनियों की अथवा लाभकारी गतिपों 25,000 रु० के कम होती तो उन पर कम दरों के अनुसार कर लगाया जायगा । अतः करदाता और कर की जोड़ी एवं नयी एकरों की जरूरत है ।

(द) धन पर वार्षिक कर (Annual Tax on Wealth) :—

यह व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों एवं साझेदारियों आदि पर लागू होगा। प्रस्तावित कर की दरें : वैयक्तिक विधुद्ध धन, जैसे, 1,00,000—4,00,000 रु० तक प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}\%$  ; 4,00,001—7,00,000 तक  $\frac{3}{4}\%$  ; 7,00,001—10,00,000 तक  $1\%$  ; 10,00,001—15,00,000 के पूंजीगत मूल्य पर  $1\%$  और 15 लाख से ऊपर  $1\frac{1}{2}\%$  (कर का दायित्व शिला प्रणाली पर आंका जायगा)।

(ई) वैयक्तिक व्यय कर :—यह प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जायगा। यह प्रत्येक वयस्क (इस कार्य के लिए सिगुमों को भावे वयस्क के बराबर माना जायगा) के प्रति वर्ष 10,000 रु० से अधिक वैयक्तिक खर्च पर आरोही या वर्द्धमान ढंग से लागू किया जायगा। यह शिला-प्रणाली से आंका जायगा और 10,000—12,500 रु० के बीच के व्यय पर 25% से आरम्भ होकर 50,000 रु० प्रति वयस्क प्रति वर्ष से ऊपर के खर्च पर 300% तक लगाया जायगा। (दृष्टान्त : चार व्यक्तियों का एक परिवार जिसमें पिता, माता व 2 बच्चे हैं, एक वर्ष में 40,000 रु० खर्च करता है। चूंकि परिवार में 3 व्यस्क इकाइयाँ हैं इसलिए प्रति वयस्क 13,333 रु० व्यय आता है और कर-देयता (tax liability) करदेय व्यय के प्रथम 3,333 रु० पर लगने वाले कर की तिगुनी होगी।<sup>2</sup>

(उ) सामान्य उपहार-कर :—यह किसी भी अकेले उपहार-प्राप्तकर्ता के लिए 10,000 रु० से अधिक के उपहारों पर दिया जायगा। कर की दर

1. खर्च-कर की ये प्रस्तावित दरें इस प्रकार से चुनी गई हैं कि इनकी वजह से कर अभी लागू होता है जब कि एक सामान्य परिवारिक इकाई का विधुद्ध व्यय प्रति वर्ष 40,000 रु० की करदेय आय पर बचने वाली विधुद्ध आय से अधिक होता है। यह वह स्तर है जिस पर इन समय मिली-जुमी आय व अधिकर (super tax) की दर एक रुपये में 7 घाने की सीमान्त दर से अधिक होने लगती है जिससे यह कर प्रति रुपये 3 घाने से ऊपर की वित्ताधों पर वर्तमान अधि-कर के घाटे की अवस्था में प्रतिस्थापित हो जाता है। वास्तव में अनेकाहृत नीची छूट की सीमाओं को निर्धारित करना सम्भव होता है जो भारत में ऊंची आय वाली वर्गों के रहन-सहन के स्तर एवं खर्च के स्तरों के ज्यादा अनुकूल होता है।

प्राप्तकर्ता की कुल विशुद्ध सम्पत्ति पर निर्भर करेगी (जो वार्षिक धन-कर के लिए माँकी गई है)। यह 1,00,000 रु० से नीचे की विशुद्ध सम्पत्ति पर 10% होगी, और अपेक्षाकृत ऊँची विशुद्ध सम्पत्ति पर उसी स्तर की प्रचलित मृत्यु-कर अथवा मृत-सम्पत्ति-कर की दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् 15 से 80% की दर होगी जो पाने वाले की विशुद्ध सम्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करेगी। (उदाहरण : (i) क को अपने भाता-पिता से 50,000 रु० का उपहार मिलता है; उसके पास अपनी सम्पत्ति नहीं है, उसका कर का दायित्व 4,000 रु० होगा। (ii) ल को 50,000 रु० की वसीयत मिलती है और उसके पास (वसीयत से पूर्व) विशुद्ध सम्पत्ति 2,50,000 रु० की थी ऐसी स्थिति में ल का दायित्व 40,000 रु० पर 25% अर्थात् 10,000 रु० होगा। (iii) म को अपने पिता से उत्तराधिकार में 2,00,000 रु० मिलते हैं, उसके पास और कोई सम्पत्ति नहीं है तो उसका कर सम्बन्धी दायित्व 26,500 रु० का होगा। (iv) घ 5,00,000 रु० की सम्पत्ति का मालिक है; उसको 50,000 रु० का उपहार मिलता है; उसकी करदेयता 40,000 रु० का 40% अर्थात् 16,000 रु० है। हमारा यह सुभाव है कि जब वार्षिक धन-कर क्रियान्वित हो जाय और वार्षिक विशुद्ध धन पर पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होने लग जाय तो उपर्युक्त उपहार-कर को पूरी तरह वर्तमान मृत-सम्पत्ति-कर का स्थान से सेना चाहिए। मृत-सम्पत्ति-कर तो पुरानी धारणा पर ही टिका हुआ है। उत्तराधिकार करों का वास्तविक भार उत्तराधिकार की राशि पाने वालों पर पड़ता है, न कि मृत व्यक्ति पर। साथ में यह बात भी है कि जीवित बंश में दिये जाने वाले उपहारों और दाय अथवा उत्तराधिकार के रूप में मिलने वाली प्राप्तियों के बीच अंतर करने का न्याय की दृष्टि से तो कोई औचित्य नहीं है। अतः यह उचित होगा कि उपहारों पर एक ही आरोही कर मृत-सम्पत्ति-कर का स्थान ग्रहण करने और साथ में वह अन्य समस्त निःशुल्क एवं अर्द्ध निःशुल्क सम्पत्ति के हस्तांतरणों पर भी कर का काम दे सके।<sup>1</sup> (वास्तव में 10,000 रु० की छूट तो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक उपहार पर ही मिलनी चाहिए।)

(३) धन पर वार्षिक कर (Annual Tax on Wealth) :—

यह व्यक्तियों, हिन्दू धर्मभाजित परिवारों एवं साभेदारियों आदि पर लागू होगा। प्रस्तावित कर की दरें : वैयक्तिक विधुद्ध धन, जैसे, 1,00,000—4,00,000 रु० तक प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}\%$  ; 4,00,001—7,00,000 तक  $\frac{3}{4}\%$  ; 7,00,001—10,00,000 तक  $1\%$  ; 10,00,001—15,00,000 के पुंजीयत मूल्य पर  $1\%$  और 15 लाख से ऊपर  $1\frac{1}{2}\%$  (कर का दायित्व शिला प्रणाली पर आंका जायगा)।

(६) वैयक्तिक व्यय कर :—यह प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जायगा। यह प्रत्येक वयस्क (इस कार्य के लिए शिशुओं को आधे वयस्क के बराबर माना जायगा) के प्रति वर्ष 10,000 रु० से अधिक वैयक्तिक खर्च पर आरोही या वर्तमान ढंग से लागू किया जायगा। यह शिला-प्रणाली से आंका जायगा और 10,000—12,500 रु० के बीच के व्यय पर 25% से आरम्भ होकर 50,000 रु० प्रति वयस्क प्रति वर्ष से ऊपर के खर्च पर 300% तक लगाया जायगा। (दृष्टान्त : चार व्यक्तियों का एक परिवार जिसमें पिता, माता व २ बच्चे हैं, एक वर्ष में 40,000 रु० खर्च करता है। चूंकि परिवार में 3 व्यस्क इकाइयां हैं इसलिए प्रति वयस्क 13,333 रु० व्यय आता है और कर-देयता (tax liability) करदेय व्यय के प्रथम 3,333 रु० पर लगने वाले कर की तिगुनी होगी।<sup>1</sup>

(७) सामान्य उपहार-कर :—यह किसी भी अकेले उपहार-दाताकर्ता के लिए 10,000 रु० से अधिक के उपहारों पर दिया जायगा। कर की दर

1. सर्व-कर की ये प्रस्तावित दरें इस प्रकार से चुनी गई हैं कि इनकी वजह से कर अभी लागू होता है जब कि एक सामान्य परिवारिक इकाई का विधुद्ध व्यय प्रति वर्ष 40,000 रु० की करदेय आय पर बचने वाली विधुद्ध आय से अधिक होता है। यह बहु-स्तरीय है जिस पर इस समय मिली-जुली आय व अधिकर (7 घाने की सीमान्त दर से अधिक होने वाले 3 घाने से ऊपर की शिला-प्रणाली) एवम् प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की दर एक हाफ में सीमाओं को निर्धारित करना है।

प्राप्तकर्ता की कुल विशुद्ध सम्पत्ति पर निर्भर करेगी (जो वार्षिक घन-कर लिए प्रांकी गई है)। यह 1,00,000 रु० से नीचे की विशुद्ध सम्पत्ति पर 10% होगी, और अपेक्षाकृत ऊँची विशुद्ध सम्पत्ति पर उसी स्तर की प्रचलित मृत-कर अथवा मृत-सम्पत्ति-कर की दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् 15 से 80%। दर होगी जो पाने वाले की विशुद्ध सम्पत्ति की भाषा पर निर्भर करेगी (उदाहरण : (i) क को अपने माता-पिता से 50,000 रु० का उपहार मिला है; उसके पास अपनी सम्पत्ति नहीं है, उसका कर का दायित्व 4,000 रु० होगा। (ii) ल को 50,000 रु० की बसीयत मिलती है और उसके पास (बसीयत से पूर्व) विशुद्ध सम्पत्ति 2,50,000 रु० की थी ऐसी स्थिति में ल का दायित्व 40,000 पर 25% अर्थात् 10,000 रु० होगा। (iii) ग को अपने पिता से उत्तराधिकार में 2,00,000 रु० मिलते हैं, उसके पास और कोई सम्पत्ति

(इ) धन पर वार्षिक कर (Annual Tax on Wealth) :—

यह व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों एवं सामेदारियों आदि पर लागू होगा। प्रस्तावित कर की दरें : वैयक्तिक विधुद्ध धन, जैसे, 1,00,000—4,00,000 रु० तक प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}\%$  ; 4,00,001—7,00,000 तक  $\frac{3}{4}\%$  ; 7,00,001—10,00,000 तक  $1\%$  ; 10,00,001—15,00,000 के पूंजीगत मूल्य पर 1% और 15 लाख से ऊपर  $1\frac{1}{2}\%$  (कर का दायित्व शिला प्रणाली पर आका जायगा)।

(ई) वैयक्तिक व्यय कर :—यह प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जायगा। यह प्रत्येक वयस्क (इस कार्य के लिए शिशुओं को आधे वयस्क के बराबर माना जायगा) के प्रति वर्ष 10,000 रु० से अधिक वैयक्तिक खर्च पर आरोही या वर्तमान ढंग से लागू किया जायगा। यह शिला-प्रणाली से आका जायगा और 10,000—12,500 रु० के बीच के व्यय पर 25% से आरम्भ होकर 50,000 रु० प्रति वयस्क प्रति वर्ष से ऊपर के खर्च पर 300% तक लगाया जायगा। (दृष्टान्त : चार व्यक्तियों का एक परिवार जिसमें पिता, माता व 2 बच्चे हैं, एक वर्ष में 40,000 रु० खर्च करता है। चूंकि परिवार में 3 व्यस्क इकाइयाँ हैं इसलिए प्रति वयस्क 13,333 रु० व्यय आता है और कर-देयता (tax liability) करदेय व्यय के प्रथम 3,333 रु० पर लगने वाले कर की तिगुनी होगी)।<sup>2</sup>

(उ) सामान्य उपहार-कर :—यह किसी भी अकेले उपहार-प्राप्तकर्ता के लिए 10,000 रु० से अधिक के उपहारों पर दिया जायगा। कर की दर

1. खर्च-कर की ये प्रस्तावित दरें इस प्रकार से चुनी गई हैं कि इनकी वजह से कर अभी लागू होता है जब कि एक सामान्य परिवारिक इकाई का विधुद्ध व्यय प्रति वर्ष 40,000 रु० की करदेय आय पर बचने वाली विधुद्ध आय से अधिक होता है। यह वह स्तर है जिस पर इस समय मिली-जुली आय व अधिकर (super tax) की दर एक रुपये में 7 घाने की सीमान्त दर से अधिक होने लगती है जिससे यह कर प्रति रुपये 3 घाने से ऊपर की शिलामों पर वर्तमान अधि-कर के पाटे की एवज में प्रतिस्थापित हो जाता है। वास्तव में अनेकाइय नीची छूट की सीमाओं को निर्धारित करना सम्भव होता है जो भारत में ऊंची आमदनी वाले वर्गों के रहन-सहन के स्तर एवं खर्च के स्तरों के ज्यादा अनुकूल होता है।

प्राप्तकर्ता की कुल विमुक्त सम्पत्ति पर निर्भर करेगी (जो वार्षिक धन-कर के लिए प्राप्ति गई है)। यह 1,00,000 रु० से नीचे की विमुक्त सम्पत्ति पर 10% होगी, और प्रवेशावृत्त ऊंची विमुक्त सम्पत्ति पर उसी स्तर की प्रचलित मृत्यु-कर अथवा मृत-सम्पत्ति-कर की दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् 15 से 80% की दर होगी जो पाने वाले की विमुक्त सम्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करेगी। (उदाहरण: (i) क को अपने माता-पिता से 50,000 रु० का उपहार मिलता है; उनके पास अपनी सम्पत्ति नहीं है; उसका कर का दायित्व 4,000 रु० होगा। (ii) ख को 50,000 रु० की वसीयत मिलती है और उसके पास (वसीयत से पूर्व) विमुक्त सम्पत्ति 2,50,000 रु० की थी ऐसी स्थिति में ख का दायित्व 40,000 पर 25% अर्थात् 10,000 रु० होगा। (iii) ग को अपने पिता से उत्तराधिकार में 2,00,000 रु० मिलते हैं, उसके पास और कोई सम्पत्ति नहीं है तो उसका कर सम्बन्धी दायित्व 26,500 रु० का होगा। (iv) घ 5,00,000 रु० की सम्पत्ति का मालिक है; उसकी 50000 रु० का उपहार मिलता है; उसकी करदेयता 40,000 रु० का 40% अर्थात् 16,000 रु० है। हमारा यह सुझाव है कि जब वार्षिक धन-कर क्रियान्वित हो जाय और वार्षिक विमुक्त धन पर पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होने लग जाय तो उपर्युक्त उपहार-कर को पूरी तरह वर्तमान मृत-सम्पत्ति-कर का स्थान से लेना चाहिए। मृत-सम्पत्ति-कर तो पुरानी धारणा पर ही टिका हुआ है। उत्तराधिकार करों का वास्तविक भार उत्तराधिकार की राशि पाने वालों पर पड़ता है न कि मृत व्यक्ति पर। साथ में यह बात भी है कि जीवित वंश में दिये जाने वाले उपहारों और दाय अथवा उत्तराधिकार के रूप में मिलने वाली प्राप्ति के बीच अंतर करने का न्याय की दृष्टि से तो कोई औचित्य नहीं है। अब यह उचित होगा कि उपहारों पर एक ही धारोही कर मृत-सम्पत्ति-कर का स्थान ग्रहण करते और साथ में यह अन्य समस्त नि:शुल्क एवं अर्द्ध नि:शुल्क सम्पत्ति के हस्तांतरणों पर भी कर का काम दे सके।<sup>1</sup> (वास्तव में 10,000 रु० की छूट तो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक उपहार पर ही मिलनी चाहिए।)

1. कर की दरें और धारोहीपन का अंश वास्तव में मृत सम्पत्ति-कर ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि दरें वैयक्तिक उपहार अथवा उत्तराधिकार के आधार के अनुसार बदलती हैं, न कि देने वाले की कुल सम्पत्ति के आधार के अनुसार; हमने यह सुझाव दिया गया है कि दरें आगे मृत-सम्पत्ति-कर की दरों की दुगुनी होनी चाहिए।





सम्पत्ति-मूल्य का सम्बन्ध एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच इतना भिन्न होता है कि इस प्रश्न पर अर्जित आय पर छूट देने की पद्धति के द्वारा पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जा सकता है, चाहे वह छूट आय को सभी सीमाओं तक फैला दी जाय और वर्तमान की तुलना में काफी अधिक कर दी जाय।)

(घ) वार्षिक प्रभावों के दृष्टिकोण से आय पर निर्धारित होने वाले करों के विपरीत सम्पत्ति-मूल्य पर निर्धारित होने वाले करों का एक बड़ा साम यह है कि सम्पत्ति-कर आयकर की भाँति पूँजी के जोखिममुक्त उपयोग के विपरीत भेद-भाव नहीं करता है। यदि एक व्यक्ति 3% भाय वाले सरकारी बांडों में अपना प्रबन्ध लगाकर "सुरक्षित" प्रतिफल प्राप्त कर सकता है जबकि वह इसको उत्पादक व्यापार में लगाकर 10% प्राप्त करने की आशा कर सकता था, तो 7% का अंतर पूँजी के उत्पादक उपयोग से सम्बन्धित जोखिमों का विनियोगकर्ता के आत्मनिष्ठ अनुमान (subjective estimate) का माप माना जा सकता है। आय-कर जोखिम उठाकर प्राप्त की गई अतिरिक्त आय पर उसी तरह से कर लगाकर जैसे कि यह "सुरक्षित" आय हो, जोखिम उठाने के विपक्ष में भेद-भाव करता है। सम्पत्ति-कर के अन्तर्गत एक से सम्पत्ति-मूल्य पर एक-सा कर लगता है चाहे वह सम्पत्ति 3% भाय देने वाले सरकारी बांडों में विनियोजित की गई हो अथवा 10% आय देने वाले उत्पादक उपयोगों में अथवा मक़द-राशि या हीरे-जवाहरात आदि में बिनासे कोई मौद्रिक आय प्राप्त नहीं होती है।

यह तो सच है कि आयकर की वर्तमान प्रणाली में जहाँ पूँजीगत लाभों अथवा पूँजीगत मुनाफ़ों को कराधान से बिलकुल मुक्त रखा जाता है, जोखिम उठाने के अतिरिक्त पारितोषिक का एक बड़ा भाग वास्तव में कोई कर नहीं उठाता है क्योंकि वह करदेय आय की अपेक्षा पूँजीगत लाभों का रूप में लेता है। इसके विपरीत सम्पत्ति-कर पूँजी की मूल्य-वृद्धि ■ उत्पन्न राशि को स्वतः कर के अन्तर्गत ला देता है। इतने पर भी वार्षिक पूँजी-वर पूँजी के उत्पादक उपयोग को वर्तमान सीमित आयकर की तुलना में कम निरत्साहित करता है। इसका कारण यह है कि आयकर पूँजीगत लाभों को तो कर से मुक्त रखता है, लेकिन साथ में यह स्वयं एवं हीरे-जवाहरात आदि के रूप में धन के सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक संग्रह को भी कर से पूर्णतया मुक्त कर देता है। सम्पत्ति-कर इन सबको धन-संग्रह के रूप में कम आकर्षक बना देता है।

(८) प्रत्यक्ष वृत्तान्त के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट बनता होता कि सम्पत्ति का मूल्य वार्षिक लाभ या आय से कुछ कम हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम दोनों का इस बारे में दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि लाभ और सभी विषय की सम्पत्ति की आय (निर्देशार्थ एवं कार्यात्मक भिन्नता से सांख्यिक मापों के माध्यम) के पीछे मूल्य कुछ बहुत परिमित नहीं है, और इसी तरह में सम्पत्ति के परिवर्तन का (आर्थिक सभी तरी) किसी-किसी तरह की धार्मिक या सामाजिक मान्यता करने है। इसलिए यदि एक ही कार्याकारी के द्वारा यात्रा और सम्पत्ति दोनों पर कर निर्धारित होते जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था की प्रत्यक्ष कार्यात्मकता द्वारा सुपरीची : इसका कारण यह है कि जब हम इस बात की जाँच करने हैं कि एक व्यक्ति के पास किसी सम्पत्ति है तो उसकी (ठोस) हुई आय का प्रदान पता लग जाता है। इसी प्रकार से किसी की आयदारी की जाँच से उसके द्वारा (ठोस) हुई सम्पत्ति को प्रदान किया जा सकता है। अतः हमें से किसी एक पर कर लगाने की अनिवार्य दोनों पर कर लगाने में कर की कमी और कर की (ठोस) पर ज्यादा अच्छी रोक लग गयेगी।

### III. धन पर वार्षिक कर के विपक्ष में तर्क

विशाल मात्रा में लाभ होने पर भी धन पर भारी वार्षिक कर अभी तक कुछ ही देशों में लगनाया गया है। अन्य देशों में कराधान के क्षेत्र में इसकी बाहर रखने के लिए अनेक कारण दिये गये हैं जिनमें से बहुत थोड़े ही गम्भीर जाँच करने पर सही निश्चय हैं। इस कर के विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों को भी ग्याय, आर्थिक प्रभाव एवं प्रशासनिक कुशलता के बगैरे विभाजित किया जा सकता है।

यह सुझाव दिया गया है (कभी कभी प्रोफेसर वीगू जैसे महान अर्थ-शास्त्री भी इसमें शामिल होते हैं) कि सम्पत्ति पर वार्षिक कर असमान (inequitable) होता है क्योंकि समस्त सम्पत्ति आय नहीं देती है और सम्पत्ति पर लगाया जाने वाला कर एक व्यक्ति को भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है "चाहे उसके पास भुगतान के लिए आय न हो"। ये सब तर्क "आय" के आशय को छिड़ करने की बजाय इसको पूर्णतया मान कर चलते हैं। जिस सम्पत्ति का धनात्मक बाजार मूल्य होता है (जो वर्तमान में खरीदी और बेची जा सकती है अथवा सम्पत्ति के अन्य रूपों से बदली जा सकती है) उससे उसके स्वामी को इतना लाभ तो अवश्य होना चाहिए जिसकी सम्पत्ति (जो वह खरीद सकता था) के अन्य रूपों से प्राप्त लाभ से तुलना अवश्य की जा सके।

यदि ऐसा नहीं हो सका तो वह इसे बेच देगा और इसके बदले में और कुछ ले लेगा (इसका एक भाग अपवाद ग्रहस्तान्तरणीय सम्पत्ति है जिसे उसका स्वामी हस्तान्तरित नहीं कर सकता है)। यदि किसी सम्पत्ति से भौतिक आय नहीं मिलती है तो इससे या तो उसके स्वामी को बराबर की बाल्पनिक आय (psychic income) मिलती है अथवा यह इस भासा से रखी जाती है कि इसके मूल्य में कुछ वृद्धि हो जायगी। यह बात इसके धारक के लिए इसे कम-से-कम उस सम्पत्ति जितना आकर्षक बना देती है जिस पर प्रचलित भौतिक प्रतिफल प्राप्त किया जाता है।<sup>1</sup> अतः यह सम्पत्ति-कर के विपक्ष में एक तर्क होने के बजाय आयकर का एक अन्तर्निहित दोष बतलाता है जो सम्पत्ति से प्राप्त-राशि के एक विशेष रूप, जैसे भौतिक आय, पर अन्य रूपों को छोड़कर ध्यान केन्द्रित करता है।

धन-कर के विपक्ष में दिये जाने वाले आर्थिक तर्कों में भी तो उत्पादक उद्यम पर कर के तथाकथित निरस्तग्राहित करने वाले प्रभाव को सूचित करते हैं और सभी करापात के बरदाता से अन्तिम उपभोक्ता तक सिसका दिये जाने की सम्भावना को सूचित करते हैं।

(घ) वही तर्क उद्यम को निरस्तग्राहित करने वाले प्रभावों का सम्बन्ध है वास्तव में यह तो सच है कि धन पर लगाया जाने वाला कर कोई भी कर न लगाने की स्थिति की तुलना में तो एक निरस्तग्राहित करने वाला प्रभाव बालता है। लेकिन जैसा कि हम बतला चुके हैं, यह उम स्थिति की तुलना में कम निरस्तग्राहित करने वाला प्रभाव बालता है जब कर की इतनी ही मात्रा आयकर के रूप में बरदाता से एकत्र की जाती है। (यह तर्क कि पूंजीपति अब आय को पूंजीगत लाभों में बदल कर आयकर की बोरी कर सकते हैं, जब कि सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में उतनी बोरी की सम्भावनाएँ नहीं पाई जाती हैं, सम्पत्ति-कर के विपक्ष में और आयकर के पक्ष में कोई उचित कारण नहीं माना जा सकता है।

1. यदि एक व्यक्ति, मान लीजिए, एक मोने की विकासशील साम के देयर रखता है और छवि वर्ष देयरों के मूल्य में वृद्धि की आशा की जाती है और वृद्धि होती भी है, तो क्या हम सबकुछ इस लाभ में (को पूंजीगत लाभ का रूप ले लेता है) और उम लाभ में जो उम पर दिये जाने वाले सामांय का रूप लेता है, अन्तर कर सकते हैं ?

(६) प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से यह स्मरण रखना होगा कि सम्पत्ति का मूल्य वार्षिक लाभ या आय से कुछ भिन्न तो होता है, लेकिन भारत में इन दोनों का इस अर्थ में निकट का सम्बन्ध होता है कि लाभ और सभी विरम की सम्पत्ति की आय (वेजेवार एवं व्यावसायिक क्रियाओं से सम्बन्धित लाभों के अनावा) के पीछे सदैव कुछ स्थूल परिसम्पत्ति पाई जाती है, और इसी तरह से सम्पत्ति के अधिकांश रूप (हालांकि सभी नहीं) किमी-न-किमी तरह की भौतिक आय या लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए यदि एक ही कराधिकारी के द्वारा आय और सम्पत्ति दोनों पर कर निर्धारित किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था की प्रशासनिक कार्यकुशलता अवश्य सुधरेगी। इसका कारण यह है कि जब हम इस बात की जाँच करते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितनी सम्पत्ति है तो उसकी छिपाई हुई आय का अवलोकन पता लग जाता है। इसी प्रकार से किसी की आमदनी की जाँच से उसके द्वारा छिपाई हुई सम्पत्ति को अवलोकन बूझा जा सकता है। अतः इनमें से किसी एक पर कर लगाने की अनिवार्यता दोनों पर कर लगाने से कर की बोरी और कर को छिपाने पर ज्यादा अच्छी रोक लग सकेगी।

### III. धन पर वार्षिक कर के विपक्ष में तर्क

विकास माना में लाभ होने पर भी धन पर भारोही वार्षिक कर अभी तक कुछ ही देशों में अपनाया गया है। अन्य देशों में कराधान के क्षेत्र से इसको बाहर रखने के लिए अनेक कारण दिये गये हैं जिनमें से बहुत मोड़े ही गम्भीर जाँच करने पर सही निकलते हैं। इस कर के विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों को भी न्याय, आर्थिक प्रभाव एवं प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से विभाजित किया जा सकता है।

यदि ऐसा नहीं हो सका तो वह इसे बेच देगा और इसके बदले में और कुछ ले लेगा (इसका एक मात्र भ्रष्टान्तरणीय सम्पत्ति है जिसे उसका स्वामी हस्तान्तरित नहीं कर सकता है)। यदि किसी सम्पत्ति से मौद्रिक आय नहीं मिलती है तो इससे या तो उसके स्वामी को बराबर की काल्पनिक आय (psychic income) मिलती है अथवा यह इस भांति से रखी जाती है कि इससे मूल्य में कुछ वृद्धि हो जायगी। यह बात इसके धारक के लिए इसे कम-से-कम उस सम्पत्ति जितना आकर्षक बना देती है जिस पर प्रचलित मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त किया जाता है।<sup>1</sup> अतः यह सम्पत्ति-कर के विपक्ष में एक तर्क होने के बजाय आयकर का एक अन्तर्निहित दोष बतलाता है जो सम्पत्ति से प्राप्त-राशि के एक विशेष रूप, जैसे मौद्रिक आय, पर अन्य रूपों को छोड़कर ध्यान केन्द्रित करता है।

धन-कर के विपक्ष में दिये जाने वाले आर्थिक तर्क सभी तो उत्पादक उद्यम पर कर के तथाकथित निरुत्साहित करने वाले प्रभाव को सूचित करते हैं और सभी करापात के करदाता से अन्तिम उपभोक्ता तक शिस्तका दिये जाने की सम्भावना को सूचित करते हैं।

(घ) जहाँ तक उद्यम को निरुत्साहित करने वाले प्रभावों का सम्बन्ध है वास्तव में यह तो सच है कि धन पर लगाया जाने वाला कर कोई भी कर न लगाने की स्थिति की तुलना में तो एक निरुत्साहित करने वाला प्रभाव डालता है। लेकिन जैसा कि हम बतला चुके हैं, यह उस स्थिति की तुलना में कम निरुत्साहित करने वाला प्रभाव डालता है जब कर की इतनी ही मात्रा आयकर के रूप में करदाता से एकत्र की जाती है। (यह तर्क कि पूँजीपति जब आय को पूँजीगत लाभों में बदल कर आयकर की थोड़ी कर सकते हैं, जब कि सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में उतनी थोड़ी की सम्भावनाएँ नहीं पाई जाती हैं, सम्पत्ति-कर के विपक्ष में और आयकर के पक्ष में कोई उचित कारण नहीं माना जा सकता है।

1. यदि एक व्यक्ति, मान लीजिए, एक सोने की विवाशशील शान के दोषर रखता है और प्रति वर्ष दोषरों के मूल्य में वृद्धि की धारा की जाती है और वृद्धि होती भी है, तो क्या हम सचमुच इस लाभ में (जो पूँजीगत लाभ का रूप ले लेता है) और उस लाभ में जो उन पर दिये जाने वाले सामान्य का रूप लेता है, अन्तर कर सकते हैं ?

(घ) यह विचार पुष्टिपूर्ण है कि सम्पत्ति-कर का भार वास्तविकी के भार की भाँति ही निगलाना या टगना या गड़ना है। जैसा इनका कि यह कर पूर्वी के मूल्य पर लगाया जाता है, चाहे पूर्वी का कुछ भी उभरीय नहीं न दिया जाय इस कर में विवेकात्मक प्रभाव की कमी होगी। त्रिकोण द्वारा ही करालाभ की निगलाना सम्भव हो सकता है। वास्तव में सम्पत्ति पर वार्षिक कर के भार को निगलाने की सम्भावना धाम पर उतने ही कर की तुलना में काफी कम होगी है।

प्रायः यह कहा जाता है कि प्रणामनिक दृष्टिकोण में वार्षिक सम्पत्ति-कर निम्न कारणों से कर-निर्धारण की विशेष समस्याएँ प्रस्तुत करता है :  
(घ) सम्पत्ति के मूल्ये स्वामियों का 'पता लगाने' की कठिनाइयाँ, और (ग) मूल्यांकन की कठिनाइयाँ। इन पट्टियों पर कुछ विस्तार में नीचे बर्तों की जाती है।

'पता लगाने' की समस्या :—कम राशि बनसाने एवं छिपाने की समस्या के सम्बन्ध में वास्तव में यह स्मरण रखना होगा कि एक व्यक्ति की सम्पत्ति का "पता लगाने" का उसकी आय का "पता लगाने" से गहरा सम्बन्ध होता है। यदि सम्पत्ति छिपाई जा सकती है तो आय भी छिपाई जा सकती है, यदि आय का पता होता है तो आय के पीछे होने वाली सम्पत्ति का भी पता लगाया जा सकता है। अतः वार्षिक सम्पत्ति-कर के माध्यम से पता लगाने की दृष्टि से जो समस्याएँ पहले ही आयकर के कारण उठानी पड़ती हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा अतिरिक्त समस्याएँ उत्पन्न नहीं हो जाती हैं। इसके विपरीत, करदाता पर उसके कुल विमुक्त धन और उसकी आय का वार्षिक प्रविवरण भेजने का दायित्व हासिल से आयकर की चोरी को रोकने में काफी मदद मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे कि आयकर के अस्तित्व से वार्षिक सम्पत्ति-कर की चोरी को रोकने में मदद मिलती है। हम प्रथम अध्याय में बतला चुके हैं कि यदि एक व्यक्ति करदाता को उसके व्यक्तिगत मामलों का व्यापक हिसाब देने के लिए कहा जाता है—वर्ष के प्रारम्भ में और अंत में उसकी परिसम्पत्ति की स्थिति; उसको प्राप्त होने वाली कुल राशि और उसका वैयक्तिक खर्चों एवं विनिर्धनों के बीच उपयोग—तो एक भी मद को छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए सातों को मिथ्या बनाने में एक तरह का खेल बैठाना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक बात यह है कि दोनों करों का निर्धारण एवं प्रशासन एक दूसरे से गहरा जुड़ा

हुआ होना चाहिए। कर-निर्धारण का कार्य एक ही व्यापक प्रविवरण के आधार पर एक ही कर-अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए।

यहाँ पर कहने का आशय यह नहीं है कि वार्षिक धन-कर का (धाय-कर से ज्यादा) प्रशासन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है (अर्थात् केवल सीमित मात्रा में ही छल से कर की चोरी करके) और इसके लिए सम्पत्ति के स्वामित्व के पञ्जीयन एवं नियन्त्रण की वर्तमान पद्धतियों में काफी बढाई लाने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधारों का वर्णन नीचे किया जाता है :

(घ) चूँकि इस समय राहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरपालिका के रिकार्ड दोषपूर्ण एवं अपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए स्थानीय वित्त-आब-समिति की विचारियों के अनुसार अलिप्त भारतीय आधार पर राहरी सम्पत्ति की सूची बनाने एवं मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय रिकार्ड कार्यालय स्थापित करना ज्यादा उचित होगा।

(आ) घात में कुछ-कुछ ऐसा ही ग्रामीण एवं वृत्तीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी करना वांछनीय होगा। लेकिन इनमें निरन्तर रूप से अधिक समय लगेगा और इन प्रक्रिया में ग्रामीण रिकार्डों पर भरोसा किया जाना चाहिए जो गैरी गमक में कम से कम गैर-अधीनारी क्षेत्रों में तो काफी ज्यादा है, और उनमें वृत्ति के लिए प्रयुक्त भूमि और भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि में घात भी किया जाता है। (यहाँ पर यह भी उल्लेख करना होगा कि ग्रामीण सम्पत्ति का एक बड़ा भाग लाभकर उन व्यक्तियों के पास होगा जिनकी कुल सम्पत्ति छूट की अनु सीमा के नीचे होती जो लाभकरदा कर के लिए मुभाई गई है।)

(इ) यहाँ तक काफ

है. "बोरे

ती में विनिर्देश का प्रान  
ने कर-निर्धार की वर्तमान  
के दिये जा लकने है। यह  
यह कभी-काल करना बहिन  
ती के कर में होने का समय  
अपनाया है कि यदि वस्तु-  
वस्तु है तो वस्तु-निर्देशों के  
की कोश-अपनाया और



समय में नव नव नव के दोहरावों की कोड़ नक़्काओं को भी शामिल किया जा सकता है जिनके माथों में दोहरों का पंजीनन किया गया है।

(६) सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ब्रिटेन की प्रेमी समस्या को हल करना ही उचित होगा जिनके द्वारा समस्त सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामियों का निवेश बैंक के नाम रजिस्ट्रेशन किया जा सके, और स्वामित्व के परिवारों का भी उनी तरह से रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) किया जाना चाहिए जिन तरह से निष्ठा नगरों के परिवारों का किया जाता है। भारत में सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज वृद्धियों में दिया जाता है और हस्तान्तरण प्रतिभूतियों की पीठ पर कोरी बेचान में ही किने जाते हैं। वृद्धों की महद-राशि के लिए प्राप्ति करने समस्त नग्नता प्रतिभूतियों को रजिस्टर्ड किन्म की प्रतिभूतियों में विनिमय करना पूर्णतया सम्भव होगा।

(७) बामु स्टॉक मनीनरी और प्लाट के सम्बन्ध में समस्याएँ उतने कोई भिन्न नहीं हैं जिनका हमें पहले ही धायकर के प्रकाशन में सामना करना पड़ा था।

(८) सभी विषय की सम्पत्ति के लिए मैंने छठे अध्याय में यह सुझाव दिया है कि बेनामी धारण (benami boldings) अथवा निष्पेधारियों (trustees) अथवा नामजद व्यक्तियों के नाम से होने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में लाभकारी स्वामित्व (beneficial ownership) का अनिवार्यतः बतलाया जाना आवश्यक और धन-कर दोनों के कुशल प्रकाशन के लिए आवश्यक होता है। ऐसा सर्वदेष्ट बंग से तभी हो सकता है जब कि नाममात्र के धारक को

1. ब्रिटेन में कम्पनियों के स्टॉक व शेयर एवं सरकारी प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण के लिए ठीक उसी तरह से एक हस्तान्तरण-दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिस तरह से कि एक वास्तविक सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए होती है। शेयरों के हस्तान्तरण के मामले में इससे स्टाम्प-मुल्क के भुगतान करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। मेरे विचार से भारत में केवल अबत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए ही हस्तान्तरण-दस्तावेज (transfer deed) भरने की रूजूरत पड़ती है। मुझे इस बात के लिए कोई मूलभूत कारण नहीं दिखताई यह प्रणाली ब्रिटेन की भाँति स्टॉक और शेयर और सरकारी प्रतिभूतियों पर क्यों नहीं लागू की जाती है।

इस बात के लिए एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाय कि वह एक लाभ पाने वाला स्वामी है, अथवा केवल एक देनामीदार, आदि है, और ऐसे घोषणा-पत्र की सम्पत्ति से सम्बन्धित बाढ़ की दीवानी कार्यवाही के दृष्टिकोण से पूरी कानूनी मान्यता होनी चाहिए ।

### मूल्यांकन की समस्या (The Problem of Valuation)

मेरे विचार में सर्वश्रेष्ठ पद्धति यह होगी कि हिसाब-किताब के साधारण नियमों का पालन किया जाय और सम्पत्ति की प्रत्येक विशिष्ट मद का उसके बिकने तक मूल्यांकन इसके "बही-मूल्य" के आधार पर किया जाय । व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि जब शुरू में एक खाता खोला जाता है तो सम्पत्ति की सारी मदों का मूल्यांकन उस आधुनिक मूल्य पर किया जाता है जिसे लागत के रूप में खातों में से आया जाता है और उस लागत पर उनका मूल्यांकन उस समय तक होता है जब तक कि सम्पत्ति बित्री, उपहार, अथवा बसीयत के रूप में हस्तान्तरित नहीं हो जाती है (केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राजस्व-विभाग मूल्य-ह्रास की इजाजत दे देता है और उनका मूल्यांकन लागत में से उस समय तक का मूल्य-ह्रास घटाने के बाद बचने वाली राशि के आधार पर किया जाता है) । अतः सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्न दिशाओं में किया जाना चाहिए : (अ) शुरू में जब कर लागू किया जाता है और वार्षिक खाते खोले जाते हैं; और (आ) बाद में जब सम्पत्ति का हस्तान्तरण बिक्री के बजाय और किसी विधि से किसी भिन्न व्यक्ति को किया जाता है ।

सम्पत्ति के प्रारम्भिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी करदाता पर होगी जिसे सभी मदों का मूल्य आधुनिक बाजार-मूल्य पर आरम्भ करने के लिए कहा जायगा । यदि राजस्व-विभाग मूल्यांकन की एक विशेष मद पर आपत्ति उठाता है तो इसे करदाता से यह पूछने का अधिकार होना चाहिए कि वह सम्पत्ति को विवादास्पद मद की अपनी रिजर्व कीमत बतसावे । कर के प्रयोजनार्थ बाजार-मूल्य के बदले में वह रिजर्व कीमत स्वीकार कर लेनी चाहिए । यदि राजस्व-विभाग की राय में करदाता के द्वारा सुझाई गई रिजर्व कीमत फिर भी सम्पत्ति के वास्तविक आधुनिक बाजार मूल्य से कम होती है तो वह केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग (P.W.D.)<sup>1</sup> की ऐसी ही सलाह दे सकता है । ऐसा करने पर लोक-निर्माण-विभाग करदाता के ही रिजर्व मूल्य पर सम्पत्ति को

1. अथवा और कोई विभाग जिसे सरकारी सम्पत्तियों की देखभाल करने का कार्य सौंपा गया है ।

ले सकता है। इस प्रकार जो करदाता जानबूझ कर अपने प्रविवरणों में संपत्ति का मूल्य कम दिसलाते हैं उन्हें बाजार मूल्य के लिए धपनी ही रिजर्व कीमत की प्रतिस्थापित करने का खतरा उठाना होगा जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कर देने की सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि उनकी रिजर्व कीमत वास्तविक बाजार मूल्य से कम भी बतलाई जाती है तो उन्हें यह खतरा उठाना पड़ेगा कि उस कीमत पर सरकार उनकी संपत्ति को "खरीद लेगी"।<sup>1</sup>

केन्द्रीय रेवेन्यू या राजस्व बोर्ड (C.B.R.) के सन्तर्गत केन्द्रीय-मूल्यांकन-विभाग की स्थापना और साथ में प्रादेशिक और उप-प्रादेशिक मूल्यांकन कार्यालयों की आवश्यकता इसलिये होगी कि करदाताओं के द्वारा दिये गये संपत्ति के मूल्यांकनों की जांच की जा सके। (खेयार बाजार में जिन स्टॉक व शेयरों का भाव बतलाया जाता है उनके सम्बन्ध में यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह मुख्यतः अचल संपत्ति के सम्बन्ध में होती है।) यह मुख्यतया संपत्तियों के प्रारम्भिक मूल्यांकन की जांच के लिए आवश्यक होगा और साथ में निःशुल्क अथवा अर्द्ध-निःशुल्क हस्तान्तरण (उपहार, उत्तराधिकार, आदि) के मामलों में मूल्यांकन की जांच के लिए आवश्यक होगा जहाँ मूल्यांकन की आवश्यकता एक तरफ उपहार-कर व पूजी-लाभ-कर के लिए और दूसरी तरफ गये स्वामियों के हाथों में बाविक बन कर<sup>2</sup> के लिए संपत्ति के मूल्यों

1. मेरी समझ में साम्य ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ यह प्रणाली वास्तव में प्रचलित हो; लेकिन शायद यह शुभाव दिया गया है (उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में पूजी-शुल्क के विवेचन के सम्बन्ध में) कि कराधान के उद्देश्य के लिए संपत्ति के मूल्यांकन की समस्या सभी प्रभावपूर्ण ढंग से हल की जा सकती है जबकि संपत्ति के मूल्यांकन की जिम्मेदारी पूर्णतया करदाता पर डाली जाय और सरकार विवाद की स्थिति में करदाता के स्वयं के मूल्यांकन पर संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखे।
2. ब्रिटेन में सन्तर्देशीय रेवेन्यू बोर्ड के नीचे केन्द्रीय मूल्यांकन-कार्यालय संपत्तियों का मूल्यांकन संपदा-कर एवं स्टॉक-शुल्क दोनों के लिए करता है और इसे सब स्थानीय करों के लिए समस्त मूल्य व इमारतों की सूची बनाने एवं इनका मूल्यांकन करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

में संशोधन करने के लिए होती है। यहाँ पर जिस प्रणाली को सुझाया गया है उसमें प्रत्येक बार सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूंजी-लाभ-कर लगाया जाता है और इसके अतिरिक्त सभी नि:शुल्क हस्तान्तरणों पर प्राप्तकर्ता से उपहार-कर वसूल किया जाता है। सम्पत्ति पर वार्षिक कर के उद्देश्य की दृष्टि से पूंजीगत मूल्य वही मूल्य होगा जो नि:शुल्क हस्तान्तरणों के मामले में पूंजी-लाभ-कर एवं उपहार कर के लिए स्वीकार किया गया है और अन्य सौदों के सम्बन्ध में विन्ध्य व क्रय-लागत की वास्तविक राशि के बराबर होता है।<sup>1</sup>

1. यदि समस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्यों के स्थान पर 'कितानी मूल्यों' से किया जाता है तो इसका आशय यह निकलता है कि वार्षिक कर के दृष्टिकोण से सम्पत्ति का मूल्यांकन इससे प्रचलित बाजार मूल्य से 8-10 वर्ष पीछे रह जाता है। यदि हम यह मान लें हैं कि सम्पत्ति के मूल्य में दीर्घकाल में 3% की औसत वृद्धि दर से बढ़ोतरी होती है तो इसका आशय यह होगा कि वर एक ऐसे बाजार पर लगाया जायगा जो औसत मामलों में एक कई वर्षों में प्रचलित बाजार मूल्य के लगभग दो-तिहाई के बराबर होगा। वास्तव में वरों की उपयुक्त सारणी का निर्धारण करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। 8-10 वर्षों के अंतर का अनुमान निम्न विधि से लगाया जाता है। यदि सम्पत्ति का मूल्य के अभाव में और किसी तरह से हस्तान्तरण नहीं होता है तो किसी भी एक समय में सम्पत्तियों का औसत कितानी मूल्य बाकी पीढ़ी पूर्व के चार मूल्यों के बराबर होगा और चूंकि एक पीढ़ी 25 वर्ष की होती है, इसलिए औसत 12.5 वर्ष का विन्ध्य (lag) पड़ जाता है। इसमें सभी विन्ध्य की सम्पत्तियों के हस्तान्तरणों के कारण क्रय-विक्रय एवं एक जीवित व्यक्ति से दूसरों को दिये जाने वाले उपहारों (inter-vivos gifts) के अतिरिक्त और भी बड़ी बरने की आवश्यकता

62. प्रथम अध्याय में यह सुझाया गया था कि अन्य प्रस्तावित सुधारों के साथ वैयक्तिक खर्च पर एक भारोही या प्रभावी कर लगाया जाना चाहिए और आय कर की अधिकतम दर घटाकर एक हाथ में 7 आना (या सर-चार्ज सहित 45%) कर देनी चाहिए। इस प्रकार इन प्रस्तावों का प्रभाव यह होगा कि वैयक्तिक आय पर अधिकर की अपेक्षाकृत ऊँची सीमाओं के स्थान पर वैयक्तिक खर्च पर एक अधिकर लग जायगा। इस अध्याय का उद्देश्य इन प्रस्तावों को और भी विस्तार से समझाना है और साथ में कुछ ऐसी आपत्तियों पर विचार करना है जो भारत में वैयक्तिक खर्च कर के लागू करने के विषय में उठाई गई हैं।

### I सामान्य धारणा

63. मैंने अपनी पुस्तक<sup>1</sup> में वैयक्तिक खर्च-कर के पक्ष में व्यापक और व्यापक आवश्यकता—दोनों के आधार पर कुछ विस्तार से चर्चा की है और मैं यहाँ पर उसके सामान्य तर्कों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में जो प्रस्ताव दिये थे उनके विरुद्ध में भारत की विशेष परिस्थिति में जो मुख्य तर्क दिये गये हैं उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

(अ) आय के वर्तमान करों के आवजुद भी खर्च-कर लागू कर देना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि यह कराधान को बहुत कठोर बना देगा।

(आ) आय पर कराधान के बदले में खर्च पर कराधान लागू करने का आशय यह होगा कि बचतों को कर से छूट मिल जायगी जिससे धनिक-वर्ग के पास संचय को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और सम्पत्ति के स्वामित्व का केन्द्रीयकरण और भी बढ़ जायगा। यदि सम्पत्ति-कर सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लगाये जाते हैं तो, बदले में, इससे बचत को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में खर्च-कर के लाभ समाप्त हो जायेंगे।

(इ) आयकर की अपेक्षा सच-कर प्रशासकीय दृष्टि से अधिक जटिल होता है।

(ई) चूंकि कृपिगत आय में से किया गया सच करराधान से मुक्त रखा जायगा, इसलिए लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपने सच का अधिकतम भाग अपनी कृपिगत आय में से किया हुआ बतलावें :

64. मेरे विचार में यह तो स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यद्यपि सच-कर आयकर से अधिक उत्तम होता है, क्योंकि एक तो 'सच' करराधान के आधार के रूप में 'आय' की बनिस्बत ज्यादा कड़ाई से परिभाषित किया जा सकता है, और दूसरे 'सच' 'आय' की अपेक्षा करदेय क्षमता का ज्यादा अच्छा सूचक होता है, फिर भी आयकर और सच-कर दोनों को साथ-साथ रखने में कोई निहित दोष नहीं है। यदि हम यों भी तर्क करें कि आय पर वर्तमान करराधान आय और अधिक-करों की ऊंची दरों पर प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है, तो भी सच-कर के लागू करने को उचित ठहराया जा सकता है, बस तो कि धार्मिक कारणों से वैयक्तिक सच पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता हो और वह प्रतिबन्ध आय व सम्पत्ति करों से और वृद्धि करके प्राप्त नहीं किया जा सके। यदि आय और सम्पत्ति पर काफी कड़ाई से कर लगाया जाता है और संचित धन में से किये जाने वाले सच पर कर नहीं लगाया जाता है अथवा इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इसका प्रभाव केवल यह होगा कि पूँजीगति अपना जीवन-स्तर कम करने के बजाय अपना धन व्यय में ही नष्ट कर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।<sup>1</sup> मैंने पिछले अध्यायों में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि यदि आय पर लगाने गये करों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है तो आय पर करराधान की वर्तमान ऊंची सीमान्त

1. इसके अलावा, ऐसी पित्रुलसर्ची नाम से वृद्धि करके पूँजीगति बचों की आय और बचत में कमी करने से ऊपे करराधान के प्रभाव को बिटा देती है; यदि समुदाय का विनियोग-गर्भ दिया हुआ है तो आय और सम्पत्ति पर करों का वास्तविक भार पूँजीगति-बचों पर उगो मोभा तब यह सचता है जिस सीमा तक कि इसके फलस्वरूप उन बचों की सच करने की प्रवृत्ति घट जाती है। इस प्रकार सच को प्रोत्साहित करने यह कर-प्रणाली जनमान में ही बरों का भार सामार्जन करने वाले बचों (व्यय रूप से किये जाने पर) से समाज के धन्य बचों पर टिमकाने से सहायक सिद्ध होती है।

इसो का मन्त्रिमन्त्री व्यक्तियों के व्यवहार पर और भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा (अर्थात् उनकी अथवा कम्पनी नियोग करने की प्रेरणाओं पर)। यह मान कि ये प्रभाव बहुत कुछ टान दिये जाते हैं, क्योंकि कर-प्रणाली में बाटी बड़े छिड़ गये हैं जिसके कारण जोमिम-पूत्री के स्वामी कर-मुक्त लाभ प्राप्त कर पाते हैं और कर-गृह्य व्यक्तों में से वे पैसे नगिन कर पाते हैं, कराधान की वर्तमान प्रणाली के विपक्ष में एक तरह है, न कि सर्व-कर के विपक्ष में। कारण यह है कि यदि ये छिड़ बंद कर दिये जाते हैं (अर्थात् सभी पूर्णगण लाभों आदि पर भी उगी छरह कर लगने लगता है जिस छरह कि धाय पर लगता है) तो सीधे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि धाय की ये ऊँची सीमाएँ बंद जायम नहीं रगी जा सकेंगी। अतः यदि आरोही कराधान की प्रभावपूर्ण एवं निष्पक्ष रतना है तो एक सीमा से परे यह आय के आधार पर नहीं बल्कि केवल सर्व के आधार पर हो लगाया जाना चाहिए।

65. यह कहना भी असम्भव होगा कि सम्पत्ति पर कर लागू करने से (चाहे यह धन पर वार्षिक कर के रूप में या सम्पदा-कर, अथवा सामान्य उपहार-कर के रूप में हो) व्यय-कर के व्यय को सीमित करने वाले लाभ मिल जायेंगे। इसके विपरीत, वैयक्तिक सर्व-कर के लागू हो जाने से धनिक वर्ग की सर्व करने एवं अक्षत करने की आदतों पर इन सम्पत्ति वर्गों के प्रेरणाकारी प्रभावों पर रोक लगेगी। एक आरोही सर्व-कर यद्यपि बड़ी पन-राशि के संघर्ष की दर में तो वृद्धि कर सकता है, लेकिन अपने धाय में यह उच्च वर्गों के जीवन-स्तर में प्रभावपूर्ण कमी कर देता है। सम्पत्ति-कर संघर्ष की दर को तो कम कर देते हैं लेकिन ये सर्व को प्रोत्साहित करते हैं। अतः दोनों किस्म के करों का मेल प्रत्येक के अच्छे प्रभावों को मिटाने में बराबर धनिक-वर्ग के जीवन-स्तर पर प्रभावपूर्ण निष्पक्ष को सम्भव बना देगा और साथ में सम्पत्ति के अधिक समान वितरण के दीर्घकालीन समाजवादी उद्देश्य का भी परिष्कार नहीं करना पड़ेगा।

66. यद्यपि सर्व-कर का संचालन वर्तमान आय-कर की तुलना में प्रशासनिक दृष्टि से ज्यादा कठिन होगा, लेकिन यह धाय-कराधान की एक व्यापक एवं प्रभावपूर्ण प्रणाली के संचालन से ज्यादा कठिन नहीं होगा। इसके विपरीत वैयक्तिक कराधान की ऐसी प्रणाली में जिसमें आय (पूरीगण लाभ सहित) और सम्पत्ति दोनों पर कर लगे हुए हैं, सर्व-कर के दायित्व पर लिए जाने से कर की बोरी को रोकने में काफी सहूलियत हो जायगी। ऐसा ध्यान तो इसलिए होगा कि सर्व-कर विशेष सौदों को छिपाने के सम्बन्ध में विभिन्न

दलों के बीच हितों का विरोध उत्पन्न कर देगा (जब कि वर्तमान व्यवस्था में यह सम्भव है कि एक सौदे से सम्बन्धित दोनों दलों का समान हित इस बात में हो कि एक विशेष सौदे के मूल्य को या तो पूर्णतया छिपा लिया जाय अथवा उसे कम करके बतलाया जाय), और अंशतः इसलिए भी होगा कि एक विशेष अवधि में वैयक्तिक कार्यों पर व्यय की गई धन-राशि का हिसाब देने की आवश्यकता के कारण एवं साथ में अवधि के प्रारम्भ एवं अन्त में वैयक्तिक विद्युत् धन के सन्तुष्ट को प्रस्तुत करने के दायित्व के कारण करदाता प्राप्त राशियों को पूर्ण रूप से बतलाने के लिए बाध्य हो; ठीक उसी तरह जिस तरह कि वास्तु प्राप्तियों एवं व्यय का पूरा प्रविवरण देने की आवश्यकता करदाता को पूँजीगत परिसम्पत्तियों की सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए बाध्य करती है।

67. यह भी स्मरण रखना होगा कि जो वैयक्तिक सर्व व्यावसायिक सर्व-साधों अथवा नगद की बजाय वस्तु रूप में दिये गये सामानों से पूरे किये जाते हैं उनकी समस्या तो पहले ही आयकर के अन्तर्गत उत्पन्न होती है। जब एक करदाता पर वैयक्तिक सर्व और आयदनी दोनों का विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व होगा तो आयकर की चोरी के ऐसे मामलों का पता लगाना अपेक्षाकृत सुगम हो जायगा क्योंकि ये मामले वैयक्तिक सर्व के अन्तर्गत दिसलाई जाने वाली अत्यधिक नीची राशि से स्वतः प्रगट हो जायेंगे। स्पष्ट है कि सर्व-कर लागू करने से आय-कर प्रशासन-कार्य बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी हो जायगा। किसी व्यक्ति के लिए यह तो सम्भव ही सचता है कि वह अपने सर्व का भाग अपनी प्राप्तियों के उतने ही भाग को छिपाकर अथवा स्वयं के सर्वों के कुछ भाग का भुगतान किसी दूसरे से करवा कर (अपने व्यावसायिक नियोजन अथवा किसी भिन्न अथवा नीची आय वाले अपने किसी सम्बन्धी से) छिपावे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ करदाता के द्वारा प्रविवरण में बतलाई जाने वाली स्वयं के सर्व की राशि उसके जीने के अंग से स्पष्टतः बेमेल प्रतीत होती है वहाँ तक इस तरह से छिपा सकना सम्भव नहीं होता है।

मेरा विश्वास है कि आयकर अधिकारियों का अनुभव इस बात को प्रमाणित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के सर्व के सम्बन्ध में वास्तु सशर्तों से काफी निश्चित ढंग से अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं होता है, लेकिन पर्याप्त



निश्चितता से ऐसा व्यवसाय किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके कई मकान, बहुत से नौकर-चाकर एवं कई कारें हैं और जो प्रायः मनोरंजन पर व्यय किया करता है, वह प्रति वर्ष अपने वास्तविक व्यय में से कुछ हजार रुपये कम करके भले ही दिखलादे, लेकिन उसके लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह अपने प्रविवरण में 10,000 रु० की राशि बतलादे जब कि वस्तुतः उसने 50,000 रु० अथवा 1,00,000 रु० व्यय किये हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में वह किसी भी सीमा तक सलत तरीकों से छिपाकर अपनी आमदनी को कम दिखा सकता है, अथवा अपनी आय को पूंजीगत सामों में परिवर्तित करके करदेय आय में कमी दिखा सकता है अथवा सम्पत्ति को ट्रस्टों एवं बन्धो-बस्तों में हस्तान्तरित करके अधिकर (Super tax) में कमी करवा सकता है।

जहां तक कृषिगत आय का सम्बन्ध है संवैधानिक स्थिति तो खर्च-कर के पक्ष में ही प्रतीत होती है। संविधान में खर्च-कर को विशिष्ट रूप से केन्द्र अथवा राज्यों को नहीं दिया गया है और न उसमें कहीं पर यह बतलाया गया है कि कृषिगत आय में से किये जाने वाले खर्च पर (जो कृषिगत आय से भिन्न होता है) केन्द्र की तरफ से कर नहीं लगना चाहिए। अतः मेरे विचार में वैयक्तिक खर्च पर लगाया जाने वाला कर वैधानिक होता है, चाहे खर्च किसी भी स्रोत से क्यों न किया गया हो, और इससे प्राप्त होने वाली आय संविधान की सातवीं सारणी की प्रथम सूची की 97 वीं मद के अन्तर्गत पूर्णतया केन्द्र की ही मानी जा सकती है।

भारत में विगत जन-समुदाय के उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर के इतने समीप हैं कि मेरे विचार में धार्मिक विकास की अपेक्षाकृत ऊँची दर को बनाये रखने के लिए धनिक-वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति में कमी लाना नितान्त आवश्यक जान पड़ता है। सब धूँटा जाय तो विलासितायों का उपभोग ही राष्ट्रीय सर्वे का वह भाग है जिसमें पूँजी संचय की अपेक्षाकृत ऊँची दर के लिए साधन जुटाने के वास्ते कमी की जा सकती है; और वैयक्तिक उपभोग पर लगाया जाने वाला प्रतिक आरोही कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से निस्संदेह एक भारी साधन माना जा सकता है।

II. सर्वे की परिभाषा और कर-निर्धारण व अनुक्रमण की विधि (Definition of Expenditure and Mode of Assessment and Graduation)

70. कर का वास्तविक आधार—भीने यह और भी स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि करदाता को सामान्यतया उपभोग पर किये जाने वाले अपने व्ययों का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती ॥ (बल्कि अपनी समस्त प्राप्त-राशियों, विनियोगों आदि, और उन समस्त मद्यों जिनके लिए वह छूट चाहता है, को प्रदर्शित करने वाले व्यापक प्रविवरण के संग के रूप में अपने कुल व्यय का हिसाब ही देना होता है), फिर भी इस दर के कानूनी आधार के रूप में तो वैयक्तिक उपभोग (अथवा सर्वे) की प्रति दिन के काम की एक उचित धारणा होनी ही चाहिए जिसमें न केवल वे भवें ही जो करदाता के स्वयं के सर्वे से पूरी की जाती हैं, बल्कि वस्तु-रूप में प्राप्त होने वाले लाभों एवं उपहारों में से लिया गया उपभोग एवं नियोजित, मित्र अथवा सम्बन्धी के द्वारा भरे गये सर्वे भी शामिल हों, हालांकि ऐसे उपहारों अथवा लाभों के लिए एक वार्षिक छूट की सीमा हो, जैसे प्रति वर्ष 2000 रु०। यदि यह कर इस तरह से परिभाषित वैयक्तिक उपभोग पर निर्भर करता ॥ तो कम व्यय करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों आदि को उपहार देकर (ताकि बदले में ऐसे व्यक्ति करदाता के सर्वे का कुछ भंडा खुरा दें) किये जाने वाले कर टालने के प्रयत्न, अथवा अपने निजी विलों का भुगतान नियोजितों या व्यवसायियों से करवा कर किये जाने वाले कर टालने के प्रयत्न विलगुल भी सम्भव नहीं हो सकेंगे। वास्तव में करदाताओं से तो वैयक्तिक उपभोग के लिए प्राप्त समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर ही कर लिया जायगा, चाहे इनके लिए भुगतान किसी ने भी और कैसे भी क्यों न किया हो।

प्रत्येक भवितव्य सचने जैसे शान्तिपूर्ण पर, करदाता की इच्छा के अनुसार पाँच वर्ष प्रत्येक सम्भवतया दस वर्ष की अवधि पर फैलाये जा सकते हैं। चूंकि एक आरोग्य या प्रतापी प्रणामी के अन्तर्गत ऐसे भवितव्य व्यय के कारण प्राप्त होने वाली कर की छूट स्वतः अपने एक आगामी वर्षों में करदाता के लिए कर योग्य व्यय की राशि को बढ़ा देगी, इसलिए इन तरह का फैलाव करदाता के हित में नहीं होगा, निम्नलिखित हमारे कि यह एक अवधि में उनके व्यय की दर को समान करने में वास्तविक सहायता प्रदान करेगा। अतः इन श्रेणियों में उक्त तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी जिस तरह के प्रमाण की आवश्यकता ऊपर पैरा 71 में (घ) से (ई) तक की श्रेणियों के अन्तर्गत छूट की माँग करने के लिए हुई थी।<sup>1</sup>

### कर-निर्धारण और क्रम-निर्धारण की विधि (Mode of Assessment and Graduation)

74. चूंकि इस कर का उद्देश्य सर्व पर सेजी से बढ़ने वाली सीमांत दरों को लगाकर व्यय के ऊँचे स्तर को निरसाहित करना है, इसलिए आयकर की अपेक्षा इस कर में यह ज्यादा आवश्यक होगा कि आवश्यकताओं के उन अंतरों पर ध्यान दिया जाय जो करदाता के द्वारा पालन-पोषण विधे जाने वाले परिवार के आकार के अंतरों से उत्पन्न होते हैं। अतः आयकर के विपरीत (जहाँ प्रारम्भिक छूट की राशि के परिवर्तन से कर के दायित्व में बहुत मामूली-सा अंतर ही आता है) सर्व-कर की दरों में सम्पूर्ण परिवार के कुल सर्व की अपेक्षा प्रति व्यक्ति सर्व की राशि के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि तथाकथित भागफल की प्रणाली (quotient system) को अपनाया जाय जो आयकर के लिए पहले से ही फ्रांस में चल रही है। इसके अन्तर्गत एक परिवार के सभी सदस्यों की आय (या सर्व) को पहले जोड़ लिया जाता है, फिर उसे प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कई टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, और प्रत्येक अंश पर अलग-अलग कर वसूल किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को प्राचीन इकाई के बराबर माना जा सकता है (यद्यपि यह अर्थ उनकी उम्र व संख्या के अनुसार

1. एक वैकल्पिक विधि यह होगी कि कर के उद्देश्य ■ लिए समस्त सर्व को फैलाने की इजाजत दी जाय और कर की राशि एक विशेष वर्ष के वास्तविक सर्व की अपेक्षा पिछले पाँच वर्षों के व्यय की परिवर्ती (moving) औसत के अनुसार माँकी जाय।

बदला जा सकता है।) स्त्री एवं बच्चों के धलावा "परिवार" की धारणा में एक संयुक्त परिवार में रहने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों को शामिल करने की इजाजत भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उनकी प्राप्त-राशियाँ आमदनी व सम्पत्ति कर के लिए परिवार के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ दी जाती हैं। लेकिन ऐसे प्रतिरिक्त सदस्यों को भी उसी तरह गिनना उचित होगा जिस तरह से कि बच्चों में प्रत्येक को पूरी द्काई व मानकर उस के रूप में माना जाता है। इसका कारण यह है कि, एक दिये हुए जीवन-स्तर को मान लेने पर, समग्र पारिवारिक खर्च में एक परिवार के सदस्यों में होने वाली वृद्धि की तुलना में अनुपात से कम वृद्धि ही होती है। अतएव मेरा यह सुभाव है कि प्रतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों को कमरा: घटे हुए कम में बयस्क इकाइयों में बदला जाना चाहिए ताकि जैसे बार सदस्यों के परिवार को तीन बयस्क इकाइयों के बराबर गिना जाय, सात सदस्यों के परिवार को चार बयस्क इकाइयों के बराबर माना जाय और एक परिवार के लिए बयस्क इकाइयों की अधिकतम संख्या पाँच रखी जानी चाहिए। इसका आशय यह है कि एक बड़े परिवार के सम्बन्ध में कर का न्यूनतम दायित्व जानने के लिए कुल पारिवारिक खर्च को पाँच से विभाजित किया जाता है, और इस दायित्व का पाँच गुना किया जाता है।

75. जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, कर लगाने की इस विधि की पूर्व-शर्त यह है कि परिवार के सदस्यों की समस्त प्राप्तियों, आमदनी व सम्पत्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ लगाया जाना चाहिए। मद्यपि, सिद्धान्ततः ऐसा योग (aggregation) बिना आय व सम्पत्ति करों पर लागू किये केवल खर्च कर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि इस तरह के जोड़ के नियम वैयक्तिक कराधान की सभी बिस्मों पर समान रूप से लागू किये जाते हैं तो यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्पष्टतः ज्यादा सुविधाजनक होगा। इंग्लैंड के विपरीत भारत में कर के लिए पति-पत्नी की साथ स्वतः मही जोड़ ली जाती है, हालांकि कर को टालने के विपरीत ऐसी विविष्ट व्यवस्थाएँ हैं जो साझेदारी के घरों आदि के सम्बन्ध में जोड़ या एकत्रीकरण

1. इसका आशय यह है कि यदि एक परिवार में दो प्रौढ़ व्यक्ति हैं तो उसे एक घरेलू व्यक्ति की तुलना में जिसका खर्च आधा है दुगुना कर देना होगा, एक विवाहित दम्पति जिसके दो बच्चे हैं, उसे एक घरेलू व्यक्ति की तुलना में जिसका व्यय संयुक्त पारिवारिक व्यय का एक-तिहाई है, तिगुना कर देना होगा, इत्यादि।

घरवा घणामान्य सचं जैसे धादियों पर, करदाता की इच्छा के अनुसार वीन वपे घरवा मभभवतया दम वर्ग की अवधि पर फैलावे जा सक्ने है। चूंकि एक आरोगी या प्रगामी प्रगाली के अन्तर्गत तेने घणामान्य ध्यय के कारण प्राप्त होने वाली कर की छूट स्वयं समयसे एवं आगामी वर्षों में करदाता के लिए कर योग्य ध्यय की राशि को बढ़ा देगी, इसलिए इस तरह का फैलाव करदाता के हित में नहीं होगा, निवाय इसके कि यह एक अवधि में उसके ध्यय की दर को समान करने में वास्तविक सहायता प्रवश्य करेगा। अतः इन श्रेणियों में उस तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी जिन तरह के प्रमाण की आवश्यकता ऊपर पैरा 71 में (घ) से (ई) तक की श्रेणियों के अन्तर्गत छूट की मांग करने के लिए हुई थी।<sup>1</sup>

### कर-निर्धारण और घम-निर्धारण की विधि (Mode of Assessment and Gradation)

74 चूंकि इस कर का उद्देश्य सचं पर तेजी से बढ़ने वाली सीमान्त दरों को लगाकर ध्यय के ऊंचे स्तर को निरस्तारहित करना है, इसलिए भागकर की अपेक्षा इस कर में यह ज्यादा आवश्यक होगा कि आवश्यकताओं के उन घंतरों पर ध्यान दिया जाय जो करदाता के द्वारा पालन-पोषण विधे जाने वाले परिवार के आकार के घंतरों से सत्यप्र होते हैं। अतः भागकर के विपरीत (जहाँ प्रारम्भिक छूट की राशि के परिवर्तन से कर के दायित्व में बहुत मामूली-सा घंतर ही आता है) सचं-कर की दरों में सम्पूर्ण परिवार के कुल सचं की अपेक्षा प्रति व्यक्ति सचं की राशि के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। इसका आशय यह है कि तथाकथित भागफल की प्रणाली (quotient system) को अपनाया जाय जो भागकर के लिए पहले से ही कांस में प्रचल रही है। इसके अन्तर्गत एक परिवार के सभी सदस्यों की आय (या सचं) को पहले जोड़ लिया जाता है, फिर उसे प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कई टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, और प्रत्येक घंश पर अलग-अलग कर वसूल किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को आधी इकाई के बराबर माना जा सकता है (यद्यपि यह घंश उनकी उम्र व सस्या के अनुसार

1. एक वैकल्पिक विधि यह होगी कि कर के उद्देश्य के लिए समस्त सचं को फैलाने की इजाजत दी जाय और कर की राशि एक विशेष वर्ष के वास्तविक सचं की अपेक्षा पिछले पाँच वर्षों के ध्यय की परिवर्ती (moving) औसत के अनुसार माँकी जाय।

बदला जा सकता है।) स्त्री एवं बच्चों के घनावा "परिवार" को धारणा में एक संयुक्त परिवार में रहने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों को शामिल करने की इजाजत भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उनकी प्राप्त-राशियाँ आमदनी व सम्पत्ति कर के लिए परिवार के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ दी जाती हैं। लेकिन ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को भी उसी तरह से गिनना उचित होगा जिस तरह से कि बच्चों में प्रत्येक को पूरी इकाई न मानकर बचत के रूप में माना जाता है। इसका कारण यह है कि, एक दिये हुए जीवन-स्तर को मान लेने पर, समग्र पारिवारिक सर्वे में एक परिवार के सदस्यों में होने वाली वृद्धि की तुलना में अनुपात से कम वृद्धि ही होती है। अतएव भेदा यह सुभाव है कि अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों को क्रमशः घटते हुए क्रम में बचत इकाइयों में बदला जाना चाहिए ताकि जैसे-जैसे परिवार को तीन बचत इकाइयों के बराबर गिना जाय, सात सदस्यों के परिवार को चार बचत इकाइयों के बराबर माना जाय और एक परिवार के लिए बचत इकाइयों की अधिकतम संख्या पाँच रखी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक बड़े परिवार के सम्बन्ध में कर का न्यूनतम दायित्व जानने के लिए कुल पारिवारिक सर्वे को पाँच से विभाजित किया जाता है, और इस दायित्व का पाँच गुना किया जाता है।

75. जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, कर लगाने की इस दिधि की पूर्व-शर्त यह है कि परिवार के सदस्यों की समस्त प्राप्तियों, आयदनी व सम्पत्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ लगाया जाना चाहिए। यद्यपि, सिद्धान्ततः ऐसा योग (aggregation) बिना आय व सम्पत्ति करों पर लागू दिये बेबल सर्वे कर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि इन तरह के जोड़ के नियम वैयक्तिक कराधान की सभी विस्मियों पर समान रूप से लागू दिये जाते हैं तो वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्पष्टतः ज्यादा सुविधाजनक होगा। इन्हीं के विपरीत भारत में कर के लिए परिवार की आय स्वयः नहीं जोड़ भी जाती है, हालाँकि कर को टाँपने के विपरीत ऐसी विविध व्यवस्थाएँ हैं जो साझेदारी के घरों आदि के सम्बन्ध में जोड़ या एक्कीकरण

1. इसका अर्थ यह है कि यदि एक परिवार में दो जोड़ द्यति है तो उसे एक घरेलू द्यति की तुलना में जिसका सर्वे आया है दुगुना कर देना होगा, एक विवाहित दम्पति जिसके दो बच्चे हैं, उसे एक घरेलू द्यति की तुलना में जिसका द्यत मनुक्त पारिवारिक द्यत का एक-तिरार्द है, दुगुना कर देना होगा, इत्यादि।

को धारक बना देती है और इनमें परिवार के सदस्यों के बीच धाय और सम्पत्ति के हस्तांतरणों पर कर के उद्देश्यों के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन विभिन्न करदाताओं के बीच यह ज्यादा ग्राह्योचित होगा कि पति-पत्नी व नाबालिग बच्चों (कानूनी पृथक्करण को छोड़कर) एकत्रीकरण का एक ही सामान्य नियम धाय और सम्पत्ति करें एवं संच-कर के लिए प्रयुक्त किया जाय। परिवार के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में धाय व सम्पत्ति करने के लिए तो एकत्रीकरण या जोड़ ऐच्छिक होगा, लेकिन संच-कर के लिए एकत्रीकरण एक अनिवार्य पूर्व-सर्त के रूप में माना जायेगा।

# शब्दावली

(अंग्रेजी-हिन्दी)

Ability to Pay	कर-दान क्षमता या करदेय क्षमता
Accrued Income	उपार्जित आय
Allocation	आवटन, वितरण
Amortisation	भूण-परिशोध
A priori Analysis	नितम्य विरलेषण
Asset	परिसम्पत्ति
Balanced Budget Incidence	संतुलित बजट करापात
Betterment Levy	मुधार-कर
Bounty	आर्थिक सहायता
Budgetary surplus	बजट-अतिरेक
Cess	उपकर
Collective Consumption	सामूहिक उपभोग
Convexity	उन्नतोदरता
Corporate Sector	निगम-क्षेत्र
Deficit Financing	घाटे की वित्त-व्यवस्था
Deflationary	अपस्फीतिकारी
Demand Function	मांग-फलन
Differential Incidence, Tax	भेदात्मक करापात
Disguised Unemployment	छिपी हुई बेरोजगारी
Disincentive Effect	प्रेरणाहारी प्रभाव
Disposable Income	प्रयोज्य आय, खर्च कर सकने योग्य आय
Distorting Effect	विपरीत या विकृत प्रभाव
Diversification Effect	मोड़-प्रभाव, व्यपवर्तन-प्रभाव
Diversification of Resources	साधनों का मोड़ या व्यपवर्तन
Duties	शुल्क
Dynamic	प्रार्वैगिक
Employer	नियोक्ता



Equal ad valorem Outlay Tax	समान मूल्यानुसार व्यय-कर
Equity	भ्यास, समानता
Employment oriented	रोजगारोन्मुख
Entrepreneurship	उद्यमशीलता
Estate Duty	मृत-सम्पत्ति कर
Fiscal Analysis	राजकोषीय या राजस्व विश्लेषण
Fiscal Operation	राजस्व-क्रिया
General Equilibrium	सामान्य समुत्तन
Grants	अनुदान
Horizontal Equity	क्षैतिज समानता
Impact of Tax	करापात, करदेयता
Implicit Assumptions	अभ्यक्त मान्यताएं या प्रच्छन्न मान्यताएं
Incentive Effect	प्रेरणाजन्य प्रभाव
Incidence of Tax	करबाह्यता, करापात
Incidence, Formal and Effective	घोषचारिक एवं प्रभावपूर्ण करबाह्यता
Incremental Saving Ratio	वचत वृद्धि-अनुपात
Indifference Map	सदस्पर्ता-मानचित्र या समभाव- मानचित्र
Individual Consumer	वैयक्तिक उपभोक्ता
Income Tax Function	आयकर-फलन
Initiative	पहल
Investment	विनियोग, निवेश
Interpersonal Comparison	अन्तर्व्यक्तिगत तुलना
Inter-vivos gift	एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाने वाला उपहार
Inconsistencies	वर्तपतियों
Lag	विलम्ब, पश्चात्तन
Laissez Faire	निर्बाध-नीति
Maladjustment	कुसमायोजन या कुसमंजन
Marketing	विपणन
Mode of Assessment	कर-निर्धारण विधि
Monetary Purge	मौद्रिक मार्जन

Monetised Economy	मुद्राधारित अर्थ-व्यवस्था
Net Rate of Return	प्रतिफल की विशुद्ध दर या खरी दर
Non-agricultural	कृषीतर
Non-development	विकासेतर
Non-tax	करेतर
Oligopoly	अल्पविक्रेताधिकार
Partial Equilibrium	आंशिक संतुलन
Poll Tax	प्रतिव्यक्ति कर
Potential Saving	सम्भाव्य बचत
Product Mix	वस्तु-मिश्रण
Progression	आरोहीपन
Progressive Tax	आरोही या प्रगामी कर
P propensity to Consume	उपभोग-प्रवृत्ति
Proportional	आनुपातिक
Proposition	प्रस्तापना
Psychic Income	काल्पनिक आय
Readjustment	पुनर्मंमाणोजन
Realised Income	वसूल या प्राप्त हो चुकी आय
Regressive Tax	अवरोही या प्रतिगामी कर
Regressivity	अवरोहीपन, प्रतिगामिता
Revenue Account	राजस्व-खाता
Revenue Approach	आय-दृष्टिकोण
Skewness	वैषम्य
Shifting of Tax	करान्तरण, कर का हस्तांतरण
Social Welfare Function	कर-भार विवा
Specific Incidence of Tax	सांघाजिक कल्याण-फलन
Specific Tax	विशिष्ट करापात
Stratification	विशिष्ट कर
	स्थैतिक
	जीवन-निर्वाह या गुजर-बसर करने
	वाले कृषक
	आवधिक, अतिरिक्त या अधिक

<b>Tax-System, Depth and Range</b>	कर-प्रणाली में गहनता व व्यापकता
<b>Taxable Capacity</b>	कर-देय क्षमता या सामर्थ्य
<b>Taxation</b>	कराधान, करारोपण
<b>Taxation Enquiry Commission</b>	कराधान जाँच आयोग
<b>Tax Evasion</b>	कर-इवन या कर छिपाना
<b>Tax Formula</b>	कर-सूत्र
<b>Tax Liability</b>	कर-देयता
<b>Tax Structure</b>	कर का ढाँचा
<b>Transfer Deed</b>	हस्तान्तरण दस्तावेज
<b>Trustee</b>	निक्षेपधारी, ट्रस्टी, ग्वास्ती
<b>Valuation</b>	मूल्यांकन
<b>Vertical Equity</b>	सम्बन्धित या उद्विग्न समानता

---

